वार्षिक प्रतिवेदन 2017 – 2018
Annual Report 2017-2018

प्रणीति अनुसंधान केंद्र
CENTRE FOR POLICY RESEARCH

दूरदृष्टि विवरण

*दूरदृष्टि सार्वजनिक नीति अनुसंधान और शिक्षण के क्षेत्रों में राय बनाने के कार्यकलापों में संलग्न प्रभावशाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक में अग्रणी बनना।

*उद्देश्य प्रणीति अनुसंधान केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. निम्नलिखित से संबंधित मामलों में अनुसंधान का आयोजन और प्रोत्साहन

   क) पर्याप्त नीति विकल्पों का विकास;
   ख) नीति के मार्गदर्शन की उपयुक्त सैद्धांतिक रूपरेखा का निर्माण;
   ग) सघन नीति विश्लेषण के माध्यम से भावी परिदृश्यों की भविष्य वाणी करना;
   घ) नीति निर्धारण से संबंधित सभी विषयों में ज्ञान का एक आधार निर्मित करना।

2. नीति आयोजना और प्रबंधन क्षेत्रों में शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना, प्रोत्साहन देना और सुविधा प्रदान करना तथा इस प्रयोजन हेतु सम्मेलनों, गोष्ठियों, अध्ययन पाठ्यक्रमों, व्याख्यानों और समान प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करना;

3. सरकार, सार्वजनिक निकायों, निधि क्षेत्र या इस मामले से जुड़ी किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी सहित अन्य संस्थानों को सलाहकार सेवाएं प्रदान करना और जो इसका निष्पादन करते हैं, सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए राष्ट्रीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना;

4. जर्नलों, रिपोर्ट, पैम्फलेट तथा अन्य साहित्य और अनुसंधान पत्रों एवं पुस्तकों आदि के प्रकाशन के लिए नीतिगत मुद्दों पर सूचना का प्रसार और नीति बनाने तथा इससे संबंधित क्षेत्रों पर जानकारी देने और प्रदान करने पर जानकारी का प्रसार;

5. विधानों के साथ समन्वय करते हुए नीतिगत मुद्दों पर वाद–विवाद में जनता को शामिल करना, नीतिगत सार तैयार करना; और

6. अनुसंधानकर्ताओं का एक समुदाय तैयार करना।

*की गई गतिविधियों / विषयों की सूची

1ण राजनैतिक मुद्दे और शासन;
2ण अंतरराष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति/कूटनीति;
3ण राष्ट्रीय, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक नीति के मुद्दे;
4ण सुरक्षा – आंतरिक और बाहरी;
5ण सार्वजनिक सेवा आपूर्ति नीति ;
6ण संस्थागत अभिकल्पना;
7ण नागरिक समाज;
8ण पूंजीवाद का विनियमन;
9ण जनसंख्या, सार्वजनिक कल्याण सेवाएं और धारणीय विकास;
10ण संविधानिक और कानूनी सिद्धांत;
11ण सुधार का सूक्ष्म प्रबंधन देने हेतु संस्थागत और प्रशासनिक ढांचा तैयार करना;
12ण दक्षिण एशियाई और अन्य एशियाई देशों में मुख्य रूप से संबंध बढ़ाने के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों से बातचीत करना;
13ण अवसंरचनात्मक विकास के लिए क्षेत्रगत नीतियां (ऊर्जा के साथ विद्युत शक्ति, दूर संचार, सड़कें, पत्तन, हवाई अड्डे आदि); और
14ण पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर के विशेष संदर्भ सहित राज्यों के बीच क्षेत्रीय विकास।

सामान्य जानकारियों के लिए कृपया संपर्क करें :
अध्यक्ष का कार्यालय
प्रणीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली – 110021 (भारत)
टेलीफोन : 91–11–2611–4797; फैक्स : + 91–11–2687–2746
ई–मेल : president.cpr@cprindia.org वेबसाइट : http://www.cprindia.org

वार्षिक प्रतिवेदन

2017 – 2018

प्रणीति अनुसंधान केंद्र
धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली–110021 (भारत)

विषय – सूची

1.	दूरदृष्टि विवरण	आंतरिक मुखपृष्ठ
2.	प्रणीति अनुसंधान केन्द्र शासी मंडल	6
3.	सीपीआर की कार्यकारिणी समिति	8
4.	अध्यक्ष की रिपोर्ट	9
5.	शोध प्रकाशन	11
6.	चर्चाएं, बैठकें और संगोष्ठी / कार्यशालाएं	12
7.	प्रणीति अनुसंधान केंद्र के प्रयास	24
8.	वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाएं	35
9.	संकाय समाचार	65
10.	अनुसंधान सहयोगियों की गतिविधियां	100
11.	पुस्तकालय और सूचना एवं प्रसार सेवाएं	114
12.	कंप्यूटर केंद्र की गतिविधियां	115
13.	अनुदान	116
14.	प्रणीति अनुसंधान केन्द्र के दानदाताओं को कर से छूट	117
15.	सीपीआर संकाय और कर्मचारी गण	118

प्रणीति अनुसंधान केन्द्र शासी मंडल

(31 मार्च 2018 के अनुसार)

1.	श्री ऐरिक गोंसाल्वेज पूर्व सचिव, भारत सरकार सी–52, आईएफएस को–ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी मयूर विहार, फेज – 1, नई दिल्ली – 110 091	अध्यक्ष
2.	श्री सुबोध भार्गव अध्यक्ष, टाटा टेलीकॉम लि. ए–15/1, डीएलएफ सिटी, फेज – 1, गुड़गांव – 122 001	सदस्य
3.	डॉ. (सुश्री) मीनाक्षी गोपीनाथ निदेशक, डब्ल्यूआईएससीओएमपी ए–86 निजामुद्दीन पूर्वी नई दिल्ली – 110 013	सदस्य
4.	सदस्य – सचिव भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् अरुणा आसफ अली मार्ग नई दिल्ली 110 067	सदस्य
5.	अम्ब. श्याम सरन वरिष्ठ अध्येता प्रणीति अनुसंधान केंद्र धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली 110021	सदस्य
6.	सुश्री. विनीता बाली पूर्व सीईओ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लि. 1104 प्रेस्टिज एक्ज़ोटिका #3 कनिंघम क्रिसेंट रोड बैंगलोर 560 052	सदस्य

7. सुश्री. रामा बीजापुरकर — सदस्य
206, निर्माण केंद्र
डॉ. ई मूसा रोड, महालक्ष्मी
मुंबई 400 011
टेली : 022–24937243 / 24932053

8. अम्ब. चंद्रशेखर दासगुप्ता — सदस्य
पूर्व राजदूत और प्रसिद्ध इतिहासकार
सी–12 / 11, डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव
फेज–1ए गुड़गांव 122 002

9. श्री केशव देसीराजू — सदस्य
पूर्व सचिव, **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय**
फ्लैट नं. बी–25, राधाकृष्णन सलाई
9वां स्ट्रीट, मायलापुर
चेन्नई 600 004

10. यामिनी अय्यर — सदस्य – सचिव
अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी
प्रणीति अनुसंधान केन्द्र
धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली – 110 021

सीपीआर की कार्यकारिणी समिति

(31 मार्च 2018 के अनुसार)

1.	श्री ऐरिक गोंसाल्वेज पूर्व सचिव, भारत सरकार सी–52, आईएफएस को–ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी मयूर विहार, फेज – 1 नई दिल्ली – 110 091	अध्यक्ष
2.	डॉ. (सुश्री) मीनाक्षी गोपीनाथ निदेशक, डब्ल्यूआईएससीओएमपी (WISCOMP) ए–86 निजामुद्दीन पूर्वी नई दिल्ली – 110 013	सदस्य
3.	अम्ब. श्याम सरन वरिष्ठ अध्येता प्रणीति अनुसंधान केंद्र धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली 110021	सदस्य
4.	यामिनी अय्यर अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी प्रणीति अनुसंधान केन्द्र धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली – 110 021	सदस्य – सचिव

अध्यक्ष की रिपोर्ट

मेरे लिए 2017–18 हेतु सीपीआर की वार्षिक रिपोर्ट पेश करने का यह एक वास्तविक विशेषाधिकार है। यह एक शानदार उत्पादक वर्ष रहा है क्योंकि सीपीआर संकाय क्षेत्र–परिभाषित पुस्तकों और सहकर्मी–समीक्षा वाली पत्रिकाओं के लेखों की एक स्थिर धारा के माध्यम से नीति अनुसंधान परिदृश्य में महत्वपूर्ण, पुरस्कार विजेता के तौर पर योगदान देना जारी रखता है। ये योगदान अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, घरेलू राजनीति और सार्वजनिक सेवा वितरण के रूप में विस्तृत मुद्दों पर नीति और सार्वजनिक बहस का प्रारंभिक बिंदु हैं। इस वर्ष हमें विशेष रूप से लवण्या राजमणि पर गर्व है, जिनके सह–लेखन में पुस्तक इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज लॉ को अंतरराष्ट्रीय कानून के एक विशेष क्षेत्र में 2018 अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया गया।

सीपीआर में भारत में नीति बनाने के रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होने, विचारों को आकार देने, विशेषज्ञता प्रदान करने और नीति निर्माताओं के साथ साझेदारी में कठिन नीतियों के जवाब खोजने के लिए अपने शोध करने की एक लंबी परंपरा रही है। इस भूमिका को पूरा करने में, इस वर्ष के दौरान सीपीआर संकाय ने 20 विभिन्न सरकारी समितियों, कार्यबलों और तकनीकी सहायता इकाइयों के रूप में कई लोगों की सेवा की है। इनमें कम कार्बन विकास के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) सलाहकार समिति शामिल हैं; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के तहत नवीकरणीय ऊर्जा अधिनियम पर विशेषज्ञ समिति; पृथ्वी के दुर्लभ तत्वों पर राष्ट्रीय कार्यनीति के लिए नीति आयोग की समिति; शिक्षा पर कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन (एनयूईपीए) में पाठ्यचर्या सलाहकार समिति; और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा विकलांगता, पेयजल, स्वच्छता, स्वच्छता और आवास की स्थिति पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 76 वें दौर के लिए कार्यकारी समूह।

शिक्षा जगत और पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स के तौर पर हम समाचार पत्रों और राय पृष्ठों में लेखन के माध्यम से एक तेजी से ध्रुवीकृ त सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ बारीकियों और साक्ष्यों को लाने की भी तलाश करते हैं। 2017–18 में, सीपीआर शोधकर्ताओं और संकाय ने मुख्यधारा के मीडिया में 432 लेख और संपादकीय लिखे थे। इसके अलावा, हमने डॉकलाम संकट और भारत–चीन संबंधों से लेकर वायु प्रदूषण, पार्टी राजनीति और चुनाव जैसे घरेलू चिंताओं के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर कई गोष्ठियां और सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किए। यह वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करता है लेकिन सीपीआर में हम कार्य की विस्तृत श्रृंखला में एक झलक देखते हैं और मुझे आशा है कि जैसे ही आप इन सामग्रियों को पढ़ लेंगे, आप भी हमारी बौद्धिक जिज्ञासा और सरोकारों में हिस्सा लेंगे क्योंकि हम भारत में नीतिगत बहस को बेहतर तरीके से समझना और उसे समृद्ध करना चाहते हैं।

वर्ष 2017–18 सीपीआर के संस्थागत प्रक्षेपण में एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। हमने नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू किया और मुझे इस अद्भुत संस्थान का नेतृत्व करने का सम्मान और विशेषाधिकार दिया गया है। इस बदलाव के लिए हमारे बोर्ड, निधि प्रदाता और शैक्षिक और नीति भागीदारों के पर्याप्त समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया था। हम उस भरोसे के लिए बहुत आभारी हैं जो उन्होंने हमारे ऊपर दर्शाया है। जैसे–जैसे हम अपने संस्थागत जीवन में एक नए चरण पर कदम रखते हैं, सीपीआर पूरी स्वतंत्रता के हमारे मूल मूल्यों, विचारों और तर्क के प्रति प्रतिबद्धता, कठिन प्रश्न पूछने और साक्ष्य का आकलन करने की इच्छा की दृढ़ता हेतु प्रतिबद्ध है। और हम आपके समर्थन पर भरोसा करेंगे क्योंकि हम इन मूल्यों को मानते हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं।

मैं सीपीआर संकाय के लिए भी व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उत्कृष्टता और साहस की खोज करने की प्रतिबद्धता प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत हैं। मैं अपने युवा शोध सहयोगियों के लिए विशेष रूप से आभारी हूं जिनकी ऊर्जा, सक्रियता और जिज्ञासा यह सुनिश्चित करती है कि हम एक जीवंत, अत्याधुनिक संस्था बने रहें। ऋचा बंसल के नेतृत्व में हमारी संचार टीम जो लगातार हमारे संस्थान पर लगातार इसका मार्ग बनाती है कि हमारे शोध का उपयोग दुनिया के साथ जुड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सके और हमारे समर्पित प्रशासनिक स्टाफ श्रीमान रवि के नेतृत्व में हमारे संस्थान का आधार हैं। सीपीआर बोर्ड के अध्यक्ष, श्री गोंसाल्वेस, कार्यकारी समिति के सदस्य, मीनाक्षी गोपीनाथ और श्याम सरन, हमेशा शक्ति का स्रोत रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से इस साल संस्थान के रूप में एक बदलाव हुआ था। मैं उन सभी संगठनों और व्यक्तियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमें निधि देते हैं। वे अपने इस समर्थन में अनुकरणीय रहे हैं।

समाप्त करने से पहले, मैं सीपीआर में मानद अनुसंधान प्रोफेसर डॉ अजीत मजुमदार को याद करना चाहूंगा, जिनका निधन 2018 की शुरुआत में हो गया था। डॉ. मजुमदार के जीवन के कार्य, शैक्षिक उत्कृष्टता के प्रति उनके जुनून और प्रतिबद्धता और खुशहाली की भावना ने इससे कहीं आगे बढ़कर, सीपीआर संकाय की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। हम उनकी कमी महसूस करते हैं।

शोध प्रकाशन

वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए :

क. प्रमुख पुस्तकें जो प्रकाशित की गईं

1. हाव इंडिया सीस द वर्ल्ड : कौटिल्य टू द 21 सेंचुरी, श्याम सरन, जगर्नोट, 2017
2. इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज लॉ, डैनियल बोडान्स्की, जुट्टा ब्रून और लवण्या राजमनी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2017 द्वारा सह–लेखन
3. रिथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स इन इंडिया, देवेश कपूर, प्रताप भानु मेहता और मिलन वैष्णव, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मई 2017 द्वारा सह–संपादन
4. सबएल्टर्न अर्बनाइजेशन इन इंडिया, एरिक डेनिस और मैरी–हेलेन जेरा, स्प्रिंगर इंडिया, 2017 द्वारा सह–संपादित
5. डिसपसेस्ड : स्टोरिस फ्रॉम इंडियाज मर्जिन्स, अमोद शाह, अनहद इमान, एनी बाक्सी, अश्विन पराकुल, रिया जॉन, सबा शर्मा, शिखा सेठिया, स्पीकिंग टाइगर पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2017 द्वारा सह–लेखन
6. वॉटर लॉ इन इंडिया, एन इंट्रोडक्शन टू लीगल इंस्ट्रुमेंट्स, सेकेंड एडिशन, फिलिप कुलेट और सुजीत कूनान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2017 द्वारा सह–संपादन

ख. प्रणीति अनुसंधान केंद्र संकाय द्वारा प्रकाशित लेख

वर्ष के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों और लोकप्रिय पत्रिकाओं में प्रणीति अनुसंधान केंद्र के संकाय सदस्यों के लगभग 412 लेख भी प्रकाशित हुए।

सम्मेलन / संगोष्ठी / व्याख्यान

(संस्थान द्वारा आयोजित)

क) राष्ट्रीय

आर्थिक नीति

1. प्रणीति अनुसंधान केंद्र में 3 फरवरी 2017 को एक स्टेप फाउंडेशन के सीईओ और सह–संस्थापक श्री शंकर मरुवादैस द्वारा ''डिजिटल स्पाइन फॉर लर्निंग – एक स्टेप फाउंडेशन'' पर वार्ता।
2. ताज महल होटल, नई दिल्ली में 4 फरवरी 2017 को प्रणीति अनुसंधान केंद्र, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनोमिक रिलेशन्स; इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन; नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनोमिक रिसर्च; और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी द्वारा इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली में 5 मार्च 2016 को संयुक्त रूप से आयोजित ''द यूनियन बजट 2016–17 : रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट परस्पेक्टिव्स'' पर 5–संस्थान की बजट संगोष्ठी।
3. सीपीआर में 16 फरवरी 2017 को सुश्री देबोराह एल वेटज़ेल, वरिष्ठ निदेशक, गवर्नेंस ग्लोबल प्रैक्टिस, वर्ल्ड बैंक द्वारा ''इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड लेसंस लर्न्ट फ्रॉम ब्राज़ील इन डिसेंट्रलाइजेशन'' पर वार्ता।
4. सीपीआर में 17 फरवरी 2017 को मास्टर कार्ड सेंटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, और वैश्विक आर्थिक सलाहकार, मास्टर कार्ड वर्ल्डवाइड में श्री यूवा हेड्रिक वॉन्ग, मुख्य अर्थशास्त्री और शैक्षणिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष द्वारा ''ए वर्ल्ड डिवाइडिड : इमर्जिंग डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक फिशर्स इन द ग्लोबल इकॉनोमी'' पर वार्ता।
5. सीपीआर में 15 फरवरी 2017 को 'जॉब्स जॉबलेसनेस एंड इंडियाज इकॉनोमिक फ्यूचर' पर चर्चा।

6. पैनलिस्ट में शामिल :
   श्री ब्रूस स्टोक्स, प्यू रिसर्च सेंटर में ग्लोबल इकॉनोमिक एटिट्यूड्स के निदेशक और द जस्ट जॉब्स नेटवर्क एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य,
   सुश्री. यामिनी अय्यर, अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकारी, प्रणीति अनुसंधान केंद्र
   सुश्री. सेबिना दीवान, अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक, जस्ट जॉब्स नेटवर्क
7. चर्चाओं सहित :
   डॉ. अजीत घोष, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट
   डॉ. श्रीनिवास अय्यर, फॉर्ड फाउंडेशन, भारत और
   श्री. गुरचरण दास, लेखक और सार्वजनिक बौद्धिक व्यक्तित्व
8. द लीला प्लेस, नई दिल्ली में 10 फरवरी 2018 को प्रणीति अनुसंधान केंद्र, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनोमिक रिलेशन्स; इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन; नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनोमिक रिसर्च;

और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी द्वारा द लीला प्लेस, नई दिल्ली में 10 फरवरी 2018 को 5–संस्थान की बजट संगोष्ठी 2018–19.

पर्यावरणीय कानून और शासन

1. सीपीआर में 23 जनवरी 2017 को डॉ. नरसिम्हा राव, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनालायसिस में प्रोजेक्ट लीडर और रिसर्च स्कॉलर द्वारा ''हाउ मच एनर्जी एंड एमिशंस डज़ इंडिया 'नीड' फॉर डिसेंट लिविंग?'' पर वार्ता।
2. सीपीआर में 7 अप्रैल 2017 को ''प्रेजिडेंट ट्रम्प एक्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन प्रोमोटिंग एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड इम्प्लीकेशन्स फॉर इंडिया'' पर गोल मेज चर्चा। पैनल में शामिल हैं प्रो. लावण्या राजमाणि, डॉ अरुणाभ घोष, डॉ. चंद्र भूषण और डॉ. नवरोज के. दुबेश। डॉ. राधिका घोष द्वारा चर्चा की अध्यक्षता की गई थी।
3. डॉ. जॉनस यर्पेलेनेन, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी द्वारा 'डज बेसिक एनर्जी एसेस जनरेट सोशल – इकॉनोमिक बेनिफिट्स?' पर 29 मई 2017 को वार्ता।
4. सीपीआर में 5 जुलाई 2017 को डॉ. अनंत सुदर्शन जो शिकागो यूनिवर्सिटी (एपिक – भारत) में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के भारतीय निदेशक हैं, द्वारा 'लाइटिंग अप बिहार : इम्प्रूविंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड रिड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूशन लोसेस' पर वार्ता।
5. सीपीआर में 17 अगस्त 2017 को श्री कौशिक देब, अर्थशास्त्री, भारत में बीपी द्वारा ''बीपी स्टेटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी'' पर वार्ता।
6. सीपीआर में 4 दिसंबर 2017 को डॉ. शरथ गुट्टिकुंडा, संस्थापक / निदेशक जो एनएएसए अर्थ एंड स्पेस साइंस के अध्येता और टीईडी अध्येता हैं, द्वारा UrbanEmissions.Info (यूईइंफो, इंडिया) द्वारा क्लियरिंग द एयर सेमिनार सीरीज : 'फिलिंग द नॉलेज गैप ऑन एयर क्वालिटी इन इंडियन सिटीज'।
7. सीपीआर में 20 दिसंबर 2017 को क्लियरिंग द एयर सेमिनार सीरिज : 'हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू एयर पोलुशन' पर पैनल। पैनलिस्ट में शामिल हैं :
8. प्रोफेसर डी. प्रभाकरन, कार्डियोलॉजिस्ट एंड एपिडमियोलॉजिस्ट द्वारा प्रशिक्षित, वर्तमान में उपाध्यक्ष – अनुसंधान और नीति, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई)
9. डॉ. राज कुमार, निदेशक, वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय
10. डॉ. प्रीत के. ढिल्लों यूएस और भारत में वैश्विक कैसर एपिडमियोलॉजी में पृष्ठभूमि और कई संगठनों के अनुभवी हैं। वे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में प्यावरण स्वास्थ्य के लिए कैंसर का प्रबंधन करते हैं।
11. सीपीआर में 10 जनवरी 2018 को वायु गुणवत्ता, जलवायु और स्वास्थ्य पर, डिपार्टमेंट ऑफ एनवार्यनमेंटल हेल्थ इंजीनियरिंग, श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी, पोरुर, चेन्नई में सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल एंड एनवार्यनमेंटल हेल्थ, एसआरयू – आईसीएमआर सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च के सहयोग से प्रो. कल्पना बालाकृष्ण, पीएच. डी., एफएएमएस, निदेशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्लियरिंग द एयर सेमिनार सीरिज : 'एयर पोलुशन एज ए प्रीवेंटेबल एक्यूज ऑफ एडवर्स बार्थ आउटकम्स इन इंडिया : न्यू एविडेंस फ्रॉम कोहॉर्ट स्टडीज इन तमिलनाडु'।

12. सीपीआर में 15 जनवरी 2018 को प्रो. अर्नफुल ग्रूबलर (ग्रबलर) द्वारा 'एन एंड यूज एंड इफिसिएंसी स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद् क्लाइमेट चेंज माइटिगेशन एज एंट्री पॉइंट' पर वार्ता दी ग, जो लेक्सेबर्ग, ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनालायसिस (आईआईएएसए) में नए प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए ट्रांसजिशन्स के कार्यवाहक कार्यक्रम निदेशक हैं।

13. सीपीआर में 1 फरवरी 2018 को क्लियरिंग द एयर सेमिनार सीरिज : 'द रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन दिल्ली एयर क्वालिटी : की ड्राइवर्स एंड आर्च्युनिटीज फॉर इंटरवेशन' पर पैनल चर्चा
पैनलिस्ट में शामिल :

श्री. अमित भट्ट, डब्लयूआरआई इंडिया में एकीकृत शहरी परिवहन निदेशक,

श्री. पार्था बसु, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित एनावार्यनमेंट डिफेंस फंड के साथ एयर पोलुशन पर प्रमुख सलाहकार।

14. सुमित शर्मा टेरी के अर्थ साइंस एंड क्लाइमेट चेंज समूह के अध्येता और एसोसिएट्स निदेशक।
इनके द्वारा पैनल की मध्यस्थता : सुश्री मुक्ता नायक, वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता, प्रणीति अनुसंधान केंद्र।

15. सीपीआर में 23 फरवरी 2018 को क्लियरिंग द एयर सेमिनार सीरिज : 'क्रॉप बर्निंग एज ए सोर्स ऑफ एयर पोलुशन इन नेशनल कैपिटल रिजन'।
वक्ताओं में शामिल हैं :

डॉ. एम एल जाट, सीनियर क्रॉपिंग सिस्टम एग्रोनोमिस्ट और सीआईएमएमवाए–सीसीएएफएस नई दिल्ली में दक्षिण एशिया समन्वयम और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज (एनएएएस) में एक अध्येता।

श्री प्रीतम सिंह हंजारा, रेजिडेट ऑफ उरलाना खुर्द, जिला पानीपत।

डॉ. राजवीर यादव, प्रधान वैज्ञानिक, आनुवंशिकी प्रभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली।

श्री. हरीश दमोदरन अनुभवी पत्रकार हैं जो कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और भारत में न्यूज एजेंसियों के साथ कार्यरत हैं। वे वर्तमान में द इंडियन एक्सप्रेस में ग्रामीण कार्य और कृषि संपादक हैं।

16. सीपीआर में 7 मार्च 2018 को क्लियरिंग द एयर सेमिनार सीरिज : 'म्युनिसिपल सोलिड वेस्ट एज ए एक्यूज ऑफ एयर पोलुशन' पर पैनल।
वक्ताओं में शामिल हैं :

श्री. रवि अग्रवाल, नई दिल्ली में आधारित टॉक्सिक लिंक (www.toxicslink.org), एक पर्यावरण गैर सरकारी संगठन के संस्थापक निदेशक।

सुश्री नलिनी शेखर, इंफॉर्मल वेस्ट इकॉनोमी में कार्यरत हसिरु दाला (http://hasirudala.in), एक गैर लाभकारी संगठन की सह–संस्थापक।

डॉ सीमा अवस्थी, आईसीयूसी कंसल्टेंट्स प्रा. लि. (http://icuc.in/site/) के संस्थापक और निदेशक।

अंतरराष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा

1. डॉ. प्रताप भानु मेहता, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी, प्रणीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली की अध्यक्षता में प्रो. डेविड आर्मिटेज, लॉयड सी. ब्लैंकफेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर और इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष द्वारा 16 जनवरी 2017 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में ''सिविल वॉर्स : ए हिस्ट्री इन आइडियाज़'' पर सार्वजनिक व्याख्यान।
2. प्रो. टिमोथी गर्टन ऐश, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में यूरोपियन स्टडीज़ के प्रोफेसर और सेंट एंटनी कॉलेज में यशायाह बर्लिन प्रोफेसोरियल फेलो द्वारा सीपीआर में 24 जनवरी 2017 को ''रिफ्लेक्शंस ऑन यूरोप एंड द यूके आफ्टर ब्रेक्सिट'' पर वार्ता।
3. प्रो. एंड्रयू केनेडी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विशेषज्ञ, चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी संबंधों में विशेष रुचि के साथ सीपीआर में 14 फरवरी 2017 को ''सुपरपावर इन सर्च ऑफ स्ट्रेटेजी : यूएस कोलेबोरेशन विद चाइना एंड इंडिया इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इनोवेशन'' पर वार्ता।
4. प्रणीति अनुसंधान केंद्र और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से चीन अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 17–18 मार्च 2017 को ''इंडिया–चाइना एंड द इमर्जेंस ऑफ पोस्ट–वार–पोस्ट–कोलोनियल एशिया, 1945–50'' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।
5. डॉ. बाबूराम भट्टराय, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा सीपीआर में 17 मार्च 2017 को ''रिस्ट्रक्टरिंग इंडिया–नेपाल रिलेशंस'' पर वार्ता।
6. प्रो. अनुश कपाड़िया, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे द्वारा 10 अप्रैल 2017 को ''इज डॉलर हेगमनी इनविटेबल? पॉसिबिलिटीज फॉर रिफॉर्म इन द ग्लोबल रिजर्व सिस्टम'' पर व्याख्यान। यह विचाराधीन वैश्वीकरण पर मासिक व्याख्यानों की सीपीआर श्रृंखला में प्रथम था।
7. डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम, मुख्य अर्थशास्त्र सलाहकार, भारत सरकार द्वारा 8 मई 2017 को ''हाइपरग्लोबलाइजेशन इज डैड। लॉन्ग लाइव ग्लोबलाइजेशन'' पर व्याख्यान। यह विचाराधीन वैश्वीकरण पर मासिक व्याख्यानों की सीपीआर श्रृंखला में दूसरा था।
8. सीपीआर में 9 जून 2017 को प्रो. टिमोथी जे कोल्टन, मोरिस एंड एन्ना फील्डबर्ग प्रोफेसर, गवर्नमेंट एंड रशियन स्टडीज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चेयर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट द्वारा 'रिसेट इन यू. एस. – रशियन रिलेशन्स डीड ऑन अराइवल?' पर वार्ता।
9. सीपीआर में 7 अगस्त 2017 प्रो. बेरेंसिस गायोट–रेचर्ड, किंग्स कॉलेज लंदन में 20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में व्याख्याता द्वारा 'ए वॉर विदआउट विनर्स : रिथिंकिंग द 1962 वॉर' पर वार्ता।
10. सीपीआर में 13 सितंबर 2017 को श्री. श्याम शरण, पूर्व विदेश सचिव, भारत सरकार और प्रणीति अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ अध्येता और डॉ. श्रीनाथ राघवन, प्रणीति अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ अध्येता द्वारा 'हाव इंडिया सी द वर्ल्ड : कौटिल्य टू द 21 सेंचुरी' पर पुस्तक चर्चा।
11. सीपीआर में 22 सितंबर 2017 को श्री. जहांगीर अज़ीज़, जे. पी. मुर्गन में ईएम एशिया इकॉनोमिक रिसर्च के प्रमुख द्वारा 'इंडियन ग्रोथ : प्रोस्पेट्स फॉर द फ्यूचर' पर व्याख्यान। यह विचाराधीन वैश्वीकरण पर मासिक व्याख्यानों की सीपीआर श्रृंखला में प्रथम था।

12. सीपीआर में 16 जनवरी 2018 को 'द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया : फॉर्जिंग एन इंडिस्पेंसेबल डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप' पर चर्चा। चर्चा में शामिल है :
13. सुश्री.यामिनी अय्यर, प्रणीति अनुसंधान केंद्र द्वारा परिचयात्मक टिप्पणी। वक्ताओं में शामिल हैं :
    सुश्री. निरूपमा रॉय, सह–पीठ, यू. एस. – भारत संबंधित सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस टास्क फोर्स; पूर्व विदेशी सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत और यू.एस. की पूर्व भारतीय राजदूत।

    एच. ई. श्री रिच वर्मा, सह–पीठ, यू. एस. – भारत संबंधित सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस टास्क फोर्स; उपाध्यक्ष, द एशिया ग्रुप और भारत गणराज्य के पूर्व यू.एस. राजदूत।

    मध्यस्थ : श्री अशोक मलिक, भारत के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव।

14. सीपीआर में 19 फरवारी 2018 को प्रो. डेविड सी. एंजरमैन, ब्रांडेस यूनिवर्सिटी, यूएसए में इतिहास के ऑटिलाइ स्प्रिंगर प्रोफेसर द्वारा 'द प्राइस ऑफ एड : द इकॉनोमिक कोल्ड वॉर इन इंडिया' पर पुस्तक चर्चा।
15. इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 26 फरवरी 2018 को प्रणीति अनुसंधान केंद्र और इंफॉसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साउथ एशिया स्टडीज के प्रो. सुनील अमृत, मेहरा परिवार के प्रोफेसर द्वारा 'इंडियन माइग्रेशन इन ग्लोबल हिस्ट्री' पर व्याख्यान।
16. सीपीआर में 19 मार्च 2018 को काउंसिल ऑन फॉरेज रिलेशन्स (सीएफआर), न्यू यॉर्क, यूएसए में भारत, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के लिए श्रीनाथ राघवन, वरिष्ठ अध्येता द्वारा 'अवर टाइम हेज कम – हव इंडिया इज मेकिंग इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड' पर पुस्तक चर्चा। चर्चा डॉ. श्रीनाथ राघवन, वरिष्ठ अध्येता, सीपीआर द्वारा संचालित थी।

<u>कानून, विनियम और राज्य</u>

1. सीपीआर में 5 जनवरी 2017 को डॉ. नमिता वाही, अध्येता, सीपीआर और अंकित भाटिया, रिसर्च एसोसिएट, सीपीआर द्वारा ''अंडरस्टैंडिंग लैंड इक्वेशन डिस्प्यूट्स इन इंडिया'' पर संगोष्ठी।
2. सीपीआर में 12 जनवरी 2017 को सुश्री प्रेरणा सिंह द्वारा लिखित पुस्तक ''हाउ सोलिडेरिटी वर्क्स फॉर वेलफेयर : सबनेशनलिज्म एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया'' पर पुस्तक चर्चा।
   पैनलिस्ट में शामिल हैं :

   प्रोफेसर. संतोष मेहरोत्रा, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी

   डॉ. पार्था मुखोपाध्याय, वरिष्ठ अध्येता, सीपीआर और

   डॉ. नीलांजना सरकार, वरिष्ठ अध्येता, सीपीआर

3. डॉ. जिष्णु दास, अतिथि वरिष्ठ अध्येता, सीपीआर द्वारा सीपीआर में 9 फरवरी 2017 को ''क्वालिटी ऑफ हेल्थकेयर इन रूरल एंड अर्बन इंडिया'' पर वार्ता।
4. सीपीआर में 16 फरवरी 2017 को डॉ. बिबेक देबरॉय, सदस्य नीति आयोग द्वारा ''संस्कृत प्रोसोडी'' पर वार्ता।

5. इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 8 मार्च 2017 को ''नेविगेटिंग द लैबीरिंथ : पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियाज़ हाइयर एजुकेशन'' पर पुस्तक चर्चा। चर्चाओं सहित : अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से पंकज चंद्रा, द यूनिवर्सिट ऑफ दिल्ली से अपूर्वानंद झा, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से दिपेश कपूर, और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से प्रताप भानु मेहता। चर्चा सीएनएन न्यूज़ 18 से अनुभा भोंसले द्वारा संचालित थी।
6. इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 10 मार्च 2017 को ''रिथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया'' पर पुस्तक चर्चा। पैनलिस्ट में शामिल हैं : अरविंद सुब्रमण्यन, जय पांडा, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, शैलजा चंद्र, और योगेंद्र यादव।
7. प्रणीति अनुसंधान केंद्र में 30 मार्च से 1 अप्रैल 2017 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक समूह से संबंधित अनुसंधान विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए ''ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑन सोशल रिसर्च'' आईसीएसएसआर – प्रायोजित।
8. सीपीआर में 3 अप्रैल 2017 को पेरिस में क्रिस्टोफ जे गुलमोटो, सीनियर फेलो, डेमोग्राफी, सीईपीईडी पर आधारित फ्रेंच इंस्टीट्यूट डि रिसर्च पोर ली डेवपलमेंट आईआरडी द्वारा ''प्रेनेटल सेक्स सिलेक्शन एंड इट्स फ्यूचर'' पर वार्ता।
9. सीपीआर में 6 अप्रैल 2017 को ''प्रीकेरियस नेबरहुड्स'' पर चर्चा
   प्रस्तुतकर्ता

   डॉ. सोलोमन बेंजामिन, एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, आईआईटी मद्रास।

   डॉ. एग्नेस डेबौलेट, सामाजशास्त्र के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी पेरिस– VIII विंसेन्स सेंट– डेनिस, और लेबरेटोर विले, आर्किटेक्चर, अर्बानिस्म एनवार्यनमेंट एलवीयूई– सीएनआरएस के एसोसिएट्स निदेशक।

   डॉ. वेरोनिक डुपॉन्ट, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर डेवलपमेंट (आईआरडी) और वरि. अतिथि अध्येता, प्रणीति अनुसंधान केंद्र (सीपीआर)

   श्री. बिपिन राय, विशेषज्ञ सदस्य (गैर अधिकारिक), दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (डीयूएसआईबी)

   पैनल में शामिल हैं :

   श्री. राकेश रंजन, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग

   श्री. एन श्रीधरन, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली।

   श्री. एस. के. तिवारी, अर्थशास्त्र सलाहकार, आवासन और शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय

   सुश्री. रेनु खोसला, निदेशक, सेंटर फॉर अर्बन एंड रिजनल एक्सीलेंस (सीयूआरई)

10. सीपीआर में 17 अप्रैल 2017 को सुश्री. प्रिया देशींगकर जो छह साल से डीएफआईडी – फंडेड माइग्रेटिंग आउट ऑफ पावर्टी रिसर्च कंसोर्शियम में अनुसंधान निदेशक हैं, द्वारा 'लो–स्किल्ड माइग्रेशन एंड प्रीकेरियस वर्क – वेयर डू द बॉर्डर ऑफ फोर्सड माइग्रेशन बीइंग एंड एंड?' पर वार्ता।

11. सीपीआर में 18 अप्रैल 2017 को प्रो. अनिरुद्ध कृष्णा, एडगर टी. थोम्पसन प्रोफेसर, सार्वजनिक नीति और ड्यूक यूनिवर्सिटी, यूएसए में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर द्वारा 'द ब्रोकन लैडर – द पैराडोक्स एंड द पोटेंशियल ऑफ इंडियाज वन बिलियन' पर वार्ता।
12. सीपीआर में 20 अप्रैल 2017 को प्रो. रोहित प्रसाद, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, एमडीआई गुड़गांव द्वारा 'डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स वी नॉ नथिंग ऑफ'' पर वार्ता।
13. सीपीआर में 17 मई 2017 को गोवा फाउंडेशन, गोएची मति मूवमेंट एंड द फ्यूचर वी नीड सहित कई पहलुओं के वर्तमान सदस्य श्री. राहुल बासु द्वारा 'द फ्यूचर वी नीड : नेचुरल रिसोर्सेस एज ए शेयर्ड इनहेरिटेंस' पर वार्ता।
14. सीपीआर में 18 मई 2017 को डॉ. च्लोए फ्राइसार्ट, निदेशक, सिंघुया यूनिवर्सिटी सिनो – फ्रेंच सेंटर इन सोशल साइंसेज, बीजिंग; वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता, राजनीति समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, फ्रेंच सेंटर फॉर रिसर्च कंटेम्परररी चाइना (सीईएफसी), हॉन्ग कॉन्ग; और एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ रेन्नेस 2 (फ्रांस) द्वारा 'नेगोशिएटिंग ऑथराइटरिनिज्म एंड इट्स लिमिट्स : वर्कर–लीड कलेक्टिव बरगैनिंग इन द पर्ल रिवर डेल्टा' पर वार्ता।
15. सीपीआर में 6 जून 2017 को डॉ. अभिषेक राय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिल्चर, असम द्वारा 'ऑफ वगरेंट्स एंड माइग्रेंट्स : ऑन द डिसकर्सिव लिमिट ऑफ लॉ' पर वार्ता।
16. सीपीआर में 22 जून 2017 को क्रमशः श्री कुमार संभव श्रीवास्तव, श्री. अंकुर पालीवाल और श्री भास्कर त्रिपाठी द्वारा 'मेपिंग लैंड कॉन्फिलेट्स इन इंडिया' पर वार्ता।
17. सीपीआर में 11 जुलाई 2017 को प्रो. आदित्य दासगुप्ता, स्टैंफॉर्ड एंड यूसी – मेर्सेड और प्रो. देवेश कपूर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया द्वारा अंडरस्टैंडिंग लोकल स्टेट कैपिसिटी : एविडेंस फ्रॉम नेशनवाइड सर्वे ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिर्स इन इंडिया पर वार्ता।
18. सीपीआर में 19 जुलाई 2017 को डॉ. माइकल लेवियन, जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी, यूएसए में समाज शास्त्र के सहायक प्रोफेसर द्वारा ''डिसपोजिशन विद्आउट डेवलपमेंट : लैंड ग्रेब्स इन नियोलेबरेल इंडिया'' पर वार्ता।
19. सीपीआर में 21 जुलाई 2017 को श्री. रोनाल्ड अब्राहम, भागीदार आईडी इनसाइट, दिल्ली द्वारा 'स्टेट ऑफ आधार रिपोर्ट 2016–17' पर वार्ता।
20. सीपीआर में 24 अगस्त 2017 को डॉ. अमिता बाविस्कर, समाजशास्त्र के प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली द्वारा 'इंडस्ट्रियल फूड्स एंड कल्चरल एंडेटिटीज इन इंडिया' पर वार्ता।
21. सीपीआर में 25 अगस्त 2017 को श्री. प्रशांत झा, एसोसिएट संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स और सीपीआर में घरेलू चयन विज्ञान और वरिष्ठ अध्येता, डॉ. नीलांजन सरकार के लेखक के बीच 'हव द बीजेपी विनस : इनसाइट इंडियाज गेटेस्ट इलेक्शन मशीन' पर पुस्तक चर्चा।
22. सीपीआर में 27 सितंबर 2017 को डॉ. फराह अहमद, मेलबर्न लॉ स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा 'रिफॉर्मिंग पर्सनल लॉ' पर वार्ता।
23. सीपीआर में 6 अक्टूबर 2017 को हार्वर्ड टीएच चेन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रो. पीटर बर्मन और टीम द्वारा ''गवर्नमेंट फाइनेसिंग ऑफ हेल्थकेयर इन इंडिया सिन 2005 : अचीवमेंट्स एंड चेलेंजेस'' पर वार्ता।

24. सीपीआर में 7 नवंबर 2017 को क्रमशः श्री. श्याम शरण, पूर्व विदेश सचिव और वरिष्ठ अध्येता सीपीआर; डॉ. निम्मी कुरियन, एसोसिएट अनुसंधान प्रोफेसर, सीपीआर और डॉ. श्रीनाथ राघवन, वरिष्ठ अध्येता, सीपीआर द्वारा 'अनपैकिंग द रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस' पर चर्चा।
25. सीपीआर में 21 नवंबर 2017 को 'ए रिव्यू ऑफ द इमोरल ट्रेफिक (प्रीवेंशन) एक्ट, 1986' पर संगोष्ठी। पैनल में शामिल हैं : श्री. आलोक दुबे, श्री रवि कांत, आकृति गौर और कुलबीर कृष्णा।
26. सीपीआर में 29 नवंबर से 2 दिसंबर 2017 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक समूह से संबंधित अनुसंधान विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए ''ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑन सोशल रिसर्च'' आईसीएसएसआर – प्रायोजित।
27. सीपीआर में 7 दिसंबर 2017 को डॉ. बजॉर्न लॉमबर्ग, डेनिश लेखक और कोपेनहेगन कंसेंसस सेंटर के अध्यक्ष के साथ साथ कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल में अतिथि प्रोफेसर द्वारा 'इंडिया कंसेंसस : हेल्पिंग प्रायोरिटीज स्टेट स्पेंडिंग' पर वार्ता।
28. सीपीआर में 22 दिसंबर 2017 को 'अनपैकिंग द रिजल्ट ऑफ द गुजरात इलेक्शन्स' पर प्रस्तुतीकरण और पैनल चर्चा।
29. डॉ. नीलांजन सरकार, वरिष्ठ अध्येता सीपीआर द्वारा प्रस्तुतीकरण
30. पैनल में शामिल हैं :

    श्री. प्रशांत झा, एसोसिएट संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स

    श्री. महेश लंगा, वरिष्ठ सहायक संपादक, द हिंदू

    सुश्री. रूही तिवारी, एसोसिएट संपादक, द प्रिंट

    डॉ. गिल्स वर्नियर, त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा, अशोक विश्वविद्यालय के सह–निदेशक

31. इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 2–3 मार्च 2017 को ''लैंड राइट्स, लैंड एक्विजिशन, एंड इंक्लुसिव डेवलपमेंट इन इंडिया'' पर सम्मेलन।
32. इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 15–16 मार्च 2018 को ''लैंड लॉ, लैंड एक्विजिशन एंड शेड्यूल्ड एरियास इन इंडिया'' पर सीपीआर–एलआरआई का चौथा वार्षिक सम्मेलन।
33. सुश्री कांची कोहली, सुश्री मंजू मेनन और सुश्री मीनाक्षी कपूर, सीपीआर नमाति एनवार्यनमेंट जस्टिस प्रोग्राम की आधिकारिक द्वारा 7 फरवारी 2018 को 'क्लोजिंग द इंफॉर्समेंट गैप : ए प्रैक्टिव गाइड फॉर एनवार्यनमेंट जस्टस पैरालेगल्स' पर वेब सम्मेलन।
34. सामाजिक विज्ञान और मानविकी केंद्र, नई दिल्ली में 9 फरवारी 2018 को सीपीआर, सीएनआरएस, आईसीएमआर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'न्य ऑर्प्युनिटीज इन कंट्रोलिंग वेक्टर – बोर्न डिजीज : बिग उेटा, न्यू इनसेक्टिसाइड्स एंड गवर्नेंस इन अर्बन इंडिया' पर कार्यशाला। चर्चा ओलिवर टेले, वरिष्ठ अतिथि अनुसंधानकर्ता, सीपीआर द्वारा संचालित थी।
35. सीपीआर में 22 मार्च 2018 को डॉ. एलन गैल्ब, वरिष्ठ अध्येता और अध्ययन निदेशक, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवपलमेंट, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए द्वारा 'द आइडेंटिफिकेशन रिवोल्यूशन एंड डेवपलमेंट' पर संगोष्ठी।

36. सीपीआर में 23 मार्च 2018 को प्रो. वेंकटेश नारायणमूर्ति, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 'टेक्नोलॉजी एंड सोसायटी : एजुकेशन ऑफ फ्यूचर लीडर्स फॉर द इंफॉर्म्ड सिटीजनरी' पर वार्ता।

शहरीकरण

1. श्री दोरै नारायणन, वॉटर कंसोर्शियम में योजना एवं अभियांत्रिकी विभाग के पूर्व प्रमुख द्वारा प्रणीति अनुसंधान केंद्र में 23 जनवरी 2017 को ''मलेशियन पर्सपेक्टिव ऑन रिवर पॉल्यूशन, सेनिटेशन एंड सिवरेज मैनेजमेंट'' पर कॉर्प संगोष्ठी।
2. सीपीआर में 19 मई 2017 को सुश्री. चॉल लेक्लेर, अर्थशास्त्र में पीएच डी छात्र, फ्रेंस इकोल नॉर्मल सुपीरियर डी लयॉन द्वारा 'एन इकॉनोमिक कैरेटराइजेशन ऑफ सैनिटेशन : बिटवीन द स्टेट्स प्रोडक्शन एंड द हाउसहोल्ड्स डिमांड' पर कॉर्प संगोष्ठी।
3. सीपीआर में 28 जून 2017 को सुश्री. ईशा कंडरी, प्रणीति अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान एसोसिएट द्वारा 'बिटवीन 'खेत' 'फैक्टरी' एंड 'कॉलोनी' : एक्सप्लोरिंग इंटरसेक्शन्स ऑफ कास्ट एंड जेंटर अमंग माइग्रेंट इंडस्ट्रियल वर्कर्स' पर वार्ता।
4. सीपीआर में 14 जुलाई 2017 को डॉ. यी जियांग, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, इकोनोमिक रिसर्च एंड रिजनल कॉ–ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दिल्ली और राणा हसन, निदेशक, डेवलपमेंट इकोनोमिक्स एंड इंडिकेटर्स डिविजन, एशियन डेवपलमेंट बैंक दिल्ली द्वारा 'प्लेस – बेस्ड प्रेफेरेंशियल टैक्स पॉलिसी एंड इट्स स्पेशियल इफेक्ट्स : एविडेंस फ्रॉम इंडियास प्रोग्राम ऑन इंडस्ट्रियल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स' पर वार्ता।
5. सीपीआर में 20 सितबंर 2017 को डॉ. संघमित्रा आचार्य जो निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज, दिल्ली है, द्वारा ' द क्लिनिंग ब्रिज्ड : कनेक्ट्स एंड डिसकनेक्ट्स' पर कॉर्प संगोष्ठी।
6. सीपीआर में 25 अक्टूबर 2017 को सुश्री. सुप्रिया सिंह द्वारा ''प्रॉब्लमेटाइजिंग वॉटर : एफेक्टिंग चेंज'' पर वार्ता, इसे हाल में दिल्ली में पानी की राजनीति पर पीएच डी के लिए उनके शोध प्रबंध हेतु जमा किया गया।
7. सीपीआर में 27 अक्टूबर 2017 को डॉ. मनोज रॉय, सस्टेनेबिलिटी लैंकास्टर एनवार्यनमेंट सेंटर, लैंकास्टर यूनिवर्सिटी, यूके के लेक्चरर द्वारा 'लास्ट 100 मीटर्स : सेफगार्डिंग पोटेबल वॉटर प्रोविजिनिंग टू अर्बन इंफॉर्मल सेटलमेंट्स' पर कॉर्प संगोष्ठी।
8. इंडिया हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 12 दिसबंर 2017 को 'सस्टेनेबल सेनिटेशन : एविडेंस एंड प्रैक्टिस' पर सम्मेलन।
9. एएफडी की सुश्री इरने सेलेंसन; सीएनआरएस की सुश्री रेमी डि बेर्सेगोल; और सीएसई की सुश्री स्वाति सिंह सम्बयाल द्वारा 12 फरवरी 2018 को 'वॉल्यूइंग वेस्ट ऑर वेस्टिंग वॉल्यू? रिथिकिंग वेस्ट प्रोसेसिंग इन फास्ट ग्रोविंग मिडल – इनकम सिटीज' पर संगोष्ठी

ख) अंतरराष्ट्रीय

1. क्विटो, इक्वाडोर में 17 अक्टूबर 2016 को यूएन–हैबिटेट ।।। सम्मेलन : थिंक स्मॉल, गो बिग'' में नेटवर्किंग आयोजन। यह आयोजन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ), द फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च (सीएनआरएस), हैबिटेट फॉर ह्यूमेनिटी, सदर्न वॉइस और द फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईआरडी), स्लम ड्वेलर्स इंटरनेशनल और यूएन–हैबिटेट के सहयोग से प्रणीति अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था।
2. हेंग मुइकेंग टेरेस, सिंगापुर में एमईआई सम्मेलन कक्ष में 30 अक्टूबर 2017 को 'द क्लीन इंडिया मिशन : चेलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स' संयुक्त रूप से आयोजित पैनल चर्चा में इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, सिंगापुर और प्रणीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली।

1. कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम (संस्थान द्वारा आयोजित)

आर्थिक नीति

1. सीपीआर में 22 अगस्त 2017 को ''मेजरिंग इकॉनोमिक इंक्लुसिविटी इन इंडिया : कंसेप्चुअल एंड इम्पीरिकल रिकमंडेशन्स फॉर एन इंडिकेटर फ्रेमवर्क'' पर कार्यशाला।

<u>कानून, विनियम और राज्य</u>

1. प्रणीति अनुसंधान केंद्र में 30 मार्च से 1 अप्रैल 2017 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक समूह से संबंधित अनुसंधान विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए ''ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑन सोशल रिसर्च'' आईसीएसएसआर – प्रायोजित।

<u>शहरीकरण</u>

1. क्लेरिजेस होटल, नई दिल्ली में 27 फरवरी 2017 को ''क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर : जैपनीज़ इंवेस्टमेंट इन इंडिया'' पर कार्यशाला। कार्यशाला का उद्घाटन भारत में जापान के महामहिम राजदूत ने किया। नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने मुख्य भाषण दिया। अन्य प्रमुख वक्ता श्री कोकी हिरोटा, जापान से जेआईसीए के मुख्य अर्थशास्त्री और श्री आर सी भार्गव, मारुति सुजुकी के अध्यक्ष और जापान और भारत से उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच थे।
2. श्री फिलिप हैरिसन स्थानिक विश्लेषण और शहर नियोजन में दक्षिण अफ्रीकी अनुसंधान अध्यक्ष द्वारा प्रणीति अनुसंधान केंद्र में 31 जनवरी 2017 को ''ब्रिक्स सिटीज़ : वॉट आर वी कम्पेयरिंग?'' पर सीपीआर–सीएसएच कार्यशाला।
3. श्रीमती सोनल शाह वरिष्ठ प्रबंधक, परिवहन और विकास नीति संस्थान द्वारा प्रणीति अनुसंधान केंद्र में 28 फरवरी 2017 को ''जेंडर एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया : हाउ डू वी मूव फ्रॉम वूमंस सेफ्टी टू जेंडर इक्विटी? '' पर सीपीआर–सीएसएच कार्यशाला।
4. प्रणीति अनुसंधान केंद्र में 28 मार्च 2017 को ''लेबर माइग्रेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया'' पर कार्यशाला।

5. सुश्री अररेली वरेल भूगोल में सीएनआरएस शोधकर्ता द्वारा सीपीआर में 28 मार्च 2017 को ''द मेट्रोपॉलिस एंड द डायस्पोरा : बैंगलोर प्रॉपर्टी मार्केट थ्रू द ट्रांसनेशनल लेंस'' पर सीपीआर–सीएसएच कार्यशाला।
6. प्रणीति अनुसंधान केंद्र में 29 मार्च 2017 को ''सेनिटेशन फॉर पीपल : असेसिंग सोशियो–कल्चरल रियलिटीज़ ऑफ सेनिटेशन प्रैक्टिस इन इंडियन सिटीज़'' पर कार्यशाला।
7. सीपीआर में 25 अप्रैल 2017 को डॉ. प्रणब सेन द्वारा 'द पजल ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन'' पर सीपीआर – सीएसएच कार्यशाला, जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय विकास केंद्र के भारत केंद्रीय कार्यक्रम के लिए देश निदेशक है।
8. सीपीआर में 30 मई 2017 को सुश्री. बनश्री बनर्जी द्वारा ''डेमोक्रिटिजेशन थ्रु पार्टिसिपेटरी एक्शन प्लानिंग इन यांगोन'' पर सीपीआर सीएचएस कार्यशाला, जो एक शहरी योजनकार, एक स्वतंत्र सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं और इंस्टीट्यूट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट स्टडीज, रॉटरडैम के एसोसिएट स्टाफ सदस्य में रूप में भी कार्य करते हैं।
9. सीपीआर में 27 जून 2017 को सुश्री अश्वथी आनंद, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्टिटेक्चर, भोपाल से प्रशिक्षक वास्तुकार; श्री. अजय श्रीवत्सन, हिंदु के पूर्व जांचकर्ता संवाददाता और सुश्री. पेर्सिस तारापोरवाला प्रणीति अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान एसोसिएट है द्वारा ''वट डोज एन इंडियन स्मार्ट सिटी लुक लाइक?'' पर सीपीआर – सीएसएच कार्यशाला।
10. सीपीआर में 25 जुलाई 2017 को सुश्री. वैलेरी क्लर्क अनुसंधान अध्येता, फ्रेंच नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवपलमेंट – आईआरडी और अफ्रीका, अमेरिका और पेरिस में एशिया के सीईएसएसएमए सेंटर फॉर सोशल साइंस स्टडीज के सदस्य द्वारा 'ए कॉम्पटिशन फॉर अर्बन लैंड, पॉलिसीस टुवर्ड्स इंफॉर्मल सेटलमेंट्स इन लेबनॉन, कम्बोडिया एंड सिरिया' पर कार्यशाला।
11. सीपीआर में 29 अगस्त 2017 को सुश्री. वंदना वसुदेवन द्वारा ''एवरीडे जर्नी ऑफ अर्बन वर्किंग मदर्स : एविडेंस फ्रॉम फ्रांस एंड इंडिया'' पर सीपीआर – सीएसएच कार्यशाला में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल, फ्रांस से उन्होंने डॉक्टरेट किया।
12. सीपीआर में 26 सितंबर 2017 को सुश्री ऐश्वर्या टिपनिस द्वारा ''द हेरिटेज ऑफ द ऑर्डिनरी – ए केस ऑफ अर्बन हेरिटेज कंर्जेवेशन इन चंदरनगर'' पर सीपीआर – सीएसएच कार्यशाला जो नई दिल्ली में स्थित एक नामांकित वास्तुशिल्प अभ्यास की मुख्य वास्तुकार हैं।
13. सीपीआर में 31 अक्टूबर 2017 को प्रो. स्टीफन तावा लामा – रेवाल, अनुसंधान अध्येता (राजनीतिक विज्ञान), सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज (सीएनआरएस – ईएचईएसएस), पेरिस द्वारा ''अवतार्स ऑफ पार्टिसिपेशन : द डेवपलमेंट ऑफ पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिस इन द सिटी – स्टेट ऑफ दिल्ली'' पर सीपीआर – सीएसएच कार्यशाला।
14. सीपीआर में 28 नवंबर 2017 को डॉ. अदनान फारूकी, सहायक प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा ''चेंजिंग पार्टी सिस्टम इन दिल्ली एंड इमर्जेंसी ऑफ आम आदमी पार्टी'' पर सीपीआर – सीएसएच कार्यशाला।

15. सीपीआर में 26 दिसंबर 2017 को डॉ. प्रगना रूगुनानन, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका द्वारा ''बिल्डिंग सोलिडेरिटीस इन द (री) कंस्ट्रक्शन ऑफ माइग्रेंट कम्युनिटी इन जोहान्सबर्ग'' पर सीपीआर – सीएसएच कार्यशाला।
16. सीपीआर में 30 जनवरी 2018 को प्रो. क्रिश्चियन स्कमिड, ईटीएच जुरिक में डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में समाजशास्त्र प्रोफेसर, द्वारा 'पैटर्न्स एंड पथवेस ऑफ प्लानेटरी अर्बनाइजेशन इन कॉम्परेटिव परस्पेक्टिव'' परसीपीआर – सीएसएच कार्यशाला।
17. सीपीआर में 27 फरवरी 2018 को डॉ. राधिका खोसला, अध्येता, सीपीआर और श्री. अंकित भारद्वाज, अनुसंधान एसोसिएट, सीपीआर द्वारा ''वी आर ग्रीनर थेन यू थिंक'' : एक्जामिनिंग इंडियन सिटीज' रिस्पोंस टू क्लाइमेट चेंज'' पर सीपीआर – सीएसएच कार्यशाला।
18. सीपीआर में 27 मार्च 2018 को सुश्री ओल्गा चेपेलियंसकाया, एक अंतरराष्ट्रीय शहरी स्थिर विकास परामर्शदाता, यूएनआईसीआईटीआई की संस्थापक और एसईएचईआर आईएनटीएसीएच के कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा ''सस्टेनेबल सिटीज थ्रु हेरिटेज रिवाइवल : एशियन केस स्टडीज'' पर सीपीआर – सीएसएच कार्यशाला।
19. सामाजिक विज्ञान और मानविकी केंद्र, नई दिल्ली में 9 फरवरी 2018 को सीपीआर, सीएनआरएस, आईसीएमआर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'न्यू ऑर्च्युनिटीज इन कंट्रोलिंग वेक्टर – बोर्न डिजीज : बिग डेटा, न्यू इनसेक्टिसिडीस एंड गवर्नेंस इन अर्बन इंडिया' पर कार्यशाला। चर्चा ओलिवर टेले, वरिष्ठ अतिथि अनुसंधानकर्ता, सीपीआर द्वारा संचालित थी।

प्रणीति अनुसंधान केंद्र के प्रयास

I. जवाबदेही प्रयास (एआई)

राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर सामाजिक क्षेत्र के व्यय का बजट विश्लेषण

- जवाबदेही पहल (एआई), जिसका नेतृत्व अब अवनी कपूर की अध्यक्षता में किया रहा है, जिन्होंने पहले सार्वजनिक वित्त पर एआई के शोध का नेतृत्व किया था, अब बजटीय आबंटन, व्यय और आउटपुट और केंद्रीय बजट से पहले प्रमुख सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के परिणामों का विश्लेषण करने वाली अपनी वार्षिक बजट संक्षिप्त श्रृंखला प्रकाशित की। इस साल, यह वर्तमान सरकार (मई 2019 में चुनाव से पहले) का अंतिम पूर्ण बजट था, एआई ने पहली बार नौ प्रमुख योजनाओं को कवर करने के लिए संक्षेप का विस्तार किया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्वच्छ भारत (शहरी और ग्रामीण), मैनुअल सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्व रोजगार योजना (एसआरएमएस), प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)।

मीडिया में बजट विश्लेषण

बजट तक पहुंचने के बाद, एआई ने लाइव मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, डेक्कन हेराल्ड, वायर, इंडिया स्पेन्ड्स, और स्थानीय समाचार पत्र हिंदुस्तान सहित मुख्यधारा के मीडिया में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित करके सार्वजनिक बहस में व्यापक योगदान दिया। एआई शोधकर्ताओं ने बजट 2018 पर दो लाइव न्यूज़लॉन्ड्री चर्चाओं में भी भाग लिया।

- इसके अलावा, जटिल बजटीय जानकारी को कम करने और बढ़ी हुई पहुंच को सक्षम करने के लिए, एआई द्वारा बजट से संबंधित जानकारी और विजुअलाइजेशन प्रसारित करने के लिए बजट दिवस पर एक माइक्रो साइट बनाई गई। साइट यहां पहुंच योग्य है : https://socialmedia490.wixsite.com/accountabilityindia
- एआई और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के लिए राजकोषीय हस्तांतरण हेतु पिछले दृष्टिकोण से पाठों को समझने में वैश्विक विकास के सहयोगी प्रयास के लिए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था।

भारत की स्वच्छता योजनाओं को कार्यान्वित करने की ट्रैकिंग और अभिनंदन वार्ता

2017 में, उदयपुर में स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पर एआई के प्रमुख कार्यक्रम पीएआईएसए (योजना, आबंटन और व्यय, जवाबदेही में संस्थान अध्ययन) ने स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की ग्रामीण शाखा के कार्यान्वयन में चुनौतियों और ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित करने में शामिल प्रक्रिया को समझने के लिए एक आधारभूत सर्वेक्षण किया। तीन महीने के लंबे अध्ययन में एसबीएम मशीनरी के

कामकाज पर अंतर्दृष्टि प्राप्त की गई और इसे प्रशासन के साथ साझा किया गया। अध्ययन निष्कर्षों की एक रिपोर्ट जून, 2018 तक उपलब्ध होगी।

- प्रणीति अनुसंधान केंद्र मेंएआई और स्केलिंग सिटी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया (एससीआई–एफआई) की टीमों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें स्वच्छता क्षेत्र में प्रमुख नीति शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को एक साथ लाया गया। सम्मेलन में नीति और कार्यान्वयन पर विचार–विमर्श, साझा शिक्षा और सुरक्षित स्वच्छता के मुद्दे पर अनुशंसाएं प्रदान की गईं, जिनमें एसबीएम की भूमिका शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है।

- स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के तीसरे वर्ष की सालगिरह समारोह के भाग के रूप में, अवनी कपूर ने मिशन के सामने की जाने वाली चुनौतियों पर एनडीटीवी चर्चा में भाग लिया।

सरकार के लिए नीति और कार्यान्वयन सूचना हेतु अनुसंधान का आयोजन करना

- जनवरी 2018 के बाद से, एआई सरकारी स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन में स्वास्थ्य व्यय के कम उपयोग और बाधाओं का निदान करने के कारणों को समझने के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के साथ कार्य करने के लिए स्थापित तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। प्रमुख कार्य क्षेत्रों को निर्धारित करने के क्रम में अनुसंधान के निष्कर्ष नियमित रूप से टीएसयू और स्वास्थ्य मिशन निदेशक के साथ साझा किए जाते हैं। अध्ययन जुलाई, 2018 तक पूरा हो जाएगा।

- दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) के अनुरोध पर, नवंबर 2017 के बाद से, एआई स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों में शिक्षकों का समय कैसे वितरित किया जाता है, यह समझने के लिए एक अध्ययन आयोजित कर रहा है कि क्या उनके प्रशासनिक कार्य शिक्षण समय को प्रभावित करते हैं, और विद्यालय से संबंधित कार्य में शामिल आधिकारिक घंटों के बाहर शिक्षक कितने समय व्यतीत करते हैं। अध्ययन का उद्देश्य शिक्षकों की अपने कार्य की धारणाओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। अनुसंधान का निष्कर्ष नियमित रूप से डीसीपीसीआर के साथ साझा किए जा रहे हैं।

- बिहार शिक्षा मिशन के अनुरोध पर, एआई ने राज्य के पूर्णिया और नालंदा जिलों में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) द्वारा वित्त पोषण के रखरखाव पर एक क्षेत्र सर्वेक्षण आयोजित किया। इस अध्ययन में मुख्य सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) अनुदान के लिए निधियों के संबंध में कैशबुक / पासबुक के रखरखाव में चुनौतियों और कठिनाइयों को दर्ज किया गया। इसके अलावा, राजकोषीय हस्तांतरण के तरीके के रूप में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के सरकार के विस्तार, छात्रवृत्ति और वर्दी अनुदान के लिए लाभार्थियों को निधियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण की प्रक्रिया में अंतर को समझने के लिए 590 परिवारों और 1000 छात्रों को कवर करने वाले एक अध्ययन के अधीन था। निष्कर्ष शीर्ष एसएसए अधिकारियों के साथ साझा किए गए थे और उन्हें प्राप्त किया गया था।

प्रशासनिक सेवाओं के कर्मचारी का क्षमता निर्माण और नीति निर्माताओं के साथ संलग्न

एआई ने प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण के अपने बड़े सेट के भाग के रूप में कई सत्र आयोजित किए, जिनमें निम्न शामिल हैं:

- अवनी कपूर ने भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए निगरानी और मूल्यांकन पर प्रशिक्षण के भाग के रूप में एक सत्र लिया।
- राजिका सेठ ने लालबाहदुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (एलबीएसएनएए) में सुशासन केंद्र में मध्य प्रदेश राज्य कैडर अधिकारियों के लिए एक सत्र लिया।
- अवनी कपूर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस – भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस – भारतीय पुलिस सेवा और आईएफएस – भारतीय वन सेवा) अधिकारियों के लिए वित्तीय नीति और मैक्रो इकॉनॉमिक प्रबंधन पर सेवाकालीन प्रशिक्षण के भाग के रूप में एक सत्र लिया।
- अवनी कपूर और राजिका सेठ ने एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित आईसीएएस (भारतीय नागरिक लेखा सेवा) परिवीक्षार्थी प्रशिक्षण के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के सार्वजनिक व्यय उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखापरीक्षा भाग पर एक सत्र लिया।

मार्च, 2018 में बैठकों, संगोष्ठियों, केंद्रित बातचीत के माध्यम से नियमित रूप से नीति निर्माता समुदाय के साथ संलग्नता के अलावा, एआई ने सीआईईएस (तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी) सम्मेलन में अपने शिक्षा अनुसंधान में भाग लिया और निष्कर्ष प्रस्तुत किया – शोधकर्ताओं, छात्रों, चिकित्सकों और दुनिया भर से नीति निर्माताओं साथ मिलकर एक वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन – तुलनात्मक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैक्सिको में आयोजित, सम्मेलन, जिसमें री–मैपिंग ग्लोबल एजुकेशन का विषय था, 117 देशों के 3,200 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

राज्य की क्षमता पर बुनियादी चिकित्सकों का प्रशिक्षण

अनुसंधान और अभ्यास के बीच के अंतराल को दूर करने के प्रयास में, एआई ने अपने पैसा (योजना, आबंटन और व्यय, जवाबदेही में संस्थान अध्ययन) पाठ्यक्रम के एक नया अवतार का शुभारंभ किया, जिसे *हम और हमारी सरकार* कहा जाता है। हिंदी में पहली बार उपलब्ध और एआई के पैसा क्षेत्र सहयोगियों द्वारा आयोजित, पाठ्यक्रम राज्य की क्षमता का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान किया जाता है, और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य कर रहे जमीनी स्तर के विकास क्षेत्र के पेशेवरों द्वारा चलाया जाता है। दिसंबर में दो प्रायोगिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे:

- पहला प्रायोगिक कार्यक्रम बिहार में एनजीओ प्रथम के जिला स्तर के समन्वयकों के साथ आयोजित किया गया था जो क्षेत्र स्तर पर शिक्षा के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य करते हैं।

- दूसरा राजस्थान में नेहरू युवा केंद्र के ब्लॉक–स्तरीय समन्वयकों के साथ आयोजित किया गया था – एक युवा संगठन सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्य कर रहा है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी लक्षित लाभार्थी इन योजनाओं को आसानी से प्राप्त कर सकें।

2018 में, पाठ्यक्रम अन्य इच्छुक संगठनों के लिए लिया जाएगा और व्यक्तियों के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी डिजाइन किया जाएगा।

II. जलवायु, ऊर्जा एवं पर्यावरण पर प्रयास (आईसीईई)

वर्ष के दौरान, *जलवायु ऊर्जा और पर्यावरण पर प्रयास (आईसीईई)* ने अपने कार्य के विस्तार को काफी बढ़ा दिया। जलवायु परिवर्तन पर अपने कार्य के अलावा, आईसीईई ने ऊर्जा मांग पैटर्न, भारतीय ऊर्जा नीति में अपेक्षाकृत उपेक्षित क्षेत्र पर कार्य के एक नए क्षेत्र का शुभारंभ किया। इसने प्रशासन और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के साथ–साथ राज्य स्तरीय बिजली वितरण के विषय पर भी कार्य आरंभ किया। इसके अलावा, आईसीईई ने स्थानीय पर्यावरण नियामक संस्थानों पर अपना कार्य गहरा कर दिया और वायु प्रदूषण पर सार्वजनिक संचार श्रृंखला शुरू की।

पिछले वर्ष आईसीईई ने अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ता और बहस के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) में अपनी भागीदारी पर अपनी संलग्नता जारी रखीः

• लवण्या राजमणि ने सह–लेखक पुस्तक शीर्षक, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज लॉ (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2017) प्रकाशित की जिसने इंटरनेशनल लॉ के एक विशेष क्षेत्र में 2018 अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त किया, और दुनिया भर में कई पठन सूचियों पर विशेषज्ञता को प्राप्त किया। राजमणि ने पेरिस समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका की घोषित वापसी के कानूनी प्रभावों पर *जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल लॉ* सहित कानूनी पत्रिकाओं में प्रकाशित करना जारी रखा। उन्होंने बहुपक्षीय जलवायु वार्ता में अपनी करीबी संलग्नता, प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता में एक शैक्षणिक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना, कानूनी सलाह देना, पृष्ठभूमि नोट तैयार करना और चल रहे पेरिस नियम पुस्तिकाओं के संबंध में 'मुद्दों और विकल्पों' की पहचान करना जारी रखा।

• नवराज दुबाश को उनके छः आकलन रिपोर्ट के भाग के रूप में राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय नीतियों और संस्थानों के अध्याय के लिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) द्वारा समन्वयक लीड लेखक नियुक्त किया गया था। इस भूमिका में, उन पर राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु नीति के साथ वैश्विक अनुभव के सह–अग्रणी संश्लेषण की जिम्मेदारी होगी। इस नियुक्ति में रिपोर्ट के लिए शर्तों को निर्धारित करते हुए स्कोपिंग मीटिंग में उनकी भागीदारी का पालन किया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, उन्होंने व्यापक रूप से पढ़ी गई पत्रिका, एनुअल रिव्यू ऑफ एनवायर्नमेंट एंड रिसोर्सेज़ में आईपीसीसी के साथ अपने अनुभव की समीक्षा का सह–लेखन किया है।

उपरोक्त के अलावा, आईसीईई का ऊर्जा पर केंद्रित कार्य ऊर्जा मांग में भारत के संक्रमण की विशेषता पर केंद्रित है :

• इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनालायसिस (आईआईएएसए) से सीपीआर अतिथि अध्येता, प्रो. अर्नाल्फ ग्रूबलर के आसपास आयोजित केंद्र मंच पर ऊर्जा नीति की मांग–पक्ष लाने के लिए एक हफ्ते की लंबी श्रृंखला मांग की गई। प्रो ग्रुबलर ने चौदह प्रारंभिक विद्वानों के एक समूह के लिए तीन दिवसीय लंबी कार्यशाला आयोजित की, तीन सार्वजनिक व्याख्यान दिए, और एक उच्च स्तरीय गोलमेज में भाग लिया जो भारत में ऊर्जा मांग पर केंद्रित कार्य के महत्व और भूमिका पर एक एजेंडा–सेटिंग नोट के साथ निष्कर्ष है।

- राधिका खोसला और अंकित भारद्वाज ने राजकोट में आवासीय ऊर्जा खपत को बेंचमार्क करने के लिए एक सर्वेक्षण किया और किफायती आवास में उपकरण खरीद और उपयोग को समझ लिया। प्रारंभिक निष्कर्ष और भारत के आवासीय ऊर्जा संक्रमण पर व्यापक सर्वेक्षण 'प्लगिंग इन' ब्लॉग श्रृंखला में प्रयास (ऊर्जा समूह) के साथ रिपोर्ट किया गया था। श्री खोसला ने जर्नल, एनवायर्नमेंट पॉलिसी एंड गवर्नेंस में ऊर्जा संक्रमण के निर्माण पर एक लेख का भी सह–लेखन किया।

- दोनों ने भारत में शहरी जलवायु कार्रवाई पर भी अपना कार्य जारी रखा, यह पता लगाया कि कैसे निर्णय निर्माताओं द्वारा अपने शहर के कार्यों और योजनाओं में कई विकास और जलवायु उद्देश्यों को एकीकृत कर सकते हैं। उनका कार्य कोयंबटूर और

राजकोट के शहरों में निर्णय निर्माताओं और कलाकारों के साथ जुड़ाव पर आधारित था। श्री खोसला के जलवायु और विकास कार्यों के बीच तालमेल खोजने का मामला एक नीति संक्षिप्त में बताया गया था और सम्मेलनों में साझा किया गया था। जलवायु परिवर्तन के लिए भारतीय शहरों की प्रतिक्रिया दस्तावेज करने वाले शैक्षणिक साहित्य की व्यापक समीक्षा भी आयोजित की गई।

दिसंबर 2017 के बाद से, आईसीईई की टीम क्लियरिंग द एयर आयोजित करके घरेलू पर्यावरण प्रशासन पर काम कर रही है? सेमिनार श्रृंखला हवा की सफाई में शामिल आंकड़ों, प्रभावों, स्रोतों और नीति चुनौतियों के आस–पास निरंतर और सूचित सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देना है। इसमें स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि, अपशिष्ट और पर्यावरण शासन सहित कई क्षेत्रों की सीमा के विशेषज्ञों ने भाग लिया है। घटनाओं के साथ–साथ, सीपीआर वेबसाइट पर उपलब्ध वायु प्रदूषण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर टीम ने सुलभ पृष्ठभूमि सामग्री भी तैयार की है।

संकाय सदस्य सलाहकार भूमिकाओं में नीति निर्माताओं से भी जुड़े हुए हैं। नवराज़ दुबाश ने निम्न कार्बन विकास के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) सलाहकार समिति पर कार्य किया, जो हाल ही में भारत की ऊर्जा और उत्सर्जन के भविष्य के अध्ययन की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने शिबानी घोष के साथ विशेष रूप से संस्थागत और प्रशासनिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के लिए अक्षय ऊर्जा कानून तैयार करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की एक समिति में भी योगदान दिया।

क्लीयरिंग द एयर? सेमिनार श्रृंखला

दिसंबर 2017 के बाद से, जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण (आईसीईई) पर पहल द्वारा आयोजित विभिन्न फोकस क्षेत्रों से सीपीआर संकाय और अन्वेषकों का एक समूह देश में वायु प्रदूषण और उससे संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रहा है। समूह की अंतर–अनुशासन सीपीआर की समझ को दर्शाता है कि वायु प्रदूषण केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं

है, बल्कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े पार–क्षेत्रीय संबंधों में से एक है। समूह की प्रमुख गतिविधियों में से एक *क्लीयरिंग द एयर* को व्यवस्थित करना है? क्लीयरिंग द एयर में शामिल आंकड़ों, प्रभावों, स्रोतों और नीति चुनौतियों के आस–पास निरंतर और सूचित सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार श्रृंखला। इस श्रृंखला में कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया है, और श्रृंखला में कुछ घटनाएं थीं :

- *भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता पर ज्ञान अंतराल को भरने* पर डॉ सारथ गुट्टीकुंडा द्वारा एक वार्ता।
- प्रोफेसर डी. प्रभाकरन, डॉ. राज कुमार और डॉ. प्रीत के. ढिलों के साथ *वायु प्रदूषण के एक्सपोजर के स्वास्थ्य प्रभाव* पर भारत के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन द्वारा सह–संगठित और नियंत्रित एक पैनल।
- *भारत में प्रतिकूल जन्म परिणामों के निवारक कारण के रूप में वायु प्रदूषण* पर प्रोफेसर कल्पना बालाकृष्णन के साथ बातचीत।
- मुक्ता नायक द्वारा नियंत्रित अमित भट्ट, पार्था बासु और सुमित शर्मा के *साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता में परिवहन क्षेत्र की भूमिका : हस्तक्षेप के लिए प्रमुख चालक और मौके* पर एक पैनल।
- हरीश दामोदरन द्वारा नियंत्रित डॉ एम एल जाट, प्रीतम सिंह हंजारा और डॉ राजबीर यादव के साथ *राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्रोत के रूप में फसल जलने* पर एक पैनल।
- अरकाजा सिंह द्वारा नियंत्रित रवि अग्रवाल, नलिनी शेखर और डॉ सीमा अवस्थी के साथ *वायु प्रदूषण के कारण के रूप में नगर निगम ठोस अपशिष्ट* पर एक पैनल।

इन घटनाओं ने वायु प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं पर सूचनात्मक चर्चा देखी, और नीतिगत हस्तक्षेपों के महत्व पर प्रकाश डाला। अपनी बातचीत के दौरान, डॉ गुट्टिकुंडा ने वायु गुणवत्ता पर डेटा में अंतराल पर चर्चा की, और अल्पकालिक प्रासंगिक घटना के बजाए वायु प्रदूषण को साल भर संकट के रूप में देखने की आवश्यकता पर बल दिया। एक्सपोजर मूल्यांकन और पर्यावरण महामारी विज्ञान में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ प्रोफेसर बालकृष्णन ने अपनी प्रस्तुति में उल्लेख किया कि रोग से संबंधित बोझ में किसी भी कमी के लिए पीएम 2.5 स्तरों को मौजूदा स्तरों से भारी कमी की आवश्यकता होगी।

सीपीआर वेबसाइट अब विशेषज्ञों के परामर्श से समूह द्वारा तैयार किए गए प्रमुख मुद्दों पर सुलभ पृष्ठभूमि सामग्री के साथ श्रृंखला में सभी घटनाओं के वीडियो रिकॉर्डिंग होस्ट करती है।

III. भूमि अधिकार प्रयास (एलआरआई)

भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के भूमि अधिकारों को समझना

भूमि अधिकार पहल (एलआरआई) टीम ने भारत में भूमि कानून, भूमि अधिग्रहण और अनुसूचित क्षेत्रों पर इसके चौथे वार्षिक सम्मेलन में *भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के भूमि अधिकारों के कानूनी शासन और राजनीतिक अर्थव्यवस्था* पर अपनी रिपोर्ट लॉन्च की। नमिता वाही और अंकित भाटिया द्वारा सह–लेखक, रिपोर्ट में सौम्या झा के अनुसंधान योगदान, साथ ही साथ पूर्व अनुसंधान सहयोगी, पल्लव शुक्ला, स्पंदना बट्टुला और पूजा पाल शामिल थे। यह रिपोर्ट प्रोफेसर सिरीग्लोपेंन के नेतृत्व में चेर. मिशेलसेन इंस्टीट्यूट (सीएमआई), नॉर्वे, में भूमि

अधिकार पहल और सेंटर ऑन लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बीच पांच साल के लंबे अनुसंधान सहयोग का परिणाम था।

रिपोर्ट प्रकाशित करती है कि आदिवासी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संवैधानिक गारंटी के अस्तित्व के बावजूद, (विशेष रूप से, भूमि के अधिकार के संबंध में), वे भारत के सभी समूहों के सबसे कमजोर, विस्थापित और साधनहीन बने हुए हैं। अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों और नीतियों की समीक्षा के माध्यम से, और वित्तीय और प्रशासनिक संरचनाएं जो इन सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, रिपोर्ट सुरक्षात्मक और विस्थापित कानूनों के एक विवादित शासन को चित्रित करती है, साथ ही साथ इन कानूनों के तहत विवादित नीतिगत कथाएं, जो अनुसूचित जनजातियों और उनके संबंधित भूमिहीनता के विस्थापन की सुविधा प्रदान करती हैं। इस रिपोर्ट में अनुसूचित क्षेत्रों के वर्तमान भौगोलिक मानचित्रण पर बांध, जंगलों और खनन गतिविधियों के वर्तमान वितरण के साथ व्यापक प्राथमिक डेटा भी शामिल है।

एलआरआई सम्मेलन में सरकार, शैक्षणिक और नागरिक समाज संगठनों के विभिन्न पणधारकों द्वारा रिपोर्ट पर टिप्पणियां शामिल हैं। पैनलिस्टों में दूसरों के बीच डॉ टी हक, चेयरमैन, स्पेशल लैंड सेल, नीति आयोग, राघव चन्द्र, सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, डॉ वी एन वी के शास्त्री, पूर्व निदेशक, जनजातीय सांस्कृतिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, आंध्र प्रदेश सरकार, सहित सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल थे। यह रिपोर्ट प्रिंट और टेलीविजन मीडिया में व्यापक रूप से कवर की गई थी, जिसमें *द वायर, द संडे गार्जियन* और *गो न्यूज* शामिल थे।

नार्वेजियन रिसर्च काउंसिल और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित भूमि अधिकार पहल का कार्य ओस्लो में भारत नॉर्वे रिसर्च सम्मेलन में उत्कृष्ट शोध सहयोग के एक उदाहरण के रूप में पहचाना गया था।

भारत में भूमि अधिग्रहण एकीकरण की समझ

निष्पक्ष मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के अधिनियमन के अनुसार 2014 से 2018 तक सुप्रीम कोर्ट मुकदमे पर निरंतर अनुसंधान का प्रदर्शन किया। यह अनुसंधान भारत में भूमि अधिग्रहण : 1950 से 2016 तक उच्चतम न्यायालय के मामलों की समीक्षा नामक एलआरआई की 2017 रिपोर्ट पर निर्मित है। कानून के पूर्वव्यापी संचालन पर विवादित उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के प्रभावों के आधार पर *लाइवलैवोन* ने नमिता वाही का इंटरव्यू किया था।

वाही ने *भारत में भूमि संघर्ष को समझने* पर सीपीआर पॉडकास्ट में 2017 की रिपोर्ट के निष्कर्षों को भी समझाया था, और अध्ययन पर 2016 सेमिनार के यूट्यूब वीडियो अब 9,000 से अधिक अभूतपूर्व दर्शकों के साथ सीपीआर वेबसाइट पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रिसर्च वीडियो में से एक है। वाही ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (टेरी) द्वारा आयोजित सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दो बैचों में इस विषय पर व्याख्यान दिया।

एक भूमि कानून डेटाबेस तैयार करना

एलआरआई टीम ने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना और मेघालय राज्यों के लिए सभी भूमि कानूनों का एक व्यापक डेटाबेस संकलित किया। टीम ने ऐसे डेटाबेस बनाने और एलआरआई सम्मेलन में कानूनों के प्रारंभिक विश्लेषण और केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा आयोजित एक सेमिनार में शोध निष्कर्ष प्रस्तुत किए।

पानी के लिए मानव अधिकार को जानना

एलआरआई को ब्राजील, कोस्टा रिका, भारत, पेरू और दक्षिण अफ्रीका में पानी के लिए मानव अधिकार को समझने पर बहु–देश अनुसंधान सहयोग के भाग के रूप में नॉर्वेजियन रिसर्च काउंसिल द्वारा एक अनुसंधान अनुदान से सम्मानित किया गया था।

- भूमि अधिकार पहल के कार्य पर, भारत में व्यापक और बढ़ते भूमि संघर्ष के कारणों और *गो न्यूज एंड लैंड पोर्टल* द्वारा, 'अस्तित्व : देश का बढ़ता भू संघर्ष' नामक लोकसभा टेलीविजन शो के लिए नमिता वाही का इंटरव्यू किया गया था।

- नमिता वाही भूमि संसाधन विभाग के डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर अनुसंधान संगठनों के एक संघ द्वारा संचालित प्रायोगिक अध्ययन की समीक्षा करने वाली तकनीकी समिति के सदस्य थी।

- नमिता वाही और अंकित भाटिया ने बर्गन एक्सचेंजेस ऑन लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्वे और नई दिल्ली में सेकेंड इंडिया लैंड एक डेवलपमेंट सम्मेलन में *द लीगल एंड पॉलिटिकल इकॉनोमी ऑफ लैंड राइट्स ऑफ शेड्यूलड ट्राइब्स इन शेड्यूल्ड एरिया,* पर अनुसंधान निष्कर्ष प्रस्तुत किया। वाही ने यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो में इन निष्कर्षों पर भी व्याख्यान दिया, और ओस्लो में भारत नॉर्वे रिसर्च सम्मेलन में भाग लिया।

- वाही ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, सिमला द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में *अंडरस्टैंडिंग लैंड एक्वीजिशन डिस्पुट्स इन इंडिया* और नई दिल्ली में *कॉम्पेरेटिव रिसर्च ऑन लैंड यूज चेंज कंफ्लिक्ट्स इन म्यांमार, इंडोनेशिया और भारत,* पर सीपीआर–नमति कार्यशाला में नए निष्कर्ष प्रस्तुत किया।

- वाही ने आईएसईआरपी कार्यशाला, ईएएफआईटी विश्वविद्यालय, मेडेलिन, कोलंबिया में *पोपर्टी राइट्स एंड सोशल एंड इकॉनोमिक राइट्स, द पोस्ट – कोलोनियल स्टेट एंड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया* पर भी अनुसंधान प्रस्तुत किया।

- वाही ने राफ्टो हाउस में *द 33 एनिवर्सरी ऑफ द भोपाल गैस डिजास्टर,* और सीएमआई, बर्गन में *बिजनेस रिलेटेड ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन्स : स्टेट ऑर कॉर्पोरेट रिस्पोंसिबिलिटी?* पर पैनलों में भाग लिया।

- श्री वाही ने ढाका में थिंक टैंक पहल की सातवीं क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया।

2015 में लॉन्च एलआरआई स्पीकर सीरीज़, शैक्षणिक, सिविल सोसायटी संगठनों, पत्रकारों और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न पणधारकों द्वारा भूमि अधिकार मुद्दों पर दृष्टिकोण प्रदर्शित करना जारी रखती है। इस वर्ष कवर किए गए विषयों में भूमि पकड़ और विस्थापन, भूमि संघर्ष से संबंधित डेटा पत्रकारिता प्रयास, और खनिज राजस्व के न्यायसंगत और कुशल अंतःविषय और अंतःक्रियात्मक आबंटन शामिल थे।

IV. शासन और सार्वजनिक नीति संबंधी पहल (जीपीपीआई)

शासन एवं सार्वजनिक नीति पहल (जीपीपीआई) द्वारा भारतीय विधायकों हेतु इसके विदेशी शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जारी रखा गया और आधार गोपनीयता चिंताओं और डेटाबेस सुरक्षा, केंद्रीय बजट 2018 में किए गए स्वास्थ्य प्रतिबद्धताओं और भारत में बाल स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने जैसे मुद्दों पर घरेलू गोलमेज चर्चा भी आयोजित की गई।

घरेलू गोलमेज चर्चाएं

- जीपीपीआई ने आधार मंच के पेशेवरों और विपक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हुए *टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस : आधार प्राइवेसी कंसर्न एंड डेटाबेस सिक्योरिटी,* पर एक गोलमेज चर्चा आयोजित की, जो गोपनीयता और राजनीतिक अधिकारों के मौलिक मुद्दों से जुड़ी कई चिंताओं के कारण बहस में थी। इस चर्चा के उद्देश्य से पवन दुग्गल, वकील, भारतीय उच्च न्यायालय और साइबर लॉ विशेषज्ञ; गौतम भाटिया, वकील, उच्चतम न्यायालय; और शुभाशीष भद्रा, एसोसिएट, ओमिडियार नेटवर्क पर डिजिटल पहचान जैसे विशेषज्ञों के साथ चर्चा के माध्यम से मंच के जोखिम और लाभ पर एक अच्छी तरह से परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में संसद सदस्यों की मदद करने के लिए एक केंद्रित प्रवचन तैयार करना था।
- जीपीपीआई और ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजीज (जीएचएस) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा और अन्य मुद्दों के साथ आयुष भारत कार्यक्रम में 1,200 करोड़ रुपए के आबंटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए *''हेल्थ कमिटमेंट्स मेड इन द यूनियन बजट 2018'',* पर चर्चा संयुक्त रूप से आयोजित की। जीपीपीआई और जीएचएस ने राजनीतिक एजेंडे पर बाल स्वास्थ्य और पोषण जैसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों को रखने में राजनीतिक नेताओं की भूमिका पर विचार–विमर्श करने के लिए *प्रायोरिटाइजिंग चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन इंडिया* पर एक चर्चा भी आयोजित की।

शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम

- जीपीपीआई द्वारा प्रिसंटन यूनिवर्सिटी में आयोजित *फिफ्थ लेग ऑफ दि प्रिंसटन – जीपीपीआई – सीपीआर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स प्रोग्राम* हेतु राजनैतिक नेताओं के बहु–दलीय समूह को ले जाया गया।
- ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एण्ड ट्रेड के साथ साझेदारी में आयोजित एक कार्यक्रम के भाग के रूप में, संसद के पांच भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी चाइना सेंटर एंड क्रॉफर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में परस्पर संवाद चचाओं में भाग लिया।
- लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स (एलएसई) में सप्ताह भर लम्बे 2017 *चेवनिंग – सीपीआर पार्लियामेंटेरियन्स फेलोशिप प्रोग्राम* में सात सांसदों वाले एक बहु–दलीय समूह ने भाग लिया।

v. पर्यावरणीय न्याय पर सीपीआर – नमति सहयोगात्मक कार्यक्रम

- सीपीआर–नमति पर्यावरण न्याय कार्यक्रम के प्रशिक्षित पैरालीगल्स ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ में उत्तरा कन्नड़ और कुलदा खानों में लैंडफिल साइटों द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के अनुपालन के कारण समुदायों द्वारा महसूस किए गए प्रभावों को रिकॉर्ड करने के लिए दो समुदाय के नेतृत्व वाले 'ग्राउंडट्रूथिंग' अभ्यास किए। रिपोर्ट उपचारात्मक कार्रवाई के लिए सरकारी अधिकारियों को संलग्न करने के लिए साक्ष्य–आधारित उपकरण हैं।
- कार्यक्रम के पैरालीगल्स ने पर्यावरणीय अनुपालन (पानी और वायु प्रदूषण, अपशिष्ट की डंपिंग, सामान्य स्थानों तक सीमित सार्वजनिक पहुंच) के साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए समुदायों के साथ कार्य किया और स्थानीय संस्थानों से जुड़ा हुए, 21 मामलों में संयुक्त साइट निरीक्षणों को प्राप्त किया। इन संयुक्त निरीक्षणों के माध्यम से, प्रभावित समुदाय उल्लंघन के प्रभाव दिखाने में सक्षम थे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग और जिला कलेक्टर

जैसे संस्थानों से प्रभावी कार्रवाई का आह्वान करते थे। अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं दोनों में प्रकरण अध्ययन एक क्यूरेटेड प्रकाशन–*मेकिंग द लॉ काउंट* में पैरालीगल्स द्वारा संकलित किए गए थे ।

- इसके अलावा पैरालीगल्स और प्रभावित समुदायों ने राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों को विशिष्ट सबमिशन दिए, जिनमें शामिल हैं 1) गुजरात में खनिजों के संचालन और परिवहन के लिए राज्य स्तरीय दिशानिर्देश; 2) कर्नाटक राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण में परिवर्तन का एक सुझाया गया सेट; 3) भूजल निकासी के लिए कोई आपत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों पर सुझाव दिए गए हैं।

पर्यावरणीय न्याय प्रैक्टिशनर्स को बढ़ावा देना

कार्यक्रम ने अपनी *हैंडबुक ऑन लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेमीडिस फॉर कम्युनिटी लेवल एनवायर्नमेंट जस्टिस प्रैक्टिशनर्स,* एक दूसरा संस्करण जारी करने का अद्यतन किया। यह अंग्रेजी के साथ चार अलग–अलग भारतीय भाषाओं (हिंदी, कन्नड़, उड़िया और गुजराती) को जोड़ता है।

पैरालीगल प्रैक्टिस गाइड मौजूदा नियामक ढांचे के भीतर प्रशासन से उपचार प्राप्त करने के लिए एक चरण–दर–चरण प्रक्रिया प्रदान करता है। यह हिंदी, कन्नड़, उड़िया, गुजराती, बहासा– इंडोनेशिया और अंग्रेजी में उपलब्ध है।

भूजल अमूर्तता के विनियमों पर सरल जागरूकता सामग्री और मौजूदा विनियामक स्थापना के भीतर जल प्रदूषण के प्रभावों का समाधान करने के लिए सतही जल के उपयोग को बनाया गया था – समुदायों और पैरालीगल्स के अनुभवों पर चित्रण था। यह अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, कन्नड़ और गुजराती में उपलब्ध है।

पर्यावरणीय मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, कोस्टल विनियमन की प्रक्रियाओं पर मीडिया और सार्वजनिक प्रबंधन

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के उत्तर में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में संशोधन में प्रस्तावित किया गया, जिसने मंत्रालय द्वारा वास्तविक तथ्यों को मंजूरी दे दी, कार्यक्रम ने एक कार्य पत्र तैयार किया जो कि प्राप्त किए गए आवेदनों का विश्लेषण करता है।

पैराग्राफ के साथ आरेखित साइड बार में उद्धरण में नीचे दी गई जानकारी दें

'शोध पत्र के निष्कर्ष मुख्यधारा के दैनिक समाचार पत्रों और *डीएनए, डेलीओ, द हिंदू, काउंटरव्यू, वायर.इन, राउटर* जैसे मीडिया पोर्टलों द्वारा उठाए गए थे। इससे ईआईए अधिसूचना, 2006 में किए गए बदलावों के प्रभाव पर सार्वजनिक जुड़ाव को सूचित करने में मदद मिली।'

- पिछले दो वर्षों में, कई राज्यों ने भूमि अधिग्रहण, पुनःस्थापन और पुनर्वास (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 में निष्पक्ष मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार से संबंधित व्यक्तिगत अधिनियमों और नियमों के माध्यम से कानून पेश किए हैं, जो सार्वजनिक भागीदारी, निष्पक्ष मुआवजे और बेहतर पुनःस्थापन अधिकारों की प्रक्रिया को कम करता है। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों द्वारा इस तरह के कमजोर पड़ने पर एक कार्यबल शोध पत्र रखा, जिसमें प्रक्रिया में केंद्रीय कानून के कुछ प्रगतिशील प्रावधानों को छोड़कर हाइलाइट किया गया।

पैराग्राफ के साथ आरेखित साइड बार में उद्धरण में नीचे दी गई जानकारी दें

'शोध पत्र इसकी वेबसाइट पर *इंडिया एनवायर्नमेंट पोर्टल* द्वारा उपलब्ध कराया गया था। काउंटरव्यू, वायर.इन और डीएनए ने शोध पत्र के निष्कर्षों को साझा करने वाली कहानियां चलाईं और देश में भूमि अधिग्रहण कानून के आसपास बहस के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा की।'

- 2017 की शुरुआत में, एक बहिष्कार तरीके से, एमओईएफसीसी ने 2011 तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना को रद्द करने के लिए एक नई अधिसूचना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की, जो भारतीय तट पर विकास को नियंत्रित करता है, और तट के पारंपरिक उपयोग को स्वीकार करते हुए नागरिक जुड़ाव के माध्यम से विकसित किया गया था। उत्तर में, इस क्षेत्र में अपने ऐतिहासिक कार्य पर चित्रण करते हुए, कार्यक्रम अप्रैल से अगस्त 2017 के बीच सीपीआर वेबसाइट पर इन प्रस्तावित परिवर्तनों से संबंधित दस ब्लॉगों की एक श्रृंखला चलाई, इसमें कानून का इतिहास, पिछले परिवर्तनों का विश्लेषण, अदालत का परिप्रेक्ष्य, और मछुआरे समुदायों के विचार शामिल है। कार्यक्रम, सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के माध्यम से, नए कानून में प्रस्तावित संशोधन प्राप्त करने में सक्षम था, जिसे किसी एक ब्लॉग के माध्यम से प्रकट किया गया था।

पैराग्राफ के साथ आरेखित साइड बार में उद्धरण में नीचे दी गई जानकारी दें

'ब्लॉग श्रृंखला का संकेत लेते हुए, मीडिया ने सीआरजेड में बदलावों पर विस्तृत और गहन रिपोर्ट की। द हिंदू, डीएनए, डेक्कन हेराल्ड और हिंदुस्तान टाइम्स के संदर्भ के अनुसार मीडिया कहानियों ने महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों के लिए श्रृंखला में जानकारी प्रदान की। इस श्रृंखला ने मछुआरे समूहों, तटीय समुदायों और नागरिकों, पर्यावरणविदों, शहरी योजनाकारों आदि से रुचि प्राप्त की, जिनमें से कई ने बाद में प्रस्तावित संशोधन के प्रभाव के बारे में मंत्रालय को लिखा।'

वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाएं

I. मानवाधिकार से लेकर स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता पर भारत में शोध का डिजाइन एवं कार्यान्वयन
यह परियोजना भारत की एक प्रमुख चुनौती पर ध्यान केन्द्रित करती है – स्वच्छता। यह परियोजना स्वच्छता का अधिकार हासिल करने के लिए भारत में कानून तथा नीतिगत रूपरेखा की जाँच करती है। यह परियोजना कानून तथा नीतिगत ढाँचे का विश्लेषण करने के जरिए स्वच्छता के अधिकार के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने और उसके बाद तीन राज्यों (राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा केरल) में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने का प्रस्ताव करती है।इसका मुख्य उद्देश्य संकल्पनात्मक रूपरेखा को समझना, कार्यान्वयन की चुनौतियों का पता लगाना, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को उजागर करना तथा स्वच्छता के अधिकार को बेहतर रूप में हासिल करने का सुनिश्चय करने के लिए नीतिगत सुझावों का प्रस्ताव करना है। इस परियोजना में नीति निर्धारकों तथा अन्य पणधारियों के साथ अधिगम समारोहों तथा कार्यशालाओं के माध्यम से सीधे सम्पर्क करना भी चाहा गया है।

सूचना अवधि के दौरान इस परियोजना के लिए कोई अद्यतन नहीं है।

II. भारत के लिए स्केलिंग सिटी संस्थान (एससीआई–एफआई) : स्वच्छता
भारत के लिए स्केलिंग सिटी संस्थान (एससीआई – एफआई) : स्वच्छता पहल का उद्देश्य है। भारत सरकार के शहरी स्वच्छता कार्यक्रमों को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए सूचना और सहयोग प्रदान करना और निवेश करना तथा शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित और अधिक टिकाऊ स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु छोटे शहरों में बिना सीवर वाली स्वच्छता सेवाओं की आपूर्ति का विस्तार करना है। पिछले वर्ष इस परियोजना में स्वच्छता क्षेत्र के कुछ उभरते सवालों और नीति सम्बन्धी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। छोटे शहरों और उच्च घनत्व वाली बस्तियों में स्वच्छता की स्थिति, जिसे औपचारिक रूप से शहरी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है; एफएसएम सेवाओं के प्रावधान आनुपातिक दरों को; और जाति, सामाजिक बहिष्कार और मैनुअल स्केवेन्जिंग के संबंध में एफएसएम के स्थान के आसपास जागरूकता विकसित करने को अधिक विशेष रूप से, इनमें शामिल किया गया। इस कार्यक्रम से इस अवधि में अपने आउटरीच और प्रसार प्रयासों को काफी हद तक बढ़ाया गया, नेटवर्क बनाने और उन अन्य संस्थानों के साथ सहयोग पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जिनके काम स्वच्छता के क्षेत्र से संबंधित हैं। सीपीआर में आयोजित स्वच्छता की सेमिनार श्रृंखला, एक सीपीआर की मेजबानी में सम्मेलन और कार्यशाला के साथ–साथ अन्य अवसरों के साथ और अधिक अवसरवादी बैठकों और चर्चाओं के माध्यम से यह आउटरीच सीओआरपी वार्ता, आयोजित की गयी थी। 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की रिपोर्टिंग अवधि में कुल 76 मुख्य आउटपुट कार्यक्रम (बैठकों सहित) पूरे किए गए।

इस अवधि के दौरान,

1. हमने अनेक अध्ययन किए :

- दिल्ली के आयानगर, में निजी सेप्टिक टैंक खाली करने का काम करने वाले संगठन पर गहन प्रकरण अध्ययन। यह अध्ययन गुणात्मक क्षेत्रवर्क पर आधारित है जो जनवरी–मार्च 2017 से आयोजित किया गया था, जिस में सेवा प्रचालकों, निवासियों और स्थानीय नेताओं के साक्षात्कार शामिल किए गए। अध्ययन में पाया गया कि छोटे पैमाने पर काम करने वाले वे प्रचालक जिन्हें स्थानीय कार्टेल में समझौते के लिए शामिल किया गया था,

वे पिट खाली करने की सेवाएं प्रदान करते थे। यह उपाय उस बाजार प्रतिस्पर्धा की जांच के लिए लिया गया था जिससे लाभ मार्जिन में गिरावट आई थी। प्रचालकों ने मजबूत सामाजिक संबंध साझा किए और एक दूसरे के साथ संबंध और दोस्ती के नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए थे। काम की लाइन में अपने लंबे समय तक एक्सपोजर को देखते हुए, उन्होंने निवासियों के बीच सेप्टिक टैंक प्रबंधन से संबंधित ज्ञान के प्रसारकों के रूप में निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में, यह पाया गया कि मशीनीकृत उपकरणों के उपयोग के बावजूद, मालिक अभी तक सामाजिक तौर पर निम्न जाति के समुदायों से मानव मल मूत्र को उठाने का निंदनीय कार्य करवा रहे थे।

- न्यू रिसर्च एंड पॉलिसी पैराडाइम: द एनालिसिस ऑफ द सेनिटेशन सिटेशन इन लार्ज डेंस गांव''नामक अध्ययन 2017 में प्रकाशित हुआ था। यह शोध शहरीकरण में उभरते रुझानों के साथ कई वर्षों के सीपीआर कार्यों के आधार तैयार किया गया था, और इसमें एक आदर्श बदलाव दिखाता है, ग्रामीण– शहरी निरंतरता, कई चीजों, योजना, उत्पादन और सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे के प्रावधान में प्रकट हुई। इस शोध में भारत के बड़े और घने गांवों (एलडीवी) में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों और राजमार्गों के निकट के क्षेत्रों में साइट पर स्वच्छता प्रणाली को बड़ी वरीयता के साथ शामिल किया गया, और इसलिए सेवाओं को बढ़ाने के लिए सामरिक दृष्टिकोण की सख्त आवश्यकता है। अध्ययन में तीन जनगणना डेटासेट से भारत के बड़े और घने गांवों में स्वच्छता बुनियादी बनावट पर द्वितीयक डेटा की खोज की गई। शोध के निष्कर्ष बड़े और सघन आबादी वाले गांवों में राज्यवार भिन्नताओं को उजागर करते हैं, जो संबंधित राज्य में आबादी के बड़े प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं और ये आम तौर पर सेप्टिक टैंक और बेहतर गड्ढे के लिए उच्च प्राथमिकता को दर्शाते हैं। अध्ययन के नतीजे बड़े घने गांवों और जनगणना कस्बों पर नए प्रोग्रामेटिक और नीतिगत फोकस की आवश्यकता को दर्शाते हैं जबकि क्षेत्रीय और स्थानीय विविधताओं को संबोधित करने के लिए विकेंद्रीकरण कार्य नीतियों की आवश्यकता भी दिखाते हैं। अध्ययन के नतीजे एक्स–एंटी और एक्स–पोस्ट हस्तक्षेप को पूर्व निर्धारित करने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण की आवश्यकता को दर्शाते हैं और साइट पर स्वच्छता के लिए स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए व्यवहार्य और प्रतिकृति विकेन्द्रीकृत कार्यनीतियों पर नीति निर्माताओं और कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं के लिए पर्याप्त रूप से संभावित निर्देश की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

- ''खुले स्थान पर शौच रहित अवस्था हासिल करने की प्रक्रिया को समझने'' के लिए उदयपुर में जिला प्रशासन के अनुरोध पर उदयपुर, राजस्थान का एक प्रकरण अध्ययन शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की परिचालन चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एसबीएम जी), और 141 पंचायतों द्वारा ओडीएफ की स्थिति सहित उनके हाल के स्वच्छता प्रयासों के सत्यापन के लिए प्रशासन की सहायता करने और प्रोत्साहन प्रक्रिया, आईईसी गतिविधियों, उनकी पहुंच और प्रभाव की जांच की गई। अध्ययन के उद्देश्य था, उदयपुर (मांग और आपूर्ति पक्ष) स्वच्छता बाजार की व्यापक समझ विकसित करना और संभावित बाजार विफलताओं की पहचान करना और एसबीएम जी प्रक्रियाओं और पंचायतों द्वारा अपनाए गए प्रोत्साहन प्रावधान और व्यवहार परिवर्तन के मॉडल को समझना और उनका मूल्यांकन करना। इस अध्ययन में कार्यक्रम कार्यान्वयन की दिशा में इन परिवर्तनीय दृष्टिकोणों के कार्यात्मक और सामाजिक आर्थिक प्रभावों को समझने और जाति, वर्ग और लिंग की अंतरंगता से निर्माण और उपयोग के प्रिज्म से समझने का प्रयास किया गया। इस अध्ययन में निम्नलिखित शोध प्रश्नों के माध्यम से उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की (1) गांव ओडीएफ कैसे बनते हैं ? विशेष रूप से, ट्रिगरिंग, आईईसी, और निर्माण की दिशा में दृष्टिकोण क्या है ? (2) शौचालयों का निर्माण किस प्रकार किया जा रहा है और निर्माण और उपयोग प्रकरण क्या है (3) प्रशासन का परिप्रेक्ष्य क्या है और विभिन्न प्रशासकों की भूमिका क्या है ? (4) प्रेरक, एसएचजी, सिविल सोसाइटी संगठन आदि जैसे बाहरी पणधारकों की भूमिका क्या है? (5) फंड प्रवाह और प्रशासनिक विवेकाधिकार जैसे प्रक्रियात्मक पहलू कैसे काम करते हैं? सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सीपीआर सिफारिशों में सार्वजनिक सुविधाओं में अच्छी तरह से बनाए रखना और उपयोग किए जा रहे शौचालय शामिल किए गए; ओडीएफ के बाद लगातार निगरानी तंत्र; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; वास्तविक लाभार्थियों

की पहचान के लिए लिंग संवेदनशीलता, प्रौद्योगिकी और एफएसएम, कार्य प्रवाह सुधार उपाय पर आईईसी फोकस आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- तीन शहरों में सेप्टिक टैंक खाली करने के व्यवसायों की बाजार विशेषताओं और व्यापार मॉडल की पहचान की गई ''3 शहरों भुवनेश्वर, जयपुर और देहरादून''में ''बिजनेस मॉडल स्टडीज ऑफ सेप्टिक टैंक एम्प्टीइंग सर्विसेज'' का अध्ययन किया गया। सभी तीन बाजारों में, सेवा प्रदाता छोटे पैमाने पर, अत्यधिक अनौपचारिक बाजारों में कम परिचालन मार्जिन के साथ काम करते थे। भुवनेश्वर के मामले में बाजार समेकन के कुछ तत्व देखे गए, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि 5 से 7 उद्यमियों के पास वाहनों को खाली करने वाले सभी निजी सेप्टिक टैंक (संख्या में 30 होने का अनुमान है) का स्वामित्व है, जबकि हमें अन्य शहरों में एकल वाहन व्यवसाय अधिक मिलते हैं। देहरादून के अध्ययन में प्रचालकों के बीच व्यापार संघ के कुछ तत्व पाए गए, और प्रचालक शहर के एसटीपी में अपने ट्रक को काफी संगठित तरीके से खाली कर रहे थे। इन सभी शहरों में विनियमन और पर्यवेक्षण की कमी या स्थानीय सरकार द्वारा वास्तव में किसी भी प्रकार की भागीदारी के प्रकार की पहचान की गई, हालांकि भुवनेश्वर में स्थानीय प्राधिकरण ने अपने स्वयं के ट्रक भी संचालित

- किए और एफएसएम सेवाओं के प्रावधान में इन व्यवसायों की भूमिका को औपचारिक रूप से सरकारी नीति में मान्यता भी दिलाई। इस प्रकरण अध्ययन में शहरों में लागत, निवेश और मूल्य निर्धारण कार्यनीतियों में भी दिलचस्प बदलाव देखे गए।

- ''मैनुअल स्केवेन्जिंग इन इंडिया'' नामक साहित्य समीक्षा को यह समझने के लिए लिया गया कि अकादमिक, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों ने उन लोगों और गतिविधियों को कैसे परिभाषित किया है जिन के लिए 'मैनुअल स्केवेन्जिंग' शब्द को अपनाया जाता है। पहले भाग 1 में भविष्य के शोध के लिए साहित्य कवर को कवर करने और संभावित शोध प्रश्नों के विश्लेषण के संकलन को संकलित किया गया है । भाग 2 किताबों, लेखों, वृत्तचित्रों, परामर्श और अन्य सामग्री की एक एनोटेटेड ग्रंथसूची प्रस्तुत करता है। कुल 49 पत्रों की समीक्षा की गई। यह खंड मैनुअल स्केवेन्जिंग पर उपलब्ध सारांशित साहित्य के एक संपूर्ण डेटाबेस के रूप में कार्य करता है, जिस विषय को अब तक परिभाषित किया गया है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। पूर्व–स्वतंत्र भारत से संबंधित थीम पर केंद्रित नवीनतम कार्यों को प्रकाशन समीक्षा में शामिल किया गया है। समीक्षा में यह परिणाम निकला कि उपलब्ध साहित्य में प्रमुख रूप से मैनुअल स्केवेंजिंग को सामाजिक प्रथा के रूप में प्रस्तुत करता है जो सामाजिक प्रथा में जाति प्रथा के क्रम में है जिसमें लोग तथाकथित ''प्रदूषणकारी जातियों'' के लोग अशोधित फीकल मैटर को परम्परागत रूप से निपटाते हैं । इन समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली जाति–आधारित भेदभाव की सामाजिक–आर्थिक स्थितियां इन कार्यों के प्रमुख विषय हैं। मैनुअल स्केवेन्जिंग पर पुराने साहित्य में सूखे शौचालयों की सफाई और 'नाइट सॉइल' को 'हेड लोड' के रूप में ले जाने के बीच एक लिंकेज है, जबकि नया साहित्य सीवर की सफाई, सेप्टिक टैंक की सफाई पर केंद्रित है।

- ''सफाई गतिविधियों की एक टाइपोग्राफी के रूप में मैनुअल स्केवेन्जिंग : ''स्वच्छता कार्य पर प्राथमिक शोध'' शीर्षक से गैर–अधिकृत बस्तियों में किए गए प्राथमिक शोध पर आधारित रिपोर्ट है। अध्ययन का उद्देश्य उन गतिविधियों की एक श्रृंखला की पहचान करना था जो इस अध्ययन के उद्देश्य के लिए 'मैनुअल स्केवेन्जिंग' के रूप में परिभाषित गैर–शोधित मानव उत्सर्जन वाले किसी भी व्यक्ति के मैन्युअल संपर्क को लागू करती हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य है उन गतिविधियों का एक करीबी मूल्यांकन – सफाई की वास्तविक प्रक्रिया और इसमें कौन संलग्न है – पॉलिसी के साथ–साथ अकादमिक में वर्षों में मैनुअल स्कैवेंजिंग को समझने के तरीके को समझना। मैनुअल स्कैवेंजिंग को परिभाषित करने में गतिविधि की तुलना में व्यक्तिगत पर अधिक फोकस बना रहा। उदाहरण के लिए, 2013 के मैनुअल स्कैवेंजिंग अधिनियम, जैसे कि 1993 के समकक्ष, ''मैनुअल स्केवेंजर'' की परिभाषा के रूप में ही परिभाषित किया किया गया है और कहा गया है कि

कि ''मैनुअल स्केवेन्जिंग'' को पूर्व के आधार पर माना जाएगा। अकादमिक काम भी मुख्य रूप से मैनुअल स्केवेंजर्स के रूप में लगे समुदायों पर केंद्रित होते हैं, जो जाति व्यवस्था के कारण अपने ऐतिहासिक नुकसान को प्रकाश में सामने लाते हैं। यह अध्ययन पिछले प्रक्षेपवक्र की पुष्टि करता है और मैन्युअल स्केवेन्जिंग के अध्ययन में सामने आया है जो – एक गतिविधि के रूप में अंतर्निहित है। यह गतिविधियों की एक टाइपोग्राफी तैयार करता है, संक्षेप में, मैनुअल स्केवेन्जिंग के रूप में अर्हता प्राप्त करता है लेकिन वर्तमान में इस अधिनियम के अनुकूल माना जाता है जो 2013 अधिनियम के परिधीय घेरे में माना जाता है।

- स्वच्छता के गैर–सरकारी पारिस्थितिक तंत्र पर मानचित्रण अध्ययन मुख्य अभिकारकों/कम्पनियों (गैर–सरकारी/निजी की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था जो विशेष रूप से ओ एंड एम (गैर–नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करने और निर्देशिका विकसित करने) में स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनकी पहचान कर उनका विवरण (नाम, संपर्क का पता, प्रमुख ताकतें, महत्वपूर्ण भूमिकाएं जिसके लिए वे स्वच्छता क्षेत्र में कार्य करती हैं) तैयार करना ताकि ओडिशा राज्य राज्य में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए उनकी सेवाओं से काफी हद तक लाभ उठा सके। वर्तमान में ओडिशा में डेटा संग्रहण प्रक्रिया प्रगति पर है।

- सामुदायिक संस्थान अध्ययन : स्वच्छता प्रणालियों और प्रथाओं में गरीब समुदायों को शामिल करने के लिए परियोजना निर्मल के तहत दोनों शहरों में झोपड़ियों में समुदाय आधारित संरचनाएं बनाई गई हैं। स्लम स्तर पर स्लम स्वच्छता समितियां और वार्ड स्तर पर वार्ड स्वच्छता समितियां यूएलबी स्तर की प्राथमिक संरचनाएं हैं। अध्ययन का उद्देश्य झोपड़पट्टी समितियों और वार्ड समितियों द्वारा सामुदायिक आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करना है, और समुदाय आधारित भागीदारी तंत्र की प्रभावशीलता और समुदायों के साथ–साथ शासन पर उनके प्रभाव को समझने के लिए भागीदारी संरचनाओं और प्रक्रियाओं के रूप में अध्ययन करना है। अध्ययन मार्च 2018 तक अंगुल में पूरा हुआ था; मसौदा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ढेंकनाल में अध्ययन का दूसरा दौर मई 2018 में शुरू होगा।

- बालासोर की शहरी स्वच्छता योजना बालासोर में पानी और स्वच्छता के दबाव वाले मुद्दों और इसके लिए व्यवहार्य समाधानों की सूची के साथ एक व्यापक दस्तावेज है। जो एचयूडीडी, गोओ के आदेश पर तैयार, संशोधित सीएसपी एनयूएसपी के दिशानिर्देशों का पालन करता है और एक प्रगतिशील दस्तावेज है जो संगत पणधारकों को कई चल रही और संभावित नीतियों और कार्यक्रमों को अनुकूलित करने के लिए मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है। अंत में यह दस्तावेज शहर की पूरी स्वच्छता मूल्य श्रृंखला और शहर की जल आपूर्ति से शुरू होने वाली संबंधित सेवाओं और घरेलू और सार्वजनिक शौचालयों तक पहुंच के तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जांचता है और कार्यनीतियों को सक्षम करने का सुझाव देता है। प्राथमिक और माध्यमिक डेटा की सावधानीपूर्वक तुलना, स्थानीय संस्थानों का अध्ययन और विभिन्न जल और स्वच्छता सेवाओं के जीआईएस मानचित्रों को शामिल करने से यह सीएसपी नीति निर्माताओं, योजनाकारों, स्थानीय प्रतिनिधियों और शोधकर्ताओं के लिए एक संसाधन दस्तावेज बन जाता है। शहर स्वच्छता योजना दिसंबर 2017 में बालासोर नगर पालिका को प्रस्तुत की गई थी और बैठक में वार्षिक रोलिंग योजना को मंजूरी दे दी गई थी।

- गैर सीवर स्वच्छता पर क्षमता निर्माण मॉड्यूल का विकास : सीवर रहित स्वच्छता पर अंतिम क्षमता निर्माण मॉड्यूल सचिव, एचयूडीडी और सदस्य सचिव ओडब्ल्यूएसएसबी के प्रस्ताव के साथ मुद्रित किए गए थे। आवास और शहरी विकास विभाग (एचयूडीडी), ओडिशा जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (ओडब्ल्यूएसएसबी),

तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू), स्वच्छ भारत मिशन परियोजना प्रबंधन इकाई (एसबीएम पीएमयू) के साथ कई दौर की चर्चा और बैठक द्वारा मॉड्यूल, इसके प्रवाह और सामग्री को अंतिम रूप देने के लिए जुलाई से नवंबर में प्रैक्टिकल एक्शन (पीए) आरम्भ किया गया गया।.

- मल के कचरे के उपचार संयंत्र से उत्पादों के पुनः उपयोग और रीसायकल के लिए मार्गदर्शन नोट। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का तेज गति से प्रसार हो रहा है और सुरक्षित संग्रह, परिवहन और मल के कचरे के शोधन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अनिवार्यता के अनुसार, ओडिशा राज्य ने पहले से ही आगे बढ़ने की योजना के साथ, अमृत और धेंकनाल शहरों में एक एफएसटीपी और 9 एफएसटीपी चालू कर दिए हैं। द्वितीयक या तृतीयक शोधन स्तर पर ब्लैक वॉटर का उपचार तरल प्रदूषण और स्थिर, और सूखे कीचड़ पैदा होते हैं। जबकि पानी, अपने और अपने आप में, तेजी से मूल्यवान होती वस्तु है, दोनों धाराएं पोषक तत्व समृद्ध हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वाणिज्यिक उर्वराकरण के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। इसलिए, एफएसटीपी एंड उत्पादों का पुनः उपयोग, बहुमूल्य संसाधनों और खराब मिट्टी के पुनर्वास के संरक्षण से पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। मार्गदर्शन नोट का तर्क है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के संभावित जोखिमों को नियंत्रित करके कृषि में प्रदूषित और बायो सोलिड्स का सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है, हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन के बावजूद स्पष्ट रूप से चित्रित दिशानिर्देश और नियामक संरचना को लागू नहीं किया गया है, उदाहरण के लिए, यूएस ईपीए बायो सोलिड्स नियम और डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देश नीति में अंतराल सफल पुनः उपयोग में बाधा के रूप में कार्य करता है, और इस के लिए राज्य स्तरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह मार्गदर्शन नोट, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बायो सोलिड्स / शोधित किए गए मल के कचरे के पुनः उपयोग की नीतियों की समीक्षा, राज्य स्तर पर पॉलिसी निर्माताओं के लिए एक पुनः उपयोग नीति विकसित करने में सहायक होती हैं, जो समझने और कार्यान्वित करने में आसान है, जो कृषि में शोधित किए गए पानी और मल के कचरे के वैज्ञानिक और सुरक्षित रूप से पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है, और किसानों, स्थानीय समुदायों, उपभोक्ताओं और मिट्टी के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

2. इसके अतिरिक्त, सम–सामायिक विषयों पर नीति संबंधी संक्षिप्त विवरण तैयार किए गए, जिन्हें क्रमबद्ध रूप में नीचे प्रस्तुत किया गया है :

- ''स्वच्छ भारत मिशन – शहरी'' (एसबीएम–यू) शीर्षक से वर्ष 2017 में दो बजट संक्षिप्त जानकारी प्रकाशित की गई। निम्नलिखित मानकों के साथ शहरी क्षेत्रों में सरकार के प्रमुख स्वच्छता कार्यक्रम के एसबीएम–यू ट्रैक किए गए व्यय और परिणामों के बजट संक्षिप्त का विवरणः (1) आबंटन और रिलीज, (2) निर्मित शौचालयों की वास्तविक प्रगति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम), (3) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए जारी धन, और (4) खुले स्थानों पर शौच समाप्त करने की दिशा में प्रगति। वित्त वर्ष 2018–19 में, एसबीएम–यू के लिए केंद्र सरकार ने 2,500 करोड़ रु. (बजट अनुमान) आबंटित किए है, जो वित्त वर्ष 2017–18 से 9 प्रतिशत अधिक है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को धन आबंटन में सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2014–15 में, केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने आबंटन का केवल 41 प्रतिशत जारी किया, जो वित्त वर्ष 2016–17 में 94 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष 2017–18 में, 10 जनवरी 2018 तक, केंद्र सरकार के आबंटन का 61 प्रतिशत राज्यों को जारी कर दिया गया था। हालांकि राज्यों को जारी किए गए धन में भिन्नता पाई गई। 10 जनवरी 2018 को राजस्थान और मध्य प्रदेश को उनके कुल मिशन आबंटन का क्रमशः 84 और 80 प्रतिशत आबंटित किया गया। दूसरी ओर कर्नाटक, पंजाब और असम को 20 प्रतिशत से भी कम मिला

था। वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 10 जनवरी 2018 तक निर्माण के लिए कुल 24 प्रतिशत जारी किया गया। नवंबर 2017 तक, भारत भर में 42.72 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया था, जो संशोधित आईएचएचएल मिशन लक्ष्य के 64 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार था। दिसंबर 2017 तक, पूरे भारत में 1846 (42 प्रतिशत) शहरों को खुले स्थानों पर शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया गया था और 30 प्रतिशत को ओडीएफ के रूप में घोषित और सत्यापित किया गया था।

- स्वच्छ भारत मिशन की ग्रामीण योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना (एसएमबी–जी) "नामक बजट संक्षेप, पर निम्नलिखित पैरामीटर (1) आबंटन और व्यय; (2) शौचालयों की भौतिक प्रगति; (3) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के तहत व्यय (4) कवरेज और खुली शौचालय के साथ डेटा ट्रैकिंग पर एक संक्षिप्त विवरण। वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2018–19 में, पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (आरईएस) से 9 प्रतिशत की गिरावट के साथ एसबीएम–जी के लिए 15,343 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे, लेकिन उपलब्ध धनराशि के अनुपात के रूप में व्यय बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2015–16 में, 97 प्रतिशत फंड उपलब्ध थे। वित्त वर्ष 2016–17 में यह उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया, जिसमें उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय हुआ । वित्त वर्ष 2017–18 में, 15 जनवरी 2018 तक, उपलब्ध 80 प्रतिशत फंड खर्च किए गए थे, जिनमें से 96 प्रतिशत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए किया गया है। इस समय तक, 76 प्रतिशत परिवारों के पास आईएचएचएल तक पहुंच थी, लेकिन ओडिशा और बिहार में सबसे कम कवरेज क्रमशः 45 प्रतिशत और 38 प्रतिशत था। दस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, और 3,09,709 गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया है, और 64 प्रतिशत गांवों की ओडीएफ घोषणा की पुष्टि की गई है।

- पॉलिसी संक्षिप्त विवरण "2019 से परेः भारतीय स्वच्छता नीति में पिछले शौचालयों को देखने की जरूरत क्यों है" भारत में स्वच्छता के एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यानी स्वच्छता मूल्य श्रृंखला के सभी पहलुओं को लक्षित करना और एनयूएसपी में निर्धारित लक्ष्य प्रश्नों का पता लगाना चाहे इस के लिए खुले शौचालय पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस में उन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रमिक नीति परिवर्तनों की पहचान की जाती है, जिन से स्वच्छता–सार्वजनिक स्वास्थ्य बहस में अपशिष्ट प्रबंधन का नेतृत्व किया जाता है। भारत में अपशिष्ट जल प्रबंधन पर विभिन्न सीपीसीबी, सीपीएचईईओ और सीएसई रिपोर्टों का सार नीति निर्माताओं के सामने आने वाले संकट के आयामों की रूपरेखा बताता है और खुले शौच से पर्यावरण के स्वास्थ्य प्रभावों को बताता है। आखिरकार, यह उन कारकों का विश्लेषण करता है, खुले निर्वहन मुक्त भविष्य की योजना बनाते समय नीति निर्माता और चिकित्सक जिन पर विचार कर सकते हैं। इन कारकों को अपशिष्ट जल शोधन की मांग के तहत समूहीकृत किया गया है (क्या अपशिष्ट जल की मात्रा को बढ़ाएगा? क्या ऐसे पैटर्न हैं जो योजनाकारों का शोषण कर सकते हैं?), अपशिष्ट जल शोधन (भारत में एसटीपी कैसे बनाए जाते हैं? विभिन्न तकनीकों क्या उपलब्ध हैं? क्या ये प्रतिष्ठान वित्त पोषित हैं निजी या सार्वजनिक धन के माध्यम से? क्या हम विभिन्न उपचार मॉडल की जांच कर सकते हैं?) और जो भारत में सेप्टेज प्रबंधन के कुछ मॉडलों और सुधार के लिए अपशिष्ट जल प्रशासन की आवश्यकता को दर्शाता है।

- ''मैनुअल स्केवेंजर्स (एसआरएमएस) के पुनर्वास के लिए स्व रोजगार योजना" नामक बजट संक्षेप में एसआरएमएस की सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय (एमएसजेई) की केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में चर्चा की गई, जिसे जनवरी 2007 में पहचाने गए मैनुअल स्केवेंजर्स के पुनर्वास के लिए पेश किया गया था। वित्त वर्ष 2008–09 के अंत तक वैकल्पिक व्यवसाय, और बाद में नवंबर 2013 में इसे संशोधित किया

गया था। हालांकि पाया गया कि 2017–18 तक इस योजना के तहत आबंटन घट रहा था। वित्त वर्ष 2013–14 में, केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए '70 करोड़ आबंटित किए थे, जो वित्त वर्ष 2014–15 में' 47 करोड़ और वित्त वर्ष 2015–16 में केवल 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। वित्त वर्ष 2018–19 में, केंद्र सरकार ने एसआरएमएस को '20 करोड़ आबंटित किया। इसके अलावा, यह पाया गया कि वित्त वर्ष 2014–15 और वित्त वर्ष 2016–17 के तहत कोई व्यय नहीं हुआ था। इस योजना के तहत कवरेज मैनुअल स्वेवेंजर्स की पहचान सत्यापन पर आधारित है, लेकिन यह एक चुनौती साबित हुई है। दिसंबर 2017 तक, राज्यों द्वारा 2011 में सोशल इकोनॉमिक जाति जनगणना में पहले बताए गए मैनुअल स्वेवेंजर्स के केवल 8 प्रतिशत (13,465) की पहचान की गई थी। हालांकि इस योजना में पहचान किए गए 94 प्रतिशत लाभार्थियों को नकदी सहायता प्रदान की है, लेकिन केवल 1233 स्व–रोजगार योजनाओं को मंजूरी दी गई है और मृत्यु के मामले में केवल उन 63 प्रतिशत मामलों में पूर्ण मुआवजा प्रदान किया गया जिसमें मुआवजे के लिए दावे किए गए हैं।

2015 के लिए वियतनाम ने पिछले दो दशकों में पानी और स्वच्छता प्रावधान में महत्वपूर्ण जो कदम उठाए हैं, डब्ल्यूएचओ–यूनिसेफ उन संयुक्त निगरानी कार्यक्रमः "वियतनाम शहरी स्वच्छता अनुभव से भारत के लिए पाठ" शीर्षक (जेएमपी) के डेटा का विश्लेषण किया। इस अवधि के दौरान वियतनाम और भारत के शहरीकरण और आर्थिक विकास के संदर्भ में एक समान प्रक्षेपण के बावजूद भारत की प्रगति काफी धीमी रही। भारत में शहरी इलाकों में 13.9 प्रतिशत आबादी खुले शौचालय जाती है, जबकि वियतनाम के लिए यह संख्या 2 प्रतिशत से भी कम है। यह नीति नोट बताता है कि शहरीकरण और आर्थिक विकास पर तुलनात्मक स्तरों के बावजूद कैसे दोनों देशों के नीति दृष्टिकोण अलग–अलग हैं और भारत वियतनाम द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से क्या सीख सकता है, और इस से यह ज्ञात हो सकता है कि क्या यह इस तरह की विभिन्न शासन व्यवस्था के तहत संभव हो सकता है।

- संक्षेप में यह नीति "सीवर और सेप्टिक टैंक की मैन्युअल सफाई" सीवर और सेप्टिक टैंक की मैन्युअल सफाई के लिए कानूनी माहौल पर केंद्रित है, यह एक ऐसी प्रथा जिसके कारण कई मौतें हुईं, हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली में दिसंबर 2013 में, मैनुअल स्वेवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम ("अधिनियम") के रूप में यह रोजगार केंद्र सरकार द्वारा निषेध अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम एक संसदीय कानून है, जो सभी राज्यों पर बाध्यकारी है। 1993 के पहले कानून ने मैनुअल स्केवेंजर्स के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण पर रोक लगा दी थी, नए अधिनियम के तहत नालियों, सीवरों, शौचालयों के गड्ढे और सेप्टिक टैंकों की सफाई को निन्न स्तर के कार्य के रोपोपन में शामिल किया गया है। यह अधिनियम "खतरनाक सफाई" की एक नई अवधारणा भी पेश करता है, जो सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए लागू होता है, यह निर्दिष्ट करता है कि ये गतिविधियां केवल कुछ स्थितियों के तहत और निर्दिष्ट सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके की जा सकती हैं। पॉलिसी संक्षिप्त में अधिनियम और नियमों के विभिन्न प्रावधानों की जांच की गयी, इस कानून में परिभाषित मैनुअल स्कवेन्जिंग और खतरनाक सफाई की अवधारणा की बेहतर समझ प्रदान करने के उद्देश्य से, और निम्नलिखित प्रश्नोंः (1) क्या हैं परिस्थितियों जिसमें सीवर और सेप्टिक टैंक की मैन्युअल सफाई की अनुमति है? (2) सुरक्षित रूप से सीवर और सेप्टिक टैंक की मैन्युअल सफाई कैसे की जा रही है? (3) सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई

के दंड के परिणाम क्या हैं? (4) अधिनियम के प्रवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? को हल करने के लिए यह पॉलिसी संक्षिप्त उन पेशेवरों, विद्वानों और कार्यकर्ताओं के लिए एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में है जो मैनुअल स्केवेन्जिंग के निषेध के लिए कानून को समझना चाहते हैं।

• "स्वच्छ भारत मिशन (शहरी): नीति संक्षिप्त शीर्षक की आवश्यकता और योजना" में मिशन की वित्तीय और वास्तविक प्रगति का विश्लेषण करके भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि क्या उन राज्यों (ऐसे राज्य जहां घरों में शौचालय नहीं हैं और खुले में शौच जाने वालों का उच्च अनुपात है) में शौचालयों की आवश्यकता है केंद्रीय निधियों के आबंटन और मंजूरी के साथ–साथ घरेलू शौचालयों के निर्माण और आबंटन का मिलान किया गया । प्रत्येक राज्य में शौचालयों की आवश्यकता के साथ–साथ प्रत्येक राज्य में शौचालयों की आवश्यकता के लिए घरेलू शौचालयों के प्रक्षेपण और मंजूरी के लिए केन्द्रीय निधियों के आबंटन और मंजूरी में काफी असमानता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, जहां शौचालयों के बिना घरों का उच्चतम अनुपात है, जिन के लिए कुल केंद्रीय निधि का केवल 10 प्रतिशत आबंटित और स्वीकृत किया गया है। भले ही छत्तीसगढ़ में शौचालयों के बिना घरों का उच्चतम अनुपात है यानी 40 प्रतिशत, और आईएचएचएल निर्माण के लिए प्रक्षेपण शौचालय के बिना कुल परिवारों का 73 प्रतिशत था, लेकिन बिना शौचालय के कुल परिवारों में से केवल 23 प्रतिशत के आवेदनों को अनुमोदित किया गया । उड़ीसा और बिहार में बिना शौचालय के 33 प्रतिशत और 31 प्रतिशत परिवार हैं, और आईएचएचएल निर्माण का प्रक्षेपण शौचालय के बिना 90 प्रतिशत से अधिक घरों में था, लेकिन आवेदन पत्र 35 प्रतिशत आवेदनों को अनुमोदित किया गया । विश्लेषण में काफी डेटा असंगतताएं भी प्रकट होती हैं, और शौचालय निर्माण पर अत्यधिक जोर देती है जो अवमूल्यन को कम करने में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को कम करती है, जो शौचालय के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करेगी।

• "ओडिशा में स्कूल स्वच्छता" नामक नीति संक्षिप्त शब्द स्कूल जाने वाले बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों के बीच स्वच्छता तक पहुंच को समझने के लिए तैयार किया गया था। स्कूलों में बच्चों विशेष रूप से के लड़कियों को स्वच्छता की जानकारी कराना महत्वपूर्ण है। सुरक्षित स्वच्छता की संस्कृति को व्यापक रूप से युवाओं के बीच फैलाना भी महत्वपूर्ण है। स्कूलों और गांव की सुविधाओं पर पीसीए डेटा पर डीआईएसई डेटा के अनूठे मैपिंग का उपयोग करते हुए, यह नोट ओडिशा के विभिन्न सीडी ब्लॉक में स्थान और लिंग और विद्यालयों में स्वच्छता तक पहुंच के बीच संबंध और स्वच्छता तक पहुंच के बीच संबंधों में स्कूल स्वच्छता में भिन्नता को दर्शाता है। यह स्कूल स्वच्छता के लिए विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काफी भिन्नता दर्शाता है, जिसके लिए आगे बढ़ने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि, ओडिशा राज्य में विद्यालय स्वच्छता तक पहुंच से ब्लॉक में स्वच्छता से बेहतर है।

- "सामाजिक पहचान और व्यावसायिक भेदभाव के सामाजिक भेदभाव : वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य से एक साहित्य समीक्षा" शीर्षक नीति नीति का शीर्षक सामाजिक पहचान पर स्वच्छता व्यवसाय से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। सबूत बताते हैं कि कुछ सामाजिक समूह इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। न केवल भारत में जहां जाति एक प्रमुख भूमिका निभाती है, लेकिन अन्य देशों में भी, यह व्यवसाय स्वच्छता कार्य से जुड़े हाशिए वाले समुदायों के साक्ष्य दर्शाता है। यह पत्र अंतरराष्ट्रीय और भारतीय साहित्य का एक स्वच्छता कार्य से संबंधित दस्तावेज है जिसमें सामाजिक पहचान, कार्य परिस्थितियों और ऐतिहासिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य

दोनों से स्वच्छता श्रमिकों के सामाजिक भेदभाव पर चर्चा की गई है। यह कचरा संग्रह, सफाई, सीवर की सफाई और सेप्टिक टैंक खाली करने जैसे व्यवसायों पर केंद्रित है, जिसे अन्यथा ग्रे और प्रकाशित साहित्य में मैन्युअल स्कैनिंग के रूप में ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है।

3. नीचे सूचीबद्ध सामयिक विषयों पर लोगों की राय के हिस्से तैयार किए गए थे :

• दिल्ली में सेप्टिक टैंक एम्प्टीयर पर हाल ही में पूरे किए गए काम के आधार पर ''मशीनीकरण डी-स्टिग्मैटाइज स्वच्छता कार्य'' नामक राय का टुकड़ा, पूरी तरह से मैन्युअल प्रक्रिया से, सेप्टिक टैंक खाली करने की काम की उस बदलती प्रकृति का पता लगाता है जिसमें फिकल कीचड़ विसर्जन में कार्यकर्ता शामिल है आंशिक रूप से मशीनीकृत के लिए, यद्यपि कम लागत वाले स्थानीय रूप से एकत्रित उपकरण शामिल हैं। हालांकि, इस में शामिल कार्यबल लगभग पूरी तरह से दलित हैं, और श्रमिकों को अपने ग्राहकों और उनके सोशल नेटवर्क के साथ उनकी बातचीत में अस्पृश्यता के भेदभाव और प्रथाओं का सामना करना पड़ता है। नीति निर्माता हालांकि सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, और जाति आधारित भेदभाव के मुद्दों पर कम ध्यान देते हैं। प्रकाशित करने के लिए नीति संक्षिप्त।

• 4 अगस्त, 2017 को हिंदुस्तान टाइम्स में ''स्वच्छ भारत के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस'' नामक ओपिनियन पीस प्रकाशित किया गया था। यह लेख ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर केंद्रित है। प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से अस्वच्छता में कमी आएगी। इस से शौचालय के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन आवश्यक होगा।

• स्वच्छता श्रमिकों की मौत के बाद ही सरकार को उनकी याद क्यों आती है ओपिनियन पीस शीर्षक ''18 मई, 2017 को डेलीओ में प्रकाशित किया गया था। यह लेख में दिल्ली में सीवर श्रमिकों की मौत पर प्रश्न उठाता है और स्वच्छता श्रमिकों की मौत के बाद ही सरकार को उनकी याद क्यों आती है। जाति परिप्रेक्ष्य द्वारा हाल की मौत का विश्लेषण करते हुए लेख का तर्क है कि राज्य को पहले अपने संस्थानों में स्वच्छता कार्य छेड़छाड़ के जातिविज्ञानीकरण की निंदा करके सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करना होगा।

• ''सीवर वर्कर्स डेथ्स: ओपिन पीस शीर्षक में ठेकेदार दोषी ठहराने के बजाय, डीजेबी अधिकारियों की भूमिका की जांच ''11 अगस्त, 2017 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित किया गया जिस में मानक–कम सार्वजनिक इंजीनियरिंग को मौत के कारण के रूप में हाइलाइट किया गया । यह लेख सीवेज श्रमिक उन सुरक्षा उपकरणों और बेहतर प्रशिक्षण के बारे में भी बात करता है जो जिन से जोखिम को काम किया जा सकता है, लेकिन नौकरी की प्रकृति ऐसी है कि किसी को अपनी सांस रोकनी पड़ेगी और सीवेज पानी में तैरना होगा, किस प्रकार का प्रशिक्षण और ''सुरक्षा उपकरण'' इस के लिए तैयार किए जा सकते हैं? इसका बुनियादी ढांचा सुरक्षित रूप से बनाया और प्रबंधित किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए भले सार्वजनिक प्राधिकरण ही सीवेज श्रमिकों से काम लेने की जिम्मेदारी ले।

4. हमने नीचे सूचीबद्ध अनुसार विभिन्न सरकारी निकायों/समर्थन समूह के साथ बैठकें कीं :

4.1 राष्ट्रीय स्तर के सरकारी अधिकारियों/मंत्रालयों और अन्य सरकारी निकायों के साथ बैठकें और प्रस्तुतियां।

- ग्रामीण क्षेत्रों में एफएसएम पर भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ सहयोग (18 दिसंबर, 2017, 22 जनवरी और 8 फरवरी 2018)। संयुक्त सचिव, एमओडीडब्ल्यूएस ने 18 दिसंबर, 2017 को ग्रामीण क्षेत्रों में मल के कचरे और सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए एनएफएसएसएम गठबंधन के सदस्यों की एक बैठक बुलाई। मंत्रालय ने अगले महीने में इस विषय पर राज्यों के साथ चर्चा के लिए एक ढांचा तैयार करने की मांग की, जिसके लिए वह उपस्थित सदस्यों से इनपुट मांग रहा था। सीपीआर ने सेप्टिक टैंक खाली करने सेवाओं पर औरअधिक घनीआवादी वाले गांवों में स्वच्छता प्राथमिकताओं के लक्षण और विश्लेषण पर एससीआई एफआई कार्यक्रम में चल रहे शोध के बारे में मंत्रालय को अवगत कराया । अन्य एनएफएसएसएम गठबंधन सदस्यों ने प्रौद्योगिकी विकल्प और सेवा प्रदाताओं के विभिन्न पहलुओं पर इनपुट प्रदान किया। 22 जनवरी, 2018 को बैठकें हुईं जब गठबंधन के सदस्यों ने राज्यों के साथ प्रस्तावित चर्चा के लिए मंत्रालय की योजना में इनपुट प्रदान किया। इसके बाद कानूनी और नीतिगत मुद्दों पर तकनीकी नोट तैयार करने के बाद मंत्रालय को अपनी योजना में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया गया। एफएसएसएम पर गोलमेज में सीपीआर भागीदारी और 8–9 फरवरी, 2018 को एमओडीडब्लूएस द्वारा आयोजित ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन के राष्ट्रीय परामर्श में कानूनी और नीतिगत मुद्दों पर एक प्रस्तुति दी।

- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (3 नवंबर, 2017 और 8 दिसंबर, 2017) द्वारा गठित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 76 वें दौर के लिए कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित की गयी । राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) ने 29 मई, 2017 को अपनी 94 वीं बैठक आयोजित की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 76 वें दौर का विषय विकलांगता, पेयजल, स्वच्छता, स्वच्छता और आवास की स्थिति पर केंद्रित होगा। एनएससी ने नमूना डिजाइन, पद्धति इत्यादि की सहायता के लिए एक कार्यकारी समूह गठित किया, सीपीआर के डॉ पार्थ मुखोपाध्याय ने इस की अध्यक्षता की। कार्यकारी समूह ने नई दिल्ली (3 नवंबर, 2017) और कोलकाता (8 दिसंबर, 2017) में अब तक दो बैठकें की हैं:

4.2 राज्य सरकारों की बैठकें और प्रस्तुतियां :

सीईओ, जिला परिषद्, उदयपुर (18 अक्टूबर, 2017) के साथ बैठक। सीपीआर ने उदयपुर जिले में एक सर्वेक्षण किया है और उदयपुर जिले में एसबीएम की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सीईओ जिला परिषद के साथ एक बैठक की सीईओ, जिला परिषद् के साथ यह दूसरी बैठक थी। बैठक में सर्वेक्षण निष्कर्षों और जिले में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- प्रधान सचिव, आवास और शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार (20 सितंबर, 2017) के साथ बैठक। राज्य में एफएसएम के कानूनी विनियमन की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव, आवास और शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार और परियोजना निदेशक, ओडिशा

- जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के साथ बैठक कर उन संभावित उपायों पर चर्चा की सरकारी आदेश या नगर निगम के नियम में शामिल किया जा सकता है ।

- करनाल नगर आयुक्त के साथ बैठक (15 सितंबर, 2017)। करनाल नगर आयुक्त के साथ बैठक जिला स्तर पर विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में एसबीएम के कार्यान्वयन को समझने के लिए विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ आयोजित चर्चा की श्रृंखला का हिस्सा थी। बैठक स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में जिले के आईईसी दृष्टिकोण और ओडीएफ की स्थिति को समझने पर ध्यान केंद्रित किया।

- करनाल डीएम के साथ बैठक (23 अगस्त, 2017)। करनाल जिले के ग्रामीण हिस्से में स्वच्छ भारत मिशन के दृष्टिकोणों पर चर्चा करने के लिए करनाल डीएम के साथ बैठक आयोजित की गई। मिशन के कार्यान्वयन में आईईसी की समझ और जिले में खुले में शौचालय मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति पर भी चर्चा हुई।

- प्रधान सचिव, आवास और शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार, बालासोर नगर पालिका के विविध अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी के साथ बैठक (19 – 20 अगस्त, 2017)। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने, शहर के स्तर पर सामना करने वाली क्षमता के मुद्दों और इसका समाधान करने की कार्यनीतियों की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए यह बैठक आयोजित की गयी थी । सीपीआर द्वारा क्षमता निर्माण मॉड्यूल तैयार करने और इसे लागू करने की योजना पर भी चर्चा की गई।

- राजिंदर पाल गौतम, जल मंत्री, दिल्ली सरकार के साथ बैठक (19 अगस्त, 2017)। राष्ट्रीय राजधानी में मैनुअल स्केवेन्जिंग और मैनुअल स्केवेन्जिंग से संबंधित मौतों पर एक सीपीआर ओप–एड के बाद, दिल्ली सरकार के जल मंत्री श्री राजिंदर पाल गौतम के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीपीआर को बुलाया गया था। बैठक के दौरान विभाग के अधिकारी और सलाहकार भी उपस्थित थे। दिल्ली में सीवर श्रमिकों के मैनुअल स्केवेन्जिंग और मौत के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। बैठक के दौरान सीवर युक्त और सीवर रहित क्षेत्रों में सीवर श्रमिकों द्वारा मैनुअल स्केवेन्जिंग और डी–स्लजिंग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। औपचारिक डी–स्लजिंग सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए डी–स्लजिंग वाहनों को लाइसेंस देने और विनियमित करने की आवश्यकता को सीवर श्रमिकों की कामकाजी स्थिति में सुधार के लिए सिफारिश के रूप में प्रस्तुत किया गया । एससीआई एफआई टीम ने इस मुद्दे के अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और डकर और मलेशिया से प्रकरण अध्ययनों पर भी चर्चा की जो दिल्ली के लिए एक सबक हो सकता है।

- उड़ीसा सरकार के लिए तकनीकी नोट : ओयूएसपी और ओयूएसएस (25 सितंबर, 2017) के तहत शेयरधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। राज्य सरकार के अनुरोधों पर ओयूएसएस और ओयूएसपी को शहरों और अन्य हितधारकों को प्रसारित करने के अनुरोध पर, एक तकनीकी नोट स्पष्ट रूप से राज्य सरकार, जिला प्राधिकरणों और यूएलबी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने के लिए तैयार किया गया था। नोट में ओयूएसएस और ओयूएसपी के तहत स्थापित मुख्य 6 परिणामों के तहत एफएसएम और स्वच्छता में शामिल प्रत्येक पणधारक की प्रमुख जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला गया ।

ओडिशा की भागीदारी की प्रस्तुति : पैमाने पर प्रभाव हासिल करने के लिए सरकार के साथ साझेदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार के साथ काम करना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन, अलग-अलग मंत्रालयों में सिविल सोसाइटी और सरकारी संस्थानों के बीच सफल सहयोग रहे हैं। यह प्रस्तुति 20 फरवरी को दशरा सहयोगी एक्शन फोरम की पृष्ठभूमि थी जहां सीपीआर ने ''नीतिगत साझेदारी : सरकार के साथ काम करने'' पर सत्र में पैनलिस्ट के रूप में सरकारी नीति और कार्यक्रमों में एफएसएम को शामिल करने में ओडिशा सरकार के साथ सफल साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों को प्रस्तुत किया।

- सीडीडी सोसाइटी द्वारा बेंगलुरु में 19 जनवरी, 2018 को आयोजित सतत जल और स्वच्छता पर तीसरे राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में साझेदारी के माध्यम से एफएसएम को स्केल करने पर ओडिशा का मामला प्रस्तुत किया। प्रस्तुति ने एफएसएम की यात्रा पर प्रकाश डाला और ओडिशा राज्य में सीपीआर, पीए, सीडीडी, अरघम, बीएमजीएफ, टीएसयू, आईटी सरकारों और राज्य सरकार जैसे विभिन्न पणधारकों की सफल भागीदारी के माध्यम से एफएसएम हस्तक्षेपों को प्रभावी बनाया।

4.3 सलाहकार समूहों के साथ बैठकें

4.3.1 एससीआई – एफआई की शोधकर्ताओं और चिकित्सकों (सीओआरपी) संगोष्ठी श्रृंखला का समुदाय : स्वच्छता परियोजना क्षेत्र में साक्ष्य आधारित ज्ञान को बढ़ावा देने से शहरी स्वच्छता में चुनौतियों और अवसरों की समझ को मजबूत करना चाहता है। इस वर्ष, निम्नलिखित चार संगोष्ठी आयोजित की गई :

- सेप्टिक टैंक खाली करने की सेवाओं के अनौपचारिक मॉडल को समझना: भारत के चार शहरों से प्रकरण अध्ययन (6 अप्रैल, 2018)। छोटे पैमाने पर अनौपचारिक उद्यमों जो वर्तमान में भारतीय शहरों में सेप्टिक टैंक खाली सेवाओं को प्रदान करती हैं उन के मुद्दों और चुनौतियों पर सीपीआर अनुसंधान के आधार पर तीन प्रस्तुतियां दी गईं । सीपीआर अनुसंधान ने देहरादून, जयपुर और भुवनेश्वर में केस स्टडीज की और दिल्ली के दो स्थानों में इन उद्यमों की हमारी समझ को बेहतर बनाने की मांग की। स्वच्छता मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावना पर कई हितधारकों के साथ इस शोध पर व्यापक चर्चा हुई। 1. सामूहिक कार्रवाई (या नहीं) : दिल्ली में सेप्टिक टैंक खाली करने का अनौपचारिक बाजार; 2. तीन शहरों से एफएसएम ऑपरेशन प्रकरण अध्ययन : निष्कर्ष और अंतर्दृष्टि; 3. छोटे पैमाने पर डिस्लागिंग संचालन को समझना: संश्लेषण और अन्य समाधानों को इन प्रस्तुतियों में शामिल किया गया था।

- अंतिम 100 मीटर : 27 अक्टूबर, 2017 शहरी अनौपचारिक निपटान के लिए पीने योग्य जल प्रावधान की सुरक्षा। ब्रिटेन के लंकास्टर विश्वविद्यालय से डॉ मनोज रॉय ने ''पिछले 100 मीटर पर चल रहे सहयोगी शोध के उभरते निष्कर्षों का परिचय : लंकास्टर विश्वविद्यालय और विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के बीच शहरी अनौपचारिक बस्तियों के लिए पीने योग्य जल प्रावधान की सुरक्षा अपनी प्रस्तुति दी। स्थायी विकास के लिए शहरी, राष्ट्रीय और तेजी से वैश्विक वास्तुकला सार्वजनिक स्वास्थ्य के गंभीर परिणामों के साथ 'फिनिश लाइन' से पहले मीटर कम हो रही है। डॉ रॉय ने ढाका में गरीब बस्तियों में चल रहे शोध से निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जिसमें इन बस्तियों में एफएसएम और नेटवर्क निपटान प्रणाली की कमी से पीने योग्य पानी के प्रदूषण के खतरे का पता चलता है ।
- सफाई ब्रिगेड : कनेक्ट और डिस्कनेक्ट (20 सितंबर, 2017)। नई दिल्ली के भारतीय दलित अध्ययन संस्थान के निदेशक डॉ संघमित्र आचार्य ने स्वच्छता कार्य की विशेषता पर अपने हाल के काम की बात की और दिल्ली और अहमदाबाद में किए गए शोध और क्षेत्रीय कार्य के आधार पर इस काम की अंतर्निहित रूप से भेदभावपूर्ण प्रकृति पर

इस बात की चर्चा की कि किस प्रकार से यह इस क्षेत्र में लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। उनके काम में सफाई और सफाई में शामिल होने के निर्धारकों की खोज; इसके साथ जुडी गरिमा की धारणा; और वे कारक जो इन कार्यों में अपनी निरंतरता को नियंत्रित करते हैं और वैकल्पिक विकल्प क्या उपलब्ध है उनका पता लगाया गया। उन्होंने साक्षरता, कौशल, स्वास्थ्य, बुनियादी आवास और संबंधित बुनियादी संरचना को बढ़ाने के लिए संसाधनों तक पहुंचने में सफाई और सफाई में लगे दलितों द्वारा अनुभवी सामाजिक भेदभाव और उनके निष्कर्षों पर भी प्रकाश डाला।

- राज्य के उत्पादन और घरेलू मांग के बीच: स्वच्छता का आर्थिक निर्धारण (19 मई, 2017)। सीपीआर ने भारत में स्वच्छता नीतियों के संदर्भ में स्वच्छता पर अपने काम को ''आर्थिक रूप से अच्छा'' के रूप में पेश करने के लिए फ्रांस में इकोले नॉर्मेल सुपरीएर डी ल्यों में अर्थशास्त्र में पीएचडी विद्वान क्लोलेक्लेयर को आमंत्रित किया। इस चर्चा

- में स्वच्छता की आवश्यकता से संबंधित उन प्रश्नों का पता लगाया, जिस से यह उत्पन्न होती है और जैविक अनिवार्य और पर्यावरण से संबंधित प्रक्रिया बहु आयामी प्रक्रिया है।

4.3.2 स्थायी स्वच्छता पर राष्ट्रीय सम्मेलन : 12, दिसंबर, 2017 को स्वच्छता क्षेत्र में काम कर रहे नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के साथ जुड़ने के लिए साक्ष्य और अभ्यास, शीर्षक से नई दिल्ली में एक सम्मलेन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि स्वच्छ भारत मिशन और फोकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय नीति द्वारा अनुमोदित टिकाऊ स्वच्छता पर उभरती नीतिगत फोकस था । सम्मेलन का उद्देश्य प्रतिभागियों के विभिन्न अनुभवों और अवलोकनों को संश्लेषित करना था ताकि वर्तमान नीति, कार्यान्वयन और निगरानी संरचना में चुनौतियों की समझ पैदा हो सके और स्थायी स्वच्छता के लिए सामुदायिक केंद्रित दृष्टिकोणों के प्रति तैयार पाठ साझा किया जा सके। वाटरएड इंडिया, राइस इंस्टीट्यूट (रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपेसिनेट फॉर इकोनॉमिक्स) और सीपीआर ने एसबीएम जी के कार्यान्वयन पर अपना हाल का शोध प्रस्तुत किया, जिसके बाद शोधकर्ताओं द्वारा उठाए गए विषयों और मुद्दों पर एक पैनल चर्चा हुई। इसके बाद शहरी स्वच्छता सत्र में शहरी स्वच्छता पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए: विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर सीएफएआर के सामुदायिक भागीदारी कार्यों की समीक्षा प्रस्तुत किया; सीपीआर ने ओडिशा के छोटे शहरों में गरीब समुदायों के साथ किए गए नृवंशविज्ञान कार्यों से स्वच्छता पर निष्कर्ष और अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की; पीआरआईए ने उत्तर प्रदेश में एसबीएम शहरी कार्यान्वयन पर अपना हाल का काम प्रस्तुत किया; और आखिरकार इन सभी अलग–अलग विषयों को शहरी स्वच्छता पर एक सीपीआर प्रस्तुति में एक साथ लाया गया।

4.3.3 स्वच्छता के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर कार्यशाला: कार्यान्वयन का अनुभव, 11 दिसंबर, 2017 को, नई दिल्ली, में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एसबीएम लागू करने के अपने अनुभव से सीखने पर राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ एक दिन लंबी क्षमता निर्माण और अनुभव साझा करने की कार्यशाला आयोजित की गयी। यह कार्यशाला विशेष रूप से वर्तमान दृष्टिकोण की स्थिरता की चुनौतियों और हाशिए के लोगों और कमजोर समुदायों पर इसके प्रभाव पर केंद्रित थी। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को लागू करने के तरीके और अनियंत्रित कार्यान्वयन समय–सारिणी के संदर्भ में सतत स्वच्छता प्राप्त करने की विशेष चुनौतियों के बारे में गहन और बेहतर जानकारी साझा की। प्रतिभागियों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता और विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में नीति की कमी की बात की। शहरी क्षेत्रों के प्रतिभागियों को मैनुअल स्केवेन्जिंग प्रथाओं के बारे में अधिक जानकारी थी, लेकिन कहा कि यह उनके वर्तमान कार्यान्वयन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को प्रतिबिंब और आत्म–शिक्षण का अवसर प्रदान किया।

4.3.4 जल अधिकार और स्वच्छता के मानव अधिकार पर विशेष संवाददाता के साथ बैठक (28 और 29 अक्टूबर)। भारत दौरे और सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ संबंधों के हिस्से के रूप में मानव अधिकार और जल स्वच्छता के मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र विशेष संवाददाता के साथ मैनुअल स्कैवेंजिंग पर 28 अक्टूबर, 2017 को सीपीआर को एक विशेष बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। एसकेए द्वारा बैठक में अध्यक्षता की गई, जिन्होंने यूएन स्पेशल रिपोर्टर के लिए मैनुअल पर डेटा और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। सीपीआर ने गैर–नेटवर्क स्वच्छता के संबंध में मैनुअल स्केवेन्जिंग और असुरक्षित स्वच्छता कार्य के मुद्दे पर चर्चा की और यह बताया कि एफएसएम हस्तक्षेप के माध्यम से इसका समाधान कैसे किया जा सकता है । 29 अक्टूबर, 2017 को स्वच्छता में जाति और लिंग आधारित भेदभाव पर नागरिक समाज संगठनों के साथ संयुक्त राष्ट्र विशेष संवाददाता की एक बैठक में भाग लेने के लिए सीपीआर को भी आमंत्रित किया गया था। अन्य संगठनों वाटरएड, सीएफएआर, सी यूआर ई, वीएसओ, वाडा ना टोडो और राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार आयोग और जगोरी ने भी इस में भाग लिया।

5. अन्य सलाहकार बैठकें :

गैर सरकारी संगठनों, मीडिया और व्यावसायिक नेटवर्क के साथ अन्य बैठकों के कुछ विवरण शामिल है :

- उदयपुर सर्वेक्षण से निष्कर्षों को साझा करने के लिए नई दिल्ली में 24 नवंबर 2017 को वॉटरएड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी के माधवन के साथ बैठक आयोजित की गई। चर्चा उन मुद्दों के आसपास भी थी जो अनुसंधान के हिस्सों में आम तौर पर उभरे हैं और उन्हें पद देने के तरीके हैं।

- प्रतिभागियों के रूप में वॉटरएड के साथ ''शौचालय महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं'' पर पैनल चर्चा 24 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर साझा किया गया था। सभी के किए शौचालय वॉटरएड कार्यालय में ट्विटर, फेसबुक पर टॉयलेट 4 ऑल हैशटैग लाइव था।

- नई दिल्ली में 24 नवंबर 2017 को आयोजित एनडीटीवी पैनल चर्चा, वर्तमान स्थिति और स्वच्छता की चुनौतियों पर केंद्रित थी। पैनल ने उदयपुर जिले में सीपीआर के हाल ही में हुए सर्वेक्षण से निष्कर्षों पर भी चर्चा की।

- कार्यशाला सुरक्षा में सुधार करने के लिए सामूहिक रूप से विचार करने, मूल्यांकन करने और प्राथमिक समाधान देने और स्वच्छता श्रमिकों के लिए मजबूत आजीविका मार्ग बनाने हेतु विभिन्न पणधारकों जैसे दलबर्ग, बीएमजीएफ, शहरी प्रबंधन केंद्र (यूएमसी) और अन्य बीएमजीएफ भागीदारों को एक साथ लाया गया। इसे 20 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

- सीपीआर ने 17 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में ''स्वच्छता नीति निर्धारित करने में साक्ष्य की भूमिका'' पर आयोजित पैनल चर्चा में भाग लिया। यह स्वच्छता नीतियों को बनाने में साक्ष्य की भूमिका पर केंद्रित था।

- यूनिसेफ, राजस्थान वॉश और सी4डी टीम को प्रतिभागियों के रूप में राजस्थान में प्रशिक्षण दृष्टिकोण को समझने के लिए नई दिल्ली में 12 अक्टूबर, 2017 को बैठक आयोजित की गई। राजस्थान में यूनिसेफ प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रणाली की भागीदारी और समझने में शामिल रहा।

- दिल्ली – केंद्रित हितों के साथ स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर एक दूसरे को सूचित करने और संलग्न करने के लिए वॉटरएड, सीएसई, सीयूआरई के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। स्वच्छता और एफएसएम से संबंधित गतिविधियों और योजनाओं और संगठनों के बीच निकट समन्वय सक्षम करने पर चर्चा। यह 22 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

- टीम सार्वजनिक रूप से नई दिल्ली में 17 अगस्त, 2017 को सीवर की सफाई करते समय सीवर श्रमिकों की लगातार मौत पर चर्चा करने के लिए सीवरेज और सहयोगी श्रमिकों के लिए विनम्रता और अधिकारों हेतु राष्ट्रीय अभियान में भाग लेने हेतु संलग्न हुई। एससीआई – एफआई टीम ने कार्य परिस्थितियों पर चर्चा करने और श्रमिकों की परिस्थितियों में सुधार के लिए तथा आगे का मार्ग तय करने हेतु बैठक में भाग लिया।

- एसबीएम जी कार्यान्वयन पर 7 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में प्रतिभागी के रूप में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ एक गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां एसबीएम जी में सफलताओं और अंतराल पर विभिन्न विचारों पर चर्चा की गई थी।

- श्रीमती मीइक वैन गिनेकेन के साथ बैठक – दक्षिण एशिया अभ्यास प्रबंधक दक्षिण एशिया, जल वैश्विक अभ्यास, विश्व बैंक 30 जून, 2017 को नई दिल्ली में एसबीएम जी के कार्यान्वयन में प्रगति, मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था।

- सीपीआर ने 4 मई 2017 को नई दिल्ली में आदर्श बस्ती में स्वच्छता पर सामुदायिक स्कोर कार्ड को प्रशासित करने के लिए जूरी सदस्य के रूप में भाग लिया।

6. सफाई कर्मचारी अंदोलन के साथ सहयोग (एसकेए)

एसकेए ने सार्वजनिक निषेध मुकदमा दायर किया था (2003 में फैसला किया गया है कि सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डब्लूआरआईटी पिटिशन (सीआईवीआईएल) 2014 में फैसला किया गया था) मैनुअल स्केवेन्जिंग को पूरी तरह से निषेध और खत्म करने के लिए उच्चतम न्यायालय से दिशानिर्देश मांगे गए थे। मामले के दस्तावेज जिसमें दशकों तक लंबी अवधि में विभिन्न पार्टियों द्वारा दायर कई सौ दस्तावेज शामिल थे, जिसमें मामला अदालत में रहा, एसकेए ने सीपीआर से समर्थन जुटाने के लिए कहा। दस्तावेजों में विभिन्न राज्य सरकारों, स्थानीय अधिकारियों और अन्य राष्ट्रीय और राज्य सरकार निकायों के बयान शामिल हैं जिनमें भविष्य की कार्रवाई करने के लिए स्टेटस रिपोर्ट और वचनबद्धताएं शामिल हैं, जिनका कार्यकर्ताओं और क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों द्वारा किया उपयोग किया जा सकता है। इन चर्चाओं के बाद, सीपीआर ने एसकेए और सार्वजनिक प्रसार के लिए इन दस्तावेजों का एक एनोटेटेड डेटाबेस बनाया।

इसके अलावा, वर्ष में आयोजित कई बैठकों के दौरान, सीपीआर और एसकेए ने आपसी रुचि के विषयों पर अनुसंधान सहयोग की योजना विकसित की। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता और एफएसएम नीति वार्ता में शामिल होने के

लिए एसकेए क्षमता विकसित करना और मैनुअल सफाई को खत्म करने की चुनौती यह है कि हमारी साझा समझ को तेज करना है। बैठकों के विवरण हैं :

- बैठक स्वच्छता कार्य से संबंधित साझा अनुसंधान रुचियों और दोनों संस्थानों के बीच घनिष्ठ समन्वय की व्यवस्था के बारे में चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में 24 नवंबर 2017 को आयोजित की गई थी।

- दिल्ली में 12 सितंबर, 2017 को लिखित याचिका डेटाबेस पर कार्य के संबंध में समन्वय बैठक

- दिल्ली में 7 अगस्त, 2017 को आयोजित बैठक में आपसी सहयोग के लिए साझा नीति लक्ष्यों और अनुसंधान रुचियों पर चर्चा की गई।

- दिल्ली में 2 अगस्त, 2017 को शुरू हुई लिखित याचिका के डेटाबेस का मार्गदर्शन।

- दिल्ली में 31 जुलाई, 2017 को लिखित याचिका से संबंधित दस्तावेजों के डेटाबेस के विकास में एसकेए का समर्थन करने के लिए सीपीआर हेतु साझा निर्णय।

7. अध्ययन दौरे के कार्यक्रम

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक निम्नलिखित चार क्षेत्रीय निरीक्षणों का आयोजन किया गया था :

- आंध्र प्रदेश में वारंगल, नरसापुर और विशाखापत्तनम की अध्ययन यात्रा : फीकल स्लज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज एंड सर्विस डिलिवरी मॉडल (21 – 25 मार्च, 2018)। वारंगल और नरसापुर के शहरों में विकसित एफएसटीपी मल के कचरे के शोधन के लिए पायरोलिसिस / ताप आधारित तकनीक का उपयोग करते हैं। यह तकनीक अधिक पारंपरिक एनारोबिक धारित शोधन का विकल्प प्रदान करती है। इस नवीन, ताप आधारित एफएसटीपी की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझने के लिए, एससीआई

- एफआई के शोधकर्ताओं की एक टीम ने आंध्र प्रदेश के वारंगल, तेलंगानांद नरसापुर, का अधययन दौरा किया जहां आंध्र प्रदेश ने हाल ही में स्थापित एफएसटीपी को कुछ महीनों में पहले ही आरम्भ किया है। संयंत्रों की प्रक्रियाओं के बारे में सीखने के अलावा, टीम ने दो शहरों में विलुप्त हो रही ऑन साइट स्वच्छता प्रणाली के लिए सेवा वितरण मॉडल में भी पहुंचाया। इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम शहर का दौरा किया, स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में विशाखापत्तनम शहर तीसरे स्थान पर रहा; उस सह उपचार प्रक्रिया को समझा गया, अपने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहर जिस पर निभर है। इसलिए अध्ययन के निष्कर्ष इस विषय पर मौजूदा ज्ञान को बढ़ाएंगे और इसका उपयोग राज्य और यूएलबी स्तर पर एफएसएम प्रौद्योगिकियों और सेवा प्रदाता मॉडल ज्ञान को और भी बनाने के लिए किया जाएगा।

- पांडिचेरी में सोशल साइंसेज शीतकालीन स्कूल, पुडुचेरी (4–8 दिसंबर, 2017)। सीपीआर ने पांडिचेरी विश्वविद्यालय और पांडिचेरी में फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट शीतकालीन स्कूल का समर्थन करने के लिए पांडिचेरी के फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग किया, जिसमें शहरी स्वच्छता एक फोकस का क्षेत्र था। शीतकालीन विद्यालय का उद्देश्य डॉक्टरेट के उन छात्रों को उन्मुख बनाना और सलाह देना था जिन्होंने शहरी स्वच्छता पर अपने शोध पर ध्यान केंद्रित किया था। इस शीतकालीन

विद्यालय में प्रस्तुत सीपीआर शोध में ''नदी प्रदूषण परिप्रेक्ष्य से शहरी स्वच्छता'' पर एक पूर्ण चर्चा शामिल थी जिसमें दिल्ली / यमुना प्रदूषण का मामला प्रस्तुत किया गया था। सीपीआर ने स्वच्छता, मैनुअल स्केवेन्जिंग के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर शोध प्रस्तुत किया और सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं के लिए स्वच्छता इंजीनियरिंग को समझने पर एक व्याख्यान दिया । कार्यशाला में प्रस्तुत अन्य शोध में गैर–नेटवर्क स्वच्छता ('नेटवर्क से परे') के सिद्धांत और अभ्यास पर व्याख्यान और शहरी स्वच्छता पर शोध के लिए मानचित्रण और बड़े डेटा का उपयोग शामिल था।

- हनोई, वियतनाम की अध्ययन यात्रा : केन्द्रीय नियोजन पर्यावरण में विषम स्वच्छता टाइपोग्राफी (20–23 नवंबर, 2017)। भारत की तरह, वियतनाम की सामाजिक–आर्थिक नीति एक उच्च केंद्रीकृत नियोजन ढांचे के भीतर निहित है, जो योजना और निवेश मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के साथ संयोजन और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पांच साल की सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं द्वारा निर्देशित है। स्वच्छता और अपशिष्ट से संबंधित कानून आम तौर पर केंद्रीय स्तर पर जारी किया जाता है, जिसका लक्ष्य विविध शहरी वातावरण में समान आधारभूत संरचना समाधान बनाना है। शहर के स्तर पर, और विशेष रूप से राजधानी शहर के रूप में हनोई के मामले में, इन केंद्रीकृत योजना संरचनाओं और बुनियादी ढांचे को हनोई शहरी पर्यावरण कंपनी जैसी एजेंसियों द्वारा दोहराया जाता है। हालांकि, ये केंद्रीकृत दृष्टिकोण हनोई में प्रदर्शित स्वच्छता टाइपोग्राफी की बहुतायत को अनदेखा करते हैं, ये प्रत्येक शहर में आवास विकास के विशिष्ट रूपों से जुड़ा हुआ है। ये आवास टाइपिंग नए शहरी क्षेत्रों में पूरी तरह से योजनाबद्ध और सीवर–नेटवर्क वाले क्षेत्रों से सार्वजनिक शौचालयों तक और लांग बिएन ब्रिज के पास किराये और अनौपचारिक आवास में खुली शौचालय विधियों से सम्बद्ध है । इस अध्ययन दौरे पर, सीपीआर शोधकर्ताओं ने इस ''दो – ट्रैक'' वास्तविकता का पता लगाया, एक ओर, नीति और विधायी संरचना को स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को नियंत्रित करने और दूसरी ओर पांच अलग अलग स्वच्छता टाइपोग्राफी में समूहित आठ अलग अलग साइटों का दौरा किया।

- देवनहल्ली, कर्नाटक के सचिव की एक्सपोजर विज़िट : देवनहल्ली के टाउन नगर निगम (टीएमसी) के समन्वय में, सीडीडी सोसायटी ने 2015 के दौरान एक फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) बनाया है। यह संयंत्र भारत में अपनी तरह का पहला संयंत्र जो समग्र और पूरे शहर के लिए एकीकृत मल के कचरे क़े शोधन सुविधा उपलब्ध करता है। सीडीडी ओडीशा में यह परियोजना निर्मल शहरों का समर्थन भी कर रही है ताकि एफएसटीपी का निर्माण किया

- जा सके। एफएसटीपी के संचालन और रखरखाव की पूरी समझ और एफएसटीपी की परिचालन लागत को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने, सीडीडी सोसाइटी और अर्घ्यम के समर्थन से नीति अनुसंधान केंद्र के लिए केंद्र स्थापित करने हेतु ओडीशा सरकार के सचिव, एचयूडीडी ने मल के लिए 28 सितंबर, 2017 को देवनहल्ली में स्थित स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) की एक एक्सपोजर विज़िट की। ओ एंड एम के अलावा, सह–कंपोस्टिंग, राजस्व मॉडल और एफएसएम में मैनुअल स्केवेन्जिंग प्रथाओं को हटाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

8. अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों में नीतिगत संक्षिप्त विवरण, श्वेत पत्र और अन्य दस्तावेज विकसित और साझा किए गए।

- अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला : एशिया में शहरी घनत्व के उभरते रूपों पर साझा परिप्रेक्ष्य; संसाधनों तक पहुंच के मुद्दे (सेवाएं, आवास, रोजगार और भूमि) पर वियतनाम (13–16 नवंबर, 2017) में प्रस्तुत 'सेप्टिक टैंक खाली करने के व्यवसाय' शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन हनोई विश्वविद्यालय, वियतनाम में बहु–संस्थान सहयोग के माध्यम से आयोजित किया गया। सीपीआर ने दिल्ली में सेप्टिक टैंक खाली करने के व्यवसायों पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया गया, यह शोध पत्र दर्शाता है कि कैसे सह–उत्पादन, अनौपचारिक स्व–संगठित व्यवसायों और स्व–प्रावधान के माध्यम से उन समुदायों के लिए प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है जो स्वच्छता आधारभूत संरचना के पारंपरिक, नेटवर्क मॉडल से वंचित हैं। भारत और वियतनाम के बीच तुलना एफएसएम परिप्रेक्ष्य से विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि दोनों देश एफएसएम के लिए राष्ट्रीय नीति और विधायी संरचना का विकास कर रहे हैं और हनोई जैसे अलग–अलग शहरों में एफएसटीपी (फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स) की विकेन्द्रीकृत प्रणाली की कल्पना करने वाले मास्टर प्लान जारी किए हैं।

- ''घनत्व और शासन और बुनियादी सेवाओं के बीच संबंधों पर बहस'' पर शोध पत्र: भारत और इंडोनेशिया में दो मामले के अध्ययन से प्राप्त तुलनात्मक विचार'' : एशिया में शहरी घनत्व के उभरते रूपों पर साझा दृष्टिकोण: संसाधनों तक पहुंच के मुद्दे (सेवाएं, आवास, रोजगार और भूमि), वियतनाम (13–16 नवंबर, 2017) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में प्रस्तुत किए गए। सम्मेलन हनोई विश्वविद्यालय, वियतनाम में बहु–संस्थान सहयोग के माध्यम से आयोजित किया गया। शोध पत्र का लक्ष्य दो मामलों के अध्ययन के माध्यम से घनत्व के स्तर और शहरी सेवाओं के प्रावधान के तरीकों के बीच संबंधों की खोज करना है। पहला मामला अध्ययन माध्यमिक इंडोनेशियाई शहर यानी सुरकार्ता के शहरी कोर में पानी के मामले को दर्शाता है, जबकि दूसरा दिल्ली के शहरी गांव में नेटवर्क से परे स्वच्छता के प्रावधान पर केंद्रित है। दोनों मामले के अध्ययन समुदाय आधारित संगठन के गठन के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाने और शिक्षित करने से जुड़े वहनीयता, स्वास्थ्य प्रभाव और सामाजिक न्याय के मुद्दों के बीच समानता दर्शाते हैं । दोनों मामले कमी में ऑन–साइट समाधान की उपस्थिति और नेटवर्क समाधान की धीमी प्रगति से संबंधित विचारों के तुलनात्मक बिंदु प्रस्तुत करते हैं। शोध में सेवा की प्रकृति से संबंधित मामलों (स्वच्छता से अलग पानी), निपटारे की सामाजिक-आर्थिक संरचना और इंडोनेशियाई और भारतीय राज्यों की नियामक क्षमता से संबंधित विचारों के इन तुलनात्मक बिंदुओं के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया।

- दिल्ली में बीमारियों के लघु–स्तरीय शासन पर अनुसंधान 'अर्ब–एंडेमिक : दिल्ली के शहरी क्षेत्र में बीमारियों के नियंत्रण में सुधार कैसे करें' नामक लघु–स्तरीय अनुसंधान पेरिस में (28–30 जून, 2017) अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया। सीपीआर ने शिकागो विश्वविद्यालय, सीएनआरएस, पेरिस और पाश्चर इंस्टीट्यूट, पेरिस के नेटवर्क कार्यक्रम में शोध निष्कर्षों को साझा करने और शहरी बीमारी नियंत्रण और प्रबंधन के संदर्भ में शहरी शासन और स्वच्छता पर सहयोगी कार्य विकसित करने में भाग लिया। सीपीआर शोधकर्ताओं द्वारा दिल्ली में बीमारियों के छोटे पैमाने पर किए गए क्षेत्रीय

कार्य के परिणाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त अनुसंधान के परिणाम भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा कार्यशाला में प्रस्तुत किए गए थे। इन संस्थानों और चल रहे शोध के साथ सीपीआर के शोध सहयोग पर चर्चा और समीक्षा की गई और डेटा साझाकरण और प्रबंधन की योजना पर सहमति बनाई गयी । सीपीआर ने इस कार्यक्रम में एमसीडी शोधकर्ताओं की समर्थित भागीदारी का समर्थन किया। अगस्त–सितंबर 2017 में बीएमजीएफ के साथ चर्चा के बाद इस गतिविधि के लिए सीपीआर समर्थन बंद कर दिया गया है।

- अप्रैल 2017 में शिकागो, इलिनॉयस में ''जनसंख्या एसोसिएशन ऑफ अमेरिका वार्षिक बैठक'' में भाग लिया और शहरी स्वच्छता तक पहुंच में ''क्षैतिज और लंबवत असमानताओं की समझ'' शीर्षक पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। बुनियादी सुविधाओं को खरीदने की घरेलू क्षमता आर्थिक और सामाजिक स्थिति और भारत के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक आधारभूत संरचना सेवाओं के प्रावधान में बढ़ती असमानताओं के अतिरिक्त सामाजिक या स्थानिक असमानताओं के प्रसार पर निर्भर करती हैं। यह शोध पत्र उन क्षैतिज या सामाजिक समूह–आधारित असमानताओं पर केंद्रित है, जिन्हें अक्सर भारत में स्वच्छता प्रवचन में उपेक्षित किया जाता है, जिनका उपभोग व्यय और जल निकासी के आधार पर असमानताओं के अस्तित्व के साथ शौचालयों तक पहुंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह शोध पत्र मूल घरेलू सुविधा शौचालयों को मानता है और आर्थिक डेटा और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर और बाइनरी बहुविकल्पीय लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का उपयोग करके पानी की आपूर्ति और जल निकासी जैसे आधारभूत मानकों पर आधारित किसी के स्वामित्व वाले घर की संभावना को मापने के लिए सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करता है। निष्कर्ष राज्य स्तर पर उन बहुआयामी असमानताओं के अस्तित्व का पता लगाते हैं, जिन्हें स्थानीय और राज्य स्तर पर अधिक केंद्रित हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

9. स्वच्छता से संबंधित अनुसंधान के लिए पहचान किए जाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ समूह

विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर और कलिंग स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट, केआईआईटी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के साथ साझेदारी एक साल के संविदा समझौतों के माध्यम से शुरू की गई है।

10. सार्वजनिक निजी साझेदारी

एफएसएम पर राष्ट्रीय नीति एक अभूतपूर्व परिवेश को स्थापित करती है जो शहर भर में अभिनव स्वच्छता के लिए एफएसएसएम और सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देती है। हालांकि, भारत में एफएसएसएम क्षेत्र सहित पानी और स्वच्छता में पीपीपी के बहुत कम सफल मामले हैं। इस संदर्भ में, सीपीआर द्वारा हस्तक्षेप बाजार उन्मुख सार्वजनिक वस्तु विकास संबंधी हस्तक्षेपों को मजबूत करने के लिए सरकारी, वाणिज्यिक और अकादमिक कलाकारों के बीच एक मजबूत और प्रतिकृति साझेदारी मॉडल का अग्रणी बनाने का आशय है; आखिरकार एफएसएसएम के माध्यम से सुरक्षित और स्थायी पानी और स्वच्छता की दिशा में प्रगति में तेजी आई।

11. ज्ञान प्रबंधन और प्रसार

दो साल से, बीएमजीएफ राज्य में तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) की स्थापना करके ओडिशा सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। नौ एएमआरयूटी शहरों से और दो परियोजना निर्मल शहरों – अंगुल और धेनकनाल से क्रॉस लर्निंग की सुविधा के लिए; अधिगम को मजबूत करने और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, टीएसयू सदस्यों, सीपीआर और पीए के बीच उप समूहों को निम्नलिखित पर गोवा का समर्थन करने के लिए गठित किया गया था :

- क्षमता निर्माण – राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षु मॉड्यूल विकसित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए क्षमता निर्माण पहल सीपीआर द्वारा की गई थी, जबकि जिला स्तर पर ट्रिगरिंग कार्यशालाएं टीएसयू द्वारा प्रस्तुतियों के विकास और अंगुल और धेनकनाल में कार्यशालाओं के संचालन के लिए सीपीआर और पीए के समर्थन के अधीन थीं।

- मल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन विनियमन, 2018 : टीएसयू द्वारा एफएसएसएम शहर विनियमनों का मसौदा तैयार किया गया और सीपीआर द्वारा इस पर फोकस करने के साथ साथ सीपीआर, पीए और टीएसयू के गठित कोर समूह सदस्यों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों सहित पहले से तैयार किए गए हैं :

  - निर्माण, नियमित रखरखाव, नियमित सफाई और कंटेनमेंट इकाई के खाली होने के लिए विनियामक संरचना प्रदान करना; परिवहन, उपचार, पुनः उपयोग और सेप्टेज का सुरक्षित निपटान;
  - सेप्टिक टैंक से जुड़े परिसर के मालिकों द्वारा किए गए कार्यों को निर्धारित करने के लिए, सेप्टेज परिवहन के संचालक और उनके दायित्वों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपचार;
  - उपयुक्त प्रवर्तन तंत्र प्रदान करना;
  - उचित मल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए एक स्थायी आधार पर लागत वसूली सुनिश्चित करना।

उपरोक्त के अलावा, सीपीआर ने ओडीएफ कार्यनीति दस्तावेज पर समर्थन प्रदान किया जो कोर समूह द्वारा तैयार किया गया था जिसमें टीएसयू और पीए और अंगुल और धेनकनाल में मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण भी शामिल था।

12. अंतरराष्ट्रीय अनावरण दौरे और शहर / राज्य स्वच्छता कार्यशालाओं के लिए तैयार सहायक समग्री

- छोटे और मध्यम कस्बों में स्वच्छता की संस्थागत व्यवस्था शीर्षक ''अवधारणा नोट: श्रीलंका से सबक'' राष्ट्रीय स्वच्छता नीतियों और पणधारकों की भूमिकाओं का पता लगाने के लिए विशेष रूप से मल के कचरे के प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभालने के लिए श्रीलंका में स्वच्छता की जिस संस्थागत व्यवस्था को चित्रित किया जाता है उन प्रथाओं को भारत के लिए संदर्भित किया जा सकता है। पिछले दशक में श्रीलंका के छोटे और मध्यम शहरों में सेप्टेज प्रबंधन में तेजी आई है। वर्ष 2008 में, शुष्क क्षेत्र शहरी जल और स्वच्छता परियोजना (डीजेडयूडब्ल्यू और एसपी), को शहरी और शहर के आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए – उत्तर–पश्चिमी प्रांत में मन्नार, वावुनिया, पुट्टलम और चिलाओ के चार शहरों को लक्षित करके शुरू किया गया था। डीजेडयूडब्ल्यू और एसपी की उप परियोजनाओं के मामले के अध्ययन के माध्यम से, शोध पत्र में इन चार छोटे और मध्यम आकार के शहरों में एफएसएम के लिए कार्यात्मक संस्थागत व्यवस्था की जांच की गई है।
- ''वियतनाम में स्वच्छता क्षेत्र'' अवधारणा नोट, वियतनाम में स्वच्छता क्षेत्र के इतिहास का पता लगाने का प्रयास करता है। वियतनाम कुछ विकासशील देशों में से एक है जिसने अपनी आबादी के लिए पानी और

स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया है। कुल मिलाकर, वियतनाम 2000 से 2015 के बीच अपनी आबादी की एक चौथाई से अधिक बुनियादी स्वच्छता लाने में कामयाब रहा। सेप्टिक टैंक और पिट शौचालय वियतनाम में अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य रूप बना हुआ है। हनोई में ऑन–साइट स्वच्छता समाधान के प्रभुत्व के बावजूद, एफएसएम समाधानों में आधारभूत संरचना वित्तपोषण और निवेश सीमित है। हालांकि, यह नियामक उत्साह की कमी के लिए नहीं है – वियतनाम में कानूनों, नियमों और विनियमों का एक संपूर्ण नेटवर्क है जो ऑन–साइट सिस्टम से कचरे के प्रबंधन की आवश्यकता को तेजी से पहचान रहे हैं। यह अवधारणा नोट वियतनाम में जल निकासी, सेप्टेज और सीवरेज प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए वियतनाम में डिक्री और कानूनों पर प्रकाश डाला गया है।

III. वैश्विक स्वास्थ्य कार्यनीतियां – बाल संरक्षण और मातृ स्वास्थ्य पर जीपीपीआई – सीपीआर सह भागिता

इस सहभागिता का उद्देश्य है, डायरिया और निमोनिया जैसे बाल्यावस्था में होने वाले रोगों से संबंधित मुद्दों को उठाने की आवश्यकता और इन जीवन रक्षक दवाओं, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने की सुनिश्चिता तय करने; बाल संरक्षण की रूपरेखा को बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदान करने और मंच का उपयोग करने में सांसद किस प्रकार से प्रभावी भूमिका आदा कर सकते हैं इस पर चर्चा करें। सांसदों की नियुक्ति का लक्ष्य है ऐसे प्रश्नों को उठाना जिन पर सांसद बाल संरक्षण एवं टीके संबंधी मुद्दे उठाएं; और इस बात का मार्गदर्शन लें कि भारत में बाल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर वे कैसे अपना पक्ष रखें।

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के दौरान इस परियोजना के तहत किए गए कार्यों में शामिल हैं –

1. जीपीपीआई और ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजीज (जीएचएस) ने अपने सहयोगी श्रृंखलाओं की सहयोगी श्रृंखला में ''केंद्रीय बजट 2018 में किए गए स्वास्थ्य प्रतिबद्धताओं'' पर एक चर्चा आयोजित की। केंद्रीय बजट 2018 में कई उपायों का प्रस्ताव दिया जिस से भारतीय स्वास्थ्य सेवा में बदलाव आने की उम्मीद है। स्वास्थ्य बीमा से संबंधित बजट का हॉलमार्क राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा और 1.5 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और कल्याण केंद्रों में बीमारी की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आयुष भारत कार्यक्रम में 2001,200 करोड़ का आबंटन किया गया है। । ये हालमें किए गए विकास भारत को अपने स्वास्थ्य लाभ में तेजी लाने का अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि, इन लक्ष्यों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मार्ग अनिश्चित है।

इस चर्चा में मौजूदा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राजनीतिक नेताओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया और नियोजन और बीमारी जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को सर्वोत्तम तरीके से प्रदान करने के लिए राजनीतिक जागरूकता की आवश्यकता है। भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव श्रीकृष्ण देसीराजू, और डॉप्रोनबसेन कंट्री डायरेक्टर, इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर (आईजीसी) ने इस मुद्दे पर अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से विस्तार से चर्चा की।

2. जीपीपीआई और जीएचएस ने राजनीतिक एजेंडे पर बाल स्वास्थ्य और पोषण जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों को रखने में राजनीतिक नेताओं की भूमिका पर चर्चा करने के लिए ''भारत में बाल स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने'' पर संयुक्त रूप से एक चर्चा का आयोजन किया। ध्रुव पावा, निदेशक – वैश्विक स्वास्थ्य कार्यनीतियों में बाजार पहुंच, जिन्होंने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी उत्पादों, सेवाओं और नीतियों के लिए पहुंच कार्यनीतियों को विकसित करने के लिए काम किया है ; और निदेशक और वरिष्ठ अध्येता रोग गतिशीलता, वाशिंगटन डीसी, अर्थशास्त्र और नीति केंद्र (सीडीडीईपी) और वरिष्ठ शोध विद्वान और व्याख्याता, प्रिंसटन पर्यावरण संस्थान, रामानान लक्ष्मीनारायण ने स्वास्थ्य देखभाल के वित्त पोषण और खर्च बढ़ाए बिना काम खर्च पर भारत में स्वास्थ्य कैसे सुधारा जा सकता है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की।

IV. कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र में नियोजन और विकास प्रयासों से संबंधित पांडुलिपियों का एकीकरण और निष्पादन

इस पुस्तक में यह अभिलेख तैयार करने का प्रयास किया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शहरी नियोजन किस प्रकार हुआ था। यह इस प्रकार का पहला विशेष अध्ययन है और शहरी वृद्धि के साथ निपटने हेतु नियोजनकर्ताओं द्वारा सामना की गई समस्याओं का स्पष्ट चित्रण किया गया है। यद्यपि आजादी प्राप्ति के तुरंत बाद भारतीय अधिकारियों को इस बात की अधिक जानकारी नहीं थी कि शहरों का एक समूह बांधने में आने वाली समस्याओं से कैसे निपटा जाएं, और नहीं उन्हें इसके बारे में अधिक अनुभव था। यह सभी संबंधितों के लिए अधिगम प्रक्रिया थी। भारत में बड़े शहर कुछ आशंकाओं के कारण पलायन कर गए क्योंकि आजादी के बाद आरंभिक वर्षों में इनकी समस्याएं और सार्वजनिक नीतियों के अनुसरण में बड़े शहरों की वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। कलकत्ता न केवल भारत बल्कि विश्व भर में शहरी समुदायों के लिए भी उत्कृष्ट अनुभव था। डब्ल्यूएचओ, फोर्ड फाउंडेशन और विश्व बैंक ने भारत की समस्याओं, विशेष रूप से शहर को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल के संबंध में विचार प्रकट किए। कलकत्ता विकासशील विश्व का एक मात्र ऐसा शहर था जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी ख्याति मिली।

प्रोफेसर के सी शिवरामाकृष्णन पुस्तक की पांडुलिपि पर कार्य कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद, कुछ सामग्री को जोड़ा और संशोधित किया गया है और पुस्तक अभी भी पुनरीक्षण और संपादन चरणों में है।

V. दिल्ली की अनियमित बस्तियों की सीमा का विस्तार

दिल्ली में राज्य–नागरिक संबंधों के बारे में सीपीआर का निकाय बनाने के लिए इस परियोजना में समुदाय मार्गदर्शित शहरी पुनर्स्थापना के सीमा–विस्तार क्रियाकलापों को समझने का प्रयास किया गया है। यह परियोजना विशेष रूप से दिल्ली में विभिन्न बस्तियों के संदर्भ में स्वयं–संगठित नागरिकों, स्थानीय समुदाय और सरकारी संस्थानों के बीच हस्तक्षेप करने वाले 'सीमा विस्तारकों की भूमिका की जांच करती है। इस परियोजना के पहले चरण में नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और भारत से प्रकरण अध्ययनों का उपयोग करने की तुलना में देखे गए एरासमस विश्वविद्यालय, रोटरडम के इंस्टीट्यूट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट स्टडीज़ (आईएचएस) द्वारा समर्थित है। इस चरण में, सीपीआर ने पुनर्जनन और मानचित्रित बाउंडरी स्पैनर्स की एक अनाधिकृत कालोनी और दिल्ली में एक पुनर्वास कॉलोनी का अध्ययन किया।

दूसरे चरण में, 'शहरी पुनर्स्थापना के लिए सीमा विस्तार और वित्तीय मध्यस्थता : 3 भारतीय शहरों में तुलनात्मक मामला अध्ययन शीर्षक से आईसीएसएसआर – वित्तपोषित एक परियोजना के तहत इस विषय पर अनुसंधान किया जा रहा है। यह परियोजना टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुंबई और सीपीआर द्वारा चलाई जा रही है और मद्रास इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ इसके सहयोगकर्ता हैं। इस चरण में, सीपीआर पूर्वी दिल्ली की अनाधिकृत और विनियमित अनाधिकृत

कालॉनियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहां राज्य के कार्मिकों से विशेष रूप से आवास वित्त के संदर्भ में निजी कंपनियों को लाने के लिए बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ एक पुनर्वास कॉलोनी है, भालस्वा, जहां गैर सरकारी संगठन उन्नत सेवाओं के लिए बातचीत के साधन के रूप में आरटीआई का उपयोग कर रहे हैं।

VI. भारत का मध्यवर्ग

यह परियोजना 'भारतीय मध्यवर्ग' के विचार की जांच करना चाहती है। यद्यपि भारतीय मध्य वर्ग की धारणा ने अधिक ध्यान खींचा है फिर भी इस समाज की परिभाषा और आकार के बारे में अभी भी संदिग्धता है। यह परियोजना स्थिति के साथ इस समुदाय के बदलते संबंध, उनकी उपभोग रुचियों और विश्लेषण के महत्वपूर्ण वर्टिसेस के रूप में आर्थिक व्यवहार सहित मौजूदा साहित्य में वृद्धि करना चाहती है।

भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद् (आईसीएसएसआर) द्वारा सहयोग प्राप्त यह अध्ययन मध्यवर्ग के निर्धारित गुणों, सामाजिक राजनैतिक पहचान और आर्थिक व्यवहार का पता लगाकर इस उभरते हुए वर्ग की समझदारी बढ़ाना चाहता है। भारतीय मध्य वर्ग का पता लगाकर, चुनाव संबंधी प्राथमिकताओं में भिन्नताओं को स्पष्टकर और घरेलू कार्य की दृष्टि के जरिए 'मध्य वर्गिता' के सूक्ष्म भेदों को स्पष्ट कर इस शोध पत्र में संकल्पना संबंधी मुद्दों की चर्चा की गई है।

इस वर्ष कोई कार्य नहीं था

VII. भारत में शहरी कायापलट

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आईसीएसएसआर) द्वारा वित्त पोषित ''भारत में शहरी कायापलट'' अनुसंधान परियोजना जुलाई 2013 से अक्टूबर 2015 तक नीति अनुसंधान केंद्र (सीपीआर), नई दिल्ली में कार्यान्वित की गई है। इस परियोजना में दो विस्तृत विषयों का ध्यान दिलाया गया है : 1. दिल्ली में सिटीजन शिप मैपिंग और 2. लोकल स्टेट किस तरह कार्य करते हैं।

इस विस्तृत परियोजना के रूप में सिटीज ऑफ दिल्ली परियोजना में इन दोनों विषयों से संबंधित तत्व शामिल किए गए हैं। इस परियोजना ने दिल्ली की अनाधिकारिक बस्तियों में रहने वाले निवासियों द्वारा अपने चुने गए प्रतिनिधियों, राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त करने वाले कारकों से संपर्क करने के बारे में पता लगाया। सिटीज ऑफ दिल्ली परियोजना के परिणाम ''स्थान'', ''संस्थान'' और प्रक्रियाओं संबंधी रिपोर्टों के तीन सेटों में व्यवस्थित किए गए हैं जो एक साथ मिलकर दिल्ली के शासन और गरीबों पर इसके प्रभाव का एक व्यापक चित्र उपलब्ध कराने की मांग करते हैं। सिटीज़ ऑफ दिल्ली परियोजना के परिणाम द्विभाषी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इन तीन तरीकों के माध्यम से परियोजना में प्रश्नों के उत्तर मांगे गए: ''स्थानीय सरकार किस प्रकार कार्य करती है?'' पहले में सांविधिक और जनगणना वाले नगरों पर मुख्य जोर देकर भारत में नगरों की प्रशासनिक स्थिति पर विचार किया जाता है। दूसरा छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों के लिए जेएनएनयूआरएम के घटकों की तुलना करके जेएनएनयूआरएम और भारत के छोटे शहरों के बीच संपर्क में तल्लीन है। तीसरे ने इन शहरों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के अलगाव और उनके लिए सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान की सीमा पर विचार करते हुए भारत के दस सबसे बड़े शहरों में स्थानिक असमानताओं का विश्लेषण किया है।

यह परियोजना अगस्त 2015 में दो दिवसीय सम्मेलन के साथ समापन पर पहुंच गई थी।

VIII. डिजिटल शहरी ऑब्जेवेटरी

परियोजना सैटेलाइट इमेजिंग और फील्ड पूछताछ के संयोजन का उपयोग करके दिल्ली में चुनिंदा अनौपचारिक बस्तियों में नागरिक सेवाओं के प्रावधान को व्यापक रूप से मानचित्रित करने की मांग करती है। अभ्यास मानचित्रण ने बस्तियों में सक्रिय सामुदायिक संगठनों को शामिल किया है, और ब्राउन यूनिवर्सिटी और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, यूएसए के शोधकर्ताओं के सहयोग से किया जा रहा है। इस साल टीम ने स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक कलाकारों के साथ भागीदारी में डेटा का संग्रह करने के लिए कई बस्तियों में कार्य किया।

IX. भारत – शहरी ग्रामीण सीमाएं और मूलभूत सेवाएं (इन्ड–यूआरबीबीएस)

इंड–यूआरबीबीएस उपक्रम, सीपीआर और अनुसंधान और विकास संस्थान (अनुसंधान और विकास संस्थान – आईआरडी) का संयुक्त उपक्रम है। इंड – यूआरबीबीएस यह समझने के लिए बनाया गया था कि शहरी बंदोवस्त जैसे व्यावसाय का ढांचा, मूलभूत सेवाओं की सुपुर्दगी और नागरिकता के विस्तृत पहलुओं के परिणाम किस प्रकार से तीन प्रकार के शहरों अर्थात : (1) 'जनगणना शहरों' के अनुरूप छोटे सांविधिक शहर; (2) समान प्रकृति की औपचारिक व्यवस्था के अनुरूप बड़े शहरों में अनौपचारिक व्यवस्था; और (3) नगरपालिका शहरी सीमा के बाहर व्यवस्था के अनुरूप शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर परिधीय व्यवस्था; में नागरिकों और राज्य सरकार की प्रणाली के बीच पास्परिक क्रिया से प्रभावित होते हैं, इस प्रकार से विस्तार क्षेत्र, जिससे राज्य इन शहरों को पहचान दी है, के अनुसार जन नीतियों में भिन्नता के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।

इंड–यूआरबीबीएस कार्यक्रम में भाग लेने वाले संस्थानों – सीपीआर; इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर) वर्धवान विश्वविद्यालय में अनुसंधान के मुख्य क्षेत्रों में संबद्ध अनुसंधान करने वाले युवा पीएच डी धारकों को सहयोग प्रदान किया गया। इस साल, सीपीआर ने फरवरी 2018 में कुआ लालम्पुर में विश्व शहरी मंच में एक पैनल का आयोजन किया ताकि स्थिर विकास लक्ष्यों और नए शहरी एजेंडा को कार्यान्वित करते समय छोटे शहरों और अनौपचारिक निपटारे पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर चर्चा की जा सके। शहरी गांवों में किराए के आवास पर शोध में मुक्ता नायक ने सीईएसएसएमए, आईआरडी, पेरिस के साथ साथ इस साल हनोई में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। वेरोनिक डुपोंट और शंकर गौड़ा ने इस साल कठपुतली कॉलोनी पर अपना शोध जारी रखा, जिसमें उन्होंने निपटारे के विध्वंस और इसके प्रभावों को ध्वस्त कर दिया।

X. एक विशाल शहर वाले क्षेत्र में परिवहन विनियमन के बीच मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को एकीकृत करना परियोजना में मेगासिटी कोलकाता में परिवहन नियामक तंत्रों में एकीकृत मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) के उद्देश्य से कोलकाता मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में परिवहन के नियामक वास्तुशास्त्र का परीक्षण किया जाता है।

सीपीआर ने इस परियोजना को शक्ति फाउंडेशन के सहयोग से इन्नोवेटिव ट्रांसपोर्ट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (आईट्रांस) के साथ शुरू किया। आईपीटी के लिए विनियामक रूपरेखा का अध्ययन करके और शहर में ऑटो रिक्शा के ड्राइवर और प्रयोक्ताओं के मार्ग सर्वेक्षण और इटरव्यू के माध्यम से, परियोजना में पाया कि ऑटो रिक्शा के एकीकरण से अधिक निर्बाध परिवहन प्रणाली उपलब्ध हो सकती है और अधिक आवाजाही व बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले सार्वजनिक परिवहन विकल्प जो प्रयोक्ता के स्थान से चलकर उसकी मंजिल तक उपलब्ध होकर प्रयोक्ताओं को निजी परिवहन से अलग करने में उनका सहयोग कर सकते हैं। यह परियोजना दिसंबर, 2016 में पूरी हो गई थी और इसकी रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस परियोजना से कोलकाता में एकीकृत परिवहन योजना संबंधी जारी विचार विमर्श में सहयोग

किया है और अनुसंधानकर्ताओं ने देश में सड़क सुरक्षा और परिवहन के संशोधित रूपरेखा के बारे में सम्मेलनों और विचार–विमर्श में भाग लिया है।

इस वर्ष, सीपीआर शोधकर्ताओं ने सम्मेलन में भाग लिया और परिवहन नीति पर सरकारी परामर्श में योगदान दिया।

XI. अनुपस्थित मध्य वर्ग : भारत में जनगणना कस्बे

भारत में बस्तियां तीन बड़ी श्रेणियों नामतः गांवों, वैधानिक शहरों (एसटी) और जनगणना शहरों (सीटी) में बंटी हैं, बाद वाली दो श्रेणियां भारत में शहरी क्षेत्रों के दो मुख्य प्रकार हैं। जनगणना शहर प्रशासनिक रूप से ग्रामीण बस्तियां है तथापि वे शहरी क्षेत्रों का मानदंड पूरा नहीं करती हैं। इस परियोजना में जनगणना शहरों की प्रकृति, इतिहास और आर्थिक एवं राजनैतिक संरचनाओं की जांच की जाएगी।

जनगणना शहरों के लक्षण–वर्णन और वर्गीकरण के बारे में कई सवाल उठते हैं इस परियोजना में इन्हीं का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है : जनगणना शहर किस मायने में गांव या वैधानिक शहर से भिन्न है? एक बस्ती ग्रामीण और दूसरी शहरी क्यों है? ग्रामीण और शहरी स्तर तथा संबंधित सरकारी संरचनाओं के बीच समझौताकारी तालमेल क्या है? इन मुद्दों पर विचार करने के लिए इस अध्ययन में बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गहन क्षेत्रीय अध्ययनों सहित भारतीय जनगणना आंकड़ों जैसे राष्ट्रीय सर्वेक्षण आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है।

सीपीआर अध्येताओं पार्था मुखोपाध्याय और मेरी–हेलन जेराह ने सहयोगियों गोपा सामंता और आंगस्टीन मारिया के साथ मिलकर दिसंबर 2016 में 'भारत की शहरी सीमा का समझना : भारत में जनगणना शहरों के उद्‌भव के पीछे क्या है?' शीर्षक से एक विश्व बैंक शोध पत्र प्रस्तुत किया।

XII. भारतीय संदर्भ में प्रवास को मजबूत बनाना तथा अनुसंधान को अनुरूप बनाना तथा कार्रवाई करना (श्रमिक)

टाटा ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित श्रमिक (एसएचआरएएमआईसी) एक बहु–हितधारक परियोजना है जिसमें प्रवास संबंधी मुद्दों का अध्ययन करने के लिए शैक्षिक संस्थानों और एनजीओ को साथ लाने के लिए सीपीआर ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान और आइरिस नॉलिज फाउण्डेशन के साथ सहयोग किया। इस पहल का लक्ष्य भारत में प्रवास की सीमा और प्रकृति के बारे में हमारी जानकारी में सुधार करना और प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण का सुझाव देना है।

शमिन्द्रनाथ रॉय, मनीष और मुक्ता नायक ने इस वर्ष प्रवासी निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र को देखते हुए एक नीतिगत संक्षिप्त जानकारी दी और आंतरिक प्रवासन पर एक हस्तपुस्तिका बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मुंबई में आयोजित एक लेखक कार्यशाला में भाग लिया। पार्थ मुखोपाध्याय और मुक्ता नायक अन्य सहयोगियों के साथ इस खंड के सह–संपादक हैं।

XIII. भारत में सबसे निम्न कोटि का शहरीकरण

सबसे निम्न कोटि के शहरीकरण का आशय उन बस्ती समूहों से है जो महानगर से मुक्त हैं और अन्य बस्तियों के साथ अपने पारस्परिक प्रभाव से स्वायत्त हैं। फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पाण्डिचेरी (आईपीएफ) और सेंटर डि साइंसेज ह्यूमंस (सीएसएच) के नेतृत्व में सब अर्बिन परियोजना का उद्देश्य विभिन्न विषयों से ''शहरी परिवर्तन'' संबंधी वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना है। अर्थव्यवस्था के त्वरित बदलाव से कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं जैसे हम ग्रामीण और शहरी, प्रशासनिक स्तर और कार्यात्मक वास्तविकता के बीच कहां पर अंतर करते हैं? कैसे और किस उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र बन जाएगा? छोटे शहरों और आर्थिक प्रक्रियाओं के प्रचुरोद्‌भवन के बीच क्या संबंध है?

सब अर्बिन आईएफपी और सीएसएच की संयुक्त परियोजना है। सीपीआर इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, दि इंस्टीट्यूट कांफ्रेंस डि पांडिचेरी, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, दि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली, बर्दवान ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली, बर्दवान विश्वविद्यालय जैसे अन्य संस्थानों के साथ इस कार्य में शामिल है।

एपोनीमसली शीर्षक और एरिक डेनिस एवं मैरी–हेलेन जेराह द्वारा संपादित पुस्तक जो वर्ष 2017 की शुरूआत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी हुई थी और शीघ्र ही भारत में उपलब्ध होगी, में इस अनुसंधान परियोजना को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया गया है।

XIV. भारत में युवा रोजगार को आकार देने में छोटे शहरों की भूमिका

थिंक टैंक्स उपक्रम और आईडीआरसी द्वारा वित्तपोषित इस नवीन अनुसंधान परियोजना, के अंतर्गत प्रवासी युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में छोटे शहरों की भूमिका को विस्तार दिया जाता है। यह परिकल्पना की जा रही है कि छोटे शहर युवा प्रवास मार्गों के साथ – साथ 'मार्ग केंद्र' के रूप में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, परियोजना में भारत और इंडोनेशिया के केस सिटीज का उपयोग कर प्रशासन और नीतिगत संरचना की भूमिका की जांच की जाती है। छोटे शहरों के श्रम बाजारों में युवा प्रवासियों के अनुभवों का अन्वेषण करने के लिए, परियोजना के अंतर्गत कौशल विकास, रोजगार परिणामों, आर्थिक गतिशीलता और प्रवास मार्गों पर इन कारकों के प्रभाव की जांच की जा रही है। छोटे शहरों की प्रवासी महिलाओं के श्रम बाजार अनुभव, मैक्रो – लेवल डेटा में उनकी अदर्शनता को दर्शाता है, जो परियोजना कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। नीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली अपने सहयोगी जस्ट जॉब्स नेटवर्क – ए ग्लोबल जॉब्स थिंक टैंक के साथ मिलकर युवा प्रवासियों, विशेष रूप से महिला प्रवासियों के रोजगार को उन्नत करने के लिए सरकारों को सक्रिय करने वाली नीतियों को संस्तुत करने हेतु परियोजना के परिणामों को उपयोग करने का प्रयास कर रहा है। परियोजना को आगे बनाने के लिए प्रवास, छोटे शहरों, प्रशासन और नागरिक संबंधी विषयों पर सीपीआर के मौजूदा कार्य पर कुछ सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

इस वर्ष, किसानगढ़, राजस्थान और मैंगलोर, कर्नाटक में दो क्षेत्रीय स्थालों से मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

महा नगरीय आवास हीनता को समझना

महानगरीय आवास हीनता को समझना एक मानव जातीय अनुसंधान परियोजना है जिसे कोशिश – टीआईएसएस की सहभागिता से चलाया जा रहा है जिसे फरवरी 2017 में आईसीएसएसआर से वित्त पोषण प्राप्त हुआ था। इस अनुसंधान में आवास हीनता के जीवन चक्र अर्थात् (क) आवास हीनता की शुरूआत (ख) आवास हीनता के दौरान जीवन यापन और (ग) आवास हीनता से निकलने अर्थात मृत्यु, रोजगार या परिवार में पुनः शामिल हो जाने के बारे में जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बेघर लोगों, जो बड़े पैमाने पर अपने जन्म स्थानों से आकर दिल्ली की गलियों में रहते हैं क्या या किस सीमा तक उन्हें आश्रय मिलता है, उनका दैनिक मजदूरी चक्र वाला कार्य उनके स्वास्थ्य पर क्या असर डालता है और व अपने पैतृक स्थान के संबंधियों के लिए क्या व्यवस्था करने में सक्षम होते हैं, और उन तथ्यों का पता लगाना है जो आवासहीनता से मर्त्यता या पुनर्वास जैसे विपरीत ध्रुवीय मार्ग का निर्धारण करते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन (एनयूएलएम) जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 790 शहरों के 900,000 बेघर लोगों को आश्रय सुविधाओं और राशन व पोषण का अधिकार देना है, के हस्तक्षेप के बावजूद दिल्ली में बेघर लोगों की मौत की वार्षिक दर अधिक और शहर के आश्रय स्थलों के उपयोग की दर कम रहती है। इस परियोजना का मानना है कि यह बेघर लोगों द्वारा सामना की जाने वाली घोर और मृत्यु दायक गरीबी के जोखिम कारकों की प्रकृति के विशद ज्ञान के अभाव के कारण है नीति निर्माताओं, स्थानीय अधिकारियों और क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को यह जानकारी होनी चाहिए कि इनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार पर्याप्त रूप से पूरा किया जाए।

विकास परियोजनाओं के लिए इस शताब्दी दिल्ली के भू–उपयोग में नाटकीय परिवर्तनों के मामले में विद्वानों ने यह भी नोट किया है कि बहुत से गरीब लोगों की रहने लायक स्थानों तक पहुंच की कमी आई है और उनकी कार्य स्थितियां प्रभावित हुई हैं तथा असमानता में वृद्धि हुई है। इस विषय पर उपलब्ध अधिकांश साहित्य का संबंध ऐसी परियोजनाओं के लिए अनियमित बस्तियों से निष्कासित लोगों के आवास और जीविकोपार्जन संबंधी प्रभावों से है। स्थायी रूप से या अनिश्चित रूप से घर के बिना दिल्ली में निवास कर रहे और सड़कों पर गरीबी से जुड़े विभिन्न सुरक्षा, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिमों का सामना कर रहे लोगों के दैनिक अनुभवों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है।

इस परियोजना का उद्देश्य काफी समय से दिल्ली की सड़कों और आश्रय गृहों में रह रहे लोगों के साथ निकट संपर्क के माध्यम से बेघर लोगों के जीवन चक्र की जांच करके इस तथ्य पर प्रकाश डालना है कि बेघर होने का गरीबी, अभिशासन और शहरीकरण के संबंधित आयामों से क्या संबंध है और सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए बेघर लोगों के सामने आने वाले अवरोधों को दूर करने की इन आवश्यकताओं के प्रति नीति निर्माताओं की संभावनाओं को बढ़ाना है। बेघर लोगों की जीविकोपार्जन और उत्तर जीविता कार्यनीतियों की जांच से भी उन क्षमताओं, मानव और सामाजिक पूंजी को विशिष्टता मिलेगी जिनसे बेघरों को शामिल करने के लिए शहरी गरीबों के लिए अभिप्रेत विकास नीतियों को विस्तार देने के लिए नीति–निर्माताओं को अवसर प्राप्त होंगे।

इन अनुभवों के अतिरिक्त, परियोजना दस्तावेज, सरकारी योजनाएं बेघरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। हमारे अनुसंधान साथी कोशिश – टीआईएसएस पूर्व बेघरों, जिनके लिए उन्होंने नौकरी ढूंढने या परिवारों तक वापस पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया था, की कहानियों को मुंबई में प्रलेखित कर रहे हैं। इस परियोजना में बेघर लोगों के लिए सफलतापूर्वक संपर्क पहलों संबंधी वर्तमान साहित्य को विस्तार देने के लिए दिल्ली में इस प्रकार की कहानियों के योगदान का प्रयास किया गया है।

गतिविधियां : अप्रैल 2017 – मार्च 2018

एथ्नोग्राफिक और जीवन इतिहास विधियों (ऑडियो पर दर्ज) का उपयोग करके हमारी परियोजना टीम ने दिल्ली में 269 मामलों (क) बेघरता में प्रवेश (ख) बेघर होने के दौरान अनुभव होने वाली कमजोरियां - कार्य परिस्थितियां, शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य बोझ, और आवास की कमी के कारण शारीरिक सुरक्षा और सुरक्षा की कमी – इस स्थिति से बाहर निकलने के टिकाऊ मार्गों को दस्तावेज में बदलने के लिए के ऑडियो साक्षात्कार एकत्र किए (जिनमें से 199 मामलों को लिखित किया गया है) – और हमारे शोध भागीदार, कोशिश - टीआईएसएस के समन्वय में सी।

इस विधि के आधार पर, बेघर रहने वालों पर शोध पत्र , ''बेघर रहनाः दिल्ली में काम करने वाले छः बेघर पुरुषों का जीवन'' उत्तर प्रदेश के प्रवासी उन बेघर लोगों का प्रकरण अध्ययन प्रस्तुत करता है जो विभिन्न अवधि के लिए यमुना नदी के पश्चिमी तट के साथ आश्रयों में और उत्तर दिल्ली में रहते हैं, जिसे स्थानीय रूप से 'यमुना पुस्ता ' कहा जाता है। गांवों और कस्बों से दिल्ली की सड़कों पर इनकी यात्रा का पता लगाने से, यह पता चलता है कि ये पुरुष बेघर कैसे बने और वे दिल्ली में बेघर होकर कैसे रहते हैं। शोध पत्र – बेघर लोगों के जीवित अनुभवों को उनकी आवाज में जानते हुए दर्शाता है कि पुरुष कैसे बेघर होने के संरचनात्मक कारणों (जैसे गरीबी, बेरोजगारी) का अनुभव करते हैं और कैसे इन्हें अंतःस्थापित किया जाता है। शोध पत्र के प्रकरण अध्ययन में घर छोड़ने से पहले इन लोगों द्वारा अपने मूल स्थानों में चरम गरीबी के अनुभव और शारीरिक दुर्व्यवहार की स्थितियों, और संयोजनों को उजागर किया।

इसके बाद यह पता चलता है कि कैसे वे दैनिक मजदूरी, आवास के बिना अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में रहते हैं, और आश्रय, स्वास्थ्य और नशे की दवाओं के व्यसन कार्यक्रम जैसे सामाजिक सेवाओं तक पहुँचाने के लिए पूंजी प्राप्त करने हेतु सड़कों पर बसेरा करते हैं। पुरुषों के प्रक्षेपणों के माध्यम से, यह शोध पत्र उन बेघर पुरुषों के बीच मतभेदों की पड़ताल करता है जो परिवारों का समर्थन करने के लिए घर लौटते हैं और जिनके पास अपने मूल स्थानों के साथ संबंध नहीं हैं और सड़कों पर अनिश्चित काल तक रहते हैं।

XV. टैसिट शहरी शोध नेटवर्क (टर्न)

फोर्ड फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित, टर्न को भारत में शहरी मुद्दों पर काम कर रहे चार अनुसंधान संस्थानों – इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स (आईआईएचएस) टीआईएसएस मुंबई, प्रणीति अनुसंधान केंद्र (सीपीआर) और हैदराबाद शहरी लैब्स (एचयूएल) के नेटवर्क के रूप में अवधारणाबद्ध किया गया है। नीति निर्माण में समर्थन प्रणाली को समझने को अंतिम लक्ष्य के रूप में शामिल करने के लिए यह नेटवर्क शहरी अनौपचारिकता और निपटारे, आवास, और अर्थव्यवस्थाओं के संबंधपरक भौगोलिक क्षेत्रों में कई लाभ बिंदुओं और कई साइटों पर एकीकृत ज्ञान के आधार पर सहयोगी रूप से अनुसंधान कर रहा है।

शोध नेटवर्क का लक्ष्य है (क) हिथेर्टो ''तैसीट'' की दृश्यता और समझ में वृद्धि करना भारत में शहरी अनौपचारिकता के बारे में ज्ञान, (ख) इस तरह के ज्ञान को बढ़ाने के लिए नीति संरचना की समावेशिता शामिल करना (ग) भारत में भविष्य के शहरी शोध के लिए एक मंच पर शहरी शोध नेटवर्क (टर्न) के संक्षिप्त ज्ञान का विकास। इस वर्ष, सीपीआर शोधकर्ता उन शोध विषयों की अवधारणा बनाने और उन शोध साइटों का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं जिन से इन सवालों को हल किया जा सके।

जल-विवाद घटना निगरानी प्रणाली (विम्स)

इस परियोजना में कृष्णा नदी बेसिन आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों पर विवादों की निगरानी की गई है। परियोजना का आधार यह है कि नीति और प्रशासन तंत्र में तालमेल के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर विवाद उभरते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर शासन के लिए नीति बनाने और संस्थानों को तैयार करने के लिए पाठ तैयार करने हेतु विवाद घटनाओं की निगरानी और अध्ययन के लिए एक पद्धति के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूआईएमएस (विम्स) एक पायलट परियोजना है।

इस परियोजना में कृष्णा बेसिन आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों : पानी, जमीन और पर्यावरण (बाढ़ के मैदानों का अतिक्रमण) पर चल रहे तीन विवादों की निगरानी की है। एक, संघर्ष है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी के पानी के अंतरराज्यीय जल का साझाकरण। इसमें गोदावरी नदी के साथ कृष्णा नदी को पोलावरम परियोजना के माध्यम से जोड़ना, केंद्र सरकार द्वारा विभाजन व्यवस्था के हिस्से के रूप में एक ''राष्ट्रीय परियोजना'' का दर्जा दिया गया है।

दो, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा ''भूमि पूलिंग योजना'' (एलपीएस) के कार्यान्वयन के लिए कृष्णा नदी के पश्चिमी तट पर अमरावती की अपनी नए राजधानी शहर के निर्माण से संबंधित भूमि को लेकर संघर्ष। तीन, प्रस्तावित अमरावती शहर के कारण पर्यावरणीय संघर्ष – अमरावती की नई राजधानी शहर के लिए बाढ़ के मैदानों का अतिक्रमण। इस परियोजना में अन्य पर्यावरणीय मुद्दे जैसे राजधानी क्षेत्र में वन भूमि के प्रस्तावित डी–नोटिफिकेशन से जुड़े विवादों को भी शामिल किया गया है।

स्थानीय समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों, सोशल मीडिया, फील्ड विज़िट्स में और अन्य सरकारी / गैर–सरकारी स्रोतों के माध्यम से घटनाएं दर्ज कर के इस परियोजना में चार महीने की अवधि में विवाद घटनाओं की निगरानी की गयी है। विवादों का दस्तावेज़ीकरण और विश्लेषण करने के इन घटनाओं को अनुसंधान प्रयास द्वारा समर्थित किया जाता है । परियोजना के परिणामस्वरूप कुल 43 विवाद घटनाएं (जल – 27; भूमि – 10; पर्यावरण –6) दर्ज की गईं हैं। इन नीतियों (उदाहरण के लिए, एलपीएस) और संस्थानों (उदाहरण के लिए, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड) में कार्यान्वयन के लिए विश्लेषण किया गया।

XVI. ट्रांसबाउंडरी वॉटर्स (एसआईएनईटीएस) में स्केल, इंस्टीट्यूशंस और नेटवर्क्स

यह परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना, एसडीआईपी (सतत विकास निवेश पोर्टफोलियो) के तहत प्रयासों को पूरा करने के लिए एक सहायक परियोजना है। एसडीआईपी का लक्ष्य है पानी, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में सुधार करके एशिया की तीन प्रमुख हिमालयी नदी घाटियों; सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र दक्षिण में क्षेत्रीय सहयोग विकसित करना। अनुसंधान और क्षमता निर्माण इनपुट प्रदान करके एसआईएनईटीएस एसडीआईपी और उसके सहयोगियों को समर्थन प्रदान करता है। इस अनुसंधान गतिविधि में दक्षिण एशिया में ट्रांसबाउंडरी नदी जल शासन में बहुसंख्यकता का आयाम : के साथ पड़ता है कैसे भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शासन अंतरराज्यीय नदी के पानी जैसे आंतरिक मामलों का समन्वय करता है।

XVII. ''डोमिनेंट'' कास्ट्स आरक्षण की मांग क्यों करते हैं? मराठा (महाराष्ट्र), जाट (हरियाणा) और पाटीदार (गुजरात) का एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. अम्बरीश डोंगरे (पीआई) और श्री डी श्यामबाबू (सह पीआई) द्वारा यह अध्ययन किया गया।

भारत ने अच्छी तरह से खेती कर रही जातियों द्वारा आरक्षण के लाभ बढ़ाए जाने के लिए आंदोलन देखे हैं। वे न केवल पर्याप्त सामाजिक और आर्थिक संघर्ष के साथ अच्छी तरह से संपन्न हैं बल्कि विशिष्ट क्षेत्रों में बड़ी संख्या में केंद्रित हैं। अतीत में इनमें से कुछ जातियों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का विरोध किया था। उन से यह सवाल पूछा जाता है कि वे अब आरक्षण प्राप्त करने के लिए ''पिछड़े'' या ''कमजोर'' वर्ग के रूप में पहचाने जाने का विकल्प क्यों चुनते हैं। क्या

उनकी भौतिक परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं कि उन्हें जीवित रहने के लिए हर समर्थक की तलाश करनी चाहिए? दूसरी तरफ, आरक्षण इतने आकर्षक हो गए हैं कि नीतियों का विरोध करने वालों को भी इसका लुत्फ उठाना पड़ा?

यह परियोजना आरक्षण के लिए इन बढ़ती मांगों को चलाने के सामाजिक और आर्थिक कारकों की हमारी समझ में योगदान देना चाहती है ताकि अधिक प्रभावी नीति विकल्प तैयार किए जा सकें। इसके अलावा, कई राज्यों में तीन जातियों में तुलनात्मक विधि पर परियोजना का फोकस भविष्य में छात्रवृत्ति क्षेत्र को और बेहतर बनाने में मदद करेगा।
पूरा करने की संभावित तिथि : दिसंबर 2018.

संकाय समाचार

1. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी, यामिनी अय्यर, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे

गैर–समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. भारतीय लोकतंत्र के लिए एक साथ चुनाव खराब क्यों हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, 15 मार्च 2018.
ii. एक बेहतर शिक्षा प्रशासन विकेंद्रीकृत और सीखने पर केंद्रित होगा, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 फरवरी 2018.
iii. राजनीतिक संदेश मास्क बजट 2018 सामाजिक क्षेत्र में वास्तविक वितरण, द वायर, 2 फरवरी 2018.
iv. बजट 2018: भारतीयों के लिए रहने की कोई वास्तविक आसानी नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स, 2 फरवरी 2018.
v. बजट 2018 के बाद, केंद्र और राज्यों को सहकारी संघवाद पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, हिंदुस्तान टाइम्स, 30 जनवरी 2018.
vi. अव्ययित धन की निरंतर समस्या एक गहरी मलिनता का एक लक्षण है, हिंदुस्तान टाइम्स, 4 जनवरी 2018.

सम्मेलन / संगोष्ठियों में प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत शोधपत्र :

i. भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, 27–28 अक्टूबर
ii. स्वास्थ्य संगोष्ठी – पैनलिस्ट, एनआईपीएफपी दिल्ली, 5 दिसंबर.
iii. एसडीजी, दिल्ली, 19 दिसंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन।
iv. राग दरबारी सम्मेलन, दिल्ली विश्वविद्यालय, 29 जनवरी।
v. विश्व बैंक स्वच्छता बैठक, विश्व बैंक, लोदी रोड, नई दिल्ली विश्व बैंक, लोदी रोड, नई दिल्ली, 30 जनवरी।
vi. केंद्रीय बजट 2018–19 पैनलिस्ट, संवैधानिक क्लब, नई दिल्ली सीबीजीए, नई दिल्ली, 2 फरवरी को पैनल चर्चा।
vii. नीति जगत में शेष प्रासंगिक तथ्यों पर टीटीआई की 7 वीं क्षेत्रीय बैठक: थिंक टैंक, बीआरएसी सीडीएम सावर, ढाका सीपीडी, ढाका और बीआईजीडी की स्थिरता चुनौतियां, ढाका, 5–6 फरवरी।
viii. दिल्ली एजुकेशन इनिशिएटिव मीटिंग, दिल्ली, 7 फरवरी 2018.
ix. पांचवीं संस्थान बजट संगोष्ठी, लीला पैलेस, नई दिल्ली सीपीआर, आईसीआरआईईआर, आईडीएफ, एनसीएईआर, एनआईपीएफपी, 10 फरवरी 2018.
x. माउंटेन स्टेट VI: एसडीजी और आईएचआर पर चर्चा, भारत पर्यावास केंद्र, 12 फरवरी।
xi. ऑक्सफैम पैनल, 22 फरवरी।
xii. सोशल इंश्योरेंस पर गोलमेज बैठक, वर्ल्ड बैंक, लोदी रोड, वर्ल्ड बैंक, नई दिल्ली, 1 मार्च।
xiii. राजकोषीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का भविष्य: एक क्षेत्र व्यापी वार्तालाप, अंतरराष्ट्रीय बजट साझेदारी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए, 12–13 मार्च।
xiv. भूमि कानून, भूमि अधिग्रहण और भारत में अनुसूचित क्षेत्रों पर चौथा वार्षिक सम्मेलन, पैनलिस्ट, इंडिया इंटरनेशल सेंटर, नई दिल्ली, सीपीआर, 16 मार्च।

गोलमेज बैठकों और सम्मेलनों में प्रस्तुतिः

i. वार्ता, नियम बनाम जिम्मेदारियां? नीचे की ओर से राज्य क्षमता की चुनौती पर प्रतिबिंब, आईआईएम अहमदाबाद, 23 नवंबर।
ii. वार्ता, जवाबदेही पहलः सार्वजनिक व्यय पर नजर, एनआईपीएफपी, दिल्ली, 15 दिसंबर
iii. व्याख्यान, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, दिल्ली विश्वविद्यालय, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, दिल्ली विश्वविद्यालय, 18 जनवरी।

कार्य बल और कार्यकारी समूहों पर बैठकः

i. कार्यकारी समूह पंचायती राज।

2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अध्येता, अरकाजा सिंह, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :–

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. सीवर वर्कर्स डेथ्स : इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कॉन्ट्रेक्टर्स, डीजेबी के अधिकारियों की भूमिका, *हिंदुस्तान टाइम्स,* 2017

उल्लेखनीय गोष्ठी और सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण

i. पोंडिचेरी में दिसंबर 2017 को पोंडिचेरी विश्वविद्यालय और आईएफपी द्वारा आयोजित सामाजिक विज्ञान के शीतकालीन स्कूल में *अर्बन सेनिटेशन फ्रॉम ए रिवर पॉल्युशन परस्पेक्टिव* पर चर्चा।

ii. नई दिल्ली में दिसंबर 2017 को प्रणीति अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित 'मैनुअल स्केवेंजिंग' पर *कम्युनिटी एप्रोचेस टू सेनिटेशन : एक्सपीरिएंस फ्रॉम इम्प्लीकेशन* पर गोल मेज।

नीति निर्माताओं के साथ लक्षित बैठकें :

i. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 18 दिसंबर, 2017, 22 जनवरी और 8 फरवरी 2018 को ग्रामीण क्षेत्रों में मल स्लेज और सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) की आवश्यकता।

3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अध्येता अवनि कपूर निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थीं :–

पत्रिकाओं में लेख :

i. फिज़िकल ट्रांसफर्स बेस्ड ऑन इनपुट्स ऑर आउटकम्स? भारत में बारहवें और तेरहवें वित्त आयोग से पाठ, विक्टोरिया वाई. फान, स्मृति अय्यर, रिफायत महबूब, अनित मुखर्जी, द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट 2017, 1–18, 3 अगस्त 2017

नीति संक्षेप :

सरीन अंकुर, अम्बरीश डोंगरे और श्रीकांत वाद द्वारा अध्याय शीर्षक लागतें, मुआवजें और चुनौतियां, 2017, स्टेट ऑफ द नेशन : आरटीई, सेक्शन 12(1)(सी), अहमदाबाद : आईआईएम अहमदाबाद अम्बरीश डोंगरे के साथ सह–लेखक, अगस्त 2017.

i. बजट संक्षेप 2018–19 : स्वच्छ भारत मिशन – शहर (एसबीएम–यू) देवाशीष देशपांडे, अवनि कपूर, 3 फरवरी 2018.

ii. बजट संक्षेप 2018–19 : स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम–जी) अवनि कपूर, देवाशीष देशपांडे, 3 फरवरी 2018.

iii. बजट संक्षेप 2018–19 : मैनुअल स्वच्छकारों से पुनर्वास हेतु स्व रोजगार योजना (एसआरएमएस) देवाशीष देशपांडे, अवनि कपूर, 3 फरवरी 2018.

iv. बजट संक्षेप 2018–19 : सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) अवनि कपूर, मृदुस्मिता बोर्डोली, ऋत्विक शुक्ला, 3 फरवरी 2018.

v. बजट संक्षेप 2018–19 : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) अवनि कपूर, मृदुस्मिता बोर्डोली, ऋत्विक शुक्ला, 3 फरवरी 2018.

vi. बजट संक्षेप 2018–19 : प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) साहित्य वेंकटशन, अवनि कपूर, 3 फरवरी 2018.

vii. बजट संक्षेप 2018–19 : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अवनि कपूर, प्रेरणा नंदिता बैष्णब, 3 फरवरी 2018.

viii. बजट संक्षेप 2018–19 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) अवनि कपूर, परम चक्रवर्ती, 3 फरवरी 2018.

ix. बजट संक्षेप 2018–19 : एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) अवनि कपूर, प्रेरणा नंदिता बैष्णब, 3 फरवरी 2018

सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण :

i. यूएन विमैन द्वारा जून 2017 को आयोजित *रूल्स वर्सिस रिस्पोंसिवनेस, फिस्कल ट्रांसफर्स सोशल पॉलिसी एंड बिल्डिंग एन एकाउंटेबल स्टेट* पर आंतरिक संयुक्त राष्ट्र महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम

ii. दिल्ली में अगस्त 2017 को सीएलईएआर और जेपीएएल द्वारा आयोजित *मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन फॉर इंडियन इकॉनोमिक सर्विस (आईईएस) प्रोबेशनरी ऑफिर्स ऑन यूजिंग एविडेंस फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड एकाउंटेबिलिटी* पर दिल्ली पाठ्यक्रम।

iii. अहमदाबाद में अगस्त 2017 को आईआईएम द्वारा आयोजित आईआईएम अहमदाबाद ज्ञान संगोष्ठी – *'एविडेंस टू पॉलिसी एक्शन फॉर एलीमेंटरी एजुकेशन इन द कॉन्टेक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन (आरटीई)।*

iv. नोएडा में अक्टूबर 2017 को इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट द्वारा आयोजित आईएसडीएम छात्रों के लिए बिल्डिंग स्टेट कैपिसिटी पर 3 दिवसीय पाठ्यक्रम मॉड्यूल।

4. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुसंधान प्रोफेसर, भारत कर्नाड, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :–

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. एम्पेरर ज़ी एंड द कॉवटन इम्पेरेटिव, द क्विन्ट, 12 मार्च 2018

ii. द आर्म्स प्रोक्योरमेंट सिंड्रोम, ओपन मैग्जीन, 23 फरवरी 2018

iii. द वन थिंग मोदी शुड आस्क फ्रॉम ट्रडेयू वेन दे मीट; इट विल सेल्वेज एन अदरवाइस इनसिपिड विजिट, स्वराज्य, 23 फरवरी 2018

iv. टाइम टू इनसुलेट इंडिया – इरान टाइस, द सिटिजन, 22 फरवरी 2018

v. स्लेइट ऑफ हैंड : लॉकहैड मार्टिन टर्न्स एफ–16 इनटू एफ–35 एंड क्रिएट्स मार्केट्स वेयर देयर आर नॉन, द सिटिजन, 25 जनवरी 2018

vi. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ : टू बी ऑर नॉट टू बी, द सिजिटन, 9 जनवरी 2018

vii. हू इज द रीयल डिफेंस मिनिस्टर?, द सिजिटन, 20 दिसंबर 2017

viii. फॉरेन फाइटर जेट्स एरेना[टीएमटी] बैटर देन ऑल – इंडियन तेजस। पीरियड, द क्विन्ट, 14 नवंबर 2017

ix. अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड द एफ–16 : मैटिस हेज टू हार्डसेल दिस इशूज ऑन हिज विजिट टू इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, 22 सितंबर 2017

x. तेजस : पर्सनल फेयूड ऑर टेक्नीकल फ्लॉव, वाय वास तेजस रिजेक्टेड? द क्विन्ट, 19 सितंबर 2017

xi. द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, द क्विन्ट, 7 सितंबर 2017

xii. द डोकलाम स्टैंडऑफ : हॉट एंड कोल्ड एट द क्रीपिंग ट्राइ – जंक्शन, ब्लूमबर्ग क्विंट, 24 जुलाई 2017

xiii. द आर्म्स ऑफ अदर्स, इंडियन एक्सप्रेस, 17 जुलाई 2017

xiv. मोदी इन इजराइल : नीड फॉर मोर क्वाइटेबल डिफेंस कोलाबोरेशन, ब्लूमबर्ग क्विंट, 3 जुलाई 2017

xv. टाइम टू रिव्यू द हसनैन स्ट्रेटेजी इन कश्मीर इज नाव, स्वराज्य, 29 जून 2017

xvi. इज द इंडियन आर्मी रेडी फॉर द ए टू एंड हाफ फ्रन्ट वॉर? द इंडियन इकॉनोमिस्ट, 21 जून 2017

xvii. ए डीलमार्कर्स ड्रॉ, ओपन मैग्जीन, 16 जून 2017

xviii. इंडिया अनप्रीपेयर्ड फॉर अनसोलिसिटेड ऑफर टू प्ले पेसमेकर ऑन कश्मीर, ब्लूमबर्ग क्विंट, 4 मई 2017

xix. वाय अरुण जेटली एज डिफेंस मिनिस्टर आउट टू बी ए इंटरिम अरैंजमेंट, ब्लूमबर्ग क्विंट, 12 अप्रैल 2017

5. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रोफेसर ब्रह्म, चेलानी निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :–

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. वाय द साउथ चीन सी इज क्रिटिकल टू सिक्योरिटी, द जापान टाइम्स, 27 मार्च 2018

ii. बीजिंग क्वाइटली प्रेसेस एहैड विद इट्स एक्सपेसियोनिस्ट एजेंडा इन द साउथ चीन सी, द नेशनल, 26 मार्च 2018

iii. द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन शूड नॉ रिवर्ड इस्लामबाद फॉर इट्स लीज, हिंदुस्तान टाइम्स, 21 मार्च 2018

iv. चाइनाज स्टेल्थ वॉर्स इन द हिमालय, निककी एशियन रिव्यू, 20 मार्च 2018

v. ए चेलेंजिंग टाइम फॉर द इंडो – पैसिफिक, लाइव मिंट, 14 मार्च 2018

vi. ए न्यू ऑर्डर फॉर द इंडो–पैसिफिक, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 12 मार्च 2018

vii. चाइना इज एंसेयरिंग वलनरेबल स्टेट्स इन डिबेट ट्रैप्स, निककी एशियन रिव्यू, 1 मार्च 2018

viii. इंडिया मस्ट इम्पोज पनिशिंग सेक्शन्स ऑन द मालदीव, हिंदुस्तान टाइम्स, 21 फरवरी 2018

ix. इंडियाज चॉइस इन द मालदीव, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 20 फरवरी 2018

x. चाइना एंसनरेस वेलनरेबल स्टेट्स इन ए डिबेट ट्रैप निककी एशियन रिव्यू, 20 फरवरी 2018

xi. हाव कैन अमेरिका चेंज पाकिस्तान बिहेवियर? प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 30 जनवरी 2018

xii. रिपब्लिक डे 2018 ए लाइगेसी ऑफ रैश डिसिजन्स, डीएनए इंडिया, 29 जनवरी 2018

xiii. चाइनाडेमफ्रेंजी, द वॉशिंगटन टाइम्स, 17 जनवरी 2018

xiv. वॉटर शॉर्टेजेस पोज ए थ्रेट टू एशियास पीस एंड स्टेबिलिटी, निककी एशियन रिव्यू, 11 जनवरी 2018

xv. बाय डेंइंग रिव्यू वॉटर डेटा टू अस बीजिंग इज यूजिंग द रिसोर्स एज ए टूल ऑफ कोएर्सिव डिप्लॉमेसी, हिंदुस्तान टाइम्स, 10 जनवरी 2018

xvi. बीजिंग इन परसुइंग ए कॉम्प्लेस स्ट्रेटेजी टू कॉर्नर नेचुरल रिर्सोसेस, द नेशनल, 4 जनवरी 2018

xvii. वॉटर शॉर्टेजेस कुड ट्रिगर एशिया कॉनफ्लिक्ट्स, निककी एशियन रिव्यू, 4 जनवरी 2018

xviii. चाइना क्रेडिटर इम्पेरिलिज्म, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 22 दिसंबर 2017

xix. चाइना एक्शन्स रिस्क क्रिएटिंग ए कोएलिशन ऑफ डेमोक्रेटिक पावर्स, चाइना यूएस फोकस, 1 दिसंबर 2017

xx. रोहिंग्या मिलिटेंसी पोसेस ए रीजनल थ्रेट, जापान टाइम्स, 29 नवंबर 2017

xxi. डेमोक्रिएटिक फोर्सेस मस्ट जॉइन हैंड्स टू प्रोटेक्ट इंडो–पेसिफिक फ्रॉम चाइनाहेगेमोनी, हिंदुस्तान टाइम्स, 17 नवंबर 2017

xxii. एशिया न्यू एंटेंट, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 6 नवंबर 2017

xxiii. ज़ी न्यू स्ट्रेंथ ओब्सक्योर्स चाइना इंटर्नल रिस्क, जापान टाइम्स, 30 अक्टूबर 2017

xxiv. ए न्यू फ्रंट इन एशिया वॉटर वॉर, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 12 अक्टूबर 2017

xxv. ज़ी स्ट्रग्लिंग टू कीप द पीएलए इन लाइन? चाइना यूएस फोकस, 5 अक्टूबर 2017

xxvi. कॉलिंग पाकिस्तान एटेरोराइस्टेन इज नॉट इंफ, इंडिया मस्ट बैक इट विद् टफ एक्शन, हिंदुस्तान टाइम्स, 4 अक्टूबर 2017

xxvii. डेमोक्रेटिक पावर्स मस्ट इंटेंसिफाई इंडियन ऑशन कॉ–ऑपरेशन, निककी एशियन रिव्यू, 4 अक्टूबर 2017

xxviii. म्यांमार जिहादी कर्स, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 28 सितंबर 2017

xxix. डोकलाम स्टैंड ऑफ : पीएलए मे हेव बीन द थॉर्न इन ज़ी जिंपिंगा साइड, स्वराज्य, 7 सितंबर 2017

xxx. चाइना ट्रबल सम सिविल – मिलिटरी रिलेशन्स, जापान टाइम्स, 7 सितंबर 2017

xxxi. इंडिया, बियर : चाइना कुड सीक रिवेंज फॉर डोकलाम, निककी एशियन रिव्यू, 4 सितंबर 2017

xxxii. चीन पुश नेचुरल एलाइस इंडिया, जापान क्लोजर टू यूएस, द सनडे गार्डियन, 28 अगस्त 2017

xxxiii. चाइना इज वेजिंग ए वॉटर वॉर ऑन इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, 22 अगस्त

xxxiv. इन बीजिंस थिंकिंग, द बेपन डू नॉट विन टुडेज वॉर्स, बट द बेस्ट नेरेटिव डोज, द नेशनल, 21 अगस्त 2017

xxxv. चाइना वॉन्ट्स वॉर विद् इंडिया, मेक नॉ मिस्टेक, डेलीओ, 17 अगस्त 2017

xxxvi. कॉलिंग द चाइनीज ब्लाफ, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 11 अगस्त 2017

xxxvii. बाय रिफ्यूजिंग टू बकल अंडर थ्रेट्स ऑन डोकलाम, इंडिया एज कॉल्ड द ब्लफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, 3 अगस्त 2017

xxxviii. चाइना वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, लाइव मिंट, 1 अगस्त 2017

xxxix. चाइना वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 27 जुलाई

xl. वॉट चाइना हिमालयन वर्मोंगरिंग रिवील्स, द जापान टाइम्स, 25 जुलाई 2017

xli. लेट फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व ऑन इंडिया – चाइना बोर्डर, द सनडे गार्डियन, 24 जुलाई 2017

xlii. डोकलाम स्टैंड ऑफ : इंडिया मस्ट बी रीड टू गिव चाइना ए रियल ब्लडी नॉज, हिंदुस्तान टाइम्स, 24 जुलाई 2017

xliii. चाइनाज भुटान लैंड ग्राब एम्स एट बिगर टारगेट, निककी एशियन रिव्यू, 12 जुलाई 2017

xliv. इट्स टाइम इंडिया यूज्ड इट्स मोस्ट पावरफुल वेपन एगेंस्ट चाइना ट्रेड, हिंदुस्तान टाइम्स, 29 जून 2017

xlv. इंडियाज इनवर्ड न्यूक्लियर टर्न : इट हेज टेकन 12 इयर्स फॉर द इंडो – यूएस न्यूक्लियर डील हाइप टू गिव वे टू सोबर रिलिज्म, टाइम्स ऑफ इंडिया, 22 जून 2017 – दोपहर 12.30 बजे।

xlvi. 'होमग्रोन' पावर प्लान विल बूस्ट इंडियन न्यूक्लियर इंडस्ट्री, निककी एशियन रिव्यू, 16 जून 2017 – 1.05 बजे

xlvii. काउंटरिंग चाइना हाइ – एल्टिटुड लैंड ग्रैब, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 16 जून 2017 – दोपहर 1.02 बजे

xlviii. द एज ऑफ ब्लॉबैक टेरर, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 8 जून 2017 – दोपहर 12.27 बजे

xlix. वलेदिमर पुटिना जियोपॉलिटिकल चेसबॉर्ड, जापान टाइम्स, 6 जून 2017 – सुबह 11.45 बजे

l. रेवाइटलाइजिंग इंडिया – रशिया टाइस ए चैलेंज फॉर मोदी, हिंदुस्तान टाइम्स, 2 जून 2017 – दोपहर 2.22 बजे

li. वाय सिस्टमेटिकली डिसक्रेडिटिंग द आइडियोलॉजी बिहाइंड जिहाडिस्ट टेरर होल्ड्स द की टू काउंटरटेररिज्म सक्सेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, 29 मई 2017

lii. चाइना इम्पेरियल ओवररीच, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 25 मई 2017

liii. चाइना – पाकिस्तान वॉटर पिंसर अगेंस्ट इंडिया : एज पार्ट ऑफ सीपीईसी, मेगा – डैम्स आर प्लान्ड इन गिलगिट – बाल्टिस्टन, इकॉनोमिक टाइम्स, 17 मई

liv. अमेरिका डीपनिंग अफगानिस्तान क्वागमर, निककी एशियन रिव्यू, 12 मई 2017

lv. एशियस अमेरिकन मेनेस, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, 26 अप्रैल 2017

lvi. रोग नेबर न्यू रोग एक्ट, डीएनए इंडिया, 18 अप्रैल 2017

6. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मानद अनुसंधान प्रोफेसर जी पार्थसारथी, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :–

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. फॉस्टरिंग ए स्पेशल रिलेशनशिप, हिंदु बिजनेस लाइन, 22 मार्च 2018

ii. पाकिस्तानी राइटर मेहर तरार टॉक्स आबउट द फ्रेल्टाइस एंड क्वालिटीज ऑफ हर होम कंट्री, इंडिया टुडे, 19 मार्च 2018

iii. टरमॉइल एंड न्यू एलाइनमेंट्स इन इस्लामिक वर्ल्ड, द इंडियन एक्सप्रेस, 19 मार्च 2018

iv. पाक मे पे प्राइज फॉर स्पोंसरिंग टेरर, बिजनेस लाइन, 8 मार्च 2018

v. एशियन : द राइट वे अहैड फॉर इंडिया, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 5 मार्च 2018

vi. शरीफ मैनी हिट्स एंड मिसेस, बिजनेस लाइन, 22 फरवरी 2018

vii. फ्री अफगानिस्तान फ्रॉम तालिबान ग्रिप, बिजनेस लाइन, 8 फरवरी 2018

viii. एशियन : द राइट वे अहैड फॉर इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, 5 फरवरी 2018

ix. इंडिया फॉरेन पॉलिसी ऑन शो, हिंदु बिजनेस लाइन, 25 जनवरी 2018

x. पाकिस्तान अर्मी डोमिनेशन मार्क्स जाधव केस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 16 जनवरी 2018

xi. ट्रम्प ट्वीट्स, पाकिस्तान डेफिस, हिंदु बिजनेस लाइन, 11 जनवरी 2018

xii. द चाइनीज रोड टू डस्टी डेबिट, हिंदु बिजनेस लाइन, 28 दिसंबर 2017

xiii. इंडियाज अनइजी स्टैंड विद् चाइना एंड रशिया, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 26 दिसंबर 2017

xiv. द यूएस एंड इट्स एंटी – टेरिज्म नरेटिव, हिंदु बिजनेस लाइन, 14 दिसंबर 2017

xv. चाइना वूस म्यांमार एट द कोस्ट ऑफ इंडिया, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 11 दिसंबर 2017

xvi. पाकिस्तान फेसेस आइसोलेशन एंड अनसर्टेनिटी, हिंदु बिजनेस लाइन, 23 नवंबर

xvii. डीलिंग विद् चाइना नेवल एसेर्टिवेनेस, हिंदु बिजनेस लाइन, 16 नवंबर 2017

xviii. अवेयर द चाइना – पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्सिस, हिंदु बिजनेस लाइन, 2 नवंबर 2017

xix. बिग स्टेप, बट नो अर्ली सोल्यूशन्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, 25 अक्टूबर 2017

xx. रिजनल प्रायोरिटीज चेंज एज बीआईएमएसटीईसी रिप्लेसेस सार्क, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 16 अक्टूबर 2017

xxi. द रोहिंग्यास पोज ए रिजनल चैलेंज, हिंदु बिजनेस लाइन, 5 अक्टूबर 2017

xxii. इंडिया कैन इगनोर वॉयलेंस – टॉर्न इस्लामिक जे एंड के रिजोल्यूशन, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, वेडनेसडे, 4 अक्टूबर 2017

xxiii. टाइस डैट बाइंड, द ट्रिबुन, 22 सितंबर 2017

xxiv. रिविजिटिंग स्ट्रेटेजी इन द इंडो – पेसिफिक, हिंदु बिजनेस लाइन, 21 सितंबर 2017

xxv. द वे अराउंड चाइना, द ट्रिबुन, 18 सितंबर 2017

xxvi. ब्लॉबैक एज ट्रम्प गोज बालेस्टिक, हिंदु बिजनेस लाइन, 7 सितंबर 2017

xxvii. इंडिया स्टैंड्स फर्म, चैलेंजेस चाइनीज हिजिमनी इन एशिया, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 4 सितंबर 2017

xxviii. चाइना रीचिंग एज फर एज इट कैन गो, हिंदु बिजनेस लाइन, 24 अगस्त 2017

xxix. डोंट एलाउ पाकिस्तान टू गेट अवे विद फॉल्स प्रोमिसेस नाव, इकॉनोमिक टाइम्स, 24 अगस्त 2017

xxx. पाकिस्तान फाइंड्स इट्सेल्फ इन ए पॉलीटिकल पिकल ओवर द पल्ट्री सम ऑफ डॉलर 2,700, डेली मेल, 14 अगस्त 2017

xxxi. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिथर्स, द ट्रिबुन, फ्राइडे, 11 अगस्त 2017

xxxii. इंडिया वेल – टाइम्ड लुक वेस्टा पॉलिसी, हिंदु बिजनेस लाइन, 27 जुलाई 2017

xxxiii. मोदी गवर्नमेंट बॉर्डर पॉलिसी एपेयर्स टू हेव रैटल्ड चाइना, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 24 जुलाई 2017

xxxiv. चेंज द कश्मीर नरेटिव, द ट्रिबुन, 13 जुलाई 2017

xxxv. यूएस सेंक्शंस ऑन सलाहुद्दीन थ्रेटन कश्मीरी सेपरेटिस्ट्स, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 10 जुलाई 2017

xxxvi. न्यू कैमिस्ट्री टू इंडो–यूएस टाइस एज मोदी एंड ट्रम्प डेफ्टली हैंडल पोटेंशियली डिवाइजिव इशूस, डेली मेल, 30 जून 2017

xxxvii. वॉच आउट फॉर पाक आर्मी ग्रोविंग क्लाउट, हिंदु बिजनेस लाइन, 29 जून 2017

xxxviii. इंडिया कंर्सन्ड एज टेंशन्स राइज बिटवीन गोल्फ मोनर्कीस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 27 जून 2017

xxxix. कोपिंग विद द चाइना फैक्टर इन म्यांमार, हिंदु बिजनेस लाइन, फ्राइडे, 16 जून 2017

xl. मोदी स्कोर्स विद हिज पर्सनल स्टैम्प ऑन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 12 जून

xli. लेट बी वरी ऑफ चाइना न्यू सिल्क रोड, हिंदु बिजनेस लाइन, 1 जून

xlii. रेटल्ड पाकिस्तान विल पे ए हेवी प्राइज इफ इट चूसेस टू डेफी आईसीजे, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 29 मई 2017

xliii. विल नवाज शरीफ विल्ट अंडर प्रेशर? हिंदुस्तान टाइम्स, 18 मई 2017

xliv. चाइना डोमिनेंस एट एशियन बैड फॉर इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, वेडनेसडे, 17 मई 2017 – दोपहर 1.33 बजे

xlv. राइवलरीज़ शार्पेनिंग इन अफगानिस्तान, हिंदु बिजनेस लाइन, 4 मई 2017

xlvi. इंडिया रिमेन्स अनटच्ड बाय द टर्मोइल इन इस्लामिक वर्ल्ड, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 1 मई 2017

xlvii. वेन द दलाई लामा विजिटेड तवांग, हिंदु बिजनेस लाइन, 20 अप्रैल 2017

xlviii. अफगानिस्तान सिमर्स एज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिथर्स, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 18 अप्रैल 2017

xlix. रिटर्न ऑफ द स्टोनिंग सीजन इन कश्मीर, हिंदु बिजनेस लाइन, 6 अप्रैल 2017

l. सुकयी सीक्स एथनिक पीस एज इंसरजेंट्स स्टेप अप प्रेशर्स, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, वेडनसडे, 5 अप्रैल 2017

7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसंधान प्रोफेसर, लवण्या राजमणि, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थीं :–

पुस्तकें :

i. *इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज लॉ,* डेनियल बोडनस्की और जट ब्रॉनी, ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा सह–लेखक, 25 मई 2017

संपादित संस्करणों में अध्याय :

i. डेनियल क्लेन, मेरिया पिया कैरैजो, मेइंहार्ड डोइल, जान बुलमर और एंड्रू हिघम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा सह–संपादित सेंट्रल कंसेप्ट्स इन द पेरिस एग्रीमेंट एंड हाव देयर एवॉल्वड एम्मानुएल गेएरिन, *द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेंट चेंज : एनालायसिस एंड कॉमेंटरी,* 20 जुलाई 2017.

ii. डेनियल क्लेन, मेरिया पिया कैरैजो, मेइंहार्ड डोइल, जान बुलमर और एंड्रू हिघम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा सह–संपादित गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड जनरल ऑब्लिगेशन (आर्टिकल 2.2 एंड आर्टिकल 3), *द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेंट चेंज : एनालायसिस एंड कॉमेंटरी,* 20 जुलाई 2017.

पत्रिकाओं में लेख :

i. इंडियास एप्रोच टू इंटरनेशनल लॉ इन द क्लाइमेंट चेंज रेजीम, इंडियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ 57 (1–2), 29 जनवरी 2018.

ii. द लीगेलिटी ऑफ डाउनग्रेडिंग नेशनली डिटरमाइन्ड कंट्रीब्यूशन्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट : लोशन्स फ्रॉम द यूएस डिसइंगेजमेंट, जट ब्रूनी, जर्नल ऑफ एनवार्यनमेंट लॉ 29 (3), 1 नवंबर 2017.

नीति संक्षेप :

i. मई 2017 में यूएनएफसीसीसी 2018 सुविधात्मक वार्ता, जलवायु और ऊर्जा समाधान केंद्र (सी2ईएस) नीति संक्षेप की संरचना

ii. पेरिस समझौते का विस्तार : कार्यान्वयन और अनुपालन, जलवायु और ऊर्जा समाधान केंद्र (सी2ईएस) नीति संक्षेप, नवंबर 2017

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. पेरिस क्लाइमेट डील : ट्रम्प इज ऑन रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिक्स एंड प्लानेट, *लाइव मिंट,* 2 जून 2017

वेब–आधारित प्रकाशन :

i. लैंडमार्क क्लाइमेट एग्रीमेंट होल्ड्स इट्स ऑन, डेनियल बोडांस्की, जट ब्रूनी, *ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ब्लॉग (ओयूपी ब्लॉग),* 3 जुलाई 2017

ii. रिफ्लेक्शन्स ऑन द यूएस विद्ड्रॉवल फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेंट चेंज एग्रीमेंट, *ब्लॉग ऑफ द यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ* (ईजेआईएल : टॉक!), 5 जून 2017

iii. द यूएस एंड द पेरिस एग्रीमेंट : इन ऑर आउट एंड एट वॉट कोस्ट? *ब्लॉग ऑफ द यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ* (ईजेआईएल : टॉक!), 10 मई 2017

iv. लेव क्यू एंड ए ऑन ट्रम्प एनाउंसमेंट ऑन यूएस विद्ड्रॉवल फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, *सीपीआर ब्लॉग,* 2 जून 2017

सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण :

i. हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, बर्लिन (जर्मनी) द्वारा जून 2017 में आयोजित *रिफ्लेक्शन्स ऑन द यूएस डिसिजन टू विद्ड्रॉ फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट : बेटर आउट देन ट्रम्प?* पर ''द इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉग – राइज ऑर डिक्लाइन?'' बर्लिन / पॉट्सडैम रिसर्च ग्रूप के लिए अतिथि अध्येतावृत्ति के भाग के रूप में प्रस्तुतीकरण।

ii. बर्लिन (जर्मनी) में जून 2017 को जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायर्नमेंट द्वारा आयोजित *द लीगलिटी ऑफ डाउनग्रेडिंग नेशनली डिटरमाइन्ड कंट्रीबुशन्स इन द पेरिस एग्रीमेंट* पर जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायर्नमेंट में प्रस्तुतीकरण।

iii. हॉबर्ट में 9 फरवरी 2018 को यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित *इक्विटी एंड डिफरेंशिएशन इन द 2015 पेरिस एग्रीमेंट* पर इमर्जिनिंग द डिफरेंट फ्यूचर : अवरकमिंग बेरियर्स टू क्लाइमेंट जस्टिस।

iv. टोक्यो, जापान में 24–25 फरवरी 2018 को सी2ईएस (सेंटर फॉर क्लाइमेंट एंड एनर्जी सोल्यूशन्स) द्वारा आयोजित नेगोशिएटर्स वर्कशॉप (सी2ईएस), जनरल इशूस इन द एलेबोरेशन ऑफ द पेरिस रूलबुक।

v. नई दिल्ली, भारत में 15 जनवरी 2018 को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा आयोजित एनएलयू, दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी डिलिस्टीडिडेल कैम्पनिया ''लुइगी वानविटेली'', विंटर स्कूल द इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज रिजीम।

vi. विमैन्स एनर्जी एंड क्लाइमेट लॉ नेटवर्क का शुभारंभ, द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न विमैन्स एनर्जी एंड क्लाइमेट लॉ नेटवर्क द्वारा 8 दिसंबर 2017 को आयोजित 'द पेरिस एग्रीमेंट एंड द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेंट लॉ' पर वार्ता।

vii. बॉन, जर्मनी में 12 नवंबर 2017 को सी2ईएस (सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी सोल्यूशन्स) द्वारा आयोजित बोन, जर्मनी, कम्पलीटिंग द पेरिस आर्किटेक्चर : कम्पलाइनेस एंड इम्पलीमेंटेशन में सीओपी – 23 गोल मेज सम्मेलन।

viii. एडवांसिंग लॉ एंड गवर्नेंस कंट्रीब्युशन्स टू क्लाइमेट एक्शन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट : फिजी / बोन क्लाइमेट लॉ एंड गवर्नेंस डे 2017, ग्लोबल क्लाइमेट रिजिम : कंटेक्स्ट, कनेक्शन्स एंड करंट इशू, विद द लॉन्च ऑफ ओयूपी बुक इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज लॉ यूनिवर्सिटी फोरम, हेसली 18–24, 53113 बोन, जर्मनी (सीओपी 23), यूनिवर्सिटी ऑफ बोन, 10 नवंबर 2017

ix. सी2ईएस (सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी सोल्यूशन्स) द्वारा 19 अक्टूबर 2017 को आयोजित नेगोशिएटर्स वर्कशॉप (सी2ईएस), एलबोरेटिंग द पेरिस एग्रीमेंट : इम्प्लीकेशन एंड कॉम्पलाइनेस नेडी, फिजी।

पुरस्कार और अन्य सम्मान :

i. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम, जुलाई 2017 में परास्नातक के लिए संकाय।

8. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अध्येता किरण भट्टी, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थीं:–

पत्रिकाओं में लेख :

i. राधिका सरफ और वृंदा गुप्ता द्वारा लिखित आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सम इनसाइट्स ऑन वॉट वी नॉ एंड वॉट वी डू नोट, *इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल 52. इशू 49,* 9 दिसंबर 2017

संपादित संस्करणों में अध्याय :

i. द गवर्नेंस आर्टिटेक्चर ऑफ मॉनिटरिंग एलीमेंटरी एजुकेशन इन इंडिया : द केस फॉर कम्युनिटी – बेस्ड रिफॉर्म, *ऑक्सफोर्ड रिसर्च एंकाइक्लोपीडिया ऑन एजुकेशन,* मैथ्यु हैरिस, गीता नम्बिसन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2018

ii. अविनाश कुमार सिंह, सेग, 2018 द्वारा सह– लेखक पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द राइट टू एजुकेशन : द स्कोप फॉर सिटिजन मॉनिटरिंग, *राइट टू एजुकेशन : ऑर्च्युनिटीज एंड चेलेंजीस,*

नीति संक्षेप :

i. अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, नवंबर 2017 की समीक्षा

गैर–समीक्षित पत्रिकाओं में लेख

i. मिड – डे मील्स एंड बायोमेट्रिक्स : ए होबसन चॉइस फॉर चिल्ड्रन दीपा सिंह, *हिंदुस्तान टाइम्स,* 16 मार्च 2017.

वेब–आधारित प्रकाशन :

i. पब्लिक वर्सिस प्राइवेट प्रोविजन ऑफ लीमेंटरी एजुकेशन : चेलेंजेस फेसिंग द राइट टू एजुकेशन इन इंडिया, *ऑक्सफॉर्ड ह्यूमन राइट्स हब,* मार्च 2018

ii. मिडडे मील्स एज ए फ्रॉम ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन एजुकेशन, द इम्पैक्ट ऑफ बायोमेट्रिक्स इन इट्स प्रोविजन, *योजना,* 13 जून 2017

iii. फ्रॉम ब्लैकबोर्ड टू डिजिटल बोर्ड : बजट एंड इट्स इम्प्लीकेशन्स फॉर द एजुकेशन सेक्टर, *योजना,* 14 फरवरी 2018

iv. एजुकेशन एंड द बजट, *द वायर,* 2 फरवरी 2017

v. ए बजट डैट प्रोमिसेस ए ग्रेट फ्यूचर बट डोज लिटल टुडे, *द वायर,* 1 फरवरी, 2018

vi. वाय सीबीएसई पेपर लीक रिफ्लेक्ट्स कॉलेप्स ऑफ इंस्टीट्यूट, *डेलीओ,* 3 मार्च 2018

सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण के लिए शोध पत्र प्रस्तुत करना :

i. सिंगापुर में मार्च 2018 को ली क्वान येव स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी द्वारा आयोजित सार्वजनिक प्रबंधन अनुसंधान सम्मेलन (पीएमआरसी) डोज गवर्नेमेंट मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल्स वर्क? ए स्टडी ऑफ द फ्रंटलाइन एजुकेशन ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया।

ii. बैंगलोर में 26 मार्च 2018 को नेशनल लॉ स्कूल (एनएलएसआईयू) द्वारा आयोजित सत्र की अध्यक्षता में 'इम्पलीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट – स्टेट्स, इशूस एंड चेंलेंजेस पर राष्ट्रीय चर्चा बैठक।

सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण :

i. व्याख्यान, शासन विषय, मुंबई, टीआईएसएस, 18 मई 2017

ii. प्राथमिक शिक्षा में व्याख्यान, शासन, उत्तरदायित्व और गुणवत्ता, दिल्ली, गार्गी कॉलेज, 14 सितंबर 2017

iii. मुख्य नोट वक्ता, भारत में राज्य प्राथमिक शिक्षा, नेशनल डिफेंस कॉलेज, 17 जनवरी 2018

iv. व्याख्यान, गुणवत्ता शिक्षा : राज्य बनाम निजी क्षेत्र, दयाल सिंह कॉलेज, 13 मार्च 2018

कार्य बल और कार्य समूह पर बैठक :

i. विभागीय सलाहकार समिति, एनयूईपीए, सदस्य, फरवरी 2018

ii. हरियाणा में जेंडर और शिक्षा पर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक स्टडी के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति।

9. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परियोजना निदेशक मंजू मेनन, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थीं :–

गैर–समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. ऑफ द फ्रिक्शनलेस डेवलपमेंट : पोर्ट्स हेव द पोटेंशियल टू एंडाएंगर द एनवायर्नमेंट, कांची कोहली और मंजु मेनन, *डीएनए इंडिया,* मई 2017

ii. कीपिंग सिविल सोसायटी एट बे हर्ट्स क्लाइमेट रेड्रेसल प्रोस्पेक्ट्स, मंजू मेनन और कांची कोहली, *डीएनए इंडिया,* जून 2017

iii. फर्म्स ऑफेन अंडरस्टेट ग्रीन इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, कांची कोहली और मंजु मेनन, *डीएनए इंडिया,* जून 2017

iv. हव ग्राम सभा डिससेंट इज क्रशड अंडर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, कांची कोहली और मंजु मेनन, *डीएनए इंडिया,* जुलाई 2017

v. वेटलैंड्स वेन रियालिटी स्ट्राइक्स : सुप्रीम कोर्ट फाइन्स एनवायर्नमेंट मिनिस्ट्री फॉर नॉट फोलोविंग डायरेक्शन्स, मंजू मेनन और कांची कोहली, इंडिया टुडे, जुलाई 2017

vi. पासिंग ऑन रेगुलेटरी बर्डन्स टू पीपल इज रेसिपी फॉर डिजास्टर, कांची कोहली और मंजु मेनन, *डीएनए इंडिया,* अगस्त 2017

vii. स्टेट रेगुलेशन इज लेजिटिमाइसिंग अनफिसिबल वॉटर मिनिंग, कांची कोहली और मंजु मेनन, *डीएनए इंडिया,* सितंबर 2017

viii. वाय द कोर्ट्स एंड द एमओईएफ आर ऑन ए कोलिजन कोर्स, कांची कोहली और मंजु मेनन, *डीएनए इंडिया,* सितंबर 2017

ix. द टेरिबल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लैंड गवर्नेंस इन इंडिया, मंजू मेनन और कांची कोहली, *डीएनए इंडिया,* सितंबर 2017

x. फाउल एयर : थर्मल पावर मोर टू ब्लेम दैन क्रेकर्स, मंजू मेनन और कांची कोहली, *डीएनए इंडिया,* अक्टूबर 2017

xi. द सेग ऑफ इंडियन माइनिंग : द लॉन्ग लाइनेज ऑफ इलीगेलिटी, मंजू मेनन और कांची कोहली, *डीएनए इंडिया,* अक्टूबर 2017.

xii. इज इजी ऑफ डुइंग बिजनेस अंडरमाइनिंग ग्रीन नॉर्म्स, मंजू मेनन और कांची कोहली, *डीएनए इंडिया,* अक्टूबर 2017

xiii. कम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन स्कीम्स आर ए केरेड, मंजू मेनन और कांची कोहली, *डीएनए इंडिया,* अक्टूबर 2017

xiv. रेगुलेटरी एफर्ट्स मे पुश ग्राउंडवॉटर बियॉन्ड रिच, मंजू मेनन और कांची कोहली, *डीएनए इंडिया,* अक्टूबर 2017

xv. पॉलिटिकल लीडरशिप फैल्ड इंडियास एनवायर्नमेंट इन 2017, मंजू मेनन और कांची कोहली, *डीएनए इंडिया,* अक्टूबर 2017

xvi. राइजिंग द बार ऑन डेमोक्रेसी एंड एनवायर्नमेंट, कांची कोहली और मंजु मेनन, *डीएनए इंडिया,* 1 जनवरी 2018

xvii. एंगेजिंग द पब्लिक टू इम्प्रूव एनवायर्नमेंटल कॉमप्लाइंस, कांची कोहली और मंजु मेनन, *डीएनए इंडिया,* 15 जनवरी 2018

xviii. लीगल एम्बिग्विटीस स्टाइमी रेड्रेस ऑफ एनवायर्नमेंटल हार्म, कांची कोहली और मंजु मेनन, *डीएनए इंडिया,* 29 जनवरी 2018

xix. कंफ्लिक्ट्स ब्रेक आउट एज इंस्टीट्यूट टेक ओवर कोस्टल लैंड्स, कांची कोहली और मंजु मेनन, *डीएनए इंडिया,* 14 मार्च 2018

xx. गवर्नमेंट मस्ट टेक ए रिलुक एट इट्स फॉरेस्ट पॉलिसी, कांची कोहली और मंजु मेनन, *डीएनए इंडिया,* 27 मार्च 2018.

वेब आधारित प्रकाशन :

i. प्रोपोज्ड एमेंडमेंट्स टू एनवायर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कुड लीगलाइज वॉयलेशन्स, मंजू मेनन, कांची कोहली, कार्तिक दिनेश और देबायण गुप्ता, *द वायर,* अगस्त 2017.

ii. इन स्टेट – लेवल चेंजेस टू लैंड लॉ, रिटर्न टू लैंड ग्रेबिंग इन डेवलपमेंट्स नाम मंजू मेनन, कांची कोहली और देबायण गुप्ता, *द वायर,* सितंबर 2017.

iii. सीआरजेड रिव्यू, बीगन इन 2014, अनलीश्ड स्टेट गर्व. एस्पिरेशन टू लूजन कोस्टल रेगुलेशन, काउंटरव्यू, अप्रैल 2017

iv. हाव इच रिव्यू / रिविजन ऑफ द सीआरजेड नॉटिफिकेशन, 2011 ऑनली डायलुटेड इंडियास कोस्टल रेगुलेशन, काउंटरव्यू, मई 2017.

v. वी डिड नॉट कंसल्ट एनबडी अदर देन स्टेट गर्व. एंड यूटी : डॉ. शैलेश नायक ऑन सीआरजेड रिव्यू, काउंटरव्यू, मई 2017.

vi. पार्टिसिपेटरी रिव्यू ऑफ एमसीआरजेड नॉटिफिकेशन क्रिटिकल : चेंजेस विल डायरेक्टली इफेक्ट 3200 मेरिन विलेज, काउंटरव्यू, मई 2017.

vii. ड्राफ्टेड इन सेक्रेसी, इंडियाज न्यू कोस्टल रुल्स एनेबल मोर टुरिज्म, हाउसेस क्लोजर टू शोर,, मई 2017.

नीति संक्षेप :

i. पैरालीगल्स फॉर एनवार्यनमेंटल जस्टिस (वर्सन 2.0) ईजे टीम, 4 जनवरी 2018

ii. अराउंड द लैंडफिल साइट्स : ए ग्राउंडट्रथिंग ऑफ सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट लॉ एक्रॉस लैंडफिल साइट्स इन कोस्टल एरियास ऑफ उत्तरा कन्नाड डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक, इजे टीम, मार्च 2018

iii. क्लोजिंग द इंफॉर्सेमेंट गैप : ग्राउंडट्रथिंग एनवायर्नमेंट वॉयलेशन्स इन सुंदरगढ़, ओडिशा सीआईआरटीडी, सीपीआर – नमति ईजे टीम, मार्च 2018

iv. रेगुलेशन फॉर ग्राउंडवॉटर एब्सट्रेक्शन, इजे टीम, मार्च 2018

v. सरफेस वॉटर : यूजिंग लॉ टू कॉम्बेट वॉटर पोलुशन, ईजे टीम, मार्च 2018

vi. मार्किंग द लॉ काउंटर – टेन एनवार्यनमेंट जस्टिस स्टोरीस बाय कम्युनिटी पैरालीगल्स इन इंडिया, ईजे टीम, मार्च 2018

vii. सरफेस वॉटर : यूजिंग लॉ टू कॉम्बेट वॉटर पोलुशन, ईजे टीम, मार्च 2018

viii. मैकिंग द लॉ काउंट – टेन एनवायर्नमेंट जस्टिस स्टोरीज बाय कम्युनिटी पैरालीगल्स इन इंडिया, ईजे टीम, मार्च 2018

10. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अध्येता नवरोज के दुबाश, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :–

पत्रिकाओं में लेख :

i. क्लाइमेट चेंज : ए हिस्ट्री एंड रिव्यू पर अंतर सरकारी पैनल। एनवायर्नमेंट एंड रिसोर्सेस की समीक्षा, एम. वर्दी, एम. ओपेहेइमर, एन. के. दुबेश, जे. ओ' रेली जे. एंड डी. जेमियसन, द्वारा सह–लेखक, *वार्षिक रिव्यू ऑफ एनवायर्नमेंट एंड रिसोर्सेस 42(1),* अक्टूबर 2017

ii. मल्टी क्राइटेरिया डिसिजन एनालायसिस इन पॉलिसी – मेकिंग फॉर क्लाइमेट माटीगेशन एंड डेवपलमेंट कोहेन, बी. ब्लेंको, एच. दुबेश, एन. के., दुक्कीपति, एस., खोसला आर, स्क्रिसियू, एस. स्टेवर्ट, टी. एंड टोरेस – गनफौस, एम., *क्लाइमेट एंड डेवपलमेंट,* मार्च 2018

गैर–समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. ट्रम्पिंग द क्लामेटिक, *द हिंदु,* जून 2017

ii. इंडिया मस्ट रिएफर्म इट्स पेरिस प्लेज, *द हिंदु,* अप्रैल 2017

सम्मेलन / संगोष्ठी में प्रस्तुतीकरण :

स्पेन में 2–5 अप्रैल 2017 को ऊर्जा अनुसंधान सामाजिक विज्ञान द्वारा आयोजित 'द ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ ''नेशनली डिर्टमाइन्ड कंट्रीबुशन्स'' : रिटर्निंग नेशनल एनर्जी पॉलिटिक्स टू सेंटर स्टेज' पर ऊर्जा अनुसंधान और सामाजिक विज्ञान।

i. मुंबई, महाराष्ट्र में 4–5 अगस्त 2017 तक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा आयोजित क्लाइमेट चेंज एट टीआईएसएस : क्लाइमेट एक्शन : मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन इन ए पोस्ट पेरिस वर्ल्ड इंटरनेशनल नेगोशिएशन्स एंड डोमेस्टीक क्लाइमेंट एक्शन इंटरकनेक्शन्स एंड कंटेस्टेशन्स विदइन एंड आउटसाइड द पेरिस एग्रीमेंट पर 8वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।

ii. भारतीय राज्य, बेलगम, कर्नाटक, इंडिपेंडेंट पावर प्रोडुसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में 27 अक्टूबर 2017 को रेगुलेटर्स एंड पॉलिसीमेकर्स रिट्रीट 2017 (आईपीपीएआई) ऑन मेपिंग पावर : द पॉलिटीकल इकोनॉमी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।

iii. स्थायित्व पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 4, स्थानीय संदर्भ एजवाल में जलवायु परिवर्तन को समझना, मिजोरम, एकीकृत पर्वतीय पहल, और मिजोरम सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन, मुख्य संबोधन, 21 सितंबर 2017.

iv. भारत – ईयू जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा सम्मेलन 2017 एन आईएनडीसी वर्ल्ड में भारत के निम्न उत्सर्जन मार्गों का विवरण, नई दिल्ली, स्थिर विकास के लिए सीआईआई – आईटीसी उत्कृष्टता केंद्र, सत्र में वक्ता, 6–7 सितंबर 2017.

v. आईसीएस बातचीत : रिसेंट डेवपलमेंट इन चाइना – यूएस रिलेशन्स एंड देयर इम्पैक्ट – पैनल चर्चा, नई दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज एंड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, पैनलिस्ट, 22 अगस्त, 2017.

vi. विधि संवाद : इंडिया इन द पेरिस एग्रीमेंट : रेमिफिकेशन्स ऑफ द यूएस विद्ड्रॉवल – पैनल चर्चा, नई दिल्ली, विधि : सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, पैनलिस्ट, 5 जुलाई, 2017.

vii. मिटिगेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट स्टेबिलाइजेशन सीनेरियोस, सोशल चेंज पर आईपीसीसी विशेषज्ञ बैठक, इंस्टीट्यूशन्स एंड पॉलिसीस, एडिस एबाबा, क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) पर अंतर सरकारी पैनल, पैनलिस्ट, 27 अप्रैल, 2017.

viii. क्लाइमेंट डिप्लोमेसी : इनोवेटिव एप्रोचेस फॉर ए क्लामेट –रिसाइलेएंट, लॉ – कार्बन फ्यूचर इन इंडिया एंड यूरोप पर विश्व पुस्तक मेले में पैनल चर्चा – नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर ईयू – भारत पैनल चर्चा, 10 जनवरी 2018

ix. 'क्लाइमेट चेंज नाव : स्टोरीस ऑफ 21 सेंचुरी कार्बन कोलोनिलाइज्म' पर सीएसई पुस्तक का विमोचन, क्लाइमेट पॉलिसी, एनवायर्नमेंटल डिग्रेडेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड अनवेयरनेस टू गेट ए बैटर डील इन क्लाइमेट नेगोशिएशन्स पर पैनल चर्चा, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायर्नमेंट, 11 जनवरी 2018.

x. ब्राउन बैग लांच – पॉलिटिकल इकोनॉमी डबल बिल, द पॉलिकल इकॉनोमी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडियास स्टेट्स, वॉशिंगटन डी. सी., वर्ल्ड बैंक, 1 फरवरी 2018.

xi. 'ड्राइविंग सब नेशनल लीडरशिप ऑन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया' पर गोल मेज सम्मेलन, भारतीय राज्यों में बिजली की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नई दिल्ली, द क्लाइमेट ग्रुप, 16 फरवरी 2018

xii. असम, दिसपुर, असम विधानसभा में 27 फरवरी 2018 को जलवायु परिवर्तन के लिए पर्यावरण और विकास प्रतिक्रिया के संरक्षण के माध्यम से स्थिर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा के सदस्यों के साथ स्थिर विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर बातचीत।

xiii. 'क्रिएटिंग इंडियास फस्ट फिलैंथ्रोपिक कोलेबोरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर गोल मेज सम्मेलन, मुंबई, ल्यूमेन परामर्श, 12 मार्च 2018

कार्य बल और कार्यकारी समिति पर बैठक :

i. ''लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर लो कार्बन डेवलपमेंट फॉर इंडिया'' पर विशेषज्ञ समिति, फरवरी 2017 को पेश।

ii. भारत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा अधिनियम और / या नवीकरणीय ऊर्जा नीति विवरणें पर विशेषज्ञ समिति, सदस्य, जारी

नीति निर्माताओं के साथ लक्षित बैठक :

i. अर्नफ ग्रूबलर, अजय माथुर, अनिल जैन और ऊर्जा नीति के लिए कार्य कर रहे अन्य संगठनों के प्रतिनिधि द्वारा 19 जनवरी 2018 को टुवर्ड्स एन एंड यूज एजेंडा फॉर इंडियास एनर्जी ट्रांजिशन।

11. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अध्येता नमिता वाही, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थीं :–

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बेंचेस, लाइव लॉ, 5 मार्च 2018

कार्य पत्र :

i. द लीगल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लैंड राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द शेड्यूल्ड एरियास ऑफ इंडिया, नमिता वाही, अंकित भाटिया, 31 जनवरी 2018

पॉडकास्ट :

i. अंडरस्टैंडिंग लैंड कंफ्लिक्ट्स इन इंडिया, नमिता वाही, सीपीआर पॉडकास्ट, एपिसोड 15, 18 अप्रैल 2017

सम्मेलन / संगोष्ठी में प्रस्तुतीकरण :

i. वर्ल्ड बैंक लैंड एंड पॉवर्टी सम्मेलन अंडरस्टैडिंग लैंड एक्विजिशन डिस्पुट्स इन इंडिया, शोध पत्र स्वीकृत, वॉशिंगटन डी. सी., वर्ल्ड बैंक, 12 दिसंबर 2017.

ii. नई दिल्ली, टेरी में 15 जनवरी 2018 को ''सोशल इम्पैक्ट एसेसमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसर बैच, ''द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ लैंड एक्विजिशन इन इंडिया'' पर अतिथि व्याख्यान।

iii. बिजनेस – रिलेटेड ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन्स : स्टेट ऑर कॉर्पोरेट रिस्पोसिबिलिटी? – एक्स्ट्रेक्टिव इंडस्ट्रीज एंड लैंड राइट्स इशूस : द केसेस ऑफ नाजिरिया एंड इंडिया द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ लैड एक्विजिशन इन

iv. इंडिया, बर्गेन, नॉर्वे, रैफ्टो फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द सेंटर ऑन लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, 4 दिसंबर 2017.

v. लेसन लर्न्ड – द 33 एनिवर्सरी ऑफ द भोपाल गैस डिजास्टर, 2017, बर्गेन, नॉर्वे, रैफ्टो फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द सेंटर ऑन लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, 2 दिसंबर 2017

vi. भारत, ट्रोमसो, नॉर्वे, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोसमो, नॉर्वे में 24 नवंबर 2017 को द लीगल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ लैंड राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर अतिथि व्याख्यान।

vii. कम्परेटिव रिसर्च ऑन लैंड यूज चेंज कॉफ्लिक्ट्स एंड रेमीडिस इन डेल्ही लैंड एक्विजिशन लिटिगेशन इन इंडिया : ए रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस फ्रॉम 1950 टू 2016 पर कार्यशाला, फरीदाबाद, टेरी, 14 नवंबर 2017.

viii. कम्परेटिव रिसर्च ऑन लैंड यूज चेंज कॉफ्लिक्ट्स एंड रेमेडिस इन देल्ही द लीगल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लैंड राइट्स इन द शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ इंडिया पर कार्यशाला, फरीदाबाद, टेरी, 14 नवंबर 2017.

ix. आईएसईआरपी वर्कशॉप, ईएएफआईटी यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी राइट्स एंड सोशल एंड इकॉनोमिक राइट्स, द पोस्ट – कोलोनियल स्टेड एंड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, मेडेलिन, कोलोम्बिया, ईएएफआईटी यूनिवर्सिटी, मेडेलिन, कोलोम्बिया, 4 नवंबर 2017

x. न्यू क्वेश्चन कंसेर्निंग लैंड इन नियो–लिबरल इंडिया, अंडरस्टैंडिंग लैंड एक्विजिशन डिस्पुट्स इन इंडिया : ए रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस फ्रॉम 1950 टू 2016 पर सम्मेलन, शिमला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, 10 अक्टूबर 2017.

xi. बर्गेन एक्सचेंज ऑन लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, द लीगल रिजिम एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लैंड राइट्स ऑफ शूड्यूल्ड ट्राइब्स इन द शेड्यूल्ड एरियास ऑफ इंडिया, बर्गेन नॉर्वे, सीएचआर. माइकलसन इंस्टीट्यूट एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गेन, बर्गेन, नॉर्वे, 25 अगस्त, 2017.

xii. ''लैंड रिकॉर्ड्स एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, 2005'' पर केंद्रीय सूचना आयोग संगोष्ठी, द लीगल आर्किटेक्चर ऑफ लैंड गवर्नेंस इन इंडिया : एसेस टू इफॉर्मेशन चेलेंजेस, नई दिल्ली, केंद्रीय सूचना आयोग, 15 जुलाई 2017.

xiii. भारत : भूमि और विकास सम्मेलन, भारत में भूमि अधिग्रहण मुकदमा, नई दिल्ली, नीति आयोग, लैंडेसा, डब्ल्यूआरआई इंडिया, आईएफएडी, एनआरएमसी, भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली, 5 अप्रैल 2017.

xiv. ''डिसपोजिशन विद्आउट डेवपलमेंट : लैंड ग्रेब्स इन नियोलिबरल इंडिया'', माइकल लेवियन

xv. सीपीआर एलआरआई अतिथि वक्ता श्रृंखला 10, 19 जुलाई 2017, प्रणीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली ''मैपिंग लैंड कंफ्लिक्ट्स इन इंडिया'', कुमार सम्भव श्रीवास्तव, अंकुर पालीवाल और भास्कर त्रिपाठी, सीपीआर एलआरआई अतिथि वक्ता श्रृंखला 9, प्रणीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली 22 जून 2017

xvi. ''द फ्यूचर वी नीड : नेचुरल रिसोर्सेस एज द शेयर्ड इंहेरिटेंस'', राहुल बासु, सीपीआर एलआरआई, अतिथि वक्ता श्रृंखला 8, 17 मई 2017, प्रणीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली, श्री रमेश शर्मा के साथ बातचीत, राष्ट्रीय संयोजक, एकता परिषद, प्रणीति अनुसंधान केंद्र, 9 मई, 2017.

xvii. ''डेवलपमेंट कंफ्लिक्ट्स वी नॉ नथिंग ऑफ'', रोहित प्रसाद, सीपीआर एलआरआई अतिथि वक्ता श्रृंखला, प्रणीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2017

कार्य बल और कार्यरत समितियों की बैठक :

i. डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर प्रायोगिक अध्ययन की तकनीकी समिति, सलाहकार, 19 जनवरी से 13 नवंबर 2017.

नीति निर्माताओं के साथ लक्षित बैठकें :

i. डिस्कस्ड फाइंडिंग्स फ्रॉम लैड एक्विजिशन स्टडी ऑन साइडलाइन्स ऑफ द इंडिया : लैंड एंड डेवलपमेंट सम्मेलन, श्री टी. हक, अध्यक्ष, भूमि नीति पर विशेष प्रकोष्ठ, नीति आयोग, 5 अप्रैल 2017.

12. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एसोसिएट प्रोफेसर निम्मी कुरियन, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थीं :–

सम्मेलन / संगोष्ठी में प्रस्तुतीकरण :

i. इंडिया चाइना इंस्टीट्यूट, द न्यू स्कूल, न्यू यॉर्क द्वारा 22 मई 2017 को आयोजित इंडिया एंड चाइना : रिथिकिंग बोर्डर्स एंड सिक्योरिटी (को–ऑथर), यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रेस, एन्ना एर्बन, 2016 की पुस्तक का विमोचन और चर्चा।

ii. माइकल कुगेलमैन, विलसन सेंटर, वॉशिंगटन ने 25 मई 2017 को चीन और दक्षिण एशिया पर पैनल चर्चा की मेजबानी की।

iii. चाइना इंडिया स्कोलर – लीडर्स, इंडिया चाइना इंस्टीट्यूट, द न्यू स्कूल, न्यू यॉर्क द्वारा 19–20 मई 2017 को आठ अनुसंधान प्रस्ताव के शैक्षणिक सलाहकार और चर्चाकर्ता का प्रस्तुतीकरण।

iv. श्रीनाथ राघवन, प्रणीति अनुसंधान केंद्र द्वारा 7 नवंबर 2017 को संचालित राजदूत श्याम शरन और निम्मी कुरियन के बीच 'अनपैकिंग द रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस' पर बातचीत।

v. न्यू यॉर्क में 18 अगस्त 2017 को विदेशी कार्यों पर संयुक्त राष्ट्र आधारित रेडियो कार्यक्रम में वेक के ल्यूक वर्गास द्वारा डोकलाम में भारत – चीन स्टैंडऑफ पर साक्षात्कार,

vi. डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स एंड रिसोर्स गवर्नेंस, शिव नादर यूनिवर्सिटी में 22 नवंबर 2017 को एमिंग लॉ, हिटिंग लोअर? द सबरीजनल टर्न इन इंडियास फॉरेन पॉलिसी, पब्लिक पर वार्ता दी।

vii. अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य हाशिए के समूहों, प्रणीति अनुसंधान केंद्र से संबंधित छात्रों और व्याख्याताओं के लिए सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पर अभिविन्यास कार्य में 1–2 दिसंबर 2017 को 'डेमोक्रेटिजिंग सोशल रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च' पर प्रस्तुतीकरण।

viii. रिसर्च सेंटर फॉर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रिजनल स्टडीज, कोलकाता (सीईएनईआरएस – के) द्वारा 1–3 फरवरी 2018 को आयोजित भारत – चीन संबंधों पर अंतरराष्ट्रीय संवाद में कलकता में 'डाउनस्ट्रीम इमप्लीकेशन्स ऑफ चाइनास डैम प्रोजेक्टस' पर शोध पत्र प्रस्तुति।

ix. मिजोरम यूनिवर्सिटी, एजवाल में 23 और 24 मार्च 2018 को आईसीएसएसआर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र और एशियन अध्ययन केंद्र (एएससी), शिलॉन्ग द्वारा आयोजित किए जा रहे ''बोर्डर एंड कनेक्टिविटी : नॉर्थ – ईस्ट इंडिया एंड साउथ – ईस्ट एशिया'' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुति किए जा रहे 'कंजर्वेशन्स बियॉन्ड द सेंटर : इंडियाज बोर्डर रिजन्स एज ड्राइवर्स ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी' शोध पत्र।

x. आर वीणा के बाह्य परीक्षक, वायवा वोस बोर्ड, 'हार्मोनिजिंग झिंजियांग' : एक्जामिनिंग चाइनास एथनिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पोस्ट – 2009', चाइना स्टडीज सेंटर, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, 12 जनवरी 2018.

xi. द जर्नल ऑफ बोर्डरलैंड्स स्टडीज के लिए अगस्त 2017 को 'ट्रांसबोर्डर पीपल, कनेक्टेड हिस्ट्री : बोर्डर एंड रिलेशनशिप्स इन द इंडो–बर्म बोर्डलैंड्स' के पांडुलिपि के बाह्य समीक्षक।

नीति संक्षेप और रिपोर्ट :

i. 'नरेंद्र मोदी कंफ्लिक्टेड चाइना पॉलिसी', इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया एंड पेसिफिक स्टडीज डायलॉग, यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंघम, 4 सितंबर 2017.

ii. 'डोकलाम : द गेम ऑफ शेडोस', चाइना फाइल, एशिया सोसायटी, न्यू यॉर्क, 09 अगस्त 2017.

iii. के. जे. जॉय आदि, पूर्वोत्तर भारत में पानी का संघर्ष, रॉटलेडज, 2017 में 'अनकार्टेड फ्लोस : नेविगेटिंग द डाउनस्ट्रीम डिबेट ऑन चाइनास वॉटर पॉलिसी।

iv. 'एड्रेसिंग द ड्रॉट ऑफ आइडियास ऑन द ब्रह्मपुत्र', चाइना– भारत संक्षेप, ली कौन येव स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, 24 अक्टूबर 2017.

v. जॉशुआ थॉम्स और गुरूदास दास संपा. बीसीआईएम : सबरिजनल कॉ–ऑपरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल एरियास, पेंटागोन, 2018 में 'बीसीआईएम सस्टेनेबिलिटी डायलॉग : ए नेटवर्क एप्रोच टू कैपिसिटी बिल्डिंग'।

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. 'हाव सुकीई कैन चेंज द रोहिंग्या नरेटिव' *द डिप्लोमेटिस्ट, वॉल. 5, इशू 11,* नवंबर 2017.

ii. 'क्रॉसिंग द लाइन : द बोर्डर एज वर्ब' *लाइव एनकाउंटर्स,* दिसंबर 2017

13. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अध्येता नीलांजन सरकार निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थीं :–

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. हाव टू विन इलेक्शन्स, ऑर पिक विनर्स, नीलांजन सरकार, एचटी सिंडिकेशन सोमवार, 26 मार्च 2018.

ii. विच एमपी यूटिलाइज कंस्टीटेंसी फंड्स द बेस्ट? नीलांजन सरकार, हिंदुस्तान टाइम्स, बुधवार, 21 फरवरी 2018.

iii. एजुकेशन्स अप्स अटैंडेंस ऑफ एमपी क्रिमिनल हिस्ट्री लॉवर्स इट, नीलांजन सरकार, हिंदुस्तान टाइम्स, बुधवार, 31 जनवरी 2018.

iv. द इनएबिलिटी टू मूल मास लीडर्स अप पार्टी रैंक्स हैज बीन ए प्रोब्लम फॉर द कांग्रेस, अशीष रंजन, नीलांजन सरकार, हिंदुस्तान टाइम्स, मंगलवार, 19 दिसंबर 2017.

v. इट्स नॉट आइडियोलॉजी बट एस्पिरेशन डैट ड्राइव्स इंडियास मिडल क्लास पॉलिटिशियन्स टेक नोट देवेश कपूर, नीलांजन सरकार, मिलन वैष्णव, क्वार्टज, मंगलवार, 5 दिसंबर 2017.

vi. थ्री इकॉनोमिस्ट्स वेंट अराउंड इंडिया आस्किंग : डू यू कॉल योरसेल्फ मिडल क्लास? नीलांजन सरकार, देवेश कपूर, मिलन वैष्णव द प्रिंट, मंगलवार, 28 नवंबर 2017 – 12.33 बजे।

कार्य पत्र :

i. इज द बीजेपी इन ट्रबल? कास्ट, क्लास एंड द अर्बन – रूरल डिवाइड इन गुजरात आशीष रंजन, नीलांजन सरकार, बुधवार, 13 दिसंबर 2017.

14. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अध्येता पार्थ मुखोपाध्याय निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :–

कार्य पत्र :

i. इंजिंस विदआउट ड्राइवर्स : सिटीज इन इंडियास ग्रोथ स्टोरी, पार्थ मुखोपाध्याय, 8 मार्च, 2018

15. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अतिथि अध्येता ऑलिवियर टेली निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :–

संगोष्ठियों और सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण :

i. जीआईएस एएसआईई, एशिया में शहरों का समोच्च, पेरिस साइंसेज पीओ, जीआईएस एएसआईई, 26 जून 2017.

ii. यूर्ब–एंडेमिक, पेरिस सोरबोन, 28 और 29 जून 2017.

iii. एक शहर में उभरते संक्रामक रोग : दिल्ली में डेंगू एंड चिकनगुनिया एनआईपीएफपी।

iv. इकॉमोर 2 : वियातनाम में डेंगू के आर्थिक परिवर्तन और स्वास्थ्य प्रसार पर प्रभाव, लियोस, वियतनाम, लियोस, 10 मार्च 2018.

v. एशिया में शहरी घनत्व के उतरते रूप : शहरीकरण का साझा परिप्रेक्ष्य : वियतनाम और भारत में संक्रामक रोगों के लिए क्या मायने रखता है, हेनॉई, वियातनाम, 20 नवंबर 2017

vi. वेक्टर से उत्पन्न बीमारियों को नियंत्रित करने में नए अवसर : शहरी भारत, एमसीडी, डब्ल्यूएचओ एशिया, डब्ल्यूएचओ इंडिया, एनआईएमआर, आयोजक (सीएसएच दिल्ली) में बिग डेटा, नई कीटनाशक और अनुप्रयोग, 26 फरवरी 2018.

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. इमर्जिंग इंफेक्शस डिजीज इन इंडिया : द स्कोरेज दैट कुड बूस्ट अर्बन डेवलपमेंट, द कंवर्जेशन, 17 अप्रैल 2018

कार्य बल और नीति सलाहकार समितियों की बैठक :

i. डेंगू कार्य बल, सलाहकार, दिल्ली नगर निगम, फरवरी 2018

ii. संक्रामक रोग और वैश्विक परिवर्तन, सलाहकार, म्युनिसिपलिटी ऑफ विएनटियन, लियो हेल्थ मिनिस्ट्री, मार्च 2018

नीति निर्माताओं के साथ लक्षित बैठकें :

i. दिल्ली में डेंगू परियोजना, डब्ल्यूएचओ एशियन

ii. भारत में एंटी माइक्रोबायोटिक रेजिस्टेंस, डब्ल्यूएचओ एशियन

16. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी डॉ. प्रताप भानु मेहता, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :

पुस्तकें :

i. नेविगेटिंग द लैबरिंथ : परस्पेक्टिव्स ऑन इंडियास हायर एजुकेशन, देवेश कपूर, प्रताप भानु मेहता, 12 मई 2017

ii. रिथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूट इन इंडिया, देवेश कपूर, प्रताप भानु मेहता, मिलन वैष्णव, 12 मई 2017

संपादित संस्करणों में अध्याय :

i. द सुप्रीम कोर्ट एंड इंडियास जुडिशियल सिस्टम, माधव खोसला, अनंत पद्मानाभन, रिथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूट इन इंडिया, देवेश कपूर, प्रताप भानु मेहता, मिलन वैष्णव, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 25 जुलाई 2017

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. स्किमिंग द शैलोस, प्रताप भानु मेहता, द इंडियन एक्सप्रेस, मंगलवार, 29 अगस्त 2017

ii. स्मॉल स्टेप, नॉ जाइंट लीप, प्रताप भानु मेहता, इंडियन एक्सप्रेस, बुधवार, 23 अगस्त 2017

iii. द टू लेट नेशन, प्रताप भानु मेहता, इंडियन एक्सप्रेस, मंगलवार, 17 अगस्त 2017

iv. रीडिंग फ्रीडम, प्रताप भानु मेहता, इंडियन एक्सप्रेस, सोमवार, 14 अगस्त 2017

v. बियॉन्ड जामिया, प्रताप भानु मेहता, द इंडियन एक्सप्रेस, मंगलवार, 8 अगस्त 2017

vi. ओल्ड वेज़ डाई हार्ड, प्रताप भानु मेहता, द इंडियन एक्सप्रेस, शुक्रवार, 28 जुलाई 2017

vii. डांसिंग ऑन द एज, प्रताप भानु मेहता, इंडियन एक्सप्रेस, बुधवार, 26 जुलाई 2017

viii. द अनटाइमली डिसिडेंट, प्रताप भानु मेहता, इंडियन एक्सप्रेस, सोमवार, 17 जुलाई 2017

ix. द फायर्स ऑफ बंगाल, प्रताप भानु मेहता, इंडियन एक्सप्रेस, सोमवार, 10 जुलाई 2017

x. मे द साइलेंट बी डैम्ड, प्रताप भानु मेहता, इंडियन एक्सप्रेस, मंगलवार, 27 जून

xi. एनलार्ज द फ्रेम, प्रताप भानु मेहता, इंडियन एक्सप्रेस, शुक्रवार, 23 जून 2017

xii. द पावर पैराडॉक्स, प्रताप भानु मेहता, द इंडियन एक्सप्रेस, शुक्रवार, 16 जून

xiii. प्रेसीस्टीट्यूट क्रॉनिकल्स, प्रताप भानु मेहता, द इंडियन एक्सप्रेस, बुधवार, 7 जून 2017

xiv. द मार्च टू स्पेक्टेकल, प्रताप भानु मेहता, द इंडियन एक्सप्रेस, सोमवार, 29 मई 2017

xv. द माइंड ऑफ द सैंट्स : स्पेकुलेशन्स अराउंड रामाकृष्णन परमहंस एंड रमन महाऋषि, प्रताप भानु मेहता, द इंडियन एक्सप्रेस, सोमवार, 29 मई

xvi. ऑन ट्रिपल तलाक, कोर्ट मस्ट से : रिलिजयस प्रैक्टिस कैन नॉट ट्रम्प मॉडर्न कंस्टीट्यूशनल मॉरेलिटी, प्रताप भानु मेहता, द इंडियन एक्सप्रेस, गुरूवार, 18 मई 2017

xvii. वीक पब्लिक इंस्टीट्यूट बिहाइंड इंडियास लॉ स्टेट कैपिसिटी मिलन वैष्णव, प्रताप भानु मेहता, देवेश कपूर, लाइव मिंट, बुधवार, 17 मई 2017

xviii. सुप्रीम टेस्ट, प्रताप भानु मेहता, द इंडियन एक्सप्रेस, सोमवार, 8 मई 2017

xix. इकबाल्स रॉन्ग टर्न, प्रताप भानु मेहता, द इंडियन एक्सप्रेस, बुधवार, 19 अप्रैल 2017

xx. सिंकिंग वेली, प्रताप भानु मेहता, इंडियन एक्सप्रेस, मंगलवार, 18 अप्रैल 2017

xxi. इट्स अबाउट यूएस, नॉट सिरिया, प्रताप भानु मेहता, इंडियन एक्सप्रेस, बुधवार, 12 अप्रैल 2017

सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण :

i. एडवोकेटा इंस्टीट्यूट, कोलम्बो में 19–24 अप्रैल 2017 को ''शूड वी हेव सोशियो इकॉनोमिक राइट्स इन द कंस्टीट्यूशन'' पर वार्ता दी।

ii. सीआईआई में सत्र, 29 अप्रैल 2017

iii. करनेजी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, वॉशिंगटन में 10 मई 2017 को अध्याय शीर्षक ''रिथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूट इन इंडिया'' के सम्मेलन का शुभारंभ।

iv. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन, एनजे में 11 मई 2017 को अध्याय शीर्षक ''रिथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूट इन इंडिया'' के सम्मेलन का शुभारंभ।

v. इंडिया हेबिटेट सेंटर में 13 जुलाई 2017 को ''ब्रॉडकास्टिंग योर कैरियर होरिजॉन्स विद् ए मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टॉक्यो'' पर सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया।

17. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अतिथि अध्येता फिलिप्प कुलेट निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :–

पुस्तकें :

i. पी. कुलेट एंड एस. कूनोडस, *वॉटर लॉ इन इंडिया – एन इंट्रोडक्शन टू लीगल इंस्ट्रुमेंट्स,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दूसरा संस्करण 477 पेज, जून 2017 में।

पत्रिकाओं में लेख :

i. पी. कुलेट, एल. भुल्लर एंड एस कूनन, 'रेगुलेटिंग द इंटरेक्शन्स बीटवीन क्लाइमेट चेंज एंड ग्राउंडवॉटर : लेसन्स फ्रॉम इंडिया', 42/6 वॉटर इंटरनेशनल (2017), पी. 646–62, अगस्त 2017

ii. पी. कुलेट एंड आर स्टेफन, 'इंट्रोडक्शन टू 'ग्राउंडवॉटर एंड क्लाइमेंट चेंज – मल्टी – लेवल लॉ एंड पॉलिसी परस्पेक्टिव्स', 42/6 वॉटर इंटरनेशनल (2017), पी. 641–45., अगस्त 2017

संपादित संस्करणों में अध्याय :

i. मैलकोलम लैंगफॉर्ड एंड एन्ना एफ. एस. रूसेल संपा., *द ह्यूमन राइट टू वॉटर : थ्योरी, प्रैक्टिस एंड प्रोस्पेक्ट्स* में पी कुलेट, 'द राइट टू वॉटर इन रूरल इंडिया एंड ड्रिंकिग वॉटर पॉलिसी रिफॉर्म्स' (कैम्ब्रिज : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2017), पेज 675–91.

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. पी. कुलेट, 'ए गैथरिंग क्रिसिस : द नीड फॉर ग्राउंडवॉटर रेगुलेशन', द हिंदु पी. 8, 8 अगस्त 2017.

ii. पी. कुलेट, 'इंडियास एम्बिशयस प्लान्स टू एचीव सेनिटेशन फॉर ऑल मस्ट लुक बियॉन्ड बिल्डिंग इंडिविजुअल टॉयलेट्स', द इंडिपेंडेंट, 10 अक्टूबर 2017.

कार्य बल और कार्य पत्रों पर बैठक :

i. कमिटी टू रेड्राफ्ट द ड्राफ्ट मॉडल बिल फॉर कंर्जेवेशन प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वॉटर, 2011 (जुलाई 2017 में पुनःआरंभ), सदस्य, जुलाई – अगस्त 2017

18. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अध्येता राधिका खोसला, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :–

नीति संक्षेप और रिपोर्ट :

i. मैनस्ट्रीमिंग क्लाइमेंट एक्शन्स इन इंडियन सिटीज : केस स्टडी ऑफ राजकोट, अंकित भारद्वाज, 1 सितंबर 2017.

ii. प्लगइंग इन : ए कलेशन ऑफ इनसाइट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूज इन इंडियन होम्स, आदित्य चुनेकर, 29 दिसंबर 2017.

कार्य पत्र :

i. इंडियाज एनर्जी एंड इमिशन्स फ्यूचर : ए सिंथेसिस ऑफ रिसेंट सीनेरियोस, नवरोज दुबेश, नरसिम्हा राव, अंकित भारद्वाज, 11 सितंबर 2017

ii. मैनस्ट्रीमिंग क्लाइमेंट एक्शन्स इन इंडियन सिटीज : केस स्टडी ऑफ राजकोट, अंकित भारद्वाज, सितंबर 2017

वेब आधारित प्रकाशन :

i. प्लगइंग इन : इलेक्ट्रिसिटी कंज्मपशन इन इंडियन होम्स, आदित्य जुनेकर, सीपीआर इंडिया वेबसाइट, 31 अक्टूबर 2017

ii. प्लगइंग इन : इलुमिनेटिंग एफॉर्डेबल होम्स अंकित भारद्वाज, सीपीआर इंडिया वेबसाइट, 21 नवंबर 2017

iii. प्लगइंग इन : एप्लाइंसेस यूज्ड इन एफॉर्डेबल हाउसिंग, अंकित भारद्वाज, सीपीआर इंडिया वेबसाइट, 6 दिसंबर 2017

iv. प्लगइंग इन : इलेक्ट्रिफाइंग द नेशनल कैपिटल रिजन, अंकित भारद्वाज, सीपीआर इंडिया वेबसाइट, 13 दिसंबर 2017

v. प्लगइंग इन : रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ड्राइविंग इलेक्ट्रिसिटी यूज, अंकित भारद्वाज, सीपीआर इंडिया वेबसाइट, 27 दिसंबर 2017

सम्मेलन और संगोष्ठियों में प्रस्तुतीकरण :

i. सिटीज एंड क्लाइमेंट कॉन्फ्रेंस 2017, पॉस्टडैम, ''वी आर ग्रीनर दैन यू थिंक'' – एन इंडियन सिटीज रिस्पोंस टू क्लाइमेंट चेंज, पोस्टडैम (जर्मनी), प्रोजेक्ट आरएएमएसईएस, 19–21 सितंबर, 2017

19. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एसोसिएट प्रोफेसर राजश्री चंद्रा, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थीं :–

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. दिल्ली यूनिवर्सिटी कैन नॉ लॉन्गर टर्न ए ब्लाइंड आई टू सिस्टेमिक फ्लॉस ड्रेगिंग द इंस्टीट्यूट डाउन, द वायर, 9 नवंबर 2017

ii. लॉ एंड इम्युनिटी, इंडियन एक्सप्रेस, 24 अक्टूबर 2017

iii. वी नीड एन एंटी – एसएलएपीपी लॉ टू इंकरेज एंड प्रोटेक्ट फ्री प्रेस, द वायर, 12 अक्टूबर 2017

iv. वाय वी नीड टू बी वरी ऑफ द पॉलिकल सेंट्रिस्ट, द वायर, 14 अगस्त, 2017

v. जीएम मस्टर्ड अबाउट टू बी एप्रूव्ड फॉर यूज : 10 फैक्ट्स डैट आउट टू वरी यू, कैच न्यू, 24 मई, 2017

vi. सैफ्रॉन ब्लाइंड, इंडियन एक्सप्रेस, 25 अप्रैल 2017

vii. फ्री स्पीच ऑन सोशल मीडिया मे नॉट बी सिविल बट लेट अस नॉट यूज द लॉ टू कर्ब इट, द वायर, 19 अप्रैल 2017

viii. वाय फॉरेस्ट राइट्स मैटर, इंडियन एक्सप्रेस. 17 मार्च 2018 – बाय द पीपल

ix. रिव्यू आर्टिकल ऑफ ऑर्निट शानीस बुक, हाव इंडिया बीकम डेमोक्रेटिक। 9 मार्च, 2018

x. अंडरस्टैंडिंग द रेशो ऑफ मेलिस टू लेगेलिटी इन द आप एमएलए डिसक्वालिफिकेशन केस। द वायर, 22 जनवरी, 2018

xi. द अल्टीमेट इनसाइडर, रिव्यू आर्टिकल ऑफ द कोलिजन इयर्स, प्रणब मुखर्जी (रुपा 2016) पायोनीयर 24 दिसंबर 2017

xii. लॉ एंड इम्युनिटी, इंडियन एक्सप्रेस, 24 अक्टूबर 2017

xiii. वी नीड एन एंटी – एसएलएपीपी लॉ टू इंकारेज एंड प्रोटेक्ट फ्री प्रेस, द वायर, 12 अक्टूबर, 2017

प्रस्तुतीकरण / संगोष्ठियों के लिए शोध पत्र प्रस्तुति :

i. लॉ सोसायटी एसोसिएशन फॉरेस्ट राइट्स : नोट्स ऑन एन आल्टर्नेटिव एजेंडा फॉर प्रोपर्टी, मैक्सिको सिटी, लॉ सोसायटी एसोसिएशन, 20 जून 2017

20. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अध्येता रमेश चंद्रन, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :–

नीति निर्माताओं के साथ लक्षित बैठकें :

i. वूड्रोव विलसन स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में भारतीय सांसदों के लिए 2017 प्रिंसटन – जीपीपीआई – सीपीआर सामरिक मामलों का कार्यक्रम, भारतीय सांसदों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम, 30 अप्रैल से 5 मई 2017.

ii. ऑस्ट्रेलिया के विदेशी कार्यालय के सहयोग से 17–26 जून 2017 को ऑस्ट्रेलिया के लिए भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का दौरा, भारतीय सांसदों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम।

iii. भारत में बाल स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने पर संवादात्मक चर्चा, संसद सदस्य और क्षेत्र विशेषज्ञ, 2 अगस्त, 2017

iv. वूड्रोव विलसन स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में भारतीय सांसदों के लिए 2017 प्रिंसटन – जीपीपीआई – सीपीआर सामरिक मामलों का कार्यक्रम, भारतीय सांसदों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम, 30 अप्रैल से 5 मई 2017.

v. ऑस्ट्रेलिया के विदेशी कार्यालय के सहयोग से 17–26 जून 2017 को ऑस्ट्रेलिया के लिए भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का दौरा, भारतीय सांसदों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम।

vi. भारत में बाल स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने पर संवादात्मक चर्चा, संसद सदस्य और क्षेत्र विशेषज्ञ, 2 अगस्त, 2017.

vii. लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स में 29 अक्टूबर – 4 नवंबर, 2017 को आयोजित भारतीय नेताओं के लिए 2017 चेवेनिंग सीपीआर संसद सदस्य अध्येतावृत्ति कार्यक्रम, चेवेनिंग कार्यक्रम, यूके के साथ वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रम।

viii. प्रौद्योगिकी और शासन पर परस्पर क्रिया पर चर्चा : आधार गोपनीयता चिंताएं और डेटाबेस सुरक्षा, संसद सदस्य और क्षेत्र विशेषज्ञ, 12 मार्च, 2018.

ix. केंद्रीय बजट 2018 में बनाए गए स्वास्थ्य प्रतिबद्धताओं पर गोलमेज चर्चा, संसद सदस्य और क्षेत्र विशेषज्ञ, 21 मार्च, 2018.

21. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एसोसिएट प्रोफेसर, रानी मुलैन, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थीं :–

नीति संक्षेप :

i. इंडिया – बांग्लादेश डेवलपमेंट पाटर्नरशिप : एक्सटेंशन ऑफ ए यूएस डॉलर 4.5 बिलियन बाय इंडिया टुवर्ड इट्स ईस्टर्न नेबर, 25 अक्टूबर 2017.

ii. साउथ – साउथ डेवलपमेंट कॉ–ऑपरेशन : एनालायसिस ऑफ इंडिया एंड चीन मॉडल ऑफ डेवपलमेंट कॉ–ऑपरेशन एब्रॉड, 21 दिसंबर 2017.

22. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अध्येता डी श्याम बाबू, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे:–

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. ''ए सोल्यूशन इन सर्च ऑफ प्रोब्लम'', द हिंदु, 27 अप्रैल 2017

ii. ''बियॉन्ड द लैंग्वेज कॉन्फिलिक्ट : द नीड फॉर द क्लीयर लैंग्वेज पॉलिसी'', द हिंदु, 30 मई 2017

iii. ''रिएप्राइजिंग द राज'', द हिंदु, 12 सितंबर 2017

iv. ''बर्थ पैंग्स ऑफ ए न्यू फेडरल पॉलिटी'', द हिंदु, 28 मार्च 2018

कार्य बल और कार्यकारी समूहों की बैठक :

i. सकारात्मक कार्यवाही पर सीआईआई समिति, सदस्य, 2007 के बाद से जारी

23. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अध्येता श्याम शरण, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :–

पुस्तकें :

i. हाव इंडिया सीस द वर्ल्ड : कौटिल्य टू द 21 सेंचुरी, श्याम शरण, बुधवार, 20 सितंबर 2017.

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. पावरिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, शुक्रवार, 16 मार्च.

ii. इंडिया मस्ट लीड द चार्ज इन प्रीजर्विंग थ्रेटेंड इकोलॉजी, श्याम शरण, हिंदुस्तान टाइम्स, गुरूवार, 8 मार्च 2018.

iii. एंटर द ड्रेगन, श्याम शरण, इंडिया टुडे, शनिवार, 17 फरवरी 2018.

iv. इंडिया – एशियन टाइस : ए कप हाफ फुल?, श्याम शरण, हिंदुस्तान टाइम्स, बुधवार, 24 जनवरी 2018.

v. अवर टाइम हैज कोमिया एलायसा एयरेस क्रोनिकल ऑफ इंडिया राइज टू ग्लोबल प्रोमिनेंस, श्याम शरण, द प्रिंट, गुरूवार, 11 जनवरी.

vi. टाइम टू रिएफर्म द कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, बुधवार, 10 जनवरी 2018.

vii. ऑप्शन्स विल मल्टीप्ले : सो विल द चेलेंजेस, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, गुरूवार, 4 जनवरी 2018.

viii. इन 2018, इंडिया मस्ट बेलेंस द डिमांड्स ऑफ द नेबरहुड अगेंस्ट द कम्पशन्स ऑफ द ग्लोबल रोल, श्याम शरण, हिंदुस्तान टाइम्स, बुधवार, 27 दिसंबर 2017.

ix. बाबरी रिकॉल : ए मिलियन म्यूटिनीज, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, बुधवार, 13 दिसंबर 2017.

x. द क्वाड्रिलेटरल : इज इट एन एलिएंस ऑर एन अलाइनमेंट?, श्याम शरण, हिंदुस्तान टाइम्स, मंगलवार, 28 नवंबर 2017.

xi. इन द फुटस्टेप्स ऑफ द 'इंडियन ट्रेडर' हू फाउंड पेट्रा, श्याम शरण, बुधवार, 22 नवंबर 2017.

xii. इवेंट्स वर्सिस प्रोसेसेस, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, बुधवार, 8 नवंबर 2017.

xiii. इनसाइड पेट्रा, द लोस्ट सिटी ऑफ स्टोन, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, सोमवार, 30 अक्टूबर 2017.

xiv. यूएस इन द क्रॉसहेयर्स : वाय क्राइसिस इज लूमइंग ओवर द कोरियन पेनिनसुला, श्याम शरण, हिंदुस्तान टाइम्स, 26 अक्टूबर 2017.

xv. द शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ वेस्ट एशिया एंड द गल्फ, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, गुरूवार, 11 अक्टूबर 2017.

xvi. द फ्रेनेमिस विदिन, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, गुरूवार, 28 सितंबर 2017

xvii. द फ्लेवर्स ऑफ तिब्बत, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, सोमवार, 25 सितंबर 2017.

xviii. स्टैंड– ऑफ विद् चाइना मे हेव एंडेड बट देयर कुड बी मोर डोकलाम, श्याम शरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, सोमवार, 18 सितंबर 2017.

xix. डिप्लोमेसी इन द एज ऑफ ट्वीटर, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, बुधवार, 13 सितंबर 2017

xx. डोकलाम बिग पिक्चर : नीदर एशिया नॉर द वर्ल्ड इज चाइना – सेंट्रिक, श्याम सरण, द क्विन्ट, मंगलवार, 29 अगस्त 2017.

xxi. इंडियाज डेस्टिनी एंड द यूएस – पाकिस्तान एम्ब्रेस, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, सोमवार, 14 अगस्त 2017.

xxii. फैक्शनल इंफाइटिंग शार्पेंस इन चाइना, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, बुधवार, 9 अगस्त 2017

xxiii. डोकलाम स्टैंड ऑफ : डेवलप गुड टाइस विद साउथ एशियन नेबर्स टू काउंटर चाइना, श्याम शरण, हिंदुस्तान टाइम्स, शुक्रवार, 28 जुलाई 2017.

xxiv. वाय इंडिया मस्ट पुश बैक अगेंस्ट चाइना क्लेम्स ऑफ बीइंग एशिया नेचुरल लीडर, श्याम शरण, 28 जुलाई 2017.

xxv. चाइना, यूएस एंड मैनिफेस्ट डेस्टिनीस, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, गुरूवार, 20 जुलाई 2017.

xxvi. इंडिया क्लोजिंग द डोर टू देयर सिटिजन्स सूट्स पाकिस्तान, श्याम सरण, नेशनल हेराल्ड, मंगलवार, 18 जुलाई 2017.

xxvii. द स्टैंड ऑफ इन डोकलाम, श्याम शरण, द ट्रिबुन, मंगलवार, 4 जुलाई 2017.

xxviii. रीड बिटवीन द यूएस लाइन्स, श्याम शरण, द इंडियन एक्सप्रेस, गुरूवार, 29 जून 2017.

xxix. रेनमिन्बी ग्रोविंग ग्लोबल इंफ्लुएंस, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, शुक्रवार, 16 जून 2017.

xxx. इज देयर ए नीड फॉर ए पेरिस एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नेंमेंट एंड सिटीजन्स? श्याम शरण, यूनाइटेड नेशन्स इंडिया, शुक्रवार, 16 जून 2017 – 12.48 बजे।

xxxi. द रोड फ्रॉम सैंट पीटरबर्ग, श्याम शरण, द हिंदु, मंगलवार, 13 जून 2017.

xxxii. ऑन क्लाइमेट चेंज, द यूनाइटेड स्टेट्स नीड्स टू बी आइसोलेटेड, नॉट एपीस्ड, श्याम शरण, द वायर, सोमवार, 5 जून 2017.

xxxiii. इन इयर फोर, मोडिया फॉरेन पॉलिसी नीड्स सम कोर्स करेक्शन, श्याम शरण, द वायर, सोमवार, 29 मई 2017.

xxxiv. द एंसिएंट इंडियन मिथ डैट कुड सेव अवर ओसीन्स, श्याम शरण, Rediff.com, सोमवार, 22 मई 2017

xxxv. लुकिंग चाइना इन द आई, श्याम शरण, द इंडियन एक्सप्रेस, सोमवार, 22 मई 2017

xxxvi. लिसन टू वाट द ओशन इज सेइंग, श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, गुरूवार, 11 मई 2017

xxxvii. नेपाल हिस्ट्री, रिवाइज्ड, श्याम शरण, द इंडियन एक्सप्रेस, शुक्रवार, 5 मई 2017

xxxviii. डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म एंड कॉस्मोपोलिटेनिज्म कैन पुट इंडिया इन ए लीडिंग रोल इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, श्याम शरण, हिंदुस्तान टाइम्स, गुरुवार, 4 मई, 2017.

xxxix. ट्रेप्ड बिटवीन टू इंडियास, श्याम शरण,, शुक्रवार, 21 अप्रैल 2017

xl. शेपिंग इंडियाज फ्यूचर श्याम शरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, बुधवार, 12 अप्रैल 2017

24. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अध्येता श्रीनिवास चोक्काकुला, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे:–

पुस्तकें :

i. वाय डू इंटरस्टेट वॉटर डिस्पुट्स इमर्ज एंड रिकर? श्रीनिवास चोक्ककुला, गुरूवार, 4 जनवरी 2018

पत्रिका लेख :

i. नहू मिरुमाची द्वारा रिव्यू : ट्रांसबाउंडरी वॉटर पॉलिटिक्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, गुरूवार, 5 अक्टूबर, 2017

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. पार्टिंग द वॉटर्स, श्रीनिवास चोक्ककुला, द इंडियन एक्सप्रेस, सोमवार, 19 फरवरी 2018.

ii. महादायी इशू डेमोंस्ट्रेट्स वाय इंडिया नीड्स ए जीएसटी काउंसिल – लाइक फोरम फॉर रिवर गवर्नेंस, श्रीनिवास चोक्ककुला, द इकॉनोमिक टाइम्स, सोमवार, 12 फरवरी 2018

iii. टेस्टिंग वॉटर्स श्रीनिवास चोक्ककुला, द हिंदु, गुरूवार, 1 फरवरी 2018

iv. कोसी रिवर एंड द (अन) मार्किंग ऑफ डिजास्टर, श्रीनिवास चोक्ककुला, एशिया एंड द पेसिफिक पॉलिसी सोसायटी, गुरूवार, 5 अक्टूबर

v. तेलांगाना : बॉर्न ऑफ हिस्टोरिक फिशर्स, श्रीनिवास चोक्ककुला, गेटवे हाउस, गुरूवार, 21 सितंबर 2017

vi. रिजोल्व वॉटर डिस्पुट्स पॉलिटकली, श्रीनिवास चोक्ककुला, हिंदु बिजनेस लाइन, गुरूवार, 21 सितंबर 2017

vii. विदआउट बेटर इंटरस्टेट कॉओर्डिनेशन, कावेरी डिस्प्यूट विल कंटीन्यू टू सिमर, श्रीनिवास चोक्ककुला, द वायर, गुरूवार, 21 सितंबर 2017

viii. वाय इंटरस्टेट वॉटर डिस्पुट्स आर डिफिकल्ट टू मैनेज ऑर कंट्रोल, श्रीनिवास चोक्ककुला, इकॉनोमिक टाइम्स, गुरूवार, 21 सितंबर 2017

ix. ए स्ट्रेंजर रिवर रिफेरी, श्रीनिवास चोक्ककुला, इंडियन एक्सप्रेस, सोमवार, 24 जुलाई 2017

25. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अध्येता श्रीनाथ राघवन, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :–

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. रिविजिटिंग द 1946 रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, मिंट, 3 अप्रैल 2017.

ii. अवर हिस्टोरियन्स हेव स्केंट इंटरेस्ट इन वॉर्स ऑर सोलजर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, 27 अप्रैल 2017.

iii. साउथ एशियास मिसिंग इंट्रा–रिजनल ट्रेड, मिंट, 1 मई 2017.

iv. डिफेंस पॉलिसी हेज टू बी ए जॉइंट एफर्ट बिटवीन सिविलियन्स एंड द मिलिटरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 11 मई 2017.

v. देयर आर नॉ डिसेंट ऑप्शन इन अफगानिस्तान, मिंट, 29 मई 2017.

vi. वाय प्राइवेट डिफेंस मैनुफेक्चरिंग इन इंडिया नीड्स टू टेक ऑफ, हिंदुस्तान टाइम्स, 12 जून 2017

vii. द एवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन हेगेमोनी, मिंट, 12 जून 2017.

viii. शेख हसीना हेट स्टेट्स कैन ओनली वीकेन डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, हिंदुस्तान टाइम्स, 21 जून 2017.

ix. टुवार्ड्स डिसिफेरिंग बीजेपी हेगेमोनिक प्रोजेक्ट, मिंट, 27 जून 2017

x. सिक्किम स्टैंड ऑफ : इंडिया कैन नॉट एफॉर्ड टू अलाउ चाइना टू चेंज द स्टेट्स क्वा, हिंदुस्तान टाइम्स, 6 जुलाई 2017.

xi. नीडेड : ए म्युचुअल रिस्ट्रेंट पेक्ट विद् चाइना, मिंट, 10 जुलाई 2017.

xii. कश्मीर आर्टिकल 35ए कनन्ड्रम : न्यू दिल्ली मस्ट ट्रीट केयरफुल, हिंदुस्तान टाइम्स, 4 अगस्त 2017.

xiii. चाइना इज रॉन्ग ऑन सिक्किम – तिब्बत बाउंडरी, मिंट, 7 अगस्त 2017.

xiv. हाव आर्म्ड फोर्सेस कैन एड डिफेंस मैन्यूफेक्चरिंग इन इंडिया, मिंट, 21 अगस्त 2017.

xv. अवेयर ऑफ द रॉन्ग लेशन्स फ्रॉम डोकलाम, मिंट, 4 सितंबर 2017.

xvi. हिस्ट्रीस वर्डिक्ट ऑन द रशियन रेवॉल्यूशन, मिंट, 18 सितंबर, 2017.

xvii. टुवर्ड्स ए लेस – रेस्ट्रेंड चाइना, मिंट, 30 अक्टूबर 2017.

xviii. इंडिया – चाइना : ए जीरो – सम रिवलरी?, संगोष्ठी, 31 जनवरी 2018.

xix. आर्मी चीफ रावत स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकल, पुअर्ली जज्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, 23 फरवरी 2018.

xx. द 56–इंच फिस्ट, द टेलीग्राफ, 11 मार्च 2018.

सम्मेलन और संगोष्ठियों में प्रस्तुतीकरण :

i. द 1970 : ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन परस्पेक्टिव्स ऑन ए डिकैड ऑफ ट्रांजिशन, ऑस्ट्रेलिया डेकिन यूनिवर्सिटी, मई 2017.

36. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अध्येता, शुभगतो दासगुप्ता, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :–

नीति संक्षेप :

i. टुवर्ड्स ए न्यू रिसर्च एंड पॉलिसी पैराडिग्म : एन एनालायसिस ऑफ द सेनिटेशन सिचुएशन इन लार्ज डेंस विलेज, शमिंद्र रॉय, आदित्य भोल, दीप्ति राज, 17 नवंबर 2017.

सम्मेलन और संगोष्ठियों में प्रस्तुतीकरण :

i. टैबू टू टोटेम : कंटीन्यूइंग मिसएडवेंचर्स ऑफ सेनीटेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, सिंगापुर, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ स्टडीज (आईएसएएस), नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, 30 अक्टूबर 2017 से 'द क्लीन इंडिया मिशन : चेलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स' पर आईएसएएस – सीपीआर की पैनल चर्चा।

ii. सस्टेनेबल सेनिटेशन : फ्रॉम एविडेंस टू प्रैक्टिस, स्वच्छत भारत मिशन से पारे स्वच्छ भारत की ओर, नई दिल्ली, प्रणीति अनुसंधान केंद्र, 12 दिसंबर 2017

कार्य बल और समिति समूहों की बैठक

i. सदस्य, शहरी बाढ़ विशेषज्ञ समूह, एनडीएमए, भारत सरकार, विशेषज्ञ सदस्य, मार्च 2017 के बाद से।

27. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अध्येता, शिबानी घोष, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थीं :–

सम्मेलन और संगोष्ठियों में प्रस्तुतीकरण :

1. एफएलएस संगोष्ठी श्रृंखला, भारत में जलवायु मुकदमा, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, 18 अप्रैल 2017, नई दिल्ली।

2. वायु और जल प्रदूषण पर राष्ट्रीय सम्मेलन, भारत में प्रदूषण विनियमन के लिए कानूनी रूपरेखा, नीति आयोग और ईपीआईसी – भारत, 7 जुलाई 2017, नई दिल्ली, भारत।

3. 'पर्यावरण कानून, व्याख्या, प्रवर्तन, कानूनी और सांविधिक आवश्यकताएं' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल – अभ्यास और प्रक्रिया, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुडगांव, हरियाणा, 23 अगस्त 2017.

4. केन्या से नागरिक समाज और मीडिया प्रतिनिधियों के लिए भारत में सूचना अधिगम कार्यक्रम का अधिकार, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए आरटीआई अधिनियम का उपयोग, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई), नई दिल्ली, भारत, 3 सितंबर 2017.

गोलमेज और सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण :

1. एनवार्यनमेंटल रेगुलेशन इन इंडिया पर गोलमेज चर्चा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, 20 सितंबर 2017, नई दिल्ली, भारत।

2. रिसोर्स राइट्स, गवर्नेंस एंड ज्यूरिसप्रूडेंस, एनवार्यनमेंटल रेगुलेशन इन इंडिया पर पीएच. डी. अनुसंधान छात्रों के लिए कार्यशाला, मुंबई, टीआईएसएस, 9 दिसंबर 2017.

28. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अध्येता, शैलश्री शंकर, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थीं:–

पुस्तकें :

i. ए सेकुलर एज बियॉन्ड द वेस्ट : रिलीजन, लॉ एंड सेकुलरिटी इन एशिया, द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कांकलर, जॉन मेडली, शैलश्री शंकर, गुरूवार, 1 जून, 2017.

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. एवरीवन लव्स ए गुड सीरियल किलर, शैलश्री शंकर, ओपन मैग्जीन, मंगलवार, 26 दिसंबर 2017

ii. द टेस्टमार्कर ट्रेंड, शैलश्री शंकर, ओपन मैग्जीन, मंगलवार, 27 जून 2017

iii. एंड देन देयर वेयर नॉन, शैलश्री शंकर, ओपन मैग्जीन, सोमवार, 12 जून 2017

iv. द जिनीयोलॉज ऑफ टेस्ट, शैलश्री शंकर, ओपन मैग्जीन, मंगलवार, 30 मई 2017

v. मिस्टीरियस माइंड्स, शैलश्री शंकर, ओपन मैग्जीन, सोमवार, 1 मई

vi. हिंदुस एंड सेक्रेड काव्स : रेसिप फॉर एंडेंटिटी पॉलिटिक्स, शैलश्री शंकर, ओपन मैग्जीन, सोमवार, 24 अप्रैल

29. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अध्येता, जोरावर दौलत सिंह, निम्नलिखित अनुसंधान तथा सहबद्ध क्रियाकलापों में रत थे :–

पत्रिकाओं में लेख :

i. लोकेटिंग द बेल्ट एंड रोड इन चाइना बोर्डर पॉलिसी शिफ्ट्स, शनिवार, 24 जून 2017, जोरावर दौलत सिंह

गैर समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. कॉल टू डोमोक्रेसी, जोरावर दौलत सिंह, द हिंदु, गुरूवार, 8 फरवरी 2018

ii. द पजल ऑफ द 1972 शिमला समिट ऑर वाय इंडिया डिड नॉट इम्पोज इट्स विल, जोरावर दौलत सिंह, द वायर, गुरूवार, 23 नवंबर.

iii. यूएस एंड चाइना विल एवॉइड ए थकाइडिडेस ट्रेप, जोरावर दौलत सिंह, आउटलुक मैग्जीन, शुक्रवार, 25 अगस्त 2017.

iv. गेम ऑफ चिकन इन द हाई हिमालयस, जोरावर दौलत सिंह, द हिंदु, गुरूवार, 13 जुलाई 2017.

v. ए ग्रेट वॉल ऑफ पैरानोया, जोरावर दौलत सिंह, द हिंदु, गुरूवार, 18 मई 2017.

अनुसंधान सहयोगी

1. आदित्या भोल, अनुसंधान एसोसिएट

कार्य पत्र :

i. क्षैतिज और लंबवत असमानता शहरी स्वच्छता तक पहुंच में असमानताओं को समझाना : भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से साक्ष्य, 17 मई, 2017

नीति संक्षेप और अनुसंधान रिपोर्ट :

i. एक नई अनुसंधान और नीति प्रतिमान की दिशा में। बड़े घने गांवों में स्वच्छता की स्थिति का एक विश्लेषण, शुभगतो दासगुप्ता, शमिंद्र, दीप्ति राज, नवंबर 2017

सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किए गए पत्र :

i. द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया, शिकागो, इलिनोइस, पोपुलेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से 28 अप्रैल 2017 को होरिजोंटल एंड वार्टिकल इनक्वेलिटीज एक्प्लेनिंग डिस्पेरिटीज इन एसेस टू अर्बन सेनिटेशन : एविडेंस पर पोपुलेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की वार्षिक बैठक।

गोल मेज सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण :

i. क्षैतिज और लंबवत असमानता शहरी स्वच्छता तक पहुंच में असमानताओं को समझाना : भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से साक्ष्य, सीपीआर, नई दिल्ली, मई 2017

कार्य बल और कार्य समूहों / नीति सलाहकार समिति पर बैठक

i. यूएलबी अधिकारियों, सलाहकार के साथ बालासोर में दिसंबर 2017 को शहरी स्वच्छता योजना और वार्षिक रोलिंग योजना चर्चा।
ii. 2 अमृत टाउन और 2 टाउन (अंगुल और ढेंकनाल) प्रशिक्षु के लिए सीवर रहित स्वच्छता पर क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षकों का कार्यक्रम, 23 नवंबर 2017.

पुरस्कार और अन्य उपलब्धियां :

i. पीएए ट्रेवल पुरस्कार और सदस्यता, पॉपुलेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, शिकागो, अप्रैल 2017

2. अंकित भारद्वाज, अनुसंधान एसोसिएट

नीति संक्षेप और अनुसंधान रिपोर्ट :

i. राजकोट, राधिका खोसला के भारतीय शहरों में मुख्यधारा की जलवायु कार्रवाई : प्रकरण अध्ययन, 1 सितंबर 2017

गैर – समीक्षित पत्रिकाओं में लेख :

i. कैन इंडियन सिटीज़ लीड ऑन क्लाइमेट एक्शन एज देयर गो अबाउट देयर डेवलपमेंट गोल्स?, राधिका खोसला, स्क्रोल.इन, 28 जून 2017

सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किए गए पत्र :

i. शहरी और जलवायु सम्मेलन 2017, ''वी आर ग्रीनर दैन यू थिंक'', सितंबर, पोट्स्डेम, जर्मनी, रामसेस।
ii. इंडो–जर्मन स्मार्ट इनिशिएटिव अर्बन लैब, इंटीग्रेटेड एप्रोचेस इन इंडियन सिटीज, जुलाई, दिल्ली, इंडो–जर्मन स्मार्ट इनिशिएटिव।
iii. कैपसिटीज क्लाइमेट एक्शन प्लान वर्कशॉप, मल्टी– ऑब्जेक्टिव एप्रोच टू क्लामेट प्लानिंग, जुलाई, कोयम्बटूर, आईसीएलईआई एसए।

3. अंजू द्विवेदी, वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट

नीति संक्षेप और अनुसंधान रिपोर्ट :

i. शहरी स्थानीय निकायों और स्वच्छता पर राज्य सरकार के लिए क्षमता निर्माण कार्यनीति : ओडिशा, पद्मजा नायर, 24 जनवरी 2018
ii. भारत में शहरी स्वच्छता में सुधार : मलेशिया से सबक, अमनदीप सिंह, 16 जून 2017

iii. क्षमता निर्माण के लिए स्वच्छता पर शहरों (अंगुल और ढेंकनाल) और राज्य सरकार के आकलन की आवश्यकता है : ओडिशा का एक प्रकरण अध्ययन, पद्मजा नायर 16 जनवरी 2018

कार्य बल पर बैठक और कार्य समिति :

i. यूएलबी अधिकारियों, सलाहकार के साथ बालासोर में दिसंबर 2017 को शहरी स्वच्छता योजना और वार्षिक रोलिंग योजना चर्चा।
ii. 2 अमृत टाउन और 2 टाउन (अंगुल और ढेंकनाल) प्रशिक्षु के लिए सीवर रहित स्वच्छता पर क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षकों का कार्यक्रम, 23 नवंबर 2017.

नीति निर्माता के साथ लक्षित बैठक :

i. अंगुल और ढेंकनाल में प्रोजेक्ट निर्मल के पिछले वर्ष की योजना पर बैठक और ढेंकनाल सचिव, एचयूडीडी, ओएसएसबी से अधिकारियों, टीएसयू के लिए प्रचालन और रखरखाव के लिए योजना, 18 मई 2018.

ii. ईओ, उपाध्यक्ष और अन्य जिला अधिकारियों के साथ ढेंकनाल डीसी, ढेंकनाल के परियोजना समर्थन के पिछले वर्ष की बैठक और योजना का प्रचालन और रखरखाव, 6 जून 2018.
iii. एचयूडीडी, ओडब्ल्यूएसएसबी, टीएसयू, अभ्यास कार्य, एसबीएम पीएमयू अधिकारियों से गैर सीवर स्वच्छता अधिकारियों पर क्षमता निर्माण मॉड्यूल पर बैठक, 5 जुलाई 2017.
iv. गैर सीवर सेनिटेशन, सचिव एचयूडीडी, टीएसयू, ओडब्ल्यूएसएसबी पर अंतिम सीबी मॉड्यूल पर बैठक, 10 अक्टूबर 2017

4. अम्बरिश करुणानिधि, वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट

कार्य बल पर बैठक और कार्य समूह :

i. यूएलबी अधिकारियों, सलाहकार के साथ बालासोर में दिसंबर 2017 को शहरी स्वच्छता योजना और वार्षिक रोलिंग योजना चर्चा।
ii. 2 अमृत टाउन और 2 टाउन (अंगुल और ढेंकनाल) प्रशिक्षु के लिए सीवर रहित स्वच्छता पर क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षकों का कार्यक्रम, 23 नवंबर 2017.

नीति निर्माओं के साथ लक्षित बैठक :

i. अंगुल और ढेंकनाल में प्रोजेक्ट निर्मल के पिछले वर्ष की योजना पर बैठक और ढेंकनाल सचिव, एचयूडीडी, ओएसएसबी से अधिकारियों, टीएसयू के लिए प्रचालन और रखरखाव के लिए योजना, 18 मई 2018.
ii. ईओ, उपाध्यक्ष और अन्य जिला अधिकारियों के साथ ढेंकनाल डीसी, ढेंकनाल के परियोजना समर्थन के पिछले वर्ष की बैठक और योजना का प्रचालन और रखरखाव, 6 जून 2018.
iii. एचयूडीडी, ओडब्ल्यूएसएसबी, टीएसयू, अभ्यास कार्य, एसबीएम पीएमयू अधिकारियों से गैर सीवर स्वच्छता अधिकारियों पर क्षमता निर्माण मॉड्यूल पर बैठक, 5 जुलाई 2017.
iv. गैर सीवर सेनिटेशन, सचिव एचयूडीडी, टीएसयू, ओडब्ल्यूएसएसबी पर अंतिम सीबी मॉड्यूल पर बैठक, 10 अक्टूबर 2017.

5. अंकित भाटिया, अनुसंधान एसोसिएट

अनुसंधान रिपोर्ट :

i. भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के भूमि अधिकारों का कानूनी शासन और राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नमिता वाही, अंकित भाटिया, 15 मार्च, 2018.

6. अश्विन परुलकर, वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट

पुस्तकें :

i. डिस्पज़ेज़्ड : स्टोरिस फ्रॉम इंडियाज मर्जिन्स, अमोद शाह, अहमद इमान, एनिया बैक्सी, अश्विन परुलकर, रहिया जॉन, साबा शर्मा, शिक्षा सेठिया, 4 जनवरी, 2018

गैर – समीक्षा पत्रिकाओं में लेख :

i. द गवर्नमेंट मस्ट कम्पेनसेट फॉर द डिमॉनिटाइजेशन सेटबैक टू माइग्रेंट्स मोबिलिटी, मुक्ता नायक, इशा कुंडुरी, अश्विन परुलकर, हिंदुस्तान टाइम्स, 17 जनवरी 2017.

कार्य पत्र :

i. बिकमिंग होमलेस, सरवाइविंग होमलेसनेस अश्विन परुलकर, 21 अप्रैल, 2017

7. देबयान गुप्ता, अनुसंधान एसोसिएट

कार्य पत्र :

i. मैपिंग डिल्यूजन्स इन इंडियाज 2013 लैंड एक्वीजिशन लॉ – ऑकेजनल पेपर, कांची कोहली और देबयान गुप्ता, 25 सितंबर 2017

वेब आधारित प्रकाशन :

i. प्रपोज्ड एमेंडमेंट्स टू एनवायर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कुड लीगलाइज्ड वायलेशन्स, मंजू मेनन, कांची कोहली, कृतिका दिनेश और देबयान गुप्ता, द वायर, 2 अगस्त 2017
ii. इन स्टेट – लेवल चेंजेस टू लैंड लॉ, ए रिटर्न टू लैंड ग्रेबिंग इन डेवलपमेंट्स नेम, मंजू मेनन, कांची कोहली और देबयान गुप्ता, द वायर, 9 सितंबर 2017

8. दीप्ति राज, अनुसंधान एसोसिएट

नीति संक्षेप :

i. एक नई अनुसंधान और नीति प्रतिमान की दिशा में : बड़े घने गांवों में स्वच्छता की स्थिति का एक विश्लेषण, शुभगतो दासगुप्ता, शमिंद्रा नाथ रॉय, आदित्या भोल, दीप्ति राज, 17 नवंबर 2017

9. देवाशीष देशपांडे, अनुसंधान एसोसिएट

गैर – समीक्षा पत्रिकाओं में लेख :

i. स्थायी स्वच्छता की ओर झुकाव, अवनी कपूर, देवाशीष देशपांडे, मिंट, 24 जनवरी 2018

नीति संक्षेप :

i. बजट संक्षेप 2018–19 : स्वच्छ भारत मिशन – अर्बन (एसबीएम –यू) देवाशीष देशपांडे, अवनी कपूर, 3 फरवरी, 2018
ii. बजट संक्षेप 2018–19 : स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम –जी), अवनी कपूर, देवाशीष देशपांडे, 3 फरवरी, 2018
iii. बजट संक्षेप 2018–19 : सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स (एसआरएमएस) देवाशीष देशपांडे, अवनी कपूर, 3 फरवरी, 2018

10. इशा कुंडुरी, अनुसंधान एसोसिएट

नीति संक्षेप :

i. भारत में युवा : संभावनाएं और चुनौतियां, भानू जोशी, 1 जुलाई 2017

सम्मेलन और गोष्ठियों में प्रस्तुतीकरण :

i. सोशल चेंज सेमिनार सीरीज बीटवीन 'खेत', 'फैक्टरी' एंड 'कॉलोनी' : एक्सप्लोरिंग इंटरसेक्शन्स ऑफ कास्ट एंड जेंडर अमंग माइग्रेंट इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दिल्ली, सीपीआर, 28 जून 2017
ii. लेखक कार्यशाला, इंटर्नल माइग्रेशन इन इंडिया (श्रमिक प्रोजेक्ट), सिटी लाइट्स ऑर लॉगिंग फॉर होम : अंडरस्टैंडिंग माइग्रेशन डिसिजन टू द सिटी ऑफ दिल्ली, मुंबई आईजीआईडीआर, 10 जुलाई, 2017
iii. यूजे सोशियालॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड डेवपलमेंट स्टडीज वेडनसडे सेमिनार, कास्ट, जेंडर एंड द (रि) शेपिंग ऑफ माइग्रेंट आइडेंटिटीज : इनसाइट्स फ्रॉम टू इंडियन सिटीज, जॉनसबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ जॉनसबर्ग (फैकल्टी ऑफ ह्यूमनिटीज), 1 नवंबर, 2017

11. कांहू चरण प्रधान, वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट

पत्रिका लेख :

i. ऑनली 'गुड पीपल', प्लीज : रेजिडेंशियल सेग्रेगेशन इन अर्बनाइजिंग इंडिया, त्रिना विठयथिल, गायत्री सिंह, कांहू चरण प्रधान, 8 मार्च 2017

गैर – समीक्षा पत्रिकाओं में लेख :

i. बीयॉन्ड लार्ज सिटीज, अंडरस्टैंडिंग सेंसस टाउन्स इन इंडिया, कांहू चरण प्रधान, माई डिजिटल एफसी, 4 जनवरी 2018

13. कृतिका दिनेश, अनुसंधान एसोसिएट

कार्य पत्र :

i. पूर्व से पश्चात तक : पर्यावरण उल्लंघन का कानूनीकरण, कृतिका दिनेश और कांची कोहली, जुलाई 2017

वेब आधारित प्रकाशन :

i. एनाटोमी ऑफ लीगलाइजिंग वॉलेशन्स : एनवायर्नमेंट मिनिस्ट्रीस पॉलिसी ऑफ पोस्ट फैक्टो एप्रूवल्स, कृतिका दिनेश और कांची कोहली, काउंटरव्यू, जुलाई 2017
ii. प्रोपोज्ड एमेंडमेंट्स टू एनवायर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कुड लीगलाइज वॉलेशन्स, मंजू मेनन, कांची कोहली, कृतिका दिनेश और देबयान गुप्ता, द वायर, अगस्त 2017
iii. इंडियाज कोस्टल लॉ इज बीइंग अल्टरर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट – बाय बाइपासिंग द पब्लिक मीनाक्षी, कपूर और कृतिका दिनेश, स्क्रोल, अक्तूबर 2017
iv. अपहोल्डिंग वर्ल्ड बैंक इम्युनिटी इन केस अगेंस्ट गुजरात फिशरमैन विल हैव लॉन्ग – टर्म रैमिफिकेशन्स, देबयान गुप्ता, कृतिका दिनेश, मंजू मेनन और कांची कोहली, द वायर, नवंबर 2017
v. अपहोल्डिंग वर्ल्ड बैंक इम्युनिटी इन केस अगेंस्ट गुजरात फिशरमैन विल हैव लॉन्ग – टर्म रैमिफिकेशन्स, देबयान गुप्ता, कृतिका दिनेश, मंजू मेनन और कांची कोहली, द वायर, नवंबर 2017

14. कश्यप अरोड़ा, अनुसंधान एसोसिएट

नीति संक्षेप :

i. भारत – बांग्लादेश विकास साझेदारी : भारत द्वारा अपने पूर्वी पड़ोसी के लिए 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार, डॉ. रानी डी. मुलेन, 25 अक्तूबर 2017
ii. दक्षिण – दक्षिण विकास सहयोग : भारत और चीन के विदेश विकास सहयोग के मॉडल का विश्लेषण, डॉ. रानी डी. मुलेन, 21 दिसंबर 2017

वेब आधारित प्रकाशन :

i. मेजरिंग इंक्लुसिविटी, इकॉनोमिक्स ऑफ एवरीथिंग वेबसाइट, 26 नवंबर 2017
ii. मेजरिंग इक्लुसिविटी इन इंडिया, इकॉनोमिक्स ऑफ एवरीथिंग वेबसाइट, 16 दिसंबर 2017

15. मधुरा जोशी, वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट

गोलमेल सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण :

i. जेंडर और ऊर्जा की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय परामर्श, नई दिल्ली, एम. एस. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन, 1 नवंबर 2017

16. मनीष, अनुसंधान एसोसिएट

गैर – समीक्षा पत्रिकाओं में लेख :

i. डिस्पाइट आरईआरए, सेंटर एंड स्टेट्स नॉट डुइंग इनफ टू प्रोटेक्ट होम बायर्स, मनीष, हिंदुस्तान टाइम्स, 23 अगस्त 2017

17. मेघना श्रीवास्तव, अनुसंधान एसोसिएट

नीति निर्माताओं के साथ लक्षित बैठक :

i. प्रौद्योगिकी और शासन पर परस्पर संवाद चर्चा : आधार गोपनीयता चिंताएं और डेटाबेस सुरक्षा, संसद सदस्य और क्षेत्र विशेषज्ञ, 12 मार्च, 2018
ii. केंद्रीय बजट 2018 में बनाए गए स्वास्थ्य प्रतिबद्धताओं पर गोलमेज चर्चा, संसद सदस्य और क्षेत्र विशेषज्ञ, 21 मार्च 2018
iii. वूड्रोव विल्सन स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में 30 अप्रैल – 5 मई, 2017 को भारतीय सांसदों के लिए 2017 प्रिंसटन – जीपीपीआई – सीपीआर सामरिक मामलों का कार्यक्रम, भारतीय संसद सदस्यों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम।
iv. भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ऑस्ट्रेलिया का दौरा, ऑस्ट्रेलिया विदेशी कार्यालय के साथ सहयोग में भारतीय सांसदों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम, 17–26 जून, 2017
v. भारत में बाल स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने पर परस्पर संवाद चर्चा, संसद सदस्य और क्षेत्र विशेषज्ञ, 2 अगस्त 2017
vi. द लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स में 29 अक्तूबर – 4 नवंबर 2017 को आयोजित भारतीय नेताओं के लिए 2017 चेवेनिंग – सीपीआर सांसदों की अध्येतावृत्ति, चेवेनिंग कार्यक्रम, यूके के साथ वार्षिक शैक्षणिक कार्यक्रम
vii. वूड्रोव विल्सन स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में 30 अप्रैल – 5 मई 2017 को भारतीय सांसदों के लिए 2017 प्रिंसटन – जीपीपीआई – सीपीआर सामरिक मामलों का कार्यक्रम, भारतीय संसद सदस्यों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम।
viii. भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ऑस्ट्रेलिया का दौरा, ऑस्ट्रेलिया विदेशी कार्यालय के साथ सहयोग में भारतीय सांसदों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम, 17–26 जून, 2017
ix. भारत में बाल स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने पर परस्पर संवाद चर्चा, संसद सदस्य और क्षेत्र विशेषज्ञ, 2 अगस्त 2017

18. मुक्ता नायक, वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट

पत्रिका लेख :

i. एन एनालायसिस ऑफ 'माइग्रेंट – इंटेंसिटी' इन इंडिया एंड इंडोनेशिया, ग्रेगरी एफ रान्डॉल्फ, पर्यावरण और शहरीकरण एशिया, खंड 8 अंक 1, 8 मार्च 2017
ii. गिविंग माइग्रेंट्स देयर ड्यू, पार्थ मुखोपध्याय, शेल्टर (हुडको – एचएसएमआई) खंड 18 सं., अक्तूबर 2017

iii. ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइएंगुलेटिंग डेटा सेट्स टू एक्जामिन इंडियन्स ऑन द मूव, एस चंद्रशेखर, शमिंद्र नाथ रॉय, इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 52 सं. 47, नवंबर 2017

संपादित खंडों में अध्याय :

i. ऑन एजेंसी, पार्टिसिपेशन एंड डिजाइन : टू कंट्रास्टिंग प्ले सेनेरियोस इन इंडियन सिटीज, हाव टू ग्रो ए प्लेस्पेस : डेवलपमेंट एंड डिजाइन, कैथरीन मैसियूलेनिस, एलिजाबेथ क्यूमिन्स, रूटलेज, टेलर और फ्रांसिस, मार्च 2017

नीति संक्षेप :

i. निर्माण कार्य में प्रवासी : उनकी कल्याण संरचना का मूल्यांकन, शमिंद्र नाथ रॉय, मनीष, जून 2017

कार्य पत्र :

i. ऑन द इम्पोटेंस ऑफ ट्राइएंगुलेटिंग डेटा सेट्स टू एक्जिमिन इंडियान्स ऑन द मूव, एस चेंद्रशेखर, शमिंद्र नाथ रॉय, नवंबर 2017

गैर – समीक्षा पत्रिकाओं में लेख :

i. द गवर्नेमेंट मस्ट कम्पेंसेट फॉर द डिमोनेटाइजेशन सेटबैक टू माइग्रेंट्स मोबिलिटी, इशा कुडुरी, अश्विन परुलकर, हिंदुस्तान टाइम्स, जनवरी 2017

सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण :

i. इमर्जेंट फॉर्म्स ऑफ अर्बन डेसिफिकेशन इन एशिया : शेयर्ड परस्पेक्टिव्स, रेंटल हाउसिंग एज ए कॉपिंग स्ट्रेटेजी इन अर्बन विलेजेस' ट्रांसफॉर्मेशन : ए कॉपरेटिव स्टडी ऑफ फु डियान विलेज, वियतनाम और सिकंदरपुर घोसी गांव, गुड़गांव, भारत, हैनॉई, वियतनाम सीईपीईडी और हैनॉई आर्किटेक्चरल यूनिवर्सिटी, नवंबर 2017
ii. सीईएसएसएमए, आईआरडी, पेरिस, फ्रांस में मासिक संगोष्ठी श्रृंखला, गुड़गांव में कॉमन्स का विनाश और रीमेकिंग : शहरी संक्रमण के लिए ग्रामीण की जनहानि, पेरिस, फ्रांस, सीईएसएसएमए, आईआरडी, पेरिस, फ्रांस, 5 अक्तूबर 2017

कार्य बल और कार्य समूहों की बैठक :

i. राष्ट्रीय शहरी आवास और आवास नीति के संशोधन के लिए विशेषज्ञ समूह, सदस्य, अगस्त 2017

19 मृदुस्मिता, वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट

नीति संक्षेप :

i. बजट संक्षेप 2018–19 : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) अवनी कपूर, मृदुस्मिता बोरदोलोई, और रितिका शुक्ला, 1 फरवरी 2018
ii. बजट संक्षेप 2018–19 : सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), अवनी कपूर, मृदुस्मिता बोरदोलोई, और रितिका शुक्ला, 1 फरवरी 2018

सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण :

i. इंटरनेशनल पॉलिसी फोरम ऑन यूजिंग ओपन स्कूल डेटा टू कोम्बेट करप्शन, यूनेस्को – आईआईईपी, यूज ऑफ ओपन स्कूल डेटा फॉर इम्प्रूविंग आउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया, मनिला, फिलिपीन्स यूनेस्को – आईआईईपी, 24 से 26 जनवरी, 2018

नीति निर्माताओं के साथ लक्षित बैठक :

i. एनसीईआरटी के साथ संभावित सहयोग की खोज, प्रमुख, सर्वे प्रभाग फरवरी, 2018

12. सामा खान, अनुसंधान एसोसिएट

संपादित खंडों में अध्याय :

i. द अदर जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएवल मिशन : वट डोज इट मीन फॉर स्मॉल टाउन इंडिया? सामा खान, भारत में उपनगरीय शहरीकरण, एरिक डेनिस और मैरी – हेलेन जेराह, स्प्रिंगर, अप्रैल 2017

गैर – समीक्षा पत्रिकाओं में लेख :

i. फॉर स्वच्छ इंडिया, फोकस ऑन सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हिंदुस्तान टाइम्स, 4 अक्तूबर 2017

20. स्टेनजिन यमचेन, अनुसंधान एसोसिएट

नीति निर्माताओं के साथ लक्षित बैठक :

i. प्रौद्योगिकी और शासन पर परस्पर संवाद चर्चा : आधार की गोपनीयता पर चिंताएं और डेटाबेस सुरक्षा, संसद सदस्य और क्षेत्र विशेषज्ञ, 12 मार्च, 2018
ii. केंद्रीय बजट 2018 में बनाए गए स्वास्थ्य प्रतिबद्धताओं पर गोलमेज चर्चा, संसद सदस्य और क्षेत्र विशेषज्ञ, 21 मार्च 2018
iii. वूड्रोव विल्सन स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में 30 अप्रैल – 5 मई, 2017 को भारतीय सांसदों के लिए 2017 प्रिंसटन – जीपीपीआई – सीपीआर सामरिक मामलों का कार्यक्रम, भारतीय संसद सदस्यों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम।
iv. भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ऑस्ट्रेलिया का दौरा, ऑस्ट्रेलिया विदेशी कार्यालय के साथ सहयोग में भारतीय सांसदों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम, 17–26 जून, 2017

v. भारत में बाल स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने पर परस्पर संवाद चर्चा, संसद सदस्य और क्षेत्र विशेषज्ञ, 2 अगस्त 2017

vi. द लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स में 29 अक्तूबर – 4 नवंबर 2017 को आयोजित भारतीय नेताओं के लिए 2017 चेवेनिंग – सीपीआर सांसदों की फैलोशिप, चेवेनिंग कार्यक्रम, यूके के साथ वार्षिक शैक्षणिक कार्यक्रम।

vii. वूड्रोव विल्सन स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में 30 अप्रैल – 5 मई, 2017 को भारतीय सांसदों के लिए 2017 प्रिंसटन – जीपीपीआई – सीपीआर सामरिक मामलों का कार्यक्रम, भारतीय संसद सदस्यों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम।

viii. भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ऑस्ट्रेलिया का दौरा, ऑस्ट्रेलिया विदेशी कार्यालय के साथ सहयोग में भारतीय सांसदों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम, 17–26 जून, 2017

ix. भारत में बाल स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने पर परस्पर संवाद चर्चा, संसद सदस्य और क्षेत्र विशेषज्ञ, 2 अगस्त 2017.

21. किम्बर्ली नोरोन्हा

नीति संक्षेप :

i. भारत में मैनुअल स्केवेन्जिंग : एक साहित्य समीक्षा और एनोटेटेड ग्रंथसूची, किम्बर्ली एम नोरोन्हा, तृप्ति सिंह, मलिक, सोमवार, 19 मार्च 2018.

22. पेर्सिस तारापोरेवाला, अनुसंधान एसोसिएट

गैर – समीक्षा पत्रिकाओं में लेख :

i. टू सक्सेस्ड, सिटीजन्स, मस्ट हेव मोर से इन द स्मार्ट सिटीज मिशन पेर्सिस तारापोरेवाला, भानू जोशी, हिंदुस्तान टाइम्स, 22 अगस्त 2016

23. भानू जोशी, अनुसंधान एसोसिएट

गैर – समीक्षा पत्रिकाओं में लेख :

i. बायवाड्र्स इन बुंदेलखंड, नीलांजन सिरकर, भानू जोशी, आशीष रंजन, द हिंदु, 28 फरवरी 2017

ii. टू सक्सेस्ड, सिटीजन्स, मस्ट हेव मोर से इन द स्मार्ट सिटीज मिशन पेर्सिस तारोपोरेवाला, भानू जोशी, हिंदुस्तान टाइम्स, 22 अगस्त 2016

नीति संक्षेप :

i. भारत में युवा : संभावनाएं और चुनौतियां, भानू जोशी, इशा कुंडुरी शनिवार, 1 जुलाई 2017

25. शमिंद्र नाथ रॉय, अनुसंधान एसोसिएट

पत्रिका लेख :

i. ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइएंगुलेटिंग डेटा सेट्स टू एक्जामिन इंडियन्स ऑन द मूव, एस. चंद्रशेखर, मुक्ता नायक, इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली खंड 52, अंक 57, 25 नवंबर 2017

नीति संक्षेप :

i. एक नई अनुसंधान और नीति प्रतिमान की दिशा में : बड़े घने गांवों में स्वच्छता की स्थिति का एक विश्लेषण, शुभगतो दासगुप्ता, शमिंद्रा नाथ रॉय, अदित्या भोल, दीप्ति राज, 17 नवंबर 2017

कार्य पत्र :

i. ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइएंगुलेटिंग डेटा सेट्स टू एक्जामिन इंडियन्स ऑन द मूव, एस. चंद्रशेखर, मुक्ता नायक, 24 नवंबर 2017

26. तृप्ति सिंह, अनुसंधान एसोसिएट

नीति संक्षेप :

i. भारत में मैनुअल स्केवेन्जिंग : एक साहित्य समीक्षा और एनोटेटेड ग्रंथसूची, किम्बर्ली नोरोन्हा, महिमा मलिक, मार्च 2018

गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण

i. जेंडर्ड हाउसहोल्ड डिजिशन मेकिंग अमंग द पुअर : ए बैरियर टू टॉयलेट एडोप्शन?, आईएचसी, दिल्ली, सीयूआरई, जनवरी 2018

कार्य बल और कार्य समूहों की बैठक :

i. स्वच्छता पर जेंडर कार्यबल, यह अपने सदस्यों के लिए उन मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है जो राष्ट्रीय स्वच्छता एजेंडा में जेंडर को एकीकृत करने के लिए आवश्यक समाधानों के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, फरवरी, 2017 – जारी

नीति निर्माताओं के साथ लक्षित बैठक :

i. स्वच्छता क्षेत्र में कौशल और आजीविका पर कार्यशाला, एमएचयूए, 12 जनवरी, 2018
ii. स्वच्छता में जाति और लिंग आधारित भेदभाव पर चर्चा करने के लिए बैठक, जल और स्वच्छता के लिए मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र विशेष संवाददाता, 29 अक्तूबर 2017

27. विंसी डेविस, अनुसंधान एसोसिएट

पत्रिका लेख :

i. आरटीई एक्ट एंड पैराडाइम शिफ्ट्स इन स्टूडेंट एसेसमेंट्स, विंसी डेविस, तान्या कपूर, आईएपीएस डायलॉग : द ऑनलाइन मैग्जीन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया एंड पेसिफिक स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, फरवरी 2018

सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण :

i. मैक्सिको सिटी, सीआईईएस, टीचर्स कॉलेज, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी, में मार्च 2018 को ''रिमैपिंग ग्लोबल एजुकेशन : साउथ – नॉर्थ डायलॉग'', ''रिथिंकिंग टीचस प्रैक्टिस – लेशन्स फ्रॉम इक्वारिज इनटू स्टडीज ऑन टीचर फंक्शनिंग इन दिल्ली'' पर तुलनात्मक और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी की वार्षिक सम्मेलन।

वेब आधारित प्रकाशन :

i. ब्रिजिंग गैप्स बीटवीन सिटीजन्स एंड द ब्यूरोक्रेसी – पार्ट 1 विंसी डेविस, 30 जून
ii. ब्रिजिंग गैप्स बीटवीन सिटीजन्स एंड द ब्यूरोक्रेसी – पार्ट 2 विंसी डेविस, 7 जुलाई
iii. राइट टू हूज एजुकेशन? विंसी डेविस, 15 जून
iv. लाइफ हैक्स टू एवेल गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड सर्विसेस, विंसी डेविस, 9 मई

गोल मेज सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण :

i. गुणात्मक अनुसंधान में एन विवो का उपयोग कर अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य उपेक्षित समूहों से संबंध में छात्रों और व्याख्यानकर्ता के लिए सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पर उन्मुख कार्यक्रम, 30 नवंबर – 2 दिसंबर, 2017, प्रणीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली, प्रणीति अनुसंधान केंद्र।
ii. विकास अभ्यास में अनुसंधान के तरीके और इसके अनुप्रयोग – विकास अभ्यास में अनुसंधान के तरीकों और इसके अनुप्रयोगों की कार्यशाला, 13 अक्तूबर, 2017 इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट, नोएडा इंडयन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट

नीति निर्माताओं के साथ लक्षित बैठक :

i. शिक्षकों के समय आबंटन अध्ययन के अस्थायी निष्कर्षों की चर्चा, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 11 अक्तूबर 2017
ii. सीआरसीसी, बिहार राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के समय पर उपयोग के अध्ययन से निष्कर्षों की चर्चा, 25 नवंबर 2017
iii. दिल्ली शिक्षा सुधार, निदेशक, शिक्षा को अनपैक करने पर चल रही परियोजना से प्रारंभिक निष्कर्षों की चर्चा; शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सलाहकार, 20 नवंबर 2017

28. संदीप भारद्वाज, अनुसंधान एसोसिएट

गैर – समीक्षा पत्रिकाओं में लेख :

i. श्री लंका : द सिली साइड ऑफ चाइनीज ''नियो – इम्पेरिलिज्म'', आईएपीएस डायलॉग, 6 फरवरी 2018
ii. 'ब्लैक पेंथर' एंड द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ एशियन एस्पिरेशन्स, मिंट, 27 फरवरी 2018
iii. इंडिया एंड द मेंटल ऑफ रिजनल हेजमोन, आईएपीएस डायलॉग 13 मार्च 2017
iv. वाय इंडिया नीड्स टू बी एग्रेसिव अगेंस्ट चाइना इन डोकलाम स्टैंडोफ, मिंट, 28 जुलाई 2017
v. डोकलाम मेय ब्रिंग भूटान क्लोजर टू इंडिया, मिंट, 9 अगस्त 2017
vi. भूटान की सुरक्षा, भारत का जिम्मा (हिंदी में) राष्ट्रीय सहारा, 9 अगस्त 2017

वेब आधारित प्रकाशन :

i. राइजिंग टाइड ऑफ एक्स्ट्रीमिज्म इन बांग्लादेश, आईएपीएस डायलॉग, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, 20 सितंबर 2017
ii. लाइफ एंड डैथ ऑफ द इंडिया – पाकिस्तान सीज़फायर एग्रीमेंट, आईएपीएस डायलॉग, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, 16 अक्तूबर 2017

29. रितिका कालिता, अनुसंधान एसोसिएट

अनुसंधान रिपोर्ट :

i. इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर एंड वॉयलेंस : विमैन एंड स्लम सेनिटेशन इनक्वालिटीज इन दिल्ली, सुसन चेप्लिन, रितिका कालिता, 16 अक्तूबर, 2017

30. सुसन चेप्लिन

कार्य पत्र :

i. जेंडर, अर्बन सेनिटेशन इनक्वालिटीज एंड एवरीडे लाइव्स : ए लिटरेचर रिव्यू एंड एनोटेशन बिबलियोग्राफी, 2017, अगस्त
ii. इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर एंड वॉयलेंस विमैन एंड स्लम सेनिटेशन इनक्वालिटीज इन दिल्ली : अनुसंधान रिपोर्ट, कालिटा, रितिका, 2017, अक्तूबर

सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण

i. सेनिटेशन फॉर पीपल : एसेसिंग सोशल – कल्चरल रियलटीज ऑफ सेनिटेशन प्रैक्टिस इन इंडियन सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर एंड वॉयलेंस : विमैन एंड स्लम सेनिटेशन इनइक्वालिटीज, 29 मार्च 2017

34. ऋत्विक शुक्ला, अनुसंधान एसोसिएट

नीति संक्षेप

i. एसएसए बजट संक्षेप, अवनी कपूर, मृदुस्मिता बोर्डोली, 2 फरवरी 2018
ii. आरएमएसए बजट संक्षेप, अवनी कपूर, मृदुस्मिता बोर्डोली, 2 फरवरी 2018

वेब आधारित प्रकाशन :

i. डिजिटाइजिंग वेलफेयर : लेसन्स फ्रॉम रूरल बिहार, एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव ब्लॉग्स 22 फरवरी 2018

35. मेरिया – हेलेन जेरह, अतिथि अध्येता

कार्य पत्र :

i. डिमेंडेट एसेप्टेबिलिटी सोशल्स डि 1' एसेनिसेमेंट : लेस, इंजेक्स इनविजिबल डि जेनरे, डि कास्ट एट डि'एम्पॉई., स्वेता केस इन एल' एसेनिसेमेंट एट सेस इंजेक्स, नोट्स टेक्नीक्स एन डिग्री 21, एगेंस फ्रांसिस डि डेवलपमेंट, पेरिस, मार्च 2018
ii. वर्किंग इन टेंडेम : द इनफार्मल सेप्टिक टैंक इम्पिटाइंग बिजनेस इन अया नगर, दिल्ली, स्वेता केस, सीपीआर वर्किंग रिपोर्ट, दिसंबर 2017

गैर – समीक्षा पत्रिकाओं में लेख :

i. ली पेटिटस विपेज, 1' एयूट्रे विसेज डि 1' अर्बनाइजेशन इन इंडे, द कंवर्जेशन, 8 मार्च 2018

सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण के लिए शोध पत्र प्रस्तुति :

i. इमर्जेंट फॉर्म्स ऑफ अर्बन डेंसिफिकेशन इन एशिया। साझा मुद्दे। डिबेटिंग द रिलेशनशिप्स बीटवीन डेंसिटी एंड गवर्नेंस एंड बेसिक सर्विसेज : कम्परेटिव व्यू फ्रॉम टू केस स्टडीज इन इंडिया एंड इंडोनेशिया, हैनॉई, वियातनाम, हैनॉई आर्किटेक्टचरल यूनिवर्सिटी, परामिता राहायु और स्वेता केस के साथ सह–लेखक, नवंबर 2017.

पुस्तकालय और सूचना एवं प्रसार सेवाएं

वर्ष 2017–18 के दौरान, केन्द्र के पुस्तकालय में 119 नई पुस्तकें मंगवाई गईं। मुख्य रूप से संग्रहण के कार्यक्रम में केवल नीति विज्ञान आर्थिक नीति, शहरीकरण, राजनीति विज्ञान, भविष्य विज्ञान, सामाजिक संसूचक, विदेश नीति, रक्षा एवं अन्य क्षेत्रों के अनुसंधान से संबंधित विषयों पर होता है।

सीपीआर के पुस्तकालय में पत्रिकाओं सहित कुल संग्रह 10742 अंकों का है। पुस्तकालय में 46 जर्नल्स आते हैं और वर्ष के दौरान 50 पत्रिकाओं अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये सीपीआर के विद्वानों के चिंतन के विषय का व्यापक हिस्सा कवर करते हैं। इसके अलावा, 16 समाचार पत्र प्रतिदिन आते हैं।

पुस्तकालय 'डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क' (डेलनेट), नई दिल्ली का सदस्य बना रहा। संचार व सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए, सैमसंग एससीएक्स 4521एफ मल्टीफंक्शनल फैक्स मशीन व ई–मेल सेवाएं पूरी तरह उपयोग में लाई जाती हैं। एक एचपी इलीट 8300 सीपीआर संकाय / अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

एक रिको एफिसियो एमपी 4000 बी डिजिटल प्लेन पेपर कॉपियर के साथ रिवर्स ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर, स्वचालित बैक टू बैक फोटोकॉपी के लिए डुप्लेक्सिंग, सेट बनाना, छांटना, रोटेट सोर्टिंग, 25 प्रतिशत–400 प्रतिशत जूम के साथ ए3 साइज़ नेटवर्क लेजर प्रिंटर और स्कैनर तथा डॉक्यूमेंट सर्वर के लिए 40 जीबी हार्ड डिस्क को खरीद कर पुस्तकालय में लगाया गया है

अन्य सामग्री व प्रकाशन हेतु सीपीआर का पुस्तकालय दिल्ली में स्थित उन सभी विभिन्न शैक्षणिक एवं अन्य अनुसंधान संस्थानों के 20 पुस्तकालयों से भी सहायता लेता है जो केन्द्र में उपयोग के लिए अपनी पुस्तकें व जर्नल्स आपसी आदान–प्रदान के सिद्धांत के अनुसार जारी करते हैं।

वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए।

1. गूगल एप पर डोमेन में होस्ट की गई सेवाओं का प्रयोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार रखरखाव किया गया और कनफिगर किया गया।
2. केंद्र ने टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड से डेटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड से अपनी इंटरनेट लीज लाइन (आईएलएल) लिंक माइग्रेट की और इंटरनेट बैंडविड्थ को इसके डेटा ट्रैफिक मांग को पूरा करने के लिए 16 एमबीपीएस से 30 एमबीपीएस तक बढ़ा दिया गया था। बैंडविड्थ आबंटन नीति को उनके उपयोग (डाउनलोड / अपलोडिंग) के अनुसार संकाय, कर्मचारी और संचार आदि जैसे समूहों के बीच वितरण द्वारा ठीक किया गया था।
3. बाहरी जोखिमों से केंद्र के नेटवर्क और गेटवे की सुरक्षा के लिए, नेटवर्क में अवांछित सामग्री फिल्टर करने की रोकथाम की और नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक विभिन्न नीतियों का कार्यान्वयन किया, डेलसोनिक वॉल फायरवॉल की परिभाषाओं को कंफिगर किया गया।
4. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लाइसेंस की खरीद और निपटान

   क. 14 लैपटॉप, एक एचपी लेजरजेट प्रिंटर, एप्पल आईपैड, दो टेबलेट, एक प्रोजेक्टर और वन जोन फ्लेक्स आर610 एसेस पॉइंट (एपी) खरीदे, कंफिगर किए गए थे और प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार इंस्टॉल किए गए थे।

   ख. एडोब क्रिएटिव क्लाउड सुइट (2 नंबर), ऑटो कैड एलटी 2018 डेस्कटॉप डीटीएस (01 नग) के लाइसेंस के लिए खरीदा और इंस्टॉल किया गया था।

   ग. केंद्र में सोनिकवॉल फायरवॉल एनएसए 250 के समर्थन सहित इंस्टॉल किए गए सीजीएसएस सुइट और हार्डवेयर प्रतिस्थापना वॉरंटी के लाइसेंस को नवीनीकृत किया गया था।

   घ. एपी का समर्थन करने के लिए एक और लाइसेंस खरीदा गया था और कंफिगर किया गया था जिससे सात एक्सेस पॉइंट (एपी) का समर्थन करने के लिए वायरलेस नियंत्रक की क्षमता बढ़ी थी।

   ङ. अप्रचलित हार्डवेयर (04 पीसी, 15 लैपटॉप, 05 प्रिंटर्स, 04 यूपीएस, 03 नेटवर्क स्विच) का निपटान किया गया था।

5. केन्द्र के स्थानीय क्षेत्र और वाइ फाइ नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रखरखाव और कंफिगरेशन आवश्यकता के अनुसार किए गए थे। केंद्र के सभी प्रयोक्ताओं को उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मामलों में भाग लेकर आईटी सहायता सेवाएं प्रदान की गई। वर्ष के दौरान केंद्र में आयोजित गोष्ठियों और सम्मेलन से संबंधित समर्थन सेवाएं भी प्रदान की गई। नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस (एनएएस) पर संग्रहीत डेटा का आवधिक बैकअप बाहरी हार्ड ड्राइव पर लिया गया था। केंद्र में हार्डवेयर इंस्टॉल / जारी करने से संबंधित आईटी का वार्षिक स्टॉक सत्यापन किया गया था।

अनुदान

सीपीआर को वित्तीय वर्ष 2017–18 में आईसीएसएसआर से निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुए (लाखों में) :

1.	आवर्ती अनुदान ओएच (36)	95.00 रु.
2.	आवर्ती अनुदान ओएच (31)	54.00 रु.
	कुल :	149.00 रु.

सीपीआर की इस समय कुल कार्पस निधि 1013.82 लाख रु है। वर्ष के दौरान, सीपीआर की सकल प्राप्ति (विशिष्ट परियोजना प्राप्ति सहित) 2131.60 लाख रु. रही। आईसीएसएसआर का आवर्ती अनुदान वर्ष के दौरान सीपीआर की प्राप्तियों का 6.99 प्रतिशत है।

वर्ष के दौरान नीचे उल्लिखित अनेक अभिकरणों और सरकारी विभागों ने अपना समर्थन जारी रखा :

परियोजना अनुदानदाताओं की सूची

1. इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली
2. आईडीआरसी, कनाडा
3. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूएसए
4. विलियम एंड फ्लोरा हेवलेट फाउंडेशन, यूएसए
5. फोर्ड फाउंडेशन, यूएसए
6. ओक फाउंडेशन
7. द एशिया फाउंडेशन, यूएसए
8. नमति इंक., यूएसए
9. ओमिदयार नेटवर्क फाउंडेशन, यूएसए
10. मैक आर्थर फाउंडेशन, यूएसए
11. इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुम्बई
12. क्रि. माइकलसन इंस्टीट्यूट, नॉर्वे
13. इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फ्रांस
14. कोरिया फाउंडेशन
15. दुलीप मथाई नेचर कंर्जेवेशन ट्रस्ट
16. जमनालाल बजाज फाउंडेशन
17. वर्ल्ड बैंक

प्रणीति अनुसंधान केन्द्र के दानदाताओं को कर से छूट

प्रणीति अनुसंधान केन्द्र को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) (iii) का अनुमोदन प्राप्त है, जिसके तहत मौजूदा आयकर कानून के अंतर्गत दानदाता को 1 अप्रैल, 2005 के बाद दी गई राशि पर 125 प्रतिशत की दर से आयकर छूट प्राप्त होती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (जी) (5) (iv) के अंतर्गत 1 अप्रैल 2011 के बाद छूट प्राप्त है, जिसमें दानदाता को निवल राशि पर 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रावधान हैं।

सीपीआर संकाय और कर्मचारी गण

(31 मार्च 2018 तक)

1. यामिनी अय्यर — सितंबर 2017
   अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी
2. ब्रह्मा चैलानी — जुलाई 1993
   श्रनसल 1993
   प्रोफेसर, पीएच. डी. (जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय) — सितंबर 2006
3. लवन्या राजमणि
   प्रोफेसर, डी. फिल (ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय)
4. श्रीनाथ राघवन
   प्रोफेसर

अवैतनिक प्रोफेसर — सितंबर 2005

5. चरण वाधवा (पीएच. डी., येल, अमेरिका)

मानद अनुसंधान / अतिथि प्रोफेसर

6. सुभाष सी कश्यप
7. वेद मरवाह (सेवा–निवृत्त आईपीएस)
8. के आर जी नायर
9. आर. रंगाचारी
10. बी. एन सक्सेना
11. संजीब बरुआ
12. संजय हजारिका
13. जी. पार्थसारथी
14. भरत कर्नाड

एसोसिएट प्रोफेसर

15. निम्मी कुरियन पीएच. डी. (जेएनयू)

वरिष्ठ अध्येता

16. पार्थ मुखोपाध्याय
17. शैलश्री शंकर
18. रमेश चंद्रन
19. शुभगतो दासगुप्ता
20. नवरोज़ दुबाश
21. श्याम सरण
22. श्याम बाबू
23. अंजली चिकेरसल
24. नीलांजन सरकार
25. किरण भट्टी
26. मंजू मेनन

वरिष्ठ अतिथि अध्येता

27. फिलिप कुलेट
28. जिश्णु दास
29. रानी मुलेन
30. मेरी हेलन जेराह
31. संजय बारू

कानूनी अनुसंधान निदेशक, नमति

32. कांचि कोहली

अध्येता

33. अवनि कपूर
34. नमिता वाही
35. राधिका खोसला
36. श्रीनिवास चोकाकुला
37. अरकाजा सिंह
38. शिबानी घोष
39. जोरावर दौलत सिंह

अतिथि अध्येता

40. अश्विनी स्वैन

वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता

41. मृदुस्मिता बोरदोलाई
42. अश्विन परुलकर
43. मुक्ता नायक
44. अनिंदिता मुखर्जी
45. अंजू द्विवेदी
46. शमिन्द्रनाथ रॉय

वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट

47. देवाशीष देशपांडे
48. आदित्य भोल
49. एमएम शंकर गोवदा (अंशकालिक)
50. अम्बरीष करुणानिधि
51. विंसी डेविस
52. कान्हू चरण प्रधान
53. पर्मा चक्रवर्ती

अनुसंधान एसोसिएट

54. संदीप भारद्वाज
55. तान्या कपूर
56. स्टेंजीन युमचेन
57. समा खान
58. प्रेरणा नंदिता बैष्णब
59. स्वाति धीमन (अंशकालिक)
60. श्रावनी दासगुप्ता
61. बाबू लाल
62. अंकित भारद्वाज

63. रीतिका कलिता

64. अंकित भाटिया

65. साहित्य वेंकटेशन

66. कश्यप अरोड़ा

67. जयदेव जोशी

68. नेहा अग्रवाल

69. मेघना पॉल

70. श्वेता सेलिन जेस

71. ऋत्विक शुक्ला

72. मेघना श्रीवास्तव

73. तृप्ति सिंह

74. कृतिका ए दिनेश

75. रुचि जुन्नारकर

76. मनीष

77. अभिश्री अग्रवाल

78. इशा कुंडुरी

79. सुनील कुमार सिंह

80. दीप्ति राज

81. पार्थ भाटिया

अनुसंधान सहायक

82. बाल गोविंद

83. सुनील कुमार

84. प्रशांत आर्य

85. डोना मैथ्यू

86. प्रणव कुट्टैया

कार्यक्रम कर्मचारी

87. विद्या विश्वनाथन, वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक

88. नीलांजन चौधरी, प्रोग्राम समन्वयक

89. भारत भाई हरि भाई दोडिया, पर्यावरण – कानूनी समन्वयक

90. मीनाक्षी कपूर, कार्यक्रम प्रबंधक

91. महाबलेश्वर हेगडे, वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक

92. संतोष राव दारा, कार्यक्रम प्रबंधक

प्रशासन, लेखा, आईटी और संचार और अन्य सेवाएं

93. एल. रवि
    प्रमुख, प्रशासनिक सेवाएं

94. अजय नायर
    वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक

95. ऋचा बंसल
    निदेशक (संचार)

96. ध्रुव अरोड़ा, डिजिटल संचार प्रबंधक

97. नेहा गौर, केंद्रीय संचार समन्वयक

98. बिपिन बिहारी नायक (अंशकालिक), कनिष्ठ डिजाइनर

99. प्रदीप खन्ना
    प्रमुख लेखा अधिकारी

100. एम. सी. भट्ट
    लेखा अधिकारी

101. रमेश कुमार
    लेखा सहायक

102. वी. के. तंवर

सहायक प्रणाली विश्लेषक और सहायक कार्यक्रम

103. दिनेश चन्द
वरिष्ठ पर्यवेक्षक

104. शिव चरण
वरिष्ठ पर्यवेक्षक

105. वाई. जी. एस. चौहान
पुस्तकालय सहायक

106. सुनील कुमार
अध्यक्ष के सहयोगी

107. प्रमोद कुमार मलिक
अध्यक्ष के सहयोगी

108. सोनिया भुटानी गुलाटी
जन संपर्क सहयोगी

109. विनोद कुमार
उप पर्यवेक्षक

110. सरला गोपीनाथन
सचिव सहायक

111. सतनाम कौर
वित्त एवं प्रशासनिक प्रबंधक

112. अजीत कुमार मिश्रा
वित्त एवं प्रशासनिक एसोसिएट्स

113. रवि रौनक रोबिन, प्रशासनिक सहायक

114. पंकज कुमार मिश्रा, नेटवर्क सहायक

115. अवन्तिका श्रीवास्तव, वरिष्ठ संचार अधिकारी

अन्य समर्थक कर्मचारी

116. रणजीत सिंह

117. पूना राम

118. रोहन

वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ्लैट नं. 202 और 301, सत्यम सिनेमा कॉम्प्लेक्स
रंजीत नगर, कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली – 110008
टेली. (011) 25702691, 25704639; ई–मेल : newdelhi@vas.co.in

स्वतंत्र लेखा परीक्षक प्रतिवेदन

सदस्य, प्रणीति अनुसंधान केंद्र

वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमने **प्रणीति अनुसंधान केंद्र (संस्था)** के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च 2018 के अनुसार तुलन पत्र और समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा एवं उल्लेखनीय लेखा नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

संस्था का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार सत्य और निष्पक्ष चित्र देते हैं। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव और धोखा धड़ी या गलती और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने, उचित लेखा नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग, ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जिन्हें गलत सामग्री विवरण से मुक्त और सत्य तथा निष्पक्ष बनाए रखा जा सके, चाहे ये किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हैं।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारे लेखा परीक्षण पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है। हमने अपना लेखा परीक्षण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में आवश्यक है कि लेखा परीक्षण की योजना और निष्पादन द्वारा इस विषय में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त किया जाएगा कि ये वित्तीय विवरण सामग्री के गलत वक्तव्य से मुक्त हैं।

एक लेखा परीक्षण में परीक्षण आधार साक्ष्य की जांच शामिल है जिसके लिए वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटन दिए जाते हैं। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय सहित वित्तीय विवरणों के गलत सामग्री विवरण के जोखिमों के आकलन के साथ होने चाहिए, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो। इन जोखिमों के आकलन के लिए लेखा परीक्षक संस्था की तैयारी और वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को विचार में लेता है, जिससे उन लेखा प्रक्रियाओं की डिजाइन करने के लिए एक सत्य और निष्पक्ष चित्र मिलता है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हैं किन्तु ये एक राय व्यक्त करने के लिए नहीं है, चाहे यह कंपनी वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखती है और उक्त नियंत्रणों की प्रभावशीलता का प्रचालन करती है। एक लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और संस्था के

शासी मंडल द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की उपयुक्तता तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारी विचार धारा के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

राय

हमारी राय में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा दी गई व्याख्याओं के अनुसार, वित्तीय विवरणों को इस पर दी गई अन्य टिप्पणियों के साथ पढ़ने पर, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सत्य और निष्पक्ष चित्र देते हैं :

क) तुलन पत्र के मामले में, संस्था के कार्य 31 मार्च 2018 के अनुसार; और
ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय तथा व्यय खाते के मामले में।

अन्य मामले

क) हमने सभी सूचना और व्याख्या प्राप्त किया है जो हमारे ज्ञान और मान्यता के अनुसार सर्वोत्तम तथा हमारे लेखा परीक्षण के प्रयोजन हेतु अनिवार्य थी।
ख) हमारी राय में संस्थान द्वारा कानून के अनुसार आवश्यक उचित बहियां रखी गई हैं, जैसा कि हमारे द्वारा अब तक इन बहियों की जांच से पता चलता है।
ग) इस रिपोर्ट के साथ संलग्न तुलनपत्र, आय तथा व्यय लेखा की इन बहियों के साथ सहमति में हैं।

वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी. सं. 109208डब्ल्यू)

sd
एम. एस. बालचंद्रन
भागीदार (सदस्यता सं. 024282)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 19.07.2018

प्रणीति अनुसंधान केंद्र

31 मार्च 2018 के लिए तुलन पत्र

					राशि रु. में
कोष और देयताएं	**अनुसूची**		**31.3.2018 के अनुसार**		**31.3.2017 के अनुसार**
कॉर्पस कोष (विशिष्ट)	1		37,959,000		37,959,000
कॉर्पस कोष (सामान्य)	1		62,723,405		62,723,405
पूंजी कोष (परिसंपत्ति)	2		8,562,407		9,387,087
संचित पूंजी			4,408,025		4,408,025
धर्मस्व निधि			700,000		700,000
आकस्मिकताओं हेतु संचय			10,200,000		10,200,000
विशिष्ट उद्देश्य / परियोजनाओं में अव्ययित शेष	3		224,425,037		230,114,206
अनुदान – राष्ट्रीय ज्ञान आयोग	4		1,370,804		1,081,532
प्रावधान	5		12,918,644		12,918,644
आय और व्यय खाता			37,649,495		35,355,682
वर्तमान देयताएं	9		735,511		691,849
कुल			401,652,328		405,539,430
संपत्ति और परिसंपत्तियां					
स्थायी परिसंपत्तियां	6				
सकल ब्लॉक		37,427,295		37,293,332	
घटाएं : संचित मूल्यह्रास		28,864,888	8,562,407	27,906,245	9,387,087
निवेश	7		355,082,059		379,373,247
(कॉपर्स निधि निवेशों सहित)					
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम :	8				
नगद व बैंक शेष	8(क)	22,775,648		7,722,851	
वसूली योग्य / समायोज्य अग्रिम	8(ख)	15,232,214	38,007,862	9,056,245	16,779,096
कुल			401,652,328		405,539,430

खाते पर लेखा नीतियां तथा टिप्पणियां 10

प्रणीति अनुसंधान केंद्र
के लिए और उनकी ओर से

हमारी समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म की पंजीकरण सं. 109208 डब्ल्यू)

(यामिनी मृणालिका अय्यर)
अध्यक्ष

(एम. एस. बालचंद्रन)
भागीदार (सदस्यता सं. 024282)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2018

(प्रदीप खन्ना)
मुख्य लेखा अधिकारी

(एल. रवि)
प्रमुख–प्रशासनिक सेवाएं

प्रणीति अनुसंधान केंद्र				
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा				
				राशि रु. में
आय		2017–18		2016–17
आईसीएसएसआर से प्राप्त सहायता अनुदान		14,900,000		13,271,000
निवेश पर ब्याज :				
धर्मस्व और कॉर्पस ब्याज	4,359,552		4,711,144	
कॉर्पस पर लाभांश आय	153,105		153,104	
आय कर वापसी पर ब्याज	92,854		180,886	
अन्य ब्याज आय	5,114,473	9,719,984	5,040,647	10,085,781
विविध आय		147,442		291,271
अनुदानों से अंतरित		17,723,850		17,751,772
पूरी हो चुकी परियोजनाएं – बट्टे खाते शेष (निवल)		69,140		612,236
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		81,507		17,265
सेवा कर बट्टे खाते		-		1,127,280
रॉयल्टी		657		1,440
कुल		42,642,580		43,158,045
व्यय		2017–18		2016–17
वेतन, मजदूरी तथा स्टाफ के लिए लाभ				
वेतन व भत्ते	29,169,247		29,003,183	
भविष्य निधि में अंशदान	1,906,235		1,954,642	
उपदान निधि में अंशदान (एलआईसी)	1,000,000		1,000,000	
अवकाश नगदीकरण लाभों का अंशदान / भुगतान	1,019,460		1,000,000	
चिकित्सा बीमा और अन्य स्टाफ कल्याण	300,091	33,395,033	311,472	33,269,297
यात्रा और वाहन		498,341		286,028
दर एवं कर		296,220		836,782
मुद्रण, लेखन सामग्री, कार्यालय सामग्री		123,403		122,176
संचार व्यय		168,352		236,405
बिजली और पानी		608,144		578,876
कार्यालय अनुरक्षण और मरम्मत		748,763		677,031

आतिथ्य व सामान्य शिष्टाचार		152,426		188,680
बीमा		38,531		37,588
पुस्तकालय पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं		591,987		378,784
लेखा परीक्षा और अन्य शुल्क		402,500		363,025
विविध व्यय		34,829		45,886
सदस्यता और अंशदान		-		74,750
सेवा कर क्रेडिट बट्टे खाते डालना		72,630		-
बैंक प्रभार और ब्याज		7,994		18,533
सम्मेलन व कार्यक्रम		888,131		570,758
विज्ञापन		223,569		-
वाहन का रखरखाव		87,255		72,090
कानूनी और व्यवसायिक		1,926,059		520,120
मूल्य ह्रास	2,051,495		2,264,854	-
घटाएं : पूंजी निधि से प्राप्त	2,051,495	-	2,264,854	-
अग्रेषित कुल		40,264,167		38,276,809
व्यय		2017–18		2016–17
पीछे से लिया गया कुल		40,264,167		38,276,809
प्रावधान / विनियोजन :				
पूंजी निधि से स्थानांतरित – गैर परियोजना निधि में से परिसंपत्तियों को जमा करने के लिए समकक्ष राशि		84,600		1,576,280
		40,348,767		39,853,089
विनियोजन के बाद वर्ष के लिए अधिशेष		2,293,813		3,304,956
अधिशेष आगे ले जाया गया		35,355,682		32,050,726
संचित अधिशेष को तुलन पत्र में ले जाया गया		37,649,495		35,355,682

प्रणीति अनुसंधान केंद्र के लिए
और उनकी ओर से

हमारी समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फ़र्म की पंजीकरण सं.109208 डब्ल्यू)

sd
(एम. एस. बालचंद्रन)
भागीदार (सदस्यता सं. 024282)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2018

sd
(यामिनी मृणालिका अय्यर)
अध्यक्ष

sd
(प्रदीप खन्ना)
मुख्य लेखा अधिकारी

sd
(एल. रवि)
प्रमुख–प्रशासनिक सेवाएं

प्रणीति अनुसंधान केंद्र

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए खाते के विवरण की अनुसूचियां

					राशि रु. में
विवरण			31.3.2018 के अनुसार		31.3.2017 के अनुसार
कॉपर्स निधियां :					अनुसूची – 1
द फोर्ड फाउंडेशन – विदेशी मुद्रा कॉर्पस		3,058,000		3,058,000	
द फोर्ड फाउंडेशन शाश्वत पीठ – पीपी आरएजी यूनिट		13,001,250		13,001,250	
द फोर्ड फाउंडेशन ट्रैक – 2 वार्ता		8,449,750		8,449,750	
विदेश मंत्री, भारत सरकार, ट्रैक – 2 वार्ता		950,000		950,000	
राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग – पीपीआरएजी		12,500,000	37,959,000	12,500,000	37,959,000
सामान्य कॉर्पस – सीपीआर					
गत वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार		62,723,405		50,223,405	
जोड़ें : वर्ष के दौरान कॉपर्स प्राप्ति		-		12,500,000	
जोड़ें : आय और व्यय खाता से स्थानान्तरित		-	62,723,405	-	62,723,405
कुल			100,682,405		100,682,405
पूंजी कोष (परिसंपत्ति)					अनुसूची – 2
गत वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार			9,387,087		9,149,426
जोड़ें : विशिष्ट प्रयोजन/परियोजना निधियों से खरीदी गई परिसंपत्तियां			1,259,614		939,603
जोड़ें : आय और व्यय से स्थानांतरित – गैर परियोजना निधियों में से जोड़ के बराबर			84,600		1,576,280
घटाएं : पूंजी निधि से प्राप्त मूल्यह्रास			2,051,495		2,264,854
घटाएं : बट्टे खाते / खारिज / बेचने के लिए परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी			117,399		13,368
कुल			8,562,407		9,387,087
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग					अनुसूची – 4
अनुप्रयुक्त अनुदान का शेष					
गत वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार			1,081,532		1,081,532
निवेश पर ब्याज			289,272		-

कुल			1,370,804		1,081,532
द्वारा प्रतिनिधित्व :					
केनरा बैंक के सावधि जमा			1,317,332		1,046,373
केनरा बैंक खाता सं. 5827			11,010		11,010
वसूली योग्य टीडीएस			42,462		24,149
कुल			1,370,804		1,081,532
प्रावधान					अनुसूची – 5
मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रावधान					
गत वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार		12,918,644		12,522,644	
जोड़ें : लिफ्ट के पूंजीकरण के लिए बदले गए प्रावधान		-	12,918,644	396,000	12,918,644
पिछले वर्ष में प्रावधान से गलत राशि काट ली गई प्रावधानों में राशि की वापस बहाली					
कुल			12,918,644		12,918,644

प्रणीति अनुसंधान केंद्र

31.03.2018 को विशिष्ट उद्देश्यों/परियोजनाओं हेतु शेष योगदान

अनुसूची –3

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	प्रायोजक व परियोजना का नाम	प्रारंभिक शेष (01.04.2017)		वर्ष के दौरान प्राप्तियां	ब्याज /लाभांश	आय व व्यय खाते में अंतरित	वर्ष के दौरान वितरित	पूर्ण परियोजना में बट्टे खाते में (निवल)	अंतिम शेष (31.3.2018)	
		डेबिट	क्रेडिट						डेबिट	क्रेडिट
	विदेशी अंशदान अनुदान									
1	द एशिया फाउंडेशन – कृष्णा नदी बेसिन के लिए जल दर निगरानी प्रणाली	-	-	1,456,000	-	220,000	1,369,668	(133,668)	-	-
2	बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन – भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और डिजिटल वित्तीय समावेशनों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को मजबूत बनाने की जागरूकता (जीपीपीआई)	-	686,928	-	-	1,307	16,789	-	-	668,832
3	बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन – एससीआई – एफ।	-	43,749,991	-	3,196,376	980,017	6,534,347	-	-	39,432,003
4	बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन – एससीआई एफ –।।		62,470,556	-	4,847,540	4,627,743	30,854,339	-	-	31,836,014
5	बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन – पूरक अनुदान सं. ओपीपी1038511 – निर्मल अध्ययन	-	26,844,907	9,608,630	3,349,701	1,311,254	8,742,401	-	-	29,749,583

6	बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन – पोषण व्यय को ट्रैक करना	-	-	28,526,822	173,250	266,535	1,777,601	-	-	26,655,936
7	ब्राउन यूनिवर्सिटी – डिजिटल शहरी अवलोकन	-	-	785,985	-	-	589,075	-	-	196,910
8	कार्नेगी एंडोवमेंट अंतरराष्ट्रीय शांति – यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-	81,724	-	-	81,724	-	-	-
9	जलवायु और विकास ज्ञान नेटवर्क (सीडीकेएन) – भारत में मजबूत जलवायु संगत विकास योजना की दिशा में	924,034	-	1,665,903	-	-	740,786	1,083	-	-
10	सीईबीआरएपी ब्राजील – भारत में नीति प्रक्रिया : सूचना, सामाजिक लेखा का अधिकार और प्रतिभागिता पूर्ण सिंचाई प्रबंधन	-	322,602	-	-	-	131,080	-	-	191,522
11	सीएमआई – भूमि अधिकार, पर्यावरण संरक्षण	-	528,914	1,570,012	-	-	2,098,926	-	-	-
12	सीएमआई – जल अधिकार	-	-	963,670	-	-	775,146	-		188,524
13	सेंटर डी साइंसेज ह्यूमैनेस – भारत में निचले शहरीकरण पर उपनगर	-	293,889				65,600	-	-	228,289
14	जापान दूतावास – कार्यशाला व्ययों की प्रतिपूर्ति	511,608	-	1,141,807			362,511	-	-	267,688
15	द फोर्ड फाउंडेशन – जबावदेही प्रयास	-	5,290,315	-	48,616	332,415	5,006,516	-	-	-

16	द फोर्ड फाउंडेशन (इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन) – कोलकाता अनुभव	-	169,316	-	-	-	-	-	-	169,316
17	द फोर्ड फाउंडेशन – विदेशी मुद्रा कॉर्पस आय (एफसीसीआई)	-	2,542,566	-	440,610	-	344,722	-	-	2,638,454
18	द फोर्ड फाउंडेशन– पर्पेच्युटी चेयर – सार्क	-	16,432,086	-	1,217,561	-	-	-	-	17,649,647
19	द फोर्ड फाउंडेशन कॉपर्स इन्कम फॉर ट्रक– 2 डायलॉग्स	-	7,996,586		2,465,222	-	3,980,313	-	-	6,481,495
20	द फोर्ड फाउंडेशन – भारत में शहरी शोध नेटवर्क का अध्ययन शहरी अनौपचारिता के ज्ञान के आधार पर किया गया है।	-	-	23,697,814	553,931	761,793	12,888,945	-	-	10,601,007
21	जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी – डिजिटल शहरी अवलोकन	-	-	835,640	-	-	835,640	-	-	-
22	वैश्विक स्वास्थ्य कार्यनीतियोंकी उभरती अर्थव्यवस्थाएं – प्रशासन और सार्वजनिक नीतिगत पहल	-	1,600,472	7,020,000	59,836	428,852	4,873,520	-	-	3,377,936
23	हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज मेसेशूट्स – व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	106,381	-	-	-	-	-	-	106,381
24	हेनरिक बॉल स्टीफ्टुंग – औद्योगिक प्रभाव को संबोधित करने के लिए पर्यावरण के नियमन	-	17,896	(17,896)	-	-	-	-	-	-
25	आईडीआरसी – कनाडा – भारत में युवा रोजगार परिणामों को	-	3,001,294	1,622,411	145,734	-	2,146,482	-	-	2,622,957

	आकार देने में छोटे शहरों की भूमिका।									
26	इनोवेशन फॉर पावर्टी एक्शन – भारत और इंडोनेशिया में वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम से स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और प्रदायगी तक पहुंच	-	4,541,371	-	-	-	31,882	-	-	4,509,489
27	इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रांस (आईआरडी) – भारतीय ग्रामीण सीमाएं और बुनियादी सेवाएं आदि।	-	2,211,828	-	-	140,517	1,405,865	-	-	665,446
28	कोरिया फाउंडेशन – पूर्वी एशिया में नए महान खेल	-	-	3,236,750	-	13,315	133,153	-	-	3,090,282
29	जॉन डी एण्ड कैथरिन टी मैक आर्थर फाउंडेशन – भारत का विकास भविष्य 16 – 1603 – 150748 – सीएलएस में समेकित जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर विकास अभ्यास	288,000	-	6,447,168		545,940	3,640,296	-	-	1,972,932
30	सुश्री चंद्रिका पाठक और श्री दिलीप पाठक – भारत में पेय जल पर अनुसंधान	-	480,573	-	85,701	-	552,184	14,090	-	-
31	नमति – पर्यावरण न्याय	90,378	-	29,096,851	112,879	3,309,347	22,065,474	-	-	3,744,531
32	ओक फाउंडेशन – अप्रबंधित सहायता – जलवायु पहल –।।	-	4,864,778	5,262,635	7,181	775,352	5,162,942	-	-	4,196,300

33	ओमिड्यर नेटवर्क निधि – जबावदेही पहल	377,497	-	10,956,500	238,615	1,377,633	9,184,218	-	-	255,767
34	सैफीस – नीदरलैंड	-	907,904	-	146,204	-	138,806	-	-	915,302
35	इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर – थिंक टैंक प्रयास चरण ।।	-	2,676,001	16,074,106	115,183	-	17,445,297	-	-	1,419,993
36	यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया – एससी	-	-	415,926	-	67,852	516,027	-	167,953	-
37	यूनिवर्सिटी ऑफ मेनचेस्टर – जवाबदेही प्रयास में इसके साथ जुड़े कार्यशाला व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	204,328	-				-	-	204,328
38	यूनेस्को जबावदेही पहल	-	-	578,790	-	57,879	520,911	-	-	-
39	विलियम एण्ड फ्लोरा हैवेट फाउंडेशन – जवाबदेही प्रयास – नए मूलसंरचना अनुदान	-	4,969,112	-	160,434	997,381	6,651,594	-	2,519,429	-
	उप कुल	2,191,517	192,910,594	151,027,248	17,364,574	16,215,132	151,664,780	(118,495)	2,687,382	194,036,864
	घरेलू अनुदान									
40	एपीसी वर्ल्डवाइड इंडिया प्रा. लि. – नीति संक्षेप विकसित करने के लिए मौजूदा अनैतिक आवागमन (रोकथाम) अधिनियम, 1986 पर मूल्यांकन	-	-	407,100	-	-	389,100	18,000	-	-

41	अशोक यूनिवर्सिटी – शहरीकरण और शहरी प्रणाली की सिटी बहस	-	-	30,509	-	-	58,438	-	27,929	-
41	दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर)	-	-	-	-	-	111,381	-	111,381	-
42	दुलीप मथाई नेचर कंर्जेवेशन ट्रस्ट – जल प्रदूषण, सामान्य आदेश और मानव वन्यजीव संघर्ष पर सूचना शिक्षा और संचार सामग्री की डिजाइन	-	-	1,300,000	-	99,673	996,727	-	-	203,600
43	ह्यूमन सेटलेमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (एचएसएमआई) – होमलेसनेस	-	-	-	-	-	15,645	-	15,645	
44	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद – पीपीपी मातृ देखभाल	-	19,940		-	-	-	-	-	19,940
45	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् – प्रजनन स्वास्थ्य के मामलों पर बल सहित स्वास्थ्य की केंद्रीय नीतियों पर अनुसंधान	-	9,523		-	-	-	-	-	9,523
46	आईसीएसएसआर – प्रमुख जाति की मांग	-	-	80,000	-	-	17,062	-	-	62,938
47	आईसीएसएसआर – उपेक्षित वर्गों में धर्म निरपेक्षता और सामाजिक पूंजी	-	17,989		-	-	-	-	-	17,989
48	आईसीएसएसआर – भारत का मध्य वर्ग	-	1,148,339	(1,148,339)	-	-	-	-	-	-

49	आईसीएसएसआर – भारत में शहरी परिवर्तन	-	43,143	156,121	-	199,264	-	-	-	-
50	आईसीएसएसआर – कृषि जैव प्रौद्योगिकी	368,251	-		-	-	-	-	368,251	-
51	आईसीएसएसआर – पर्यावरण न्यायशास्त्र	264,736	-	264,736	-	-	-	-	-	-
52	आईसीएसएसआर – महानगर में गृह विहीनता को समझना, दिल्ली का एक प्रकरण अध्ययन	-	1,510,510	-	-	-	1,924,809	-	414,299	-
53	आईसीएसएसआर – भूमि अधिकारों का विकास और संविधान : भारत में मानचित्रण भूमि विधान	-	1,441,926	-	-	-	1,144,305	-	-	297,621
54	आईसीएसएसआर उन्मुखीकरण कार्यक्रम – अनु. जाति घटक के तहत अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य वंचित समूह से संबंधित अनुसंधानकर्ताओं और संकाय सदस्यों के लिए	-	1,285,718	1,000,000	-	-	333,812	-	-	1,951,906
55	आईजीआईडीआर / श्रमिक – स्टेंग्थेन एंड हार्मोनिज रिसर्च एंड एक्शन ऑन माइग्रेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट (श्रमिक)	817,222	-	1,688,457	-	-	871,235	-	-	-
56	आईजीआईडीआर / श्रमिक – गोष्ठी व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	16,441	1,881	-	-	18,322	-	-	-

57	इंडिया हेल्थ एक्शन ट्रस्ट – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने के लिए सेवाएं	-	-	463,740	-	19,615	463,045	-	18,920	-
58	जमनालाल बजाज फाउंडेशन – सार्वजनिक नीति पहल में शासन	-	10,388,012	5,000,000	325,613	577,798	5,778,660	-	-	9,357,167
59	इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च – (आईएफएमआर) – चेन्नई – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रयास चुनौती के कार्यान्वयन का एक गुणात्मक अध्ययन आयोजित करना।	-	180,000	-	-	-	486,000	-	306,000	-
60	कार्यशाला व्यय का किला रिम्ब	-	-	-	-	-	26,223	-	26,223	-
61	विदेश मंत्रालय – बीसीआईएम 10वीं वार्ता 18–19 फरवरी 12 और बीसीआईएम 11वीं वार्ता 23–24 फरवरी 2013	-	112,699	-	-	-	-	-	-	112,699
62	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार–ट्रैक–2 वार्ताओं के लिए कॉर्पस आय	2,926	-	-	-	-	-	-	2,926	-
63	वित्त मंत्रालय – भारत सरकार – कॉर्पस आय	-	8,189		450,000	450,000	118	-	-	8,071
64	मेटोमोर्फोसेस टेक टॉल्क सीरिज	-	-	200,000	-	-	13,843	-	-	186,157

65	राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (एनसीपी) – कॉर्पस आय	-	14,661,773	-	712,463	-	-	-	-	15,374,236
66	नीति आयोग – मेटामोर्फोज टेक टॉक सीरिज	-	-	1,180,000	-	-	314,964	-	-	865,036
67	पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया – दो राज्यों में गहरे पीआईपी प्रक्रिया में 18 राज्यों के लिए परिणाम विश्लेषण – जवाबदेही पहल	-	470,988	2,098,936	-	177,680	2,061,145	-	-	331,099
68	सम्बोधी रिसर्च एण्ड कॉम्युनिकेशंस प्रा. लि. – उ. प्र. तकनीकी समर्थन की निगरानी और मूल्यांकन	-	4,226,087	-	-	-	4,056,452	169,635	-	-
69	स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एण्ड कोऑपरेशन – स्विजरलैंड दूतावास, नई दिल्ली (एसडीसी) – ऊर्जा तथा जलवायु के उद्देश्य भारतीय शहरों में समेकित करना।	966,554	-	3,500,000	-	387,724	2,584,826	-	439,104	-
70	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान – शहर संबंधी (टीआईएसएस)	7,913	-	259,540	-	-	247,666	-	-	3,961
71	यूएनओपीएस / डब्ल्यूएसएससीसी – सुरक्षित पीने के पानी और स्वच्छता के लिए मानव अधिकारों पर भारत में डिजाइन और अनुसंधान का कार्यान्वयन	-	1,416,335	-	-	8,625	50,000	-	-	1,357,710

72	यूनेस्को – जवाबदेही पहल	-	-	383,385		38,339	345,046	-	-	-
73	यूनेस्को – मोबाइल फोन आधारित डेटा संग्रह साधन की डिजाइनिंग द्वारा स्कूल में उपस्थिति का पता लगाना	-	246,000	-	-	-	246,000	-	-	-
74	यूनिसेफ – कार्यक्रम सहयोग करार के तहत जवाबदेही पहल	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-
75	यूनिसेफ – कार्यक्रम सहयोग करार के तहत जवाबदेही पहल	225,684	-	-	-	-	-	-	225,684	-
76	विश्व बैंक – अंतरराष्ट्रीय अनुभव पर कार्यशाला के व्यय की प्रतिपूर्ति तथा विकेंद्रीकरण पर ब्राजील से सीखे गए पाठ	39,007	-	39,007	-	-	-	-	-	-
77	विश्व बैंक – पानी साझेदारी कार्यक्रम अनुदान सं. 718221	-	-	1,021,480	-	-	972,980	-	-	48,500
78	विश्व बैंक – ओडिशा अनुदान सं. 7183159 में सामाजिक संरक्षण	-	-	1,036,088	-	-	1,229,388	-	193,300	-
79	विश्व बैंक – स्वास्थ्य और शिक्षा वितरण विश्लेषण अनुदान सं. 7185776	-	-	212,424	-	-	32,404	-	-	180,020
	उप कुल	2,892,293	37,203,612	19,175,065	1,488,076	1,958,718	24,789,596	187,635	2,349,662	30,388,173
	कुल	**5,083,810**	**230,114,206**	**170,202,313**	**18,852,650**	**18,173,850**	**176,454,376**	**69,140**	**5,037,044**	**224,425,037**

	⊕ आय और व्यय खाते में अंतरित									

प्रणीति अनुसंधान केंद्र

31.03.2018 के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची

(राशि रुपए में) अनुसूची – 6

विवरण	मूल्य ह्रास की दर	लागत				मूल्य ह्रास				बट्टे खाते मूल्य	
		1.4.2017 के अनुसार	वृद्धि	कटौती	31.3.2018 के अनुसार	01.04.2017 तक	वृद्धि	कटौती	31.3.2018 तक	31.3.2018 के अनुसार	31.3.2017 के अनुसार
भूमि		85,221	-	-	85,221		-	-	-	85,221	85,221
भवन	5 प्रतिशत	9,643,471	-	-	9,643,471	6,660,235	149,162	-	6,809,397	2,834,074	2,983,236
फर्नीचर एवं फिक्सचर	15 प्रतिशत	3,526,571	96,779	35,020	3,588,330	2,877,104	111,910	34,843	2,954,171	634,159	649,467
कार्यालय उपकरण	15 प्रतिशत	6,450,160	141,641	157,870	6,433,931	4,529,035	302,984	114,996	4,717,023	1,716,908	1,921,125
विद्युत संस्थापन	15 प्रतिशत	319,331	7,200	-	326,531	316,186	1,552	-	317,738	8,793	3,145
वाहन	20 प्रतिशत	799,668	-	35,199	764,469	484,390	62,991	34,874	512,507	251,962	315,278
वातानुकूल व्यवस्था	15 प्रतिशत	56,789	-	-	56,789	56,707	12	-	56,719	70	82
कार्यालय मशीनरी	40 प्रतिशत	11,859,388	1,098,594	982,162	11,975,820	10,004,957	1,151,601	908,139	10,248,419	1,727,401	1,854,431
लिफ्ट	15 प्रतिशत	1,805,413	-	-	1,805,413	650,630	173,217	-	823,847	981,566	1,154,783
अग्निशमन उपकरण	15 प्रतिशत	1,510,369	-	-	1,510,369	1,353,920	23,467	-	1,377,387	132,982	156,449
ऑप्टिकल मार्क स्केनर	40 प्रतिशत	740,000	-	-	740,000	682,458	23,017	-	705,475	34,525	57,542
अमूर्त परिसम्पत्तियां	25 प्रतिशत	496,951	-	-	496,951	290,623	51,582	-	342,205	154,746	206,328
योग		**37,293,332**	**1,344,214**	**1,210,251**	**37,427,295**	**27,906,245**	**2,051,495**	**1,092,852**	**28,864,888**	**8,562,407**	**9,387,087**
गत वर्ष		34,841,996	2,515,883	64,547	37,293,332	25,692,570	2,264,854	51,179	27,906,245	9,387,087	9,149,426

प्रणीति अनुसंधान केंद्र					
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए खाते के विवरण की अनुसूचियां					
					राशि रु. में
विवरण			31.3.2018 के अनुसार		31.3.2017 के अनुसार
निवेश (लागत पर)					अनुसूची – 7
(कॉपर्स निधि निवेशों सहित)					
भारत सरकार में 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बॉन्ड			20,720,000		20,220,000
बैंकों में सावधि जमा			218,685,739		237,979,246
एचडीएफसी लि. के साथ सावधि जमा			37,237,457		39,161,113
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. के साथ सावधि जमा			33,954,973		37,528,998
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. के साथ सावधि जमा			40,387,000		40,387,000
हुडको के साथ सावधि जमा			1,500,000		1,500,000
यूटीआई की इकाइयां			2,096,890		2,096,890
केनरा रोबेको म्युचुअल फंड की इकाइयां			500,000		500,000
कुल			355,082,059		379,373,247
					अनुसूची – 8
क) नगद और बैंक शेष					
चालू खाते में :					
केनरा बैंक चालू खाता सं. 0157201000348 – खाता			9,515,238		636,054
केनरा बैंक – चालू खाता सं. 0157201004775			12,891,158		6,269,290
केनरा बैंक – चालू खाता सं. 0157201005222			8,071		8,189
पंजाब नेशनल बैंक चालू खाता सं. 1736002100011174			339,689		791,950
केनरा बैंक – चालू खाता सं. 0157201005827 (एनकेसी)			11,010		11,010
हाथ में नकद – एफसी		9,598			4,664
हाथ में नकद – गैर एफसी		884	10,482		1,694
उप कुल			22,775,648		7,722,851
ख) वसूली योग्य / समायोज्य अग्रिम					

(अप्रतिभूति – अच्छा माना गया और वसूली योग्य)					
स्टाफ अग्रदाय और अन्यों के लिए अग्रिम			408,814		1,055,744
प्रतिभूति जमा			137,245		125,245
स्रोत पर कर कटौती			3,360,334		2,791,446
आगे अनुदान निपटान की प्रतीक्षा कर रहा है।			6,288,777		-
विशेष अनुदान/परियोजनाओं में शेष राशियां			5,037,044		5,083,810
(अनुदान की प्रत्याशा में अधिक खर्च) (संदर्भ अनुसूची –3)					
उप कुल			15,232,214		9,056,245
कुल			38,007,862		16,779,096
वर्तमान देयताएं					अनुसूची – 9
बकाया देयताएं			735,511		691,849
कुल			735,511		691,849

प्रणीति अनुसंधान केन्द्र

अनुसूची – 10

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत तथा जारी संगठन के अनुसार तैयार किए गए हैं। आय तथा व्यय को मान्यता देने के लिए प्रणीति अनुसंधान केंद्र द्वारा लेखा के नकद आधार का पालन किया जाता है। जबकि, विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में परियोजना स्टाफ / परामर्शदाताओं द्वारा किए गए व्यय को अलग अलग आकस्मिक खाते के रूप में रखा जाता है, जिससे कि परियोजना निधियों की सही उपयोगिता को प्रदर्शित किया जाता है।

संस्था के प्राथमिक उद्देश्य और गतिविधियां अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में हैं। संस्था ने इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा व्यापार के प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की है और परिणामस्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक अनिवार्य नहीं है। जबकि संगत सीमा और व्यावहारिक रूप से इन मानकों का पालन किया गया है।

2. स्थायी परिसम्पत्तियां

स्थायी परिसम्पत्तियों को लागत रहित मूल्य ह्रास पर दर्ज किया गया है। विनिर्दिष्ट अनुदान से खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियों के बराबर राशि को पूंजीगत निधि में अंतरित किया गया है। अचल परिसंपत्तियों को गैर परियोजना निधि (अर्थात् अपनी निधि) के जरिए लिया जाता है, एक समकक्ष राशि वर्तमान वर्ष के आय तथा व्यय खाते से अंतरित की गई है। आय तथा व्यय खाते के जरिए किए गए मूल्यह्रास को पूंजी निधि से पूरा किया जाता है। पूंजी निधि में निधि की राशि (अपनी या परियोजनाओं की) का उपयोग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, अब तक मूल्य ह्रास के निवल हेतु किया जाता है।

3. मूल्य ह्रास

मूल्य ह्रास अवलेखित मूल्य पद्धति पर लगाया जाता है। वृद्धि के संबंध में मूल्य ह्रास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है। परिसम्पत्तियों को हटा देने की स्थिति में यह छोड़ दिया जाता है।

4. निवेश : निवेशों के मूल्य लागत पर लगाया जाता है।

5. कर्मचारी लाभ

केंद्र भविष्य निधि, उपदान और अवकाश नकदीकरण के संबंध में संस्थान विधिवत गठित निधि में नियमित अंशदान देता है। केंद्र ने इस दायित्व को पूरा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह उपदान और छुट्टी के बदले नकद भुगतान योजनाओं के अंतर्गत पॉलिसियाँ ली हैं। केंद्र द्वारा निधि में तद्र्थ अंशदान किया जाता है और इसे भुगतान कर दिए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। भावी भुगतान संबंधी देनदारी का हिसाब लगाया नहीं गया है।

एलआईसी के साथ निधि की शेष राशि 31.03.2018 के अनुसार (निधि की शेष राशि पर ब्याज क्रेडिट सहित) उपदान निधि और अवकाश नकदीकरण नीति के लिए क्रमशः 168.75 लाख रुपए और 87.55 लाख रुपए है।

6. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन–देन

विदेशी मुद्रा संबंधी लेन देन को सामान्यतः लेन–देन के समय प्रचलित विनियम दर के अनुसार दर्ज किया जाता है।

7. आयकर :

(i) सीपीआर, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 क (क) के अंतर्गत पंजीकृत है जिसका पंजीकरण सं. डीएलआई (सी) (आई–682) दिनांक 15.04.1976 है।

(ii) अधिनियम के अंतर्गत इसे स्थायी खाता सं. (पैन) **AAATC0180H** आबंटित किया गया है।

(iii) सीपीआर नियमित रूप से आयकर विवरणी जमा करता है, पिछली विवरणी मूल्यांकन वर्ष 2017–18 (वित्तीय वर्ष 2016–17 से संबंधित) के लिए भरी गई। आयकर के संदर्भ में कोई मांग नहीं है।

(iv) सीपीआर को आयकर निदेशक के कार्यालय के दिनांक 15.09.2011 के पत्र द्वारा आकलन वर्ष 2012–13 और उसके बाद से अधिनियम की धारा 80जी के अंतर्गत भी अनुमोदन प्राप्त है।

8. सीपीआर विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है, इसकी पंजीकरण सं. 231650007 है तथा यह नियमित रूप से वार्षिक रिटर्न भर रहा है, पिछला रिटर्न वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए भरा गया था। पंजीकरण को गृह मंत्रालय द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात 30 नवंबर 2021 तक विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम, 2010 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किया गया है।

9. योजना आयोग (राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी) ने दिनांक 03.10.2005 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें सीपीआर को रा.ज्ञा.आ. के सचिवालय के रूप में कार्य करने का प्रावधान किया गया है। आदेश में आगे यह भी कहा गया है कि सीपीआर सचिवालय के खर्चों के लिए एक अलग खाता रखेगा, जिसकी पूर्ति रा.ज्ञा. आ. के सहायता अनुदान से की जाएगी तथा यह योजना आयोग को एक लेखा–परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगा। तदनुसार, शेष और संगत निवेश को अलग–अलग दर्शाया जाता है।

10. संस्था के विरुद्ध प्रस्तुत दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना जाता : परिणाम स्वरूप 31 मार्च 2016 तक प्रतिदावा जो सेवा के आयोजन के दौरान जांच में कमियों के साथ क्षतियों के प्रति किया गया, जिसे संस्था द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है – 11.73 करोड़ रुपए

11. बकाया पूंजीगत संविदाओं की अनुमानित राशि : शून्य रुपए

12. लेखा परीक्षक महानिदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा वर्ष 2004–05 से 2006–07 की अवधि के लिए सीपीआर लेखा का निरीक्षण किया गया। अपने पर्यवेक्षण में उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए कि आईसीएसएसआर द्वारा जारी अनुदान के लिए स्वीकृत पत्र में निर्धारित शर्तों और निबंधनों के अनुसार सीपीआर ने 110.75 लाख रु. वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान अतिरिक्त प्राप्त किए है, जो वापसी योग्य है। सीपीआर ने शासकीय लेखा परीक्षण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया है। उनकी रिपोर्ट जांच के अधीन है।

अनुसूची 1 से 10 तक हस्ताक्षरित

कृते प्रणीति अनुसंधान केन्द्र

के लिए और उनकी ओर से

sd
कृते वी शंकर अय्यर एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म की पंजीकरण संख्या 109208डब्ल्यू)

sd
(यामिनी मृणालिका अय्यर)
अध्यक्ष

sd
(एम एस बालचंद्रन)
भागीदार (सदस्यता. सं. 024282)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2018

sd
(प्रदीप खन्ना)
मुख्य लेखा अधिकारी

sd
(एल. रवि)
प्रमुख – प्रशासनिक सेवाएं

VISION STATEMENT

*** VISION** To be a leader among the influential national and international think tanks engaged in the activities of undertaking public policy research and education for moulding public opinion.

*** OBJECTIVES** The main objectives of the Centre for Policy Research are:

1. to promote and conduct research in matters pertaining to
   a) developing substantive policy options;
   b) building appropriate theoretical frameworks to guide policy;
   c) forecasting future scenarios through rigorous policy analyses;
   d) building a knowledge base in all the disciplines relevant to policy formulation;
2. to plan, promote and provide for education and training in policy planning and management areas, and to organise and facilitate Conferences, Seminars, Study Courses, Lectures and similar activities for the purpose;
3. to provide advisory services to Government, public bodies, private sector or any other institutions including international agencies on matters having a bearing on performance, optimum use of national resources for social and economic betterment;
4. to disseminate information on policy issues and know-how on policy making and related areas by undertaking and providing for the publication of journals, reports, pamphlets and other literature and research papers and books;
5. to engage the public sphere in policy debates; produce policy briefs to liaise with legislatures; and
6. to create a community of researchers.

*** LIST OF ACTIVITIES/SUBJECTS PURSUED**

1. Political Issues and Governance;
2. International Relations and Foreign Policy/Diplomacy;
3. Economic Policy Issues, National, Bilateral, Regional, and Global;
4. Security - Internal and External;
5. Public Services Delivery Policies;
6. Institutional Design;
7. Civil Society;
8. Regulation of Capitalism;
9. Population, Public Welfare Services, and Sustainable Development;
10. Constitutional and Legal Theory;
11. Institutional and Administrative Capacity Building for delivering Macro- Management of Reforms;
12. Dialogues with Strategic Partner Countries for Enhancing Engagement with Focus on South Asian and other Asian Countries;
13. Sectoral Policies for Infrastructural Development (Energy including Electric Power, Telecommunications, Roads, Ports, Airports etc.); and
14. Regional Development among States with Special Reference to Northeast India and Kashmir.

For general enquiries, please contact:
Office of the President
CENTRE FOR POLICY RESEARCH, NEW DELHI –110021 (INDIA) Telephone: +91-11-2611-4797;
Fax: +91-11-2687-2746
E-mail: president.cpr@cprindia.org **Website**: http://www.cprindia.org

Annual Report

2017 – 2018

CENTRE FOR POLICY RESEARCH
Dharma Marg, Chanakyapuri
New Delhi 110021 (INDIA)

CONTENTS

1.	Vision Statement	Inside front cover
2.	CPR Governing Board	7
3.	CPR Executive Committee	9
4.	President's Report	10
5.	Research Publications	12
6.	Discussions, Meetings and Seminars/Workshops	13
7.	CPR's Initiatives	22
8.	Funded Research Projects	32
9.	Faculty News	57
10.	Activities of Research Associates	90
11.	Library and Information & Dissemination Services	102
12.	Computer Unit's Activities	103
13.	Grants	104
14.	Tax Exemption for Donations to CPR	104
15.	CPR Faculty and Staff	105

CPR GOVERNING BOARD

(As on 31st March 2018)

1. Mr. Eric Gonsalves — Chairman
   Former Secretary, Government of India
   C-52, IFS Coop.Group Housing Society
   Mayur Vihar, Phase – I
   New Delhi – 110 091

2. Mr. Subodh Bhargava — Member
   Chairman, Tata Telecom Ltd.
   A-15/1, DLF City Phase-1
   Gurgaon – 122 001

3. Dr. (Ms.) Meenakshi Gopinath — Member
   Director, WISCOMP
   A-86 Nizamuddin East
   New Delhi – 110 013

4. Member-Secretary — Member
   Indian Council of Social Science Research
   Aruna Asaf Ali Marg
   New Delhi 110 067

5. Amb. Shyam Saran — Member
   Senior Fellow
   Centre for Policy Research
   Dharma Marg, Chanakyapuri
   New Delhi 110021

6. Ms. Vinita Bali — Member
   Former CEO Britannia Industries Ltd
   1104 Prestige Exotica
   #3 Cunningham Crescent Road
   Bangalore 560 052

9. Ms. Rama Bijapurkar — Member
   206, Nirman Kendra
   Dr. E Moses Road, Mahalakshmi
   Mumbai 400 011
   Tel: 022-24937243/24932053

10. Amb. Chandrashekhar Dasgupta
    Former Ambassador and well-known Historian — Member
    C-12/11, DLF Qutab Enclave
    Phase-I
    Gurgaon 122 002

11. Mr Keshav Desiraju — Member
    Former Secretary Ministry of Health & Family Welfare
    Flat No. B-25, Radhakrishnan Salai
    9th Street, Mylapore,
    Chennai 600 004

12. Yamini Aiyar — Member-Secretary
    President and Chief Executive
    Centre for Policy Research
    Dharma Marg, Chanakyapuri
    New Delhi - 110 021

CPR EXECUTIVE COMMITTEE

(As on 31 March 2018)

1.	Mr. Eric Gonsalves Former Secretary to Government of India C-52, IFS Coop. Group Housing Society Mayur Vihar, Phase – I New Delhi – 110 091	Chairman
2.	Dr. (Ms.) Meenakshi Gopinath Director, WISCOMP A-86 Nizamuddin East New Delhi – 110 013	Member
3.	Amb. Shyam Saran Senior Fellow Centre for Policy Research Dharma Marg, Chanakyapuri New Delhi 110021	Member
4.	Yamini Aiyar President and Chief Executive Centre for Policy Research Dharma Marg, Chanakyapuri New Delhi– 110 021	Member Secretary

PRESIDENT's REPORT

It is a real privilege for me to present CPRs annual report for 2017-18. This has been a wonderfully productive year as CPR faculty continued to make important, award-winning contributions to the policy research landscape through field-defining books and a steady stream of peer-reviewed journal articles. These contributions are now the starting point of policy and public debate on issues as wide ranging as international relations, climate change and energy, domestic politics and public service delivery. This year we are especially proud of Lavanya Rajamani whose co-authored book titled, International Climate Change Law received the 2018 American Society of International Law Certificate of Merit in a Specialised Area of International Law.

CPR has a long tradition of drawing on its research to engage in the everyday life of policy making in India, shaping ideas, offering expertise and seeking to find answers to difficult policy conundrums in partnership with policymakers. In fulfilling this role, CPR faculty have, over this year, served on as many as 20 different government committees, task forces, and technical support units. These include the Ministry of Environment, Forest and Climate Change's (MoEFCC) advisory committee on a Long Term Strategy for Low Carbon Development; the expert committee on Renewable Energy Act under the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE); the NITI Aayog's Committee for national strategy on Rare Earths; the curriculum advisory committee at the National University of Educational Planning and Administration (NUEPA) to develop the curriculum for programmes on education; and the Working Group for the National Sample Survey 76th Round on Disability, Drinking Water, Sanitation, Hygiene and Housing Condition by the National Statistical Commission.

As academics and policy practitioners we also seek to bring some nuance and evidence in to an increasingly polarised public sphere through writings in newspapers and opinion pages. In 2017-18, CPR researchers and faculty wrote as many as 432 articles and op-eds in the mainstream media. In addition, we organized a number of seminars and public lectures on critical policy issues from the Doklam crisis and India-China relations to domestic concerns like air pollution, party politics and elections. This annual report offers but a glimpse in to the wide range of work that we do at CPR and I hope that as you read these contents, you will share in our intellectual curiosity and excitement as we seek to better understand and enrich policy debates in India.

2017-18 has been an important year in CPR's institutional trajectory. We undertook a critical leadership transition and I have been given the honour and privilege of leading this wonderful institution. This transition was made easy thanks, in no small measure, to the unflinching support of our board, funders, and academic and policy partners. We are extremely grateful for the trust they have reposed in us. As we enter a new phase in our institutional life, CPR remains steadfastly committed to our core values of fierce independence, a commitment to ideas and argument, a willingness to ask difficult questions and objectively assess evidence. And we will be counting on your support as we hold on to these values and scale new heights.

I am, also personally grateful to CPR faculty whose commitment to the pursuit of excellence and courage to ask difficult questions is a source of motivation and inspiration. I am particularly grateful to our young research associates whose energy, excitement and curiosity ensures that we remain a vibrant, cutting edge institution. Our communications team led by Richa Bansal that constantly pushes us out of our ivory towers to use our research as a tool to engage with the world and our dedicated administrative staff admirably led by Mr. Ravi, are the backbone of our institution. The Chair of the CPR Board, Mr Gonsalves, Executive Committee Members, Meenakshi Gopinath and Shyam Saran, have, as always been a been a source of strength but especially more so this year as the institution underwent a transition. I would also like to thank all the organisations and individuals that fund us. They have been exemplary in their support.

Before signing off, I would like to remember Dr Ajit Mozoomdar, Honorary Research Professor at CPR, who passed away in early 2018. Dr Mozoomdar's life's work, his passion and commitment to academic excellence and above all his sense of humour inspired many generations of CPR faculty. We miss him deeply.

RESEARCH PUBLICATIONS

The following research publications were brought out during the year 2017-18:

A. Major Books Published

1. *How India Sees the World: Kautilya to the 21st Century* by Shyam Saran, Juggernaut, 2017
2. *International Climate Change Law*, co-authored by Daniel Bodansky, Jutta Brunne, and Lavanya Rajamani, Oxford University Press, 2017
3. *Rethinking Public Institutions in India*, co-edited by Devesh Kapur, Pratap Bhanu Mehta, and Milan Vaishnav, Oxford University Press, May 2017
4. *Subaltern Urbanisation in India*, co-edited by Eric Denis and Marie-Helene Zérah, Springer India, April 2017.
5. *Dispossessed: Stories from India's Margins*, co-authored by Amod Shah, Anhad Imaan, Annie Baxi, Ashwin Parulkar, Rhea John, Saba Sharma, and Shikha Sethia, Speaking Tiger Publishing Private Limited, 2017
6. *Water Law in India: An Introduction to Legal Instruments*, Second Edition, co-edited by Philippe Cullet and Sujith Koonan, Oxford University Press, 2017

B. Articles Published by CPR Faculty

About **432 articles** were also published by CPR Faculty Members in major national international dailies and popular journals during the year.

DISCUSSIONS, MEETINGS AND SEMINARS/WORKSHOPS

(Organised by CPR)

During the year under review, the CPR organised several seminars and special discussion meetings in addition to weekly faculty meetings with distinguished experts as also some Workshops-cum-Conferences. These are listed below:

a) National

ECONOMIC POLICY

1. Talk on "Digital Spine for Learning – Ek Step Foundation" by Mr. Shankar Maruwada is the CEO and Co-founder of Ek Step Foundation on 3 February 2017 at CPR.
2. 5-Institute Budget Seminar on "The Union Budget 2017-18: Reforms and Development Perspectives", jointly hosted by the Centre for Policy Research; Indian Council for Research on International Economic Relations; India Development Foundation; National Council of Applied Economic Research; and National Institute of Public Finance and Policy on 4 February 2017 at Taj Mahal Hotel, New Delhi
3. Talk on "International Experience and Lessons Learnt from Brazil in Decentralisation" by Ms. Deborah L Wetzel, Senior Director, Governance Global Practice, World Bank on 16 February 2017 at CPR.
4. Talk on "A World Divided: Emerging Demographic and Geographic Fissures in the Global Economy" by Mr. Yuwa Hedrick Wong, Chief Economist and Chair of the Academic Advisory Council at MasterCard Center for Inclusive Growth, and Global Economic Advisor, MasterCard Worldwide on 17 February 2017 at CPR.
5. Discussion on 'Jobs, Joblessness and India's Economic Future' on 15 November 2017 at CPR.
6. Panelists include:
   Mr. Bruce Stokes, Director of Global Economic Attitudes at Pew Research Centre and member of the JustJobs Network Advisory Group,

   Ms.Yamini Aiyar, President & Chief Executive, Centre for Policy Research

   Ms. Sabina Dewan, President & Executive Director, JustJobs Network

7. Discussants include:
   Dr. Ajit Ghose, Institute for Human Development

   Dr. Srinivasan Iyer, Ford Foundation, India, and

   Mr. Gurcharan Das, Author and Public Intellectual

8. 5-Institute Budget Seminar 2018-19, jointly hosted by the Centre for Policy Research; Indian Council for Research on International Economic Relations; India Development Foundation; National Council of Applied Economic Research; and National Institute of Public Finance and Policy on 10 February 2018 at The Leela Palace, New Delhi

ENVIRONMENTAL LAW AND GOVERNANCE

1. Talk on “How much energy and emissions does India ‘need’ for decent living?” by Dr. Narasimha Rao, Project Leader and Research Scholar at the International Institute for Applied Systems Analysis on 23 January 2017 at CPR.
2. Roundtable Discussion on “President Trump's Executive Order on Promoting Energy Independence and Implications for India” on 7 April 2017 at CPR. Panelists include Prof. Lavanya Rajamani, Dr. Arunabha Ghosh, Dr. Chandra Bhushan, and Dr. Navroz K Dubash. The discussion was chaired by Dr. Radhika Khosla.
3. Talk on 'Does Basic Energy Access Generate Socio-Economic Benefits?' Dr. Johannes Urpelainen, Associate Professor of Political Science, Columbia University on 29 May 2017.
4. Talk on 'Lighting Up Bihar: Improving Electricity Supply and Reducing Distribution Losses' by Dr. Anant Sudarshan is India Director of the Energy Policy Institute at Chicago University (EPIC-India) on 5 July 2017 at CPR.
5. Talk on 'The BP Statistical Review of World Energy' by Dr. Kaushik Deb is an economist at BP in India on 17 August 2017 at CPR.
6. Clearing the Air Seminar Series: 'Filling the Knowledge Gap on Air Quality in Indian Cities' by Dr Sarath Guttikunda, founder/director of UrbanEmissions.Info (UEinfo, India), is a NASA Earth and Space Science Fellow; and a TED fellow on 4 December 2017 at CPR.
7. Clearing the Air Seminar Series: Panel on 'Health Effects of Exposure to Air Pollution' on 20 December 2017 at CPR. Panelists include:
   Professor D. Prabhakaran, Cardiologist and epidemiologist by training, currently the Vice President- Research & Policy, Public Health Foundation of India (PHFI)
   Dr. Raj Kumar, Director, Vallabhhai Patel Chest Institute, University of Delhi
   Dr. Preet K. Dhillon has a background in global cancer epidemiology and experience from several organizations in the US and India He manages the Centre for Environmental Health at the Public Health Foundation of India
8. Clearing the Air Seminar Series: ‘Air pollution as a preventable cause of adverse birth outcomes in India: New evidence from cohort studies in Tamil Nadu' by Prof Kalpana Balakrishnan Ph.D., FAMS, Director, World Health Organization Collaborating Center for Occupational and Environmental Health, SRU-ICMR Centre for Advanced Research on Air Quality, Climate and Health, Department of Environmental Health Engineering, Sri Ramachandra University, Porur, Chennai. on 10 January 2018 at CPR.
9. Talk on ‘An End-use and Efficiency Strategy for Sustainable Development with Climate Change Mitigation as Entry Point' by Prof. Arnulf Grubler (Grübler) is Acting Program Director of the Transitions to New Technologies Program at the International institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Laxenburg, Austria on 15 January 2018 at CPR
10. Clearing the Air Seminar Series: Panel Discussion on ‘The role of the transport sector in Delhi’s air quality: key drivers and opportunities for intervention’ on 1 February 2018 at CPR.
    Panelists include:

    Mr. Amit Bhatt, Director of Integrated Urban Transport at WRI India,

    Mr. Parthaa Bosu, lead consultant on air pollution with Environment Defence Fund, based in the United States

    Sumit Sharma Fellow and Associate Director of the Earth Science and Climate Change group of TERI.
    Panel moderated by: Ms. Mukta Naik, Senior Researcher, Centre for Policy Research
11. Clearing the Air Seminar Series: ‘Crop Burning as a source of Air Pollution in National Capital Region' on 23 February 2018 at CPR.
    Speakers include:

Dr M L Jat, Senior Cropping Systems Agronomist and CIMMYT-CCAFS South Asia Coordinator in New Delhi and a fellow at the National Academy of Agricultural Sciences (NAAS).

Mr. Pritam Singh Hanjra, Rsident of Urlana Khurd, District Panipat.

Dr Rajbir Yadav, Principal Scientist, Division of Genetics, IARI, New Delhi.

Mr. Harish Damodaran is a veteran journalist who has worked with several prestigious newspapers and news agencies in India. He is currently the Rural Affairs and Agriculture Editor at *The Indian Express*

12. Clearing the Air Seminar Series: Panel on 'Municipal Solid Waste as a cause of Air Pollution' on 7 March 2018 at CPR.
    Speakers include:
    Mr. Ravi Agarwal, Founder Director of Toxics Link (www.toxicslink.org), an environmental NGO based in New Delhi
    Ms. Nalini Shekhar, Co–founder of Hasiru Dala (http://hasirudala.in), a non-profit organization working on the informal waste economy.
    Dr Seema Awasthi, Founder and Director of ICUC Consultants Pvt. Ltd.(http://icuc.in/site/)

INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY

1. Public Lecture on "Civil Wars: A History in Ideas" by Prof. David Armitage, Lloyd C. Blankfein Professor of History and former Chair of the Department of History at Harvard University, Chaired by Dr. Pratap Bhanu Mehta, President & Chief Executive, Centre for Policy Research, New Delhi on 16 January 2017 at India International Centre, New Delhi
2. Talk on "Reflections on Europe and the UK after Brexit" by Prof. Timothy Garton Ash, Professor of European Studies in the University of Oxford and Isaiah Berlin Professorial Fellow at St Antony's College on 24 January 2017 at CPR.
3. Talk on "Superpower in Search of a Strategy: US Collaboration with China and India in the Globalisation of Innovation" by Prof. Andrew Kennedy specializes in international politics, with particular interest in the foreign relations of China, India, and the United States on 14 February 2017 at CPR.
4. International Conference on "India-China and the Emergence of Post-War Post-Colonial Asia, 1945-50", organised by the Institute of Chinese Studies, New Delhi in collaboration with the Cenre for Policy Research and the India International Centre, New Delhi on 17-18 March 2017 at India International Centre, New Delhi
5. Talk on "Restructuring India-Nepal Relations" by Dr. Baburam Bhattarai, former Prime Minister of Nepal on 17 March 2017 at CPR.
6. Lecture on "Is Dollar Hegemony Inevitable? Possibilities for Reform in the Global Reserve System" by Prof Anush Kapadia, Humanities and Social Sciences Department, Indian Institute of Technology, Bombay on 10 April 2017. It was first in CPR series of monthly lectures on Globalization in Question.
7. Lecture on "Hyperglobalisation is dead. Long Live Globalisation" by Dr. Arvind Subramanian, Chief Economic Advisor, Government of India on 8 May 2017. It was second in CPR series of monthly lectures on Globalization in Question.
8. Talk on 'Is the Latest 'Reset' in U.S.-Russian Relations Dead on Arrival?' by Prof. Timothy J Colton, Morris and Anna Feldberg Professor of Government and Russian Studies and the Chair of the Department of Government at Harvard University on 9 June 2017 at CPR.
9. Talk on 'A War without Winners: Rethinking the 1962 War' by Prof. Bérénice Guyot-Réchard, Lecturer in 20th International History at King's College London on 7 August 2017 at CPR.
10. Book Discussion on 'How India Sees the World: Kautilya to the 21st Century' by Mr. Shyam Saran, former Foreign Secretary, Government of India and Senior Fellow at the Centre for Policy Research and Dr. Srinath Raghavan, Senior Fellow at the Centre for Policy Research on 13 September 2017 at CPR.

11. Lecture on 'Indian Growth: Prospects for the Future' by Mr. Jahangir Aziz, Head of EM Asia Economic Research at J.P. Morgan on 22 September 2017 at CPR. It was third in CPR series of monthly lectures on Globalization in Question.
12. Discussion on 'The United States and India: Forging an Indispensable Democratic Partnership' on 16 January 2018 at CPR. Discussants include:
13. Introductory remarks Ms. Yamini Aiyar, President, Centre for Policy Research
    Speakers include:
    Ms. Nirupama Rao, Co-Chair, Center for American Progress Task Force on U.S.-India Relations; former Foreign Secretary, Ministry of External Affairs, India and former Indian Ambassador to the U.S.
    H.E. Mr. Rich Verma, Co-Chair, Center for American Progress Task Force on U.S.-India Relations; Vice Chairman, The Asia Group and former U.S. Ambassador to the Republic of India
    Moderator: Mr. Ashok Malik, Press Secretary to the President of India
14. Book Discussion on 'The Price of Aid: The Economic Cold War in India' by Prof. David C. Engerman, Otillie Springer Professor of History at Brandeis University, USA on 19 February 2018 at CPR.
15. Lecture on 'Indian Migration in Global History' by Prof Sunil Amrith, Mehra Family Professor of South Asian Studies at Harvard University, jointly organised by the Centre for Policy Research and Infosys Science Foundation on 26 February 2018 at India International Centre, New Delhi.
16. Book Discussion on 'Our Time Has Come - How India is Making its Place in the World' by Prof. Alyssa Ayres, Senior Fellow for India, Pakistan, and South Asia at the Council on Foreign Relations (CFR), New York, USA on 19 March 2018 at CPR. The discussion was moderated by Dr. Srinath Raghavan, Senior Fellow, CPR

LAW, REGULATIONS, AND THE STATE

1. Seminar on “Understanding Land Acquisition Disputes in India” by Dr. Namita Wahi, Fellow, CPR and Mr. Ankit Bhatia, Research Associate, CPR on 5 January 2017 at CPR.
2. Book Discussion on “How Solidarity Works for Welfare: Subnationalism and Social Development in India” authored by Ms. Prerna Singh on 12 January 2017 at CPR.
   Panelists include:

   Prof. Santosh Mehrotra, Jawaharlal Nehru University

   Dr. Partha Mukhopadhyay, Senior Fellow, CPR and

   Dr. Neelanjan Sircar, Senior Fellow, CPR

3. Talk on “Quality of Healthcare in Rural and Urban India” by Dr. Jishnu Das, Visiting Senior Fellow, CPR on 9 February 2017 at CPR.
4. Talk on “Sanskrit Prosody” by Dr. Bibek Debroy, Member NITI Aayog on 16 February 2017 at CPR.
5. Book Discussion on “Navigating the Labyrinth: Perspectives on India’s Higher Education” on 8 March 2017 at India Habitat Centre, New Delhi. Discussants included: Pankaj Chandra from Ahmedabad University, Apoorvanand Jha from the University of Delhi, Devesh Kapur from the University of Pennsylvania, and Pratap Bhanu Mehta from the Centre for Policy Research. The discussion was moderated by Anubha Bhonsle from CNN News18.
6. Book Discussion on “Rethinking Public Institutions in India” on 10 March 2017 at India Habitat Centre, New Delhi. Panelists include: Arvind Subramanian, Jay Panda, Montek Singh Ahluwalia, Shailaja Chandra, and Yogendra Yadav.
7. ICSSR-sponsored “Orientation Programme on Social Science Research” for research scholars and lecturers belonging to SC/ST and other Marginalised Group from 30 March to 1 April 2017 at CPR
8. Talk on “Prenatal Sex Selection and its Future” by Christophe Z Guilmoto, Senior Fellow, Demography, French Institut de recherche pour le développement (IRD) based at CEPED in Paris on 3 April 2017 at CPR.

9. Discussion on “Precarious Neighbourhoods” on 6 April 2017 at CPR.
   Presenters

   Dr. Solomon Benjamin, Associate Professor, Department of Humanities and Social Sciences, IIT Madras.

   Dr. Agnès Deboulet, Professor of Sociology, Université Paris-VIII Vincennes Saint-Denis, and Associate Director of the Laboratoire Ville, Architecture, Urbanisme Environnement, LAVUE-CNRS.

   Dr. Véronique Dupont, Senior Research Fellow, Institute of Research for Development (IRD), and Sr. Visiting Fellow, Centre For Policy Research (CPR).

   Mr. Bipin Rai, Member-Expert (Non-Official), Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB)

   Panelists:

   Mr. Rakesh Ranjan, Senior Consultant, NITI Aayog.

   Mr. N Sridharan, Professor at the School of Planning and Architecture, New Delhi.

   Mr. S.K. Tiwari, Economic Advisor, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.

   Ms. Renu Khosla, Director, Centre for Urban and Regional Excellence (CURE)

10. Talk on 'Low-skilled migration and precarious work - Where do the borders of forced migration begin and end?' by Ms. Priya Deshingkar is Research Director of the six-year DFID-funded Migrating out of Poverty Research Consortium on 17 April 2017 at CPR.
11. Talk on 'The Broken Ladder - The Paradox and the Potential of India’s One Billion' by Prof. Anirudh Krishna, Edgar T. Thompson Professor of Public Policy and Professor of Political Science at Duke University, USA on 18 April 2017 at CPR.
12. Talk on “Development Conflicts We Know Nothing of” by Prof. Rohit Prasad, Professor of Economics, MDI Gurgaon on 20 April 2017 at CPR.
13. Talk on 'The Future We Need: Natural Resources as a Shared Inheritance' by Mr. Rahul Basu, presently a member of a number of initiatives, including the Goa Foundation, the Goenchi Mati Movement and The Future We Need on 17 May 2017 at CPR.
14. Talk on 'Negotiating authoritarianism and its limits: Worker-led collective bargaining in the Pearl River Delta' by Dr Chloé Froissart, Director, Tsinghua University Sino-French Centre in Social Sciences, Beijing; Senior Researcher, Political Sociology and Political Science, French Centre for Research on Contemporary China (CEFC), Hong Kong; and Associate Professor, University of Rennes 2 (France) on 18 May 2017 at CPR.
15. Talk on 'Of Vagrants & Migrants: On the Discursive Limit of Law' by Dr Avishek Ray, National Institute of Technology Silchar, Assam on 6 June 2017 at CPR.
16. Talk on 'Mapping Land Conflicts in India' by Journalists Mr. Kumar Sambhava Shrivastava, Mr. Ankur Paliwal and Mr. Bhaskar Tripathy respectively on 22 June 2017 at CPR.
17. Talk on Understanding Local State Capacity: Evidence from a Nationwide Survey of Block Development Officers in India by Prof. Aditya Dasgupta of Stanford and UC-Merced and Prof. Devesh Kapur of University of Pennsylvania on 11 July 2017 at CPR.
18. Talk on “Dispossession without Development: Land Grabs in Neoliberal India” by Dr Michael Levien, Assistant Professor of Sociology at Johns Hopkins University, USA on 19 July 2017 at CPR.
19. Talk on 'State of Aadhar Report 2016-17' by Mr. Ronald Abraham, Partner IDinsight, Delhi on 21 July 2017 at CPR.
20. Talk on 'Industrial Foods and Cultural Identities in India' by Dr. Amita Baviskar, Prof. of Sociology, Institute of Economic Growth, Delhi on 24 August 2017 at CPR.

21. Book Discussion on 'How the BJP Wins: Inside India's Greatest Election Machine' between author Mr. Prashant Jha, Associate Editor, Hindustan Times and CPR's in-house election expert and Senior Fellow, Dr. Neelanjan Sircar on 25 September 2017 at CPR.
22. Talk on 'Reforming Personal Laws' by Dr. Farrah Ahmed, Associate Professor at Melbourne Law School, University of Melbourne on 27 September 2017 at CPR.
23. Talk on "Government Financing of Healthcare in India since 2005: Achievements and Challenges" by Prof. Peter Berman & Team from Harvard TH Chan School of Public Health on 6 October 2017 at CPR.
24. Discussion on 'Unpacking the Rohingya Refugee Crisis' by Mr. Shyam Saran, former Foreign Secretary & Senior Fellow, CPR; Dr. Nimmi Kurian, Associate Research Professor, CPR and Dr. Srinath Reghavan, Senior Fellow, CPR respectively on 7 November 2017 at CPR.
25. Seminar on 'A Review of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1986' on 21 November 2017 at CPR. Panelists include: Mr. Alok Dubey, Mr. Ravi Kant, Ms. Akriti Gaur and Mr. Kulbir Krishna.
26. ICSSR-sponsored "Orientation Programme on Social Science Research" for research scholars and lecturers belonging to SC/ST and other Marginalised Group from 29 November to 2 December 2017 at CPR
27. Talk on 'India Consensus: Helping priorities state spending' by Dr Bjorn Lomborg, Danish author and visiting professor at the Copenhagen Business School, as well as President of the Copenhagen Consensus Center on 7 December 2017 at CPR.
28. Presentation and panel discussion on 'Unpacking the results of the Gujarat elections' on 22 December 2017 at CPR.
    Presentation by: Dr. Neelanjan Sircar, Senior Fellow CPR
    Panelists:
    Mr. Prashant Jha, Associate Editor, Hindustan Times
    Mr. Mahesh Langa, Senior Assistant Editor, The Hindu
    Ms. Ruhi Tewari, Associate Editor, ThePrint
    Dr. Gilles Verniers, Co-Director of Trivedi Centre for Political Data, Ashoka University
29. Conference on "Land Rights, Land Acquisition, and Inclusive Development in India" on 2-3 March 2017 at India International Centre, New Delhi.
30. CPR-LRI Fourth Annual Conference on "Land Laws, Land Acquisition, and Scheduled Areas in India" on 15-16 March 2018 at India International Centre, New Delhi
31. Webinar on: 'Closing the enforcement gap: A Practice Guide for Environment Justice Paralegals' by Ms. Kanchi Kohli, Ms.Manju Menon and Ms. Meenakshi Kapoor, officials of CPR's Namati Environmental Justice Program on 7 February 2018.
32. Workshop on 'New opportunities in controlling vector-borne diseases: Big data, new insecticides and governance in urban India' jointly organised by CPR, CNRS, ICMR on 9 February 2018 at Centre for Social Science and Humanities, New Delhi. The discussion was moderated by Oliver Telle, Senior Visiting Researcher, CPR.
33. Seminar on 'The Identification Revolution and Development' by Dr. Alan Gelb, Senior Fellow and Director of Studies, Center for Global Development, Washington DC, USA on 22 March 2018 at CPR.
34. Talk on 'Technology and society: Education of future leaders for an informed citizenry' by Prof Venkatesh Narayanamurti, Harvard University on 23 March 2018 at CPR.

URBANISATION

1. CORP Seminar on "Malaysian Perspective on River Pollution, Sanitation and Sewerage Management" by Mr. Dorai Narayanan, fomerly Head of Department of the Planning & Engineering Department in Indah Water Konsortium on 23 January 2017 at CPR.

2. CORP Seminar: 'An Economic Characterisation of Sanitation: Between the State's Production and the Household's Demand' by Ms. Chloé Leclère, PhD Scholar in Economics, Ecole Normale Superieure de Lyon in France on 19 May 2017 at CPR.
3. Talk on 'Between 'khet,' 'factory' and 'colony': Exploring intersections of caste and gender among migrant industrial workers' by Ms. Eesha Kunduri, Research Associate at Centre for Policy Research on 28 June 2017 at CPR.
4. Talk on 'Place-based Preferential Tax Policy and its Spatial Effects: Evidence from India's Program on Industrially Backward Districts' by Dr. Yi Jiang, Senior Economist, Economic Research and Regional Cooperation Department, Asian Development Bank, Delhi and Dr. Rana Hasan, Director, Development Economics and Indicators Division, Asian Development Bank, Delhi on 14 July 2017 at CPR.
5. CORP Seminar on 'The Cleaning Brigade: Connects and Disconnects' by Dr. Sanghmitra Acharya is Director, Indian Institute of Dalit Studies, Delhi on 20 September 2017 at CPR.
6. Talk on 'Problematising Water: Effecting Change' by Ms. Supriya Singh, recently submitted her thesis for a PhD on Politics of Water in Delhi on 25 October 2017 at CPR
7. CORP Seminar on 'Last 100 metres: Safeguarding potable water provisioning to urban informal settlements' by Dr Manoj Roy, Lecturer of Sustainability, Lancaster Environment Centre, Lancaster University, UK on 27 October 2017 at CPR.
8. Conference on 'Sustainable Sanitation: Evidence and Practice' on 12 December 2017 at India Habitat Centre, New Delhi on 12 December 2017
9. Seminar on 'Valuing Waste or Wasting value? Rethinking waste processing in fast growing middle-income cities' by Ms. Irène Salenson of AFD; Ms. Rémi de Bercegol of CNRS; and Ms. Swati Singh Sambyal of CSE on 12 February 2018 at CPR

b) International

1. Networking Event at the UN-Habitat III Conference: Think Small, Go Big" on 17 October 2016 in Quito, Ecuador. The event was organised by the Centre for Policy Research in collaboration with the Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), the French National Centre for Scientific Research (CNRS), Habitat for Humanity, Southern Voice, the French National Institute for Sustainable Development (IRD), Slum Dwellers International, and UN-HABITAT.
2. Institute of South Asian Studies, Singapore and Centre for Policy Research, New Delhi jointly organniged a Panel Discussion on 'The Clean India Mission: Challenges and Prospects' on 30 October 2017 at MEI Conference Room, at the Heng Mui Keng Terrace, Singapore.

1. Workshops/Training Programmes (conducted by the Institute)

ECONOMIC POLICY

1. Workshop on "Measuring Economic Inclusivity in India: Conceptual and Empirical Recommendations for an Indicator Framework" on 22 August 2017 at CPR.

LAW, REGULATIONS, AND THE STATE

1. ICSSR-sponsored "Orientation Programme on Social Science Research" for research scholars and lecturers belonging to SC/ST and other Marginalised Group from 30 March to 1 April 2017 at CPR

URBANISATION:

1. Workshop on "Quality Infrastructure: Japanese Investment in India" on 27 February 2017 at Claridges Hotel, New Delhi. The workshop was inaugurated by His Excellency, the Ambassador of Japan to India. Mr Amitabh Kant, CEO of NITI Aayog delivered the keynote address. Other key speakers were Mr. Koki Hirota, Chief

Economist of JICA from Japan and Mr R C Bhargava, Chairman of Maruti Suzuki and representatives of industry from Japan and India.

2. CPR-CSH Workshop on “BRICS Cities: What are we comparing?” by Mr. Philip Harrison is the South African Research Chair in Spatial Analysis and City Planning on 31 January 2017 at CPR
3. CPR-CSH Workshop on “Gender and Public Transport in India: How do we move from women's safety to gender equity?'” by Ms. Sonal Shah, Senior Manager, Institute for Transportation and Development Policy, on 28 February 2017 at CPR
4. Workshop on “Labour Migration and Social Change in India” on 28 March 2017 at CPR.
5. CPR-CSH Workshop on “The Metropolis and the Diaspora: Bangalore Property Market through the Transnational Lens” by Ms. Aurélie Varrel, a CNRS researcher in Geography, on 28 March 2017 at CPR
6. Workshop on “Sanitation for People: Assessing Socio-Cultural Realities of Sanitation Practice in Indian Cities” on 29 March 2017 at CPR.
7. CPR-CSH Workshop on “The Puzzle of Indian Urbanisation” by Dr Pronab Sen is currently the Country Director for the International Growth Centre's India Central Programme, on 25 April 2017 at CPR
8. CPR-CSH Workshop on “Democratisation through Participatory Action Planning in Yangon” by Ms. Banashree Banerjee, an urban planner, working as an independent consultant and also as an associate staff member of the Institute for Housing and Urban Development Studies, Rotterdam, on 30 May 2017 at CPR
9. CPR-CSH Workshop on “What does an Indian smart city look like?” by by Ms. Ashwathy Anand, a trained architect from the School of Planning and Architecture, Bhopal; Mr. Ajai Sreevatsan, former investigative reporter with The Hindu and Ms. Persis Taraporevala is a Research Associate at the Centre for Policy Research on 27 June 2017 at CPR
10. Workshop on 'A Competition for Urban Land, Policies towards Informal Settlements in Lebanon, Cambodia and Syria' by Ms. Valérie Clerc, Research Fellow, French National Research Institute for Sustainable Development – IRD, and a member of the CESSMA Centre for Social Sciences Studies on Africa, America and Asia in Paris on 25 July 2017 at CPR.
11. CPR-CSH Workshop on “Everyday journeys of urban working mothers: Evidence from France and India” by Ms. Vandana Vasudevan, doing her doctorate from the University of Grenoble, France on 29 August 2017 at CPR
12. CPR-CSH Workshop on “The Heritage of the Ordinary – A Case of Urban Heritage Conservation in Chandernagore” by Ms. Aishwarya Tipnis is the principal architect of an eponymous architectural practice based in New Delhi on 26 September 2017 at CPR
13. CPR-CSH Workshop on “Avatars of participation: The development of participatory practices in the city-state of Delhi” by Prof. Stéphanie Tawa Lama-Rewal, Research Fellow (Political Science), Centre for South Asian Studies (CNRS-EHESS), Paris on 31 October 2017 at CPR
14. CPR-CSH Workshop on “Changing party system in Delhi and the emergence of Aam Aadmi Party” by Dr. Adnan Farooqi, Assistant Professor, Department of Political Science, Jamia Millia Islamia, New Delhi on 28 November 2017 at CPR
15. CPR-CSH Workshop on “Building Solidarities in the (Re) Construction of Migrant Communities in Johannesburg” by Dr. Pragna Rugunanan, Associate Professor, University of Johannesburg, South Africa on 26 December 2017 at CPR
16. CPR-CSH Workshop on “Patterns and pathways of planetary urbanisation in comparative perspective” by Prof. Christian Schmid, Professor of Sociology at the Department of Architecture at ETH Zurich on 30 January 2018 at CPR
17. CPR-CSH Workshop on “We Are Greener Than You Think": Examining Indian Cities' Response to Climate Change” by Dr. Radhika Khosla, Fellow, CPR and Mr. Ankit Bhardwaj, Research Associate, CPR on 27 February 2018 at CPR

18. CPR-CSH Workshop on “Sustainable Cities through Heritage Revival: Asian Case Studies" by Ms. Olga Chepelianskaia, an international sustainable urban development consultant, Founder of UNICITI and Program Manager of SEHER INTACH on 27 March 2018 at CPR
19. Workshop on 'New opportunities in controlling vector-borne diseases: Big data, new insecticides and governance in urban India' jointly organised by CPR, CNRS, ICMR on 9 February 2018 at Centre for Social Science and Humanities, New Delhi. The discussion was moderated by Oliver Telle, Senior Visiting Researcher, CPR.

CPR's INITIATIVES

I. Accountability Initiative (AI)

BUDGETARY ANALYSIS OF SOCIAL SECTOR EXPENDITURE AT NATIONAL AND STATE LEVELS

- The Accountability Initiative (AI), now headed by Avani Kapur, who earlier led AI's research on public finance, published its annual Budget Brief series analysing budgetary allocations, expenditures and outputs, and outcomes of key social sector programmes ahead of the Union Budget. This year, given it was the last full budget of the current government (before elections in May 2019), AI expanded the breath of its briefs to cover nine key schemes for the first time, including: *Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), National Health Mission (NHM), Integrated Child Development Services (ICDS) Swachh Bharat (Urban and Rural), the Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS), Pradhan Mantri Awaas Yojana (PMAY), and the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS).*

Budget analysis in the media

In the run up to the budget, AI contributed widely to the public debate by publishing a series of articles in mainstream media, including *Live Mint*, *Business Standard*, *Deccan Herald*, *the Wire*, *IndiaSpends*, and the vernacular newspaper *Hindustan*. AI researchers also participated in two live *Newslaundry* discussions on Budget 2018.

- Further, in order to demystify complex budgetary information and enable increased access, AI created a micro-site on budget day to disseminate information and visualizations related to the budget. The site is accessible at: https://socialmedia490.wixsite.com/accountabilityindia
- AI's and the Centre for Global Development's collaborative effort in understanding lessons from past approaches to fiscal transfers for health related schemes was published by the *International Journal of Health Planning and Management.*

TRACKING IMPLEMENTATION OF & FACILITTATING DIALOGUE ON INDIA'S SANITATION SCHEMES

- In 2017, AI's flagship programme PAISA (Planning, Allocations and Expenditures, Institutions Studies in Accountability), on the request of the local administration in Udaipur, conducted an on-ground survey to understand the challenges in implementation of the rural arm of *Swachh Bharat Mission (SBM)*, and the process involved in declaring Gram Panchayats Open Defecation Free (ODF). The three-month-long study yielded insights on the functioning of the SBM machinery and were shared with the administration. A report of the study findings will be available by June, 2018.
- AI and Scaling City Institutions for India (SCI-FI) teams at the Centre for Policy Research organised a conference, which brought together prominent policy researchers and practitioners in

the sanitation sphere. The conference deliberated on sanitation policy and implementation, shared learnings and provided recommendations on the issue of safe sanitation, including but not limited to the role of SBM.

- As part of the third year anniversary celebrations of the launch of the Swachh Bharat Mission, Avani Kapur participated in an NDTV discussion on Challenges faced by the Mission.

CONDUCTING RESEARCH FOR GOVERNMENT TO INFORM POLICY & IMPLEMENTATION

- Since January 2018, AI has been working closely with the Technical Support Unit (TSU) set up to work with the National Health Mission (NHM) in Uttar Pradesh to understand reasons for low utilisation of health expenditure and diagnose bottlenecks in implementation of government health interventions. Findings from the research have regularly been shared with the TSU and the health Mission Director in order to determine key action areas. The study will be completed by July, 2018.

- On the request of the Delhi Commission for the Protection of Child Rights (DCPCR), since November 2017, AI has been conducting a study to understand how teachers' time is distributed across different activities in schools, whether their administrative tasks affect teaching time, and the amount of time teachers spend outside of official hours engaging in school related work. The study also aims to provide insights on teachers' perceptions of their job. The findings from the research are regularly being shared with the DCPCR.

- On the request of the Bihar Education Mission, AI conducted a field survey on maintenance of finances by School Management Committees (SMCs) in Purnia and Nalanda districts of the state. The study recorded challenges and difficulties in maintenance of cashbooks/passbooks with respect to funds for key Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) grants. Moreover, given the government's expansion of Direct Benefit Transfers (DBTs) as the mode of fiscal transfers, a study covering 590 households and 1000 students was undertaken to understand the gaps in the process of direct transfer of funds to beneficiaries for scholarship and uniform grants. The findings were shared with top SSA officials and were well received.

CAPACITY BUILDING OF ADMINISTRATIVE SERVICES STAFF AND ENGAGING WITH POLICY MAKERS

AI conducted a number of sessions as part of its larger set of trainings for members of the administrative services, including:

- Avani Kapur took a session as part of a training on Monitoring and Evaluation for Indian Economic Service (IES) Probationary Officers.
- Rajika Seth took a session for Madhya Pradesh State Cadre officials at the Centre of Good Governance at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA).
- Avani Kapur took a session as part of the in-service training on Fiscal Policy and Macroeconomic Management for All India Services (IAS – Indian Administrative Service, IPS – Indiaan Police Service and IFS – Indian Forest Service) officers organised by the National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP).

- Avani Kapur and Rajika Seth took a session on Public Expenditure Accountability and Social Audits as part of the in-service training for ICAS (Indian Civil Accounts Service) Probationer training organised by NIPFP.

In addition to engaging with the policy-making community regularly through meetings, seminars, focused interactions, in March, 2018, AI participated and presented findings from its education research in the CIES (Comparative and International Education Society) Conference – an annual academic conference bringing together researchers, students, practitioners and policy-makers from across the world – working in the area of comparative international education. Organised in Mexico, the conference, which had the theme of *Re-mapping Global Education*, was attended by 3,200 participants from 117 countries.

TRAINING GRASSROOT PRACTITIONERS ON STATE CAPABILITY

In an effort to bridge the gap between research and practice, AI launched a new avatar of its PAISA (Planning, Allocations and Expenditures, Institutions Studies in Accountability) course called *Hum aur Hamaari Sarkaar***.** Available for the first time in *Hindi* and conducted by AI's PAISA field associates, the course offers a critical analysis of state capability, and caters to grassroot-level development sector professionals working towards improving the quality of public services. Two pilots were conducted in December:

- The first pilot was conducted with district-level coordinators of the NGO Pratham in Bihar who work to implement Pratham's programmes on education at the field-level.
- The second one was conducted with block-level coordinators of the Nehru Yuva Kendra in Rajasthan – a youth organisation working to create awareness about government schemes and ensure all intended beneficiaries are able to avail these schemes with ease.

In 2018, the course will be taken to other interested organisations and an online module for individuals will also be designed.

II. Initiative on Climate, Energy and Environment (ICEE)

During the year, the ***Initiative on Climate Energy and Environment (ICEE)*** significantly broadened the scope of its work. In addition to its work on climate change, ICEE launched a new area of work on energy demand patterns, a relatively neglected area in Indian energy policy. It also initiated work on the subject of state-level electricity distribution, with a focus on governance and political economy. Furthermore, ICEE deepened its work on local environmental regulatory institutions and initiated a public communication series on air pollution.

In the past year ICEE continued its engagement on the **international climate change negotiations and debate** as well as its participation in the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC):

- Lavanya Rajamani published a co-authored book titled, *International Climate Change Law* (Oxford University Press, 2017) that received the 2018 American Society of International Law Certificate of Merit in a Specialised Area of International Law, and features on numerous reading lists across the world. Rajamani continued to publish in legal journals including in the

Journal of Environmental Law on the legal implications of the announced withdrawal of the United States of America from the Paris Agreement. She also continued her close engagement in the multilateral climate negotiations, acting as an academic expert in high-level dialogues between heads of delegations, offering legal advice, preparing background notes, and identifying 'issues and options' in relation to the ongoing Paris Rulebook negotiations.

- Navroz Dubash was appointed as the Coordinating Lead Author by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) for the chapter on *National and Sub-National Policies and Institutions* as part of their Sixth Assessment Report. In this role, he will have the responsibility of co-leading synthesis of the global experience with climate policy at national and sub-national levels. This appointment followed his participation in the Scoping Meeting, setting the terms for the report. Additionally, during the year, he co-authored a review of his experience with the IPCC in the widely read journal, *Annual Review of Environment and Resources*.

In addition to the above, ICEE's **energy focused work** concentrated on characterising India's transition in energy-demand:

- A week-long series of events sought to bring the demand-side of the energy policy to the centre stage, organised around CPR Visiting Fellow, Prof Arnulf Grubler from the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Prof Grubler held a three-day long workshop for a group of fourteen early scholars, delivered three public lectures, and participated in a high-level roundtable that concluded with an agenda-setting note on the importance of and role for energy-demand focused work in India.
- Radhika Khosla and Ankit Bhardwaj conducted a survey in Rajkot to benchmark residential energy consumption, and understand appliance purchase and use in affordable housing. Initial findings and a broader survey on India's residential energy transition were reported in the '*Plugging In*' blog series with Prayas (Energy Group). Khosla also co-authored an article on building energy transitions in the journal, *Environmental Policy and Governance*.
- Both of them also continued their work on urban climate action in India, exploring how decision makers can integrate multiple development and climate objectives in their city actions and planning. Their work was based on sustained engagement with decision makers and actors in the cities of Coimbatore and Rajkot. Khosla's case of finding synergies between climate and development actions was reported in a policy brief and shared at conferences. An extensive review of the academic literature documenting the response of Indian cities to climate change was also conducted

Since December 2017, the team at ICEE has been working on **domestic environmental governance** by organising the *Clearing the Air? Seminar Series* to promote sustained and informed public understanding around the data, impacts, sources and policy challenges involved in cleaning the air. Experts from a range of areas including health, transport, agriculture, waste and environmental governance have participated in this Series. Along with the events, the team has also prepared accessible background material on key issues relating to air pollution that is made available on the CPR website.

Faculty members also engaged with policy makers in advisory roles. Navroz Dubash served on the Ministry of Environment, Forest and Climate Change's (MoEFCC) advisory committee on a Long Term Strategy for Low Carbon Development, drawing on recent work reviewing studies of India's energy and

emissions future. He, along with Shibani Ghosh, also contributed to a committee of the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) to draft a Renewable Energy law for the country, particularly focusing on the institutional and governance requirements.

Clearing the Air? Seminar Series

Since December 2017, a group of CPR faculty and researchers from different focus areas, convened by Initiative on Climate, Energy and Environment (ICEE), has been working on air pollution in the country and issues related to it. The inter-disciplinarity of the group reflects CPR's understanding that air pollution is not just an environmental problem, but one with cross-sectoral linkages involving diverse constituencies. One of the key activities of the group has been to organise the *Clearing the Air? Seminar Series* to promote sustained and informed public understanding around the data, impacts, sources and policy challenges involved in cleaning the air. Experts from a range of areas have participated in this Series, and some of the events in the Series were:

- A talk by Dr Sarath Guttikunda on *Filling the Knowledge Gap on Air quality in Indian Cities*
- A panel co-organised and moderated by the Public Health Foundation of India on *Health Effects of Exposure to Air Pollution* with Professor D. Prabhakaran, Dr Raj Kumar, and Dr Preet K. Dhillon
- A conversation with Professor Kalpana Balakrishnan on *Air pollution as a preventable cause of adverse birth outcomes in India*
- A panel on the *Role of the transport sector in Delhi's air quality: key drivers and opportunities for intervention* with Amit Bhatt, Parthaa Bosu, and Sumit Sharma, moderated by Mukta Naik
- A panel on *Crop Burning as a source of Air Pollution in National Capital Region* with Dr M.L Jat, Pritam Singh Hanjra, and Dr Rajbir Yadav, moderated by Harish Damodaran
- A panel on *Municipal Solid Waste as a cause of Air Pollution* with Ravi Agarwal, Nalini Shekhar and Dr Seema Awasthi, moderated by Arkaja Singh

These events witnessed informative discussions on different aspects of air pollution, and highlighted the importance of policy interventions. During his talk, Dr Guttikunda discussed gaps in data on air quality, and emphasised the need to view air pollution as an around-the-year crisis rather than a short-term episodic event. Professor Balakrishnan, a well-known expert in exposure assessment and environmental epidemiology, noted in her presentation that for any reduction in the associated burden of disease, PM 2.5 levels would need to decrease drastically from current levels.

The CPR website now hosts video recordings of all the events in the Series, accompanied by accessible background material on key issues prepared by the group in consultation with experts.

III. Land Rights Initiative (LRI)

UNDERSTANDING LAND RIGHTS OF SCHEDULED TRIBES IN SCHEDULED AREAS OF INDIA

The Land Rights Initiative (LRI) team launched its report on *The Legal Regime and Political Economy of Land Rights of Scheduled Tribes in the Scheduled Areas of India* at its Fourth Annual Conference on *Land Laws, Land Acquisition, and Scheduled Areas in India*. Co-authored by Namita Wahi and Ankit Bhatia, the report included research contributions by Soumya Jha, as well as former research associates, Pallav Shukla, Spandana Battula, Upasana Chauhan and Pooja Pal. The report was the outcome of a five-year long research collaboration between the Land Rights Initiative and the Centre on Law and Social Transformation at Chr. Michelsen Institute (CMI), Norway, led by Professor Siri Gloppen.

The report illuminates why despite the existence of special constitutional guarantees for *adivasis* or Scheduled Tribes, (including, in particular, with respect to their right to land), they continue to be the most vulnerable, displaced and impoverished of all groups in India. Through a review of constitutional provisions, laws, and policies governing the rights of Scheduled Tribes and the administration of Scheduled Areas, and the financial and administrative structures that effectuate these protections, the report delineates a conflicting regime of protective and displacing laws, as well as conflicting policy narratives underlying these laws, which facilitate the displacement of Scheduled Tribes and their corresponding landlessness. The report also contains extensive primary data on the current geographical mapping of Scheduled Areas along with the current distribution of dams, forests, and mining activities there.

The LRI Conference featured commentaries on the report by various stakeholders from the government, academia, and civil society organisations. The panelists included eminent experts from across sectors, including Dr T Haque, Chairman, Special Land Cell, NITI Aayog, Raghav Chandra, Secretary, National Commission on Scheduled Tribes, Dr VNVK Sastry, former Director, Tribal Cultural Research and Training Institute, Government of Andhra Pradesh, among others. The report was covered extensively in print and television media, including The *Wire*, the *Sunday Guardian*, and *Go News*.

The work of the Land Rights Initiative, funded by the Norwegian Research Council and the Indian Council for Social Science Research, was recognised as an example of outstanding research collaboration at the India Norway Research Conference in Oslo.

UNDERSTANDING LAND ACQUISITION LITIGATION IN INDIA

At the LRI Conference, the team also showcased ongoing research on the Supreme Court litigation from 2014 to 2018 pursuant to the enactment of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation, and Resettlement Act, 2013. This research builds on LRI's 2017 report titled, *Land Acquisition in India: A Review of Supreme Court Cases from 1950 to 2016.* Shortly before the conference, Namita Wahi was interviewed by *LiveLaw* on the implications of conflicting Supreme Court decisions on the retrospective operation of the law.

Wahi had also explained the findings of the 2017 report in a CPR podcast on *Understanding Land Conflict in India,* and the YouTube video of a 2016 seminar on the study is now the one of the most watched research video on the CPR website with an unprecedented viewership of over 9,000. Wahi gave lectures on this subject in two batches of training programmes for government officials organised by The Energy and Resources Institute (TERI).

BUILDING A LAND LAWS DATABASE

The LRI team compiled a comprehensive database of all land laws for the states of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Jharkhand, Telangana, and Meghalaya. The team presented research findings on the making of such a database and preliminary analysis of the laws at the LRI Conference and at a seminar organised by the Central Information Commission.

REALISING HUMAN RIGHT TO WATER

LRI was awarded a research grant by the Norwegian Research Council as part of a multi-country research collaboration on *Realising the Human Right to Water* in Brazil, Costa Rica, India, Peru, and South Africa.

- Namita Wahi was interviewed for a *Lok Sabha* Television show called 'अस्तित्व: देश का बढ़ता भू संघर्ष', on reasons for extensive and growing land conflict in India, and by *Go News* and *Land Portal*, on the work of the Land Rights Initiative.
- Namita Wahi was a member of the Technical Committee reviewing the Pilot Study led by a consortium of research organisations on the Digital Land Records Modernisation Programme of the Department of Land Resources.
- Namita Wahi and Ankit Bhatia presented research findings on *The legal and political economy of Land Rights of Scheduled Tribes in Scheduled Areas*, at the Bergen Exchanges on Law and Social Transformation, Norway, and the Second India Land and Development Conference in New Delhi. Wahi also lectured on these findings at the University of Tromso, and participated in the India Norway Research Conference in Oslo.
- Wahi presented findings on *Understanding Land Acquisition Disputes in India* at a workshop organised by the Indian Institute of Advanced Study, Simla, and at the CPR-Namati workshop on *Comparative Research on land use change conflicts in Myanmar, Indonesia, and India*, in New Delhi.
- Wahi also presented research on *Property rights and social and economic rights, the post-colonial state and the rule of law in India*, at the iSERP Workshop, EAFIT University, Medellin, Colombia.
- Wahi participated in panels on *The 33rd anniversary of the Bhopal Gas Disaster* at Rafto House, and *Business Related Human Rights Violations: State or Corporate Responsibility?* at CMI, Bergen.
- Wahi participated in the Seventh Regional Meeting of the Think Tank Initiative in Dhaka.

The LRI Speaker Series launched in 2015, continues to showcase perspectives on land rights issues by diverse stakeholders, including academics, civil society organisations, journalists, and policymakers. Topics covered this year included land grabs and displacement, data journalism efforts pertaining to land

conflicts, and equitable and efficient intergenerational and intragenerational allocation of mineral revenues.

IV. Governance and Public Policy Initiative (GPPI)

The Governance and Public Policy Initiative (GPPI) continued its overseas academic training programmes for Indian parliamentarians and also organised domestic roundtable discussions on issues such as Aadhaar privacy concerns and database security, health commitments made in the Union Budget 2018, and prioritising child health and nutrition in India.

DOMESTIC ROUNDTABLE DISCUSSIONS

- GPPI organised a roundtable discussion on *Technology and Governance: Aadhaar Privacy Concerns and Database Security*, focusing on the pros and cons of the Aadhaar platform, which was in debate due to the several concerns it raised related to fundamental issues of privacy and political rights. The discussion aimed to create a focused discourse to help parliamentarians gain a well-rounded perspective on the risks and benefits of the platform through discussions with experts such as Pavan Duggal, Advocate, Supreme Court of India and Cyber Law expert; Gautam Bhatia, Advocate, Supreme Court; and Subhashish Bhadra, Associate, Digital Identity at Omidyar Network.

- GPPI and Global Health Strategies (GHS) jointly organised a discussion on *"Health Commitments Made in the Union Budget 2018*, focusing on the announcement of the National Health Protection Scheme and the allocation of Rs 1,200 crores to the Ayushman Bharat Programme, among other issues. GPPI and GHS also organised a discussion on *Prioritising Child Health and Nutrition in India* to deliberate on the role of political leaders in putting major public health issues such as child health and nutrition on the political agenda.

ACADEMIC OUTREACH PROGRAMMES

- GPPI took a multi-party group of political leaders for the sixth leg of the *Princeton-GPPI-CPR Strategic Affairs Program* held at the Princeton University.

- A delegation of five Indian Members of Parliament participated in interactive discussions at the Australia National University's China Centre and Crawford School of Public Policy, as part of a programme organised in partnership with Australia's Department of Foreign Affairs and Trade.

- A group of seven multi-party Members of Parliament attended the week-long 2017 *Chevening—CPR Parliamentarians Fellowship Programme* at the London School of Economics (LSE).

V. CPR-Namati Collaborative Programme on Environmental Justice

- Trained paralegals of the CPR-Namati Environment Justice Program undertook two community-led 'groundtruthing' exercises to record the impacts felt by communities due to non-compliance of environmental safeguards by landfill sites in Uttara Kannada and Kulda mines in Sundargarh, Odisha. The reports are an evidence-based tool to engage government authorities for remedial action.

- The paralegals of the Program worked alongside communities to generate evidence of environmental non-compliance (water and air pollution, dumping of waste, restricted public access to common spaces) and engaged with local institutions, achieving joint site inspections in twenty-one cases. Through these joint inspections, the affected communities were able to show the impacts of the violations and invoke effective actions from institutions such as pollution control boards, irrigation departments and the district collector. Case studies in both English and regional languages were compiled by the paralegals in a curated publication – *Making the law count*.

- Further the paralegals and affected communities made specific submissions to state governments and other authorities, including, **i)** State Level Guidelines for handling and transportation of minerals in Gujarat; **ii)** a suggested set of changes to the Karnataka State Coastal Zone Management Authority; **iii)** suggestions on the guidelines put together by the Central Ground Water Authority for issuance of No Objection Certificate (NOC) for groundwater withdrawal.

EMPOWERING ENVIRONMENTAL JUSTICE PRACTIONERS

The Program updated its *Handbook on Legal and Administrative Remedies for Community Level Environment Justice Practitioners,* releasing a second version. It pairs four different Indian languages (*Hindi, Kannada, Odiya and Gujarati*) with English.

The *Paralegal Practice Guide* provides a step-by-step procedure for obtaining remedies from the administration within the existing regulatory framework. It is available in *Hindi, Kannada, Odiya, Gujarati, Bahasa- Indonesia* and English.

Simple awareness material on regulations for groundwater abstraction and the use of surface water to remedy impacts of water pollution within the existing regulatory setup was created – drawing on the experiences of the communities and paralegals. It is available in English, *Hindi, Odiya, Kannada and Gujarati*.

MEDIA & PUBLIC ENGAGEMENT ON PROCESSES OF ENVIRONMENTAL CLEARANCES, LAND ACQUISITION, COASTAL REGULATION

- In response to a Ministry of Environment, Forest and Climate Change's (MoEFCC) proposed amendment to the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006, which allowed for post-facto clearances, the Program prepared a working paper analysing the applications received by the Ministry.

  Put info below in a quote in the side bar aligned with the paragraph

  'Findings of the paper were picked up by mainstream dailies and media portals such as *DNA, DailyO, The Hindu, Counterview, Wire.in, Reuters*. This helped in informing public engagement on the implications of the alterations being made to the EIA Notification, 2006.'

- Over the past two years, many states have introduced legislations through individual Acts and Rules concerning the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Resettlement and Rehabilitation (RFCTLARR) Act, 2013, which dilute processes of public participation, fair compensation and better resettlement entitlements. The Program put together a working paper on such dilutions by the various states, highlighting the bypassing of certain progressive provisions of the central law in the process.

  Put info below in a quote in the side bar aligned with the paragraph

  'The paper was made available by *India Environment Portal* on its website. *Counterview, Wire.in* and *DNA* ran stories sharing findings of the paper and created awareness among the public about the debate around the land-acquisition law in the country.'

- In the beginning of 2017, in an exclusionary manner, the MoEFCC initiated a process of drafting a fresh Notification to supersede the 2011 Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification, which governs development on the Indian coastline, and was developed through citizen engagement acknowledging traditional uses of the coast. In response, drawing on its historical work in this area, the Program ran a series of ten blogs pertaining to these proposed changes on the CPR website between April to August 2017, covering – the history of the law, analysis of previous changes, the court's perspective, and views of the fisher communities. The Program, through a Right to Information (RTI) Application, was able to obtain the proposed revisions in the new law, which were disclosed through one of the blogs.

  Put info below in a quote in the side bar aligned with the paragraph

  'Taking cues from the blog series, the media did detailed and in-depth reportage on alterations to the CRZ. Media stories by *The Hindu, DNA, Deccan Herald* and *Hindustan Times* contextualised the information provided in the series for states such as Mahasrahtra, Kerala and Karnataka. The series garnered interest from fisher groups, coastal communities and citizens, environmentalists, urban planners, etc., many of whom, subsequently wrote to the Ministry about the implications of the proposed revisions.'

FUNDED RESEARCH PROJECTS

I. Design and Implementation of Research in India on the Human Rights to Safe Drinking Water and Sanitation

This project focuses on one of the most important development challenges in India – sanitation. The project examines the law and policy framework in India for the realisation of the right to sanitation. It proposes an assessment of the implementation of the right to sanitation through an analysis of the law and policy framework followed by fieldwork in three states (Rajasthan, Uttar Pradesh and Kerala). The underlying purpose is to understand the conceptual framework, identify implementation challenges, highlight best practices and propose policy suggestions to ensure better realisation of the right to sanitation. The project also seeks to directly engage with policy makers and other stakeholders through learning events and workshops.

No updates for the project during the reported period.

II. Scaling City Institutions for India (SCI-FI): Sanitation

The Scaling City Institutions for India (SCI-FI): Sanitation initiative aims to inform and support the formulation and implementation of the Government of India's urban sanitation programmes and investments, and explores non-sewered sanitation service delivery models in small towns in order to create safer and more sustainable sanitation in urban areas. Over the past year, the project focused attention on some emerging questions and policy challenges of the sanitation sector. More particularly, these include: the sanitation situation in small towns and high-density settlements that are not formally classified as urban; scaling up the provision of FSM services; and developing discourse around the place of FSM in relation to caste, social exclusion and manual scavenging. The programme significantly scaled up its outreach and dissemination efforts in this period, focusing its efforts on building networks and collaborations with other institutions whose work is related to the field of sanitation. This outreach was carried out through CORP talks, a seminar series of sanitation hosted in CPR, a CPR-hosted conference and workshop, as well as through more opportunistic meetings and discussions with other institutions. A total of 76 key outputs (including meetings) have been completed for the reporting period from April 1, 2017 to Mar 31, 2018.

During this period,

1. We undertook a number of studies:

- An in-depth case study on the organization of private septic tank emptying service in the unsewered settlement of Aya Nagar, Delhi. It is based on qualitative fieldwork that was conducted from January-March 2017 gathered from interviews with service operators, residents and local leaders. The study found that small-scale operators who were organized into a local cartel provided pit emptying services to the settlement. This measure was taken in order to check market competition that had caused a decline in profit margins. The operators shared strong social ties and were associated with one another through networks of kinship and friendship. Given their prolonged exposure in the line of work, they played a key role in the settlement as disseminators of knowledge pertaining to septic tank

management among residents. Lastly, it was found that despite the use of mechanized equipment, the owners were still subject to stigmatization due to the association of human excreta with low caste communities.

- The study titled "Towards a New Research and Policy Paradigm: An Analysis of the Sanitation Situation in Large Dense Villages" was published in 2017. This research builds on several years of CPR engagement with emerging trends in urbanization, and reveals a paradigm shift in rural – urban continuum manifested in, amongst many things, planning, production and provision of public and private infrastructure. The research reveals a large preference for on-site sanitation systems in large and dense villages (LDVs) in India, especially in areas proximate to urban areas and highways, and hence the dire need for strategic approaches to augment services therewith. The study explored the secondary data on sanitation infrastructure in large and dense villages in India from three census datasets. The findings of the research highlight the state wise variations in large and dense villages, which account for sizeable percentages of respective state population and depict a generally high preference for septic tanks and improved pits. The results of the study substantiate the need for new programmatic and policy focus on large dense villages and census towns, while also showing the need for decentralization strategies to address regional and local variations. The results of the study substantiate the need for a primary survey to gauge ex-ante and ex-post SBM-Gramin intervention and adequately instruct policy makers and programme implementers on the feasible and replicable decentralized strategies to improve sanitation services for prevalent on-site sanitation systems.

- The study titled "Unpacking The Process Of Achieving Open Defecation Free Status", A Case Study Of Udaipur, Rajasthan was initiated at the request of the district administration in Udaipur, to understand better the operational challenges of Swachh Bharat Mission (Gramin) ('SBM G'), and to assist the administration in undertaking a verification of their recent sanitation efforts including ODF status by 141 panchayats and seek to examine the incentive process, IEC activities, their reach and impact. The objectives of the study were to develop a comprehensive understanding of the sanitation market in Udaipur (demand and supply sides) & identify potential market failures, and to understand and evaluate the SBM G processes and models of incentive provision and behavior change adopted by the Panchayats. The study also sought to understand the functional and socioeconomic impacts of these variable approaches towards programme implementation, and to understand from the prism of construction and usage, the intersectionality of caste, class, and gender. The study tried to achieve the mentioned objectives through the following research questions (i) how do villages become ODF? Particularly, what is the approach towards triggering, IEC, and construction? (ii) What are the type of toilets being constructed and what is the construction and usage narrative (iii) what is the perspective of the administration and what is the role of different administrators? (iv) What is the role of external stakeholders such as the preraks, SHGs, civil society organisations etc.? (v) How do the procedural aspects such as funds flow and administrative discretion work? CPR recommendations, based on the findings from the survey, include well maintained and functioning toilets in public facilities; consistent monitoring mechanism post ODF; focus on training and capacity building; IEC focus on gender sensitivity, technology and FSM, course correction measure to identify real beneficiaries.

- The study titled "Business Model Studies of Septic Tank Emptying Services in 3 Cities: Bhubaneswar, Jaipur and Dehradun" explored market characteristics and business models of septic tank emptying businesses in three cities. In all three markets, the service providers functioned at small scale, in highly informal markets, and with low operating margins. The Bhubaneswar case showed some elements of market consolidation, in that it was estimated with 5-7 entrepreneurs owned all the private septic tanks emptying vehicles (estimated to be 30 in number), whereas we found more single-vehicle businesses

in the other cities. The Dehradun study found some elements of business association between the operators, and that the operators seemed to be emptying their trucks at the city STP in a fairly organized manner. Lack of regulation and oversight or indeed any participation by local government is a common finding across all cities, although in Bhubaneswar the local authority also operated its own trucks and the role of these businesses in the provision of FSM services was formally recognized in government policy. The case studies also found interesting variations in costs, investment and pricing strategies across cities.

- The literature review titled "Manual Scavenging in India" was undertaken to understand how academia, policy makers and practitioners have defined the people and activities that encompass the term 'manual scavenging'. Part I is the compilation of an analysis of terms that the literature covers, and discus possible research questions for future research. Part II presents an annotated bibliography of the books, articles, documentaries, opinion pieces and other material reviewed. A total of 49 papers were reviewed. This section acts as an exhaustive database of summarized literature available on manual scavenging, with a special focus on the manner in which the subject has been defined so far. The time frame of the review includes publications from pre-independent India to latest works focused on the theme. The review deduces that available literature predominantly present manual scavenging as a social practice ordered around the caste system, wherein people from the so-called "polluting castes" are engaged to manually deal with untreated faecal matter. The socio-economic conditions of and caste-based discrimination faced by these communities are the dominant themes in the summarized works. Older literature on manual scavenging draws a linkage between cleaning of dry latrines and carrying of 'night soil' as 'head loads', while the new literature focuses on sewer cleaning, septic tank cleaning.

- The report titled "Manual Scavenging as a typology of cleaning activities: Primary research on sanitation work" is based on primary research conducted in an un-authorized settlements. The objective of the study was to identify a range of activities that entail the manual contact of any person with untreated human excreta, defined as "manual scavenging" for the purpose of this study. A close assessment of these activities – the actual process of cleaning and who engages in it – widens the contours of how manual scavenging has been understood over the years, in policy as well as academia. The focus in defining manual scavenging remained more on individual than on activity. For instance, the 2013 Manual Scavenging Act, like its 1993 counterpart, lays down the definition of "manual scavenger" and reckons that "manual scavenging" be construed based on the former. Academic works too are predominantly centered on communities engaged as manual scavengers, highlighting their historical disadvantages owing to the Caste system. This study reveres the past trajectory, and is fore grounded in the study of manual scavenging – underpinned as an activity. It builds up a typology of activities which, in essence, qualify as manual scavenging but are currently considered peripheral to the issue, lying outside the explicit focus of the 2013 Act.

- Mapping Study on non-government ecosystem of sanitation was designed to identify key actors/players (non-government/private) who are playing significant role in the sanitation in the State especially on O&M (focusing on non-networked; and develop a directory of those agencies with details (name, contact address, key strengths, key roles they play in sanitation sector so that the State of Odisha can largely benefit from their services in improving the sanitation situation in the State. The data collection process in Odisha is currently under way.

- Community Institutions Study: Community based structures in the slums in the two towns are formed under Project Nirmal to involve poor communities in sanitation systems and practices. Slum sanitation

committees at the slum level and ward sanitation committees at ward level are the primary structures at the ULB level. The purpose of the study is to focus on community mobilization by slum committees and ward committees, study them as participatory structures and processes to understand the effectiveness of community based participatory mechanisms and their impact both on the communities as well as on governance. The study was completed in Angul by March 2018; the draft report is being prepared. The second round of fled visit in Dhenkanal will commence in May 2018.

- The City Sanitation Plan of Balasore is a comprehensive document encompassing the pressing issues of water and sanitation in Balasore and list of feasible solutions for the same. Drafted at the behest of the HUDD, GoO, the revised CSP adheres to the guidelines of the NUSP and is a progressive document which strives to guide relevant stakeholders to adapt to multiple ongoing and prospective policies and programmes. To this end this document investigates the city's entire sanitation value chain and associated services beginning from city water supply and access to household and public toilets to liquid and solid waste management and suggests enabling strategies. The meticulous comparison of primary and secondary data, study of local institutions and inclusion of GIS maps of different water and sanitation services make the CSP a resourceful document for policymakers, planners, local representatives and researchers. The city sanitation plan was presented to Balasore Municipality in December 2017 and the annual rolling plan was approved in the meeting.

- Development of Capacity Building Modules on Non Sewered Sanitation: Final capacity building modules on non sewered sanitation were printed with a foreword and preface from Secretary, HUDD and Member Secretary OWSSB. Several rounds of discussions and meeting with Housing and Urban Development Department (HUDD), Odisha Water Supply and Sewerage Board (OWSSB), Technical Support Unit (TSU), Swachh Bharat Mission project management unit (SBM PMU) and Practical Action (PA) have taken place July to November to finalise the modules, its flow and contents.

- Guidance note for Reuse and Recycle of products from faecal sludge treatment plant. The proliferation of toilets under the flagship Swachh Bharat Mission has proceeded at a breakneck pace and has necessitated the safe collection, conveyance, and treatment of faecal waste. In accordance with the national imperative, the state of Odisha has already commissioned 9 FSTPs in the AMRUT cities, an FSTP each in Angul and Dhenkanal, with plans to scale-up further. The treatment of blackwater produces secondary or tertiary treated liquid effluent and stabilised, dewatered, and dried sludge. While water, in and of itself, is an increasingly prized commodity, both streams are nutrient-rich as well and can compete with commercial fertilization for bettering soil health. The reuse of the FSTP end products can, therefore, promote environmental sustainability by conserving precious resources and reclamation of poor soils. The guidance note argues that treated effluent and biosolids can be safely used in agriculture by controlling possible risks to human health and environment, however, clearly delineated guidelines and a regulatory framework have not been enforced, despite espousal of internationally adopted best practices, viz., US EPA Biosolids Rule and WHO Guidelines. The lacuna in policy acts as an obstacle to successful reuse, and necessitates state-level intervention. This guidance note, reviewing various international biosolids/treated faecal sludge reuse policies, is intended as an aid for policymakers at the state level in developing a reuse policy which is easy to interpret and implement, promotes scientific and safe reuse of treated water and faecal sludge in agriculture, and also ensures the protection of the health of the farmers, the local communities, the consumers, and the soil.

2. Additionally, policy briefs on topical subjects such as those listed below were prepared:

- The budget brief titled "Swachh Bharat Mission-Urban (SBM-U) was published in 2017. Budget brief of SBM-U tracked expenditure and outcomes of the government's flagship sanitation programme in urban areas along the following parameters: (i) allocations and releases, (ii) physical progress of toilets built and Solid Waste Management (SWM), (iii) funds released for Information, Education and Communication (IEC) activities, and (iv) progress towards ending Open Defecation. In FY 2018-19, central government allocations for SBM-U stand at 2,500 crore (Budget Estimates), an increase of 9 per cent from FY 2017-18. Release of funds by the central government to states has been improving. In FY 2014-15, the central government released only 41 percent of its allocation to states, which increased to 94 percent in FY 2016-17. In FY 2017-18, till 10 January 2018, 61 percent of central government allocations had been released to states.There are however variations in releases of funds to states.As on 10 January 2018, Rajasthan and Madhya Pradesh had already received 84 and 80 per cent of their total mission allocations, respectively. Karnataka, Punjab, and Assam, on the other hand, had received less than 20 per cent. Forty-four percent of total releases for FY 2017-18 till 10 January 2018 were for construction. As of November 2017, 42.72 lakh Individual Household Latrines (IHHL) had been constructed across India, accounting for 64 per cent of the revised IHHL mission target. Till December 2017, 1,846 (42 per cent) cities across India had been declared Open Defecation Free (ODF) and 30 percent had been both declared and verified as ODF.

- The budget brief titled "Swachh Bharat Mission Gramin (SMB-G)", a budget brief on the Swachh Bharat Mission's rural scheme tracking data along the following parameters: (i) allocation and expenditures; (ii) physical progress of toilets built; (iii) expenditures incurred under the information, education and communication (IEC) activities; and (iv) coverage and open defecation. In Financial Year (FY) 2018-19, `15,343 crore was allocated for SBM-G, a 9 per cent decrease from the Revised Estimates (REs) of the previous year, but expenditure as a proportion of funds available has been increasing. In FY 2015- 16, 97 per cent of funds available were spent. This increased significantly in FY 2016-17, with more funds spent than available. In FY 2017-18, till 15 January 2018, 80 per cent of funds available had been spent, of which 96 percent has been for construction of Individual Household Latrines (IHHLs). By this time, 76 percent of all households had access to IHHLs, but Odisha and Bihar had the lowest coverage at 45 percent and 38 percent, respectively. Ten states and Union Territories, and 3, 09,709 villages have been declared ODF, and 64 percent of villages declared ODF have been verified.

- The policy brief titled "Beyond 2019: Why Indian Sanitation Policy Needs To Look Past Toilets" makes the case for an integrated approach to sanitation in India, i.e. targeting all aspects of the sanitation value chain and questions whether a focus on open defecation will achieve the goals laid out in the NUSP. It identifies the gradual policy shifts, both national and internationally, that have led to waste management entering the sanitation-public health debate. By summarizing the various CPCB, CPHEEO and CSE reports on wastewater management in India, it outlines the dimensions of the crisis facing policymakers and explains the health impacts of an open-discharge environment. Finally, it analyzes the factors that policy makers and practitioners might consider when planning for an open-discharge free future. These factors are grouped under wastewater treatment demand (what will drive the amount of wastewater generated? Are there patterns which planners can exploit?), wastewater treatment supply (how are STPs built in India? What are the different technologies available? Are these installations funded through private or public funds? Can we examine different treatment models?) and wastewater governance, which looks at the few models of septage management in India and the need to improve.

- The budget brief titled “Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS)” discusses SRMS as a Central Sector Scheme of the Ministry of Social Justice and Empowerment (MSJE) which was introduced in January 2007, to rehabilitate the identified manual scavengers in alternative professions by the end of FY 2008-09, and was subsequently revised in November 2013. It was found however that allocations have been declining under the scheme until 2017-18. In FY 2013-14, the central government had allocated `70 crore to the scheme, which was decreased to `47 crore in FY 2014-15 and further to only `5 crore in FY 2015-16. In FY 2018-19, the central government allocated `20 crore to SRMS. Further, it was found that there was no expenditure under the scheme FY 2014- 15 and FY 2016-17. Coverage under the scheme is based on identification and verification of manual scavengers, but this has proved to be a challenge. Till Dec 2017, states had identified only 8 percent (13,465) of the manual scavengers previously enumerated in the Socio Economic Caste Census in 2011. While the scheme has provided cash assistance to 94 percent of identified beneficiaries, it sanctioned only 1,233 self-employment schemes and could provide complete compensation in case of death to only 63 percent of cases in which claims for compensation have been made.

- The Policy Brief titled “Lessons for India from Vietnams Urban Sanitation Experience” analyses WHO-UNICEF Joint Monitoring Program (JMP) data for 2015 which shows that Vietnam has made significant strides in water and sanitation provision over the last two decades. India’s progress during same period has been quite muted inspite of Vietnam and India sharing a very similar trajectory in terms of urbanization and economic growth. In urban areas 13.9% of the population in India practice open defecation, while the number is less than 2% for Vietnam. This policy note explores how despite being at comparable levels on urbanization and economic growth how the policy approaches of the two countries are different and what India can learn from the approach adopted by Vietnam, questioning whether that may be possible under such a varied governance arrangement.

- The Policy Brief titled “Manual Cleaning Of Sewers And Septic Tanks” focuses on the legal environment for manual cleaning of sewers and septic tanks, a practice that has led to many deaths, most recently in Delhi, the national capital. In December 2013, the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act (“the Act”) was notified by the Central Government. The Act is a Parliamentary law, binding on all states. While an earlier 1993 law prohibited the employment of manual scavengers and construction of dry latrines, the strength of the new Act is that it brings cleaning of drains, sewers, latrine pits and septic tanks under its ambit. The Act also introduces a new concept of “hazardous cleaning”, which is applied to cleaning of sewers and septic tanks, specifying that these activities may be carried out only under certain conditions and using specified safety equipment. The policy brief examined the various provisions of the Act and Rules, with the objective of providing a better understanding of the concept of manual scavenging and hazardous cleaning, as defined in this law, and to address the following questions: (i) What are the circumstances in which manual cleaning of sewers and septic tanks is permissible? (ii) How is manual cleaning of sewers and septic tanks to be carried out safely? (iii) What are the penal consequences of hazardous cleaning of sewers and septic tanks? (iv) Who is responsible for enforcement of the Act? The policy brief is intended as a reference document for professionals, scholars and activists who seek to understand the law for the prohibition of manual scavenging.

- The Policy Brief titled "Swachh Bharat Mission (Urban): Need Vs. Planning" analyses the effectiveness of the Swachh Bharat Mission (Urban) in claiming to improve the sanitation situation in India by analyzing the financial and physical progress of the mission to uncover whether the need for toilets in the most deserving states (that are states that have a higher proportion of households without toilets and households defecating in the open) matched the allocation and sanction of central funds as well as the projection and sanction of household toilets to be constructed. There is considerable disparity in the allocation and sanction of central funds to the need for toilets in each state as well as in the projection and sanction of household toilets to be constructed to the need for toilets in each state. Chattisgarh, Odisha and Bihar, that have the highest proportion of households without toilets, have been allocated and sanctioned only 10% of the total central funds. Even though Chhattisgarh has the highest proportion of households without toilets i.e. 40%, and projection for IHHL construction was 73% of the total households without toilets, but the applications approved are only 23% of the total households without toilet. Orissa and Bihar have 33% and 31% of households without toilet, and the projection of IHHL construction was more than 90% of the households without toilet, but the applications approved are 35% of the households without toilet. The analysis also reveals considerable data inconsistencies, and questions the overemphasis on toilet construction that devalues the significance of solid waste management in reducing insanitary spaces, which will influence behavioural change necessary to ensure toilet usage.

- The Policy Brief titled "School Sanitation in Odisha" was prepared to understand the access to sanitation among the school going children specially the girl children. Sanitation access in schools is important to keep children, especially girl children in school. It is also important to spread the culture of safe sanitation more widely, especially among the young. Using a unique mapping of DISE data on schools and PCA data on village amenities, this note looks at the variation in school sanitation across different CD blocks of Odisha by location and gender and the relationship between access to sanitation in schools and the access to sanitation within households of the block. It finds considerable variation, especially across rural and urban areas for school sanitation, which need greater focus, going forward. However, access to school sanitation is consistently better than sanitation in the block as a whole in the state of Odisha.

- The Policy Brief titled "Social Identity and Occupational Discrimination of Sanitation Workers: A Literature Review from the Global and Indian Perspective" discusses Social identity to be strongly linked to the sanitation occupation. Anecdotal evidence suggests that certain social groups are associated with this occupation. Not only in India where caste plays a prominent role, but in other countries also, the occupation draws strong evidence of marginalized communities associated with the sanitation work. The paper is a summary of international and Indian literature pertaining to sanitation work that discuss social identity, working conditions and social discrimination of sanitation workers from both a historical and contemporary perspective. It takes into account occupations such as garbage collection, sweeping, sewer cleaning and septic tank emptying, which have otherwise have not received as much attention as manual scavenging in grey and published literature.

3. Opinion pieces on topical subjects such as those listed below were prepared:

- The Opinion Piece titled "Can Mechanization De-Stigmatize Sanitation Work?" based on recently completed work on septic tank emptiers in Delhi traces the changing nature of septic tank emptying work, from a completely manual process that involved immersion of the worker in faecal sludge to a partly mechanized one, albeit one that involves low-cost locally assembled equipment. However, the workforce involved is almost entirely Dalit, and workers report facing discrimination and practices of untouchability in their interactions with their customers and within their social networks. Policy-makers however remain focused on service delivery, and tend to pay less attention to persistent issues of caste based discrimination. Policy brief to be published.

- The Opinion Piece titled "For Swachh India, Focus on Solid Waste Management" was published in the Hindustan Times on Oct 4, 2017. The article focuses on management of solid waste. Effective solid waste management will lead to a reduction in insanitary spaces. This in turn will create a behavioral change essential to ensure toilet usage.

- The Opinion Piece titled "Why Government is Reminded of Sanitation Workers Only after they die?" was published in DailyO on September 18, 2017. The article raises questions on the death of the sewer workers in Delhi and why government is reminded of sanitation workers only after they die. Analyzing the recent death by the caste perspective the article argues that the state must inspire a social change by denouncing casteist organisation of sanitation work rife in its own institutions first.

- The Opinion Piece titled "Sewer Workers Deaths: Instead of Blaming Contractors, Probe Role of DJB Officials" was published in the Hindustan Times on August 11, 2017 the op-ed highlights the norm-less public engineering as a reason for the death of sewage workers. The article also talks about safety equipment and better training which could have lessened the risk, but the nature of job is such that one has to hold their breath and swim in sewage water, what sort of training and "safety equipment" could prepare one for it? Regardless of who commissioned the sewage workers, the responsibility must lie with the public authority to ensure that its infrastructure is safely built and managed.

4. We undertook meetings and presentations to various Government bodies/Advocacy Group as listed below:

4.1 Meetings and Presentations to National Level Government Officials/Ministries and other Government Bodies

- Engagement with Ministry Of Drinking Water and Sanitation, Government of India on FSM in Rural Areas (Dec 18, 2017, Jan 22 & 8 Feb 2018). The Joint Secretary, MoDWS called a meeting of members of the NFSSM Alliance to discuss the need for faecal sludge and septage management (FSSM) in rural areas on December 18, 2017. The Ministry sought to create a framework for discussion with states on this subject in the following month, for which it was seeking inputs from members present. CPR briefed the Ministry about ongoing research in the SCI FI programme on septic tank emptying services and on the characterization and analysis of sanitation preferences in large dense villages. Other NFSSM alliance members provided inputs on various aspects of technology choice and service providers. This was followed up by meetings on January 22, 2018 when Alliance members invited provided inputs to the Ministry's plan for the proposed discussion with states. This was followed up by preparation of a technical note on legal and policy issues which were submitted to the Ministry for inclusion in its plan. CPR participation in the Roundtable on FSSM and made a

presentation on legal and policy issues at the National Consultation of Solid and Liquid Resource Management convened by MoDWS on 8-9 Feb, 2018.

- Meeting of the Working Group for the National Sample Survey 76th Round Constituted by the National Statistical Commission (Nov 3, 2017 & Dec 8, 2017). The National Statistical Commission (NSC) held its 94th meeting held on May 29, 2017, in which it was decided that the subject coverage of 76th round of the National Sample Survey would be on Disability, Drinking Water, Sanitation, Hygiene and Housing Condition. The NSC constituted a Working Group to assist with sampling design, methodology etc, which is chaired by Dr Partha Mukhopadhyay from CPR. The working group has held two meetings so far: New Delhi (Nov 3, 2017) and Kolkata (Dec 8, 2017)

4.2 Meetings and Presentations to State Government Bodies

- Meeting with CEO, Zilla Parishad, Udaipur (Oct 18, 2017). CPR has conducted a survey in the Udaipur district and this meeting was the second meeting with the CEO, Zilla Parishad to discuss the status of SBM in Udaipur district. The meeting focused on survey findings and means to improve implementation of the programme in the district.

- Meeting with Principal Secretary, Housing & Urban Development Department, Govt of Odisha (Sept 20, 2017). Meeting with the Principal Secretary, Housing & Urban Development Department, Govt of Odisha and the Project Director, Odisha Water Supply and Sewerage Board to discuss need for legal regulation of FSM in the state and possible ways forward which could include a government order or municipal regulations.

- Meeting with Karnal Municipal Commissioner (Sept 15, 2017). The meeting with Karnal Municipal Commissioner was part of the series of discussion held with different government officials to understand the implementation of SBM at the district level, in particular the urban areas. The meeting focused on understanding of IEC approach and ODF status of the district in achieving Sawchh Bharat Mission.

- Meeting with Karnal DM (Aug 23, 2017). The meeting with the Karnal DM was held to discuss the approaches of the Swachh Bharat Mission in the rural part of the Karnal district. Understanding of IEC in the implementation of the mission and status of open defecation free (ODF) in the district was also discussed.

- Meeting with Principal Secretary, Housing & Urban Development Department, Govt Of Odisha, Miscellaneous Officials & Executive Officer Of Balasore Municipality (Aug 19-22, 2017). Meeting to discuss need for strengthening urban local bodies in the state, capacity issues faced at the city level and strategies to address the same. The capacity building modules prepared by CPR, and plans for roll out of the same was also discussed.

- Meeting with Rajinder Pal Gautam, Minister for Water, Govt Of Delhi (Aug 19, 2017). Following up on a CPR op-ed on the persistence of manual scavenging and manual scavenging related deaths in the national capital, CPR was called to discuss the issue with Shri Rajinder Pal Gautam, Minister for Water, Govt of Delhi. Officials and advisors from the department were also present during the meeting. Discussion was held around the issue of manual scavenging and death of sewer workers in Delhi. Various issues pertaining to manual scavenging and de-sludging by sewer workers in sewered and

non-sewered areas was discussed during the meet. Need for licensing and regulating de-sludging vehicles in order to improve access to formal de-sludging services was put forward as a recommendation for improvement of working condition of the sewer workers. SCI_FI team also discussed international approaches to the issue and case studies from Dakar and Malaysia which could be a lesson for Delhi.

- Technical Note for Government of Orissa: Roles and Responsibilities of Stakeholders under the OUSP and OUSS (Sept 25, 2017). On the request of the State Government to disseminate OUSS and OUSP to cities and other stakeholders, a technical note was prepared clearly defining roles and responsibilities of State government, district authorities and ULBs. The note highlighted key responsibilities of each stakeholder involved in FSM and sanitation under key 6 outcomes enshrined under OUSS and OUSP.

- Presentation of Odisha Partnership: Partnership with the government is important to achieve impact at scale, but working with the government is often challenging. But, there have been successful collaborations between civil societies and government institutions across different ministries. This was the background of Dasra Collaborative Action Forum on February 20th where CPR presented key areas of successful partnership with Odisha government in embedding FSM in government policy and programmes as a panelist in the session on "Fruitful Partnerships: Working with the Government."

- Presented the Case of Odisha on Scaling up FSM through partnership in the 3rd National Summit on Sustainable Water and Sanitation held on 19th Jan, 2018 at Bengaluru organized by CDD Society. The presentation highlighted the journey of FSM and deepening of FSM interventions in the State of Odisha through successful partnership of various stakeholders like CPR, PA, CDD, Arghyam, BMGF, TSU, ity Governments and State Government

4.3 Meetings with Advocacy Groups

4.3.1 Community of Researchers and Practitioners (CORP) Seminar Series of the SCI-FI: Sanitation Project seeks to strengthen the understanding of challenges and opportunities in urban sanitation by promoting evidence-based knowledge in the sector. This year, the following four seminars were organized:

- Understanding Informal Models of Septic Tank Emptying Services: Case Studies from four cities in India (April 6, 2018). Three presentations based on CPR research on the issues and challenges of small-scale informal enterprises that currently provide septic tank emptying services in Indian cities. CPR research sought to deepen our understanding of these enterprises through case studies in Dehradun, Jaipur and Bhubaneswar, and in two locations in Delhi. This seminar presentation of this research was followed up by a broader discussion with multiple stakeholders on the potential for private sector participation in the sanitation value chain. Presentations included (1) Collective action (or not): The informal septic tank emptying markets in Delhi; (2) FSM operation case studies from 3 cities: Findings and Insights; (3) Understanding Small-Scale Desludging Operations: Synthesis and Way Forward

- Last 100 Metres: Safeguarding Potable Water Provisioning to Urban Informal Settlements on Oct 27, 2017. Dr. Manoj Roy from Lancaster University, UK. Introduced emerging findings of an on-going collaborative research on "Last 100 metres: Safeguarding potable water provisioning to

urban informal settlements between Lancaster University and the Centre for Science and Environment. Urban, national and increasingly global architectures for sustainable development are falling short - just metres before the 'finish line', with severe consequences for public health. Dr Roy presented findings from the on-going research in poor settlements in Dhaka which identified the risk of contamination of potable water from the lack of FSM and network disposal systems in these settlements.

- The Cleaning Brigade: Connects And Disconnects (Sept 20, 2017). Dr Sanghamitra Acharya, Director, Indian Institute of Dalit Studies, New Delhi, spoke of her recent work on characterizing sanitation work and how the intrinsically discriminatory nature of this work impacts the lives of those engaged in it, based on research and fieldwork carried out in Delhi and Ahmedabad. Her work explored the determinants of engaging in scavenging and cleaning; notion of dignity associated with it; and the factors which govern their continuance in these works and what is the alternative available. She also highlighted her findings on social discrimination experienced by Dalits engaged in scavenging and cleaning in accessing resources to enhance literacy, skills, health, basic housing and related infrastructure.
- An Economic Characterisation of Sanitation: Between the State's Production and the Household's Demand (May 19, 2017). CPR invited Chloé Leclère, PhD Scholar in Economics at the Ecole Normale Superieure de Lyon in France to present her work on sanitation as an 'economic good' in the context of on sanitation policies in India. This talk explored questions pertaining to the need of sanitation, what it produces and the process that relates a biologic imperative and the environment circumscribe a multi-dimensional scape.

4.3.2 National Conference on Sustainable Sanitation: Evidence and Practice, New Delhi on Dec 12, 2017 to engage with policy makers, practitioners and researchers working in the sanitation sector. The backdrop to this conference was the Swachh Bharat Mission and the emerging policy focus on sustainable sanitation exemplified by the recently released National Policy on Faecal Sludge and Septage Management. The objective of the conference was to synthesize the diverse experiences and observations of the participants to create an understanding of challenges in the current policy, implementation and monitoring framework and to share lessons geared towards community-centric approaches to sustainable sanitation. Wateraid India, RICE Institute (Research Institute for Compassionate Economics) and CPR presented their recent research on the implementation of SBM G, which was followed by a panel discussion on the themes and issues raised by the researchers. This was followed by an 'urban' session in which diverse perspectives on urban sanitation were presented: Institute of Development Studies, Jaipur its review of the community participation work of CFAR; CPR presented findings and insights on sanitation from ethnographic work carried out with poor communities in Odisha small towns; PRIA presented its recent work on SBM urban implementation in Uttar Pradesh; and finally all these disparate themes were brought together in a CPR presentation on urban sanitation.

4.3.3 Workshop on Community Approaches to Sanitation: Experiences from Implementation, New Delhi on Dec 11, 2017, a day-long capacity-building and experience-sharing workshop with officials and local representatives from state governments and local authorities in Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Odisha on learnings from their experience of implementing SBM in

urban and rural areas. The workshop focused especially on the challenges of sustainability of the current approach, and its impact on marginalized and vulnerable communities. Participants provided a deep and well grounded understanding of how the programme is implemented, and the particular challenges of achieving sustainable sanitation in the context of aggressive implementation timelines. Participants spoke of the need for solid and liquid waste management in both rural and urban areas, and the lack of policy for the same especially in rural areas. Participants from urban areas were more aware of manual scavenging practices, but said that this had not been a focus of their current implementing efforts. The programme provided an opportunity for reflection and self-learning for all the participants.

4.3.4 Meeting with Special Rapporteur on the Human Right to Water and Sanitation (Oct 28 & 29, 2017). CPR was invited to attend a special meeting on manual scavenging with the UN Special Rapporteur on the Human Right to Water and Sanitation as a part of his India country visit and engagement with civil society organisations on Oct 28, 2017. The meeting was led by SKA, who presented data and perspectives on manual scavenging to the UN Special Rapporteur. CPR discussed the issue of manual scavenging and unsafe sanitation work in relation to non-network sanitation, and how this could be addressed through FSM interventions. CPR was also invited to attend a meeting of the UN Special Rapporteur with civil society organisations on caste and gender based discrimination in sanitation on Oct 29, 2017. The other participating organizations were Wateraid, CFAR, CURE, VSO, Vada Na Todo, and National Commission for Dalit Human Rights and Jagori.

5. Other Advocacy Meetings:

Details of some of the other meetings with non-government organisations, media and professional networks include:

- Meeting with V K Madhavan, Chief Executive, WaterAid on Nov24, 2017 in New Delhi was held to share findings from Udaipur Survey. Discussion was also around issues that have emerged in common across research pieces and ways to position them.
- Panel discussion on “Toilets are critical for women” with WaterAid as participants was held on Nov 24, 2017 in New Delhi It was lived shared on different platforms of social media. #Toilets4All hashtag on twitter Facebook live at WaterAid office.
- NDTV Panel Discussion held on Nov24, 2017 in New Delhi, focused on the current status and challenges of sanitation. The panel also discussed findings from CPR’s recently conducted survey in Udaipur district.
- The workshop brought together diverse stakeholders such as Dalberg, BMGF, Urban Management Centre (UMC), and other BMGF partners to collectively ideate, evaluate, and prioritize solutions for improving the safety of, and create robust livelihood pathways for sanitation workers. It was held on Nov 20, 2017 in New Delhi.
- CPR participated in the panel discussion held on Nov 17, 2017 in New Delhi on “Role of evidence in determining sanitation policy”. It focused on role of evidence in making of sanitation policies.

- Meeting was held Oct 12, 2017 in New Delhi, to understand the training approach in Rajasthan with UNICEF, Rajasthan WASH & C4D team as participants. UNICEF's involvement and understanding of training and capacity building systems in Rajasthan.

- Meeting with representatives from WaterAid, CSE, CURE to inform and engage each other on sanitation related issues with Delhi-focused interests. Discussion on activities and plans relating to sanitation and FSM, and to enable closer coordination between organisations. It was held on 22 Sept 2017, New Delhi.

- The team publically engaged with participants from National Campaign for Dignity and Rights for Sewerage and Allied Workers to discuss the frequent death of the sewer workers while cleaning the sewer in August 17, 2017 in New Delhi. SCI-FI team participated in the meeting to discuss the working conditions and way forward in improving the conditions of the workers.

- A Round table conference was organized with Observer Research Foundation as participant on July 7, 2017 in New Delhi on SBM G implementation where various views on the successes and gaps in SBM G were discussed

- Meeting with Mrs. Meike van Ginneken– South Asia Practice Manager South Asia, Water Global Practice, World Bank was organized to discuss progress, issues and challenges in the implementation of SBM G on June 30, 2017 in New Delhi

- CPR participated as a jury member to administer the community score card on sanitation in Adarsh Bastis on May 4, 2017 in New Delhi

6. Collaboration with Safai Karamchari Andolan (SKA)

SKA had filed a public interest litigation (Safai Karamchari Andolan v. Union of India, WRIT PETITION (CIVIL) NO. 583 OF 2003, decided in 2014) to seek directions from the Supreme Court for the complete prohibition and elimination of manual scavenging. SKA sought CPR support in organizing the case documentation, which involved several hundred documents filed by various parties in the decade-long period in which the case remained in court. The documents include statements from various state governments, local authorities, and other national and state government bodies including status reports and commitments to undertake future action, which could be followed up by activists and others working in the field. Following these discussions, CPR created an annotated database of these documents for use by SKA and for public dissemination.

In addition, over the course of several meetings held in the year, CPR and SKA developed a plan for research collaboration on topics of mutual interest. The principal objective of this collaboration is to develop SKA capacity to engage in sanitation and FSM policy dialogue, and to sharpen our shared understanding of the challenge of eliminating manual scavenging. Details of the meetings are:

- Meeting was held on Nov 24, 2017 in New Delhi to discuss shared research interests relating to sanitation work and arrangements for close coordination between the two institution

- Coordination meeting regarding work on writ petition database on Sept 12, 2017 in Delhi

- Discussed shared policy goals and research interests for mutual collaboration in a meeting held on Aug 7, 2017 in Delhi

- Pilot of writ petition database initiated on Aug 2, 2017 in Delhi
- Shared decision for CPR to support SKA in developing a database of writ petition related documents on July 31, 2017 in Delhi

7. Study Visit Programmes

The following four field visits were organized from April 2017 to March 2018:

- Study Visit to Warangal, Narsapur And Vishakapatnam in Andhra Pradesh: Faecal Sludge Treatment Technologies And Service Delivery Models (Mar 21-25, 2018). FSTPs developed in the cities of Warangal and Narsapur use pyrolysis/ heat based technology to treat faecal sludge. This technology provides an alternative to more conventional anaerobic digestion based treatment. To better the understanding of how this novel, heat-based FSTPs function, a team of researchers from SCI-FI undertook a study visit to Warangal, Telangana and Narsapur, Andhra Pradesh where these recently installed FSTPs have had a few months of operation. In addition to learning about the plant processes, the team also delved into the service delivery model for desludging of on-site sanitation systems in the two cities. Furthermore, the researchers also visited the city of Vishakhapatnam in Andhra Pradesh, third ranker in the Swachh Survekshan 2017; understand co-treatment process, which the city relies on for the treatment of its faecal waste. The findings from the study visit, therefore, will augment existing knowledge on the subject, and will be used for enabling informed dialogue around FSM technologies and service provider models at the state and ULB level.
- Social Sciences Winter School in Pondicherry, Puducherry (Dec 4-8, 2017). CPR collaborated with Pondicherry University and the French Institute of Pondicherry to support the Social Sciences Winter School in Pondicherry, in which urban sanitation was an area of focus. The objective of the winter school was to orient and advise doctoral students who have focussed their research on urban sanitation. CPR research presented at this winter school included a plenary talk on 'Urban Sanitation from a River Pollution Perspective' in which the case of Delhi/ Yamuna pollution was presented. CPR also presented research on community approaches to sanitation, manual scavenging and provided a lecture on understanding sanitation engineering for social science researchers. Other research presented at the workshop included lectures on theory and practice of non-network sanitation ('beyond networks') and use of mapping and big data for research on urban sanitation.
- Study Visit to Hanoi, Vietnam: Heterogeneous Sanitation Typologies In A Centralized Planning Environment (Nov 20-23, 2017). Much like India, Vietnam's socio-economic policy is contained within a highly centralized planning framework, guided by five-year Socio Economic Development Plans developed by the Ministry of Planning and Investment in conjunction with other ministries and implemented by the Ministry of Construction. Sanitation and waste related legislation is typically issued at the central level, aiming to create uniform infrastructure solutions across diverse urban environments. At the city-level, and especially in the case of Hanoi as the capital city, these centralized planning structures and infrastructures are replicated by agencies like Hanoi Urban Environmental Company. However, these centralized approaches seem to ignore the multiplicity of sanitation typologies exhibited in Hanoi, each linked to distinct forms of housing evolution in the city. These housing typologies range from the fully planned and sewer-networked areas of new urban areas to the public toilets and open defecation modalities found in rental and informal housing near the Long Bien Bridge. On this study visit, CPR researchers explored this 'two-track' reality, tracing out, on the one

hand, overarching policy and legislative framework governing sanitation and waste management activities, and visiting eight different sites grouped into five distinct sanitation typologies.

- Exposure Visit of Secretary to Devnahal Li, Karnataka: In coordination with Devanahalli's Town Municipal Corporation (TMC), CDD Society has built a faecal sludge treatment plant (FSTP) during 2015. This plant is first of its kind in India which provides a holistic and integrated faecal sludge treatment facility for the entire town. CDD is also supporting Project Nirmal towns in Odisha to construct FSTP. In order to have a complete understanding of the operation and maintenance of FSTP and the factors influencing the operational cost of FSTP, Centre for Policy Research with the support of CDD Society and Arghyam organised an exposure visit for Secretary, HUDD, Govt of Odisha to the Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP) located at Devanhalli on 28 Sep 2017. Other than O&M, the discussions were held on possibility of co composting, revenue models and removal of manual scavenging practices in FSM.

8. Policy Briefs, White Papers and other Documents Developed and shared at International and Regional Conferences

- Paper on 'Septic Tank Emptying Businesses in Delhi' presented at an International Workshop: Shared Perspectives Upon Emergent Forms of Urban Densification in Asia: Issues of Access to Resources (Services, Housing, Employment and Land), Vietnam (Nov 13-16, 2017). Conference organized through multi-institute collaboration at Hanoi University, Vietnam. CPR presented a paper on septic tank emptying businesses in Delhi, demonstrating how co-production, such as through informal self-organised businesses and self-provisioning, might serve as a response mechanism for communities that are underserved by traditional, networked models of sanitation infrastructure. The comparison between India and Vietnam is particularly relevant from the FSM perspective, since both countries are developing a national policy and legislative framework for FSM and individual cities, like Hanoi, have released master plans envisioning a decentralized system of FSTPs (Faecal Sludge Treatment Plants).

- Paper on 'Debating the Relationships between density and governance and basic services: Comparative views from two case studies in India and Indonesia' Presented at an International Workshop: Shared Perspectives upon emergent forms of urban densification in Asia: Issues of access to resources (Services, Housing, Employment And Land), Vietnam (Nov 13-16, 2017). Conference organized through multi-institute collaboration at Hanoi University, Vietnam. The paper aims at exploring the relationship between the level of density and modes of provisioning of urban services through two case studies. The first case study looks at the case of water in an urban core of a secondary Indonesian city, i.e. Surakarta while the second one focuses on the provision of sanitation beyond the network in an urban village in Delhi. The two case studies draw parallels around issues of affordability, health impacts and social justice linked to empowering and educating community through the formation of community based organization. The two cases present comparative points of views related to the presence of on-site solutions in the shortage and the slow progress of networked solutions. The research sought to explore reasons for these comparative points of views that could be related to the nature of the service itself (water being different from sanitation), the socio-economic structure of the settlement and the regulatory capacity of the Indonesian and Indian states.

- Research on Small-Scale Governance of diseases in Delhi presented at International Workshop titled 'Urb-Endemic: How to improve diseases control in the urban area of Delhi', Paris (Jun 28-30, 2017). CPR participated in network event of University of Chicago, CNRS, Paris and Pasteur Institute, Paris

to share research findings and develop collaborative work on urban governance and sanitation in the context of urban disease control and management. Results from fieldwork on small scale governance of diseases in Delhi carried out by CPR researchers were presented along with research from the North Delhi Municipal Corporation and the Indian Council for Medical Research was presented at the workshop. The research collaboration of CPR with these institutions and ongoing research was discussed and reviewed, and plans for data sharing and management were agreed upon. CPR supported the supported participation of MCD researchers in this event. CPR support for this activity has since been discontinued following discussions with BMGF in Aug-Sept 2017.

- Participated in the "Population Association of America Annual Meeting" at Chicago, Illinois in April 2017 and presented the paper titled "Horizontal and Vertical Inequalities Explaining Disparities in Access to Urban Sanitation". A household's ability to procure basic amenities is also subject to its economic and social condition and the prevalence of social or spatial inequalities in addition to the growing disparities in the provision of public infrastructure services in urban areas of India. The paper focuses on Horizontal or social group-based inequalities, which are often neglected in the sanitation discourse in India, are found to have a significant impact on access to toilets along with the existence of disparities based on consumption expenditure and drainage. This paper considers a basic household amenity – toilets – and uses survey data to gauge a household's likelihood of owning one based on economic and social conditions, and on infrastructural parameters such as water supply and drainage, using a binary multivariate logistic regression model. The findings ascertain the existence of multidimensional disparities at the state level, which may require more focused interventions at the local and state level.

9. Think Tanks in different regions to be identified for sanitation related research

Partnerships with Vidya Bhawan Society, Udaipur and Kalinga School of Rural Management, KIIT University, Bhubaneswar have been initiated through one-year contract agreements.

10. Public Private Partnership

The National policy on FSM establishes an unprecedented environment that promotes FSSM and public private partnerships (PPP) for citywide innovative sanitation. However, there are very few successful cases of PPP in water and sanitation including the FSSM sector in India. Within this context, the intervention by CPR intends to pioneer a robust and replicable partnership model between governmental, commercial and academic actors to bolster market oriented public good developmental interventions; ultimately accelerating progress towards safe and sustainable water and sanitation through FSSM.

11. Knowledge Management and Dissemination

Since two years, BMGF has been extending the technical Support to Odisha Government by establishing a Technical Support Unit (TSU) in the state. To facilitate cross learning from nine AMRUT cities and from two Project Nirmal cities - Angul and Dhenkanal; to consolidate learning and ensure better coordination, subgroups between TSU members, CPR and PA was constituted to support the GoO on :

- Capacity building- The capacity building initiative for developing trainer's modules and conduct of training programme for Master Trainers at the State level was undertaken by CPR, while the triggering workshops at the district level were undertaken by TSU with the support of CPR and PA on development of presentations and for the conduct of workshops in Angul and Dhenkanal.

- Faecal Sludge and Septage Management Regulations, 2018: FSSM city regulations were drafted by TSU and CPR together focusing on is already drafted by the core group members constituted of CPR, PA and TSU with the following objectives:

  - To provide a regulatory framework for construction, routine maintenance, regular cleaning and emptying of containment unit; transportation, treatment, reuse and safe disposal of septage;
  - To prescribe the actions to be taken by the owners of the premises connected to septic tanks, operators of septage transportation and treatment to ensure compliance with their obligations;
  - To provide for appropriate enforcement mechanisms;
  - To ensure cost recovery on a sustainable basis for proper Faecal sludge and septage management

  In addition to the above, CPR provided support on ODF strategy document that was prepared by the core group consisting of TSU and PA and also on the Survey of manual scavengers in Angul and Dhenkanal.

12. Supporting Material Prepared for International Exposure Visits and City/State Sanitation Workshops

- The concept note titled "Institutional Arrangements of sanitation in small and medium towns: Lessons from Sri Lanka" maps the institutional arrangements of sanitation in Sri Lanka by tracing the evolution of national sanitation policies and roles of stakeholders particularly in faecal sludge management to identify best practices that can be contextualized for India. In the last decade, there has been a push towards septage management in small and medium towns of Sri Lanka. In 2008, the Dry Zone Urban Water and Sanitation Project (DZUW&SP) was initiated to improve water supply and sanitation infrastructure in urban and peri-urban areas by targeting four towns namely- Mannar, Vavuniya, Puttalam and Chilaw in North-western province. Through the case study of the sub projects of DZUW&SP, this paper examines the functional institutional arrangement for FSM in these four small and medium size towns.

- The concept note "Sanitation Sector in Vietnam" attempts to trace the history of sanitation sector in Vietnam. Vietnam is one of the few developing countries that has achieved high levels of access to water and sanitation services for its population. Overall, Vietnam managed to bring basic sanitation to more than a quarter of its population between 2000 and 2015. Septic tanks and pit latrines remain the predominant form of waste capture in Vietnam. Despite the dominance of on-site sanitation solutions in Hanoi, infrastructure financing and investment in FSM solutions has been limited. This is not, however, for a lack of regulatory zeal- Vietnam has an entire network of laws, decrees and regulations that are increasingly recognizing the necessity of managing waste from on-site systems. This concept note highlights Decree and laws which are practiced in Vietnam to regulate drainage, septage and sewerage system in Vietnam.

III. Global Health Strategies – GPPI-CPR Collaboration on Child Survival and Maternal Health

The objective of this collaboration is to highlight the need to elevate the issue of childhood diseases such as diarrhea and pneumonia and discuss how Members of Parliament can play an effective role in ensuring that life-saving medicines, tools and technologies reach children who need them the most; create awareness and utilize platforms to raise the profile of child survival. The engagements with Parliamentarians also aim to address questions that Parliamentarians might have around child survival issues and vaccines; and offer guidance on how they can be advocates for child health in India.

Activities undertaken under this project during April 2017 to March 2018 include –

1. GPPI and Global Health Strategies (GHS) in their collaborative series of roundtables organized a discussion on the "Health Commitments Made in the Union Budget 2018". The Union Budget 2018 proposed a host of measures which is expected to transform the Indian healthcare system. The hallmark of the Budget pertaining to health insurance is the announcement of the National Health Protection Scheme and allocation of ₹1,200 crores to the Ayushman Bharat Programme in order to convert 1.5 lakh primary health centres (PHCs) to health and wellness centres focusing on disease prevention. These recent developments provide an opportunity for India to accelerate its health gains. The pathway for implementation of these targets and programmes, however, remains uncertain.

   This discussion focused on the role of political leaders in ensuring existing targets are met and planning how best to give public health goals like immunization and disease eradication the political stimulus they need. Mr Keshav Desiraju, Former Health Secretary, Government of India, and Dr Pronab Sen Country Director, International Growth Centre (IGC) discussed this issue in detail through their presentations.

2. GPPI and GHS also jointly organised a discussion on "Prioritising Child Health and Nutrition in India" to discuss the role of political leaders in putting major public health issues such as Child Health and Nutrition on the political agenda. Dhruv Pahwa, Director – Market Access at Global Health Strategies who has worked to develop access strategies for health & nutrition related products, services and policies; and Ramanan Laxminarayan, Director & Senior Fellow, Center for Disease Dynamics, Economics & Policy (CDDEP) in Washington, D.C., and senior research scholar and lecturer, Princeton Environmental Institute, discussed the topic in detail on financing healthcare, and how health in India can be improved without vastly increasing spending.

IV. Integration and Editing of Manuscripts Relating to the Planning and Development Efforts in the Calcutta Metropolitan Area

This book is an attempt to place on record how urban planning in India took shape after independence. It is the first exhaustive study of its kind and gives a vivid account of the problems faced by planners on how to deal with urban growth. While officials of newly independent India had not much idea of how to tackle the problem of teeming cities, neither was there much experience abroad. It was a learning process for all concerned. In India large cities were moved with some apprehension because of their problems and public policy in early years after independence sought to restrain growth of large cities. Calcutta was a great experiment not just for India but for urban communities across the world. The WHO, Ford

Foundation and the World Bank shared India's concern, particularly the West Bengal government to save the city. Calcutta was the only city in the developing world to get so much international attention.

The book manuscript was being worked on by Prof. KC Sivaramakrishnan. After his demise, some content additions and revisions have been made and the book is still in the review and editing stages.

V. Boundary Spanning in Delhi's informal settlements

Building on CPR's body of work on state-citizen relationships in Delhi, the project seeks to understand 'boundary-spanning' activities in community-led urban regeneration. Specifically, the project examines the role of 'boundary spanners'—those who provide interfaces between self-organised citizens, local community and government institutions—with reference to different settlements in Delhi. The first phase of this project, supported by the Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) of Erasmus University, Rotterdam looked at comparisons using case studies from the Netherlands, the United Kingdom and India. In this phase, CPR studied urban regeneration and mapped boyndary spanners one unauthorised colony and one resettlement colony in Delhi.

In the second phase, research on this topic is being taken up under an ICSSR-funded project titled 'Boundary Spanning and Intermediation for Urban Regeneration: Comparative Case Studies from 3 Indian Cities'. This project is led by Tata Institute of Social Sciences, Mumbai and CPR and Madras Institute for Development Studies are collaborators. In this phase, CPR is focusing on East Delhi's unauthorised and regularised unauthorised colonies where negotiations are moving beyond State actors to envelop private players especially in the context of housing finance. The other site is a resettlement colony, Bhalswa, where NGOs are using RTI as a tool to negotiate for imprived services.

VI. India's Middle Class

This project seeks to examine the idea of the 'Indian middleclass'. The notion of the Indian middle class has attracted much attention, however there still ambiguity with regard to the definition and size of the community. The project seeks to add to the existing literature along with the changing relationship of the community with the state, their consumption choices and economic behaviour as important vertices of analysis.

This study supported by the Indian Council for Social Science Research (ICSSR), tries to expand the understanding of the emerging middle class by investigating its defining characteristics, socio-political identity and economic behaviour. The papers discuss the conceptual issues while examining the Indian middle class, bring out differences in electoral preferences, and discuss consumption choices, and bring out nuances of 'middle classness' through the lens of domestic work.

No activity this year

VII. Urban Transformation in India

The "Urban Transformations in India" research project, funded by the Indian Council for Social Science Research (ICSSR) has been carried out at the Centre for Policy Research (CPR), New Delhi, from July 2013 to October 2015. Two broad themes have been addressed in the project: 1) 'Mapping Citizenship in Delhi' and 2) 'How does the local state work?.'

As part of this wider project, the Cities of Delhi project has included elements pertaining to both these themes. The project looked at how the residents living in informal settlements of Delhi interact with their elected representatives, state agencies, and other agents in securing public services. It has carefully documented the degree to which access to basic services varies across different types of settlements. The outputs of the Cities of Delhi project are organised as three sets of reports on "places", "institutions" and "processes", which together seek to provide a comprehensive picture of how Delhi is governed, and especially how this impacts the poor. The outputs of the Cities of Delhi project are available on a bilingual website: http://citiesofdelhi.cprindia.org/ (English), http://citiesofdelhi.cprindia.org/hi/ (Hindi).

There are three ways through the project sought to answer the question: "How does the local state work?" The first considers the administrative status of towns in India by focusing on statutory and census towns. The second has delved into the link between JNNURM and smaller cities of India by comparing the components of JNNURM for bigger cities with those for smaller cities. The last one has analysed the spatial inequalities in India's ten largest cities by considering the extent of segregation of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in these cities and the provision of public goods to them.

The project culminated with a two-day conference in August 2015.

VIII. Digital Urban Observatory

The project seeks to comprehensively map the provision of civic services in select informal settlements in Delhi using a combination of satellite imaging and field enquiry. The mapping exercise has engaged community organisations active in the settlements, and is being carried out in collaboration with researchers from Brown University and Georgetown University, USA. This year the team worked across several settlements to gather data in patnership with local NGOs and community actors.

IX. India-Urban Rural Boundaries and Basic Services (IND-URBBS)

The IND-URBBS initiative is a collaboration between CPR and the Institute of Research and Development (Institut de recherche pour le développement- IRD). The IND-URBBS is constructed around understanding how outcomes in urban settlements like structure of occupation, delivery of basic services, and broader aspects of citizenship are affected by the interaction between citizens and state governance mechanisms in three types of sites, viz.: (i) 'census towns' vis-à-vissmall statutory towns; (ii) informal settlements in large cities vis-à-vis formal settlements of similar nature; and (iii) peripheral settlements inside the municipal boundary of the city vis-à-vis settlements outside the municipal city boundary, thereby assessing the effect of differences in public policies according to the extent to which these sites are acknowledged by the state.

The IND-URBBS program has supported young PhD scholars in its participating institutions—CPR, Indira Gandhi Institute for Development Research (IGIDR) and University of Burdwan—in pursuing their research aligned to the main areas of enquiry. This year, CPR organised a panel at the World Urban Forum in Kuala Lumpur in February 2018, to discuss the importance of focusing on small towns and informal settlement while implementing the Sustainable Development Goals and the New Urban Agenda. Research on rental housing in urban villages was presented by Mukta Naik in CESSMA, IRD, Paris as well as in an international conference in Hanoi this year. Veronique Dupont and Shankere Gowda continued their research on Kathputli Colony this year, in which they tracked the demolition of the settlement and its after effects.

X. Integrating intermediate public transport within transport regulation in a megacity region

The project examines the regulatory architecture of transportation in the Kolkata Metropolitan Area with the aim of integrating intermediate public transport (IPT) within transportation regulatory structures in the megacity of Kolkata.

CPR undertook the project in association with Innovative Transport Solutions Private Limited (iTrans) with the support of the Shakti Foundation. By studying the regulatory framework for IPT and through route surveys and interviews of drivers and users of auto rickshaws in the city, the project found that the integration of auto rikshaws could allow for a more seamless transport system and support the shift of users away from private transport by providing high frequency assured seating public transport options that start and end close to user origins and destinations.The project was completed in December 2016 and the report is available on the website. The project has contributed to ongoing discussions on integrated transport planning in Kolkata and researchers have participated in conferences and consultations around the revised frameworks for road safety and transportation in the country. This year, CPR researchers participated in conferences and contributed to government consultations on transportation policy.

XI. Missing Middle: Census Towns in India

Settlements in India are grouped into three broad categories, namely villages, statutory towns (STs) and census towns (CTs), the latter two being the two main types of urban areas in India. CTs are administratively rural settlements which nevertheless satisfy the criteria of urban areas. This project will investigate the nature, history, as well as economic and political structures of Census Towns.

Census Towns raise a number of questions regarding their characteristics and classification which the project seeks to address: In what respects is a Census Town different from a village or a statutory town? Why is one settlement rural and another one urban? What are the trade-offs between the rural and urban status and the associated government structures? In order to consider these issues, the study analyses national survey data, such as the Indian Census data, along with in-depth field studies in Bihar, Odisha, Jharkhand and West Bengal.

CPR fellows Partha Mukhopadhyay and Marie-Helene Zerah released a World Bank research paper titled ‘Understanding India’s Urban Frontier: What Is behind the Emergence of Census Towns in India?’ along with collaborators Gopa Samanta and Augustin Maria in December 2016.

XII. Strengthen and Harmonize Research and Action on Migration in the Indian Context (SHRAMIC)

Funded by the Tata Trusts, SHRAMIC is a multi-stakeholder project in which CPR collaborated with Indira Gandhi Institute of Development Research, National Institute of Urban Affairs and IRIS Knowledge Foundation to bring together academia and NGOs to study migration related issues. The goal of the initiative is to improve our understanding of the extent and nature of migration in India as well as to suggest evidence based policy prescriptions for protection of the rights of migrants.

Shamindra Nath Roy, Manish and Mukta Naik brought out a policy brief looking at social protection mechanisms for migrant construction workers this year, and also participated in an author’s workshop held in Mumbai as a significant step towards compiling a handbook on internal migration. Partha Mukhopadhyay and Mukta Naik are co-editors of this volume, along with other collaborators.

XIII. Subaltern urbanisation in India

Subaltern urbanisation refers to the growth of settlement agglomerations that are independent of the metropolis and autonomous in their interactions with other settlements. The SUBURBIN project, headed by the French Institute of Pondicherry (IPF) and Centre de Sciences Humaines (CSH), aims to offer alternative perspectives on "urban transition" from different disciplines. The quick transformation of economies raises several important questions: Where do we draw the line between rural and urban, between administrative status and functional reality? How and for what purpose would a rural area become an urban area? What is the relation between the proliferation of small towns and economic processes?

SUBURBIN is a joint project of IFP and CSH. CPR along with other institutions like Indira Gandhi Institute for Development Research, the Institut Français de Pondicherry, the Jawaharlal Nehru University, the School of Planning and Architecture, New Delhi, University of Burdwan are involved in this work.

This research project has culminated in a book titled eponymously and edited by Eric Denis and Marie-Helene Zerah, which was released internationally in early 2017 and will be soon available in India as well.

XIV. Role of Small Cities in Shaping Youth Employment Outcomes in India

This new research project, funded by the Think Tanks Initiative and IDRC, explores the role of small cities in positively shaping the employment outcomes of migrant youth. Hypothesizing that the small city could be serving as a 'way station' along the migration pathways of the young, the project investigates the role of governance and policy frameworks using case cities in India and Indonesia. Exploring the experiences of young migrants in small city labour markets, the project is investigating skill development, employment outcomes, economic mobility and the impacts of these factors on migration pathways. The labour market experiences of women migrants in small cities, given their invisibility in macro-level data, will be a significant contribution of the project. Centre for Policy Research, New Delhi with collaborator JustJobs Network - a global jobs think tank, seeks to use project outputs to propose policy recommendations that enable governments to improve the employment outcomes of migrant youth, especially women migrants. The project takes forward, in some measure, CPR's existing work on themes related to migration, small towns, governance and citizenship. This year, the focus was on collecting quantitative and qualitative data from two field sites, in Kishangarh, Rajasthan and Mangalore, Karnataka.

Understanding Metropolitan Homelessness

Understanding Metropolitan Homelessness is an ethnographic research project in partnership with Koshish-TISS that received funding by ICSSR in February 2017. The research follows the life cycle of homelessness -- i.e. (a) entry into homelessness, (b) survival during homelessness and (c) exit from homelessness: through death, employment or reintegration with family. The goal, specifically, is to capture journeys of homeless people – who are largely migrants - from their native places to the streets of Delhi, if or the extent to which they access shelters, how their jobs in daily wage circles impacts health and the ability to provide for relatives in native places, and factors that determine polar opposite pathways – mortality or rehabilitation - out of homelessness.

The yearly death toll of homeless people in Delhi remains high and the usage of the city's shelters low, despite regular intervention by the Hon'ble Supreme Court and national social support schemes, such as the National Urban Livelihood Mission (NULM), which aims to provide shelter and services for 900,000 homeless people in 790 cities, and ration and nutrition entitlements under the National Food Security Act. The project posits this is due to the lack of robust knowledge on the nature of risk factors homeless people

face to chronic and death-inducing poverty that could inform policymakers, local officials and implementing agencies on how to adequately respond to their needs.

Scholars have also noted that in the case of Delhi dramatic changes in land use this century for development projects has reduced access among many poor people to livable spaces and impacted working conditions, increasing inequality. Much of the literature on this subject concerns impacts on housing and livelihood of people evicted from informal settlements for such projects. Little is known about the daily experiences of people who inhabit Delhi without housing permanently or indefinitely and who face distinct safety, environmental, and health risks associated with poverty on the streets.
By examining the life cycle of homelessness through close engagement with people on the streets and in shelters of Delhi over time, this project aims to shed light how homelessness connects to cohering dimensions of urban poverty, governance and urbanization and address barriers homeless people face to accessing services, thus enhancing the potential for policymakers to respond to these needs. An examination of the livelihood and survival strategies of homeless people will also highlight capabilities, human and social capital, that may also provide scope for policymakers to broaden development policies intended for the urban poor to include the homeless.

In addition to these experiences, the project documents government schemes designed to address the needs of the homeless. Our research partner, Koshish-TISS, has been documenting stories in Mumbai of formerly homeless clients for whom they had successfully helped find jobs or return to their families. This project seeks to contribute such stories in Delhi to broaden the ongoing literature on successful outreach initiatives to homeless people.

Activities: April 2017-March 2018

Using ethnographic and life history methods (recorded on audio) our project team collected audio-interviews of 269 cases in Delhi (of which 199 cases have been transcribed) to capture (a) entry into homelessness (b) vulnerabilities experienced during homelessness – work conditions in the urban informal economy, health burdens, and the lack of physical safety and security due to the lack of housing – and in coordination with our research partner, Koshish-TISS, c) exit from homeless – to document sustainable pathways out of this situation.

Based on this method, the paper Becoming Homeless, Surviving Homelessness: The lives of six working homeless men in Yamuna Pushta, Delhi presents case studies of migrant homeless men from Uttar Pradesh who live, for various durations, in shelters along the western bank of the Yamuna River in North Delhi, locally referred to as 'Yamuna Pushta'. Through tracing their journeys from villages and towns to Delhi's streets, it explores how these men became homeless and how they survive homelessness in Delhi. The paper explores how men experience structural causes of homelessness (e.g. poverty, unemployment) and how these are interlinked – through capturing the lived experiences of the homeless in their voice. The case studies in the paper uncover conditions, and combinations, of extreme poverty and physical abuse experienced by these men in their native places before they left home. It then traces how they secure jobs, and survive, in daily wage, informal economies without housing, and access social services like shelter, health and drug de-addiction programs to endure the streets of the capital. Through men's trajectories, this paper also explores differences between working homeless men who return home to support families and those who have no ties with their native places and live on the streets indefinitely.

XV. Tacit Urban Research Network (TURN)

Funded by Ford Foundation, TURN is conceptualized as a network of four research institutions – The Indian Institute for Human Settlements (IIHS), TISS Mumbai, Centre for Policy Research (CPR) and Hyderabad Urban Labs (HUL) – in India working on urban issues. The network is collaboratively carrying out research on urban informality and the tacit knowledge integral in it from multiple vantage points in the relational geographies of settlement, housing, and economies and at multiple sites, with the eventual goal of incorporating that understanding into knowledge systems that support policymaking.

The research networks aims to (a) increase the visibility and understanding of hitherto 'tacit' knowledge about urban informality in India, (b) incorporate such knowledge to increase the inclusivity of policy frameworks (c) evolve of the tacit knowledge urban research network (TURN) into a platform for future urban research in India. In this year, CPR researchers have been working to conceptualize research themes and explore research sites that could address these questions.

XVI. Water-Dispute Incidence Monitoring Systems (Wims)

The project has monitored disputes over natural resources in the Krishna river basin in Andhra Pradesh. The project's premise is that disputes over natural resources emerge due to gaps in corresponding policy and governance mechanisms. WIMS is a pilot project to experiment a methodology for monitoring and studying dispute incidences to draw lessons for policy making and designing institutions for better governance of natural resources. The project has monitored three ongoing disputes over natural resources in the Krishna basin, Andhra Pradesh: water, land, and environment (flood plains encroachment). One, the conflict over interstate water sharing of Krishna river waters between Andhra Pradesh and Telangana. This includes the conflict around the linking of Krishna with Godavari river through the Polavaram project – a project given a status of "National Project" by the Union government as part of the bifurcation arrangement. Two, the land related conflicts around the implementation of the "Land Pooling Scheme" (LPS) by the state of Andhra Pradesh for building their new capital city of Amaravati on the western banks of Krishna river. Three, the environmental conflicts due to proposed Amaravati city - the encroachment of flood plains for the new capital city of Amaravati. The project has also documented disputes over other environmental issues such as the proposed de-notification of the forest land in the capital region.

The project has monitored dispute incidences over a period of four months by pursuing incidences reported in the local newspapers, television channels, social media, field visits, and other government/non-government sources. These incidences are backed by research efforts for documenting and analyzing the disputes. The project has resulted in documenting a total of 43 dispute incidences (Water-27; Land-10; Environment-6). These have been analyzed to draw implications for corresponding policies (for e.g., LPS), and institutions (for e.g., Krishna River Management Board).

XVII. Why 'Dominant' Castes Demand Reservations? A Comparative Study of Marathas (Maharashtra), Jats (Haryana) and Patidars (Gujarat)

Carried out by: Dr Ambrish Dongre (PI) & Mr D Shyam Babu (Co-PI)

India has witnessed agitations by well-off farming castes demanding that the benefits of Reservations be extended to them. They are not only well-endowed with enough social and economic clout but concentrated in large numbers in specific areas. In the past some of these castes opposed Reservations for

the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This begs the question why they now choose to be identified as 'backward' or 'weaker' sections to obtain Reservations. Have their material conditions so deteriorated that they must seek every prop for survival? Have the Reservations, on the other hand, become so attractive that even those opposed to the policy succumb to its lure?

The project will seek to contribute to our understanding of social and economic factors driving these ever-increasing demands for Reservations so that more effective policy alternatives could be devised. Moreover, the project's focus on comparative method across three castes in as many states will help future scholarship to further deepen the field.

Expected Date of Completion: December 2018.

XVIII. Scale, Institutions and Networks in Transboundary Waters (SINeTs)

The project is an adjunct project to supplement the efforts under a multilateral project, SDIP (Sustainable Development Investment Portfolio). SDIP aims at regional cooperation in South Asia by improving water, energy and food security across the three major Himalayan river basins; the Indus, Ganges and Brahmaputra. SINeTs extends support to SDIP and its partners by providing research and capacity building inputs. The research activity explores with the dimension of multiscalarity in transboundary river water governance in South Asia: how governance at international scale is shaped by internal drivers such as interstate river water coordination within India.

FACULTY NEWS

1. During the year under review, the President & Chief Executive, **Yamini Aiyar** was involved in the following research and allied activities:

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Why simultaneous elections are bad for Indian democracy, *Hindustan Times*, 15 March 2018

ii. A better education administration will be decentralised and focused on learning, *Hindustan Times*, 28 February 2018

iii. Political Messaging Masks Budget 2018 Actual Delivery in the Social Sector, *The Wire*, 2 February 2018

iv. Budget 2018: No real ease of living for Indians, *Hindustan Times*, 2 February 2018

v. After Budget 2018, Centre and states need to focus more on cooperative federalism, *Hindustan Times*, 30 January 2018

vi. The persistent problem of unspent funds is a symptom of a deeper malaise, *Hindustan Times*, 4 January 2018

Paper submitted for presentation at conferences/seminars:

i. India's Political Economy, Carnegie Endowment for International Peace, 27-28 October

ii. Health Seminar – Panelist, NIPFP Delhi, 5 December

iii. National Conclave on SDGs, Delhi, 19 December

iv. Raag Darbari Conference, Delhi University, 29 January

v. World Bank Sanitation Meeting, World Bank, Lodhi Road, New Delhi World Bank, Lodhi Road, New Delhi, 30 January

vi. Panel Discussion on the Union Budget 2018-19 Panelist, Constitutional Club, New Delhi CBGA, New Delhi, 2 February

vii. 7th Regional Meeting of TTI on Remaining Relevant in the Policy World: Sustainability Challenges of Think Tanka , BRAC CDM Savar, Dhaka CPD, Dhaka and BIGD, Dhaka, 5-6 February

viii. Delhi Education Initiative Meeting, Delhi , 7 February 2018

ix. 5 Institute Budget Seminar , Leela Palace, New Delhi CPR, ICRIER, IDF, NCAER, NIPFP, 10 February 2018

x. Mountain State VI: Discussion on SDG & IHR, India Habitat Centre, 12 February

xi. OXFAM Panel, 22 February

xii. Roundtable on Social Insurance, World Bank, Lodhi Road, World Bank, New Delhi, 1 March

xiii. The Future of Fiscal Transparency and Accountability: A Field Wide Conversation, International Budget Partnership, Washington DC, USA, 12-13 March

xiv. 4th Annual Conference on Land Laws, Land Acquisition, and Scheduled Areas in India, Panelist, India International Centre, New Delhi, CPR, 16 March

Presentation at round tables and conferences:

i. Talk, Rules Vs Responsibilities? Reflections on the Challenge of State Capacity from the Bottom up, IIM Ahmedabad, 23 November

ii. Talk, Accountability Initiative: Public Expenditure Tracking, NIPFP, Delhi, 15 December

iii. Lecture, Lady Shri Ram College for Women, University of Delhi, Lady Shri Ram College for Women, University of Delhi, 18 January

Sitting on task forces and working groups:

i. Working Group Panchayati Raj

2. During the year under review, Fellow, **Arkaja Singh** was involved in the following research and allied activities:

Articles in Non Reviewed Periodicals:

i. Sewer Workers Deaths: Instead of Blaming Contractors, Probe Role of DJB Officials, *Hindustan Times*, 2017

Notable Seminar and Conference Presentations:

i. *Urban Sanitation from a River Pollution Perspective* on 'Plenary talk at the Social Sciences Winter School organised by Pondicherry University and IFP in Pondicherry in December 2017.

ii. Round table on *Community Approaches to Sanitation: Experiences from Implementation* on ' Manual Scavenging' organized by the Centre for Policy Research in New Delhi in December 2017

Targeted Meetings with Policy Makers:

i. Need for faecal sludge and septage management (FSSM) in Rural areas, Ministry of Drinking Water and Sanitation, 18 December , 2017, 22 January and 8 February 2018

3. During the year under review, Fellow, **Avani Kapoor** was involved in the following research and allied activities:

Journal Articles:

i. Fiscal transfers based on inputs or outcomes? Lessons from the Twelfth and Thirteenth Finance Commission in India, Victoria Y. Fan, Smriti Iyer, Rifaiyat Mahbub, Anit Mukherjee, The International Journal of Health Planning and Management 2017, 1-18, 30 August 2017

Policy Briefs:

i. Chapter titled Costs, Compensations and Challenges in Sarin, Ankur, Ambrish Dongre, and Shrikant Wad. 2017, State of the Nation: RTE , Section 12(1)(c), Ahmedabad: IIM Ahmedabad co-authored with Ambrish Dongre, August 2017

ii. Budget Brief 2018-19: Swachh Bharat Mission - Urban (SBM-U) Devashish Deshpande, Avani Kapu r, 3 February 2018

iii. Budget Brief 2018-19:Swachh Bharat Mission- Gramin (SBM-G) Avani Kapur, Devashish Deshpande, 3 February 2018

iv. Budget Brief 2018-19: Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS), Devashish Deshpande, Avani Kapur, 3 February 2018

v. Budget Brief 2018-19: Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Avani Kapur, Mridusmita Bordoloi, Ritwik Shukla, 3 February 2018

vi. Budget Brief 2018-19: Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) Avani Kapur, Mridusmita Bordoloi, Ritwik Shukla, 3 February 2018

vii. Budget Brief 2018-19: Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) Sahithya Venkatesan, Avani Kapur, 3 February 2018

viii. Budget Brief 2018-19: National Health Mission (NHM) Avani Kapur, Prerananandita Baisnab, 3 February 2018

ix. Budget Brief 2018-19: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)Avani Kapur, Parma Chakravartti, 3 February 2018

x. Budget Brief 2018-19: Integrated Child Development Services (ICDS), Avani Kapur, Prerananandita Baisnab, 3 February 2018

Presentation at Conferences:

i. Internal UN Women Training Program on *Rules versus Responsiveness, Fiscal Transfers, Social Policy & Building an Accountable State* organised by UN WOMEN in June 2017

ii. Delhi Course on *Monitoring and Evaluation for Indian Economic Service (IES) Probationary Officers on Using Evidence for Public Service Delivery and Accountability,* organised by CLEAR and JPAL in Delhi in August 2017

iii. IIM Ahmedabad Knowledge Symposium- '*Evidence to Policy Action for Elementary Education in the context of Right to Education (RTE*) organised by IIM in Ahmedabad in August 2017

iv. 3 day course module on building state capacity for ISDM students organised by Indian School of Development Management in Noida in October 2017

4. During the year under review, Research Professor, **Bharat Karnad** was involved in the following research and allied activities:

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Emperor Xi And The Kowtow Imperative, The Quint, 12 March 2018

ii. The Arms Procurement Syndrome, Open Magazine, 23 February 2018

iii. The One Thing Modi Should Ask From Trudeau When They Meet; It Will Salvage An Otherwise Insipid Visit, Swarajya, 23 February 2018

iv. Time to Insulate India-Iran Ties, The Citizen, 22 February 2018

v. Sleight of Hand: Lockheed Martin Turns F-16 into F-35, and Creates Markets Where There Are None, The Citizen , 25 January 2018

vi. Chief Of Defence Staff:To Be Or Not to Be, The Citizen, 9 January 2018

vii. Who Is The REAL Defence Minister?, The Citizen, 20 December 2017

viii. Foreign Fighter Jets Arenâ€™t Better Than All-Indian Tejas. Period., The Quint, 14 November 2017

ix. Afghanistan, Pakistan and the F-16: Mattis has to hardsell these issues on his visit to India, Hindustan Time , 22 September 2017

x. Tejas: Personal Feud or Technical Flaw, Why Was Tejas Rejected?, The Quint , 19 September 2017

xi. The Priority List For Defence Minister Nirmala Sitharaman, The Quint, 7 September 2017

xii. The Doklam Standoff: Hot And Cold At The Creeping Tri-Junction, Bloomberg Quint,, 24 July 2017

xiii. The Arms Of Others, Indian Express , 17 July 2017

xiv. Modi In Israel: Need For More Equitable Defence Collaboration, Bloomberg Quint, 3 July 2017

xv. Time To Revive The Hasnain Strategy In Kashmir Is Now , Swarajya , 29 June 2017

xvi. Is the Indian Army ready for a â€˜Two and halfâ€™ front war?, The Indian Economist, 21 June 2017

xvii. A Dealmakersâ€™ Draw, Open Magazine , 16 June 2017

xviii. India Unprepared For Unsolicited Offer To Play Peacemaker On Kashmir, Bloomberg Quint , 4 May 2017

xix. Why Arun Jaitley As Defence Minister Ought To Be An Interim Arrangement, Bloomberg Quint, 12 April 2017

5. During the year under review, Professor, **Brahma Chellaney** was involved in the following research and allied activities:

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Why the South China Sea is critical to security, The Japan Times, 27 March 2018

ii. Beijing quietly presses ahead with its expansionist agenda in the South China Sea,The National, 26 March 2018

iii. The US administration should not reward Islamabad for its lies,Hindustan Times , 21 March 2018

iv. China's stealth wars in the Himalayas,Nikkei Asian Review, 20 March 2018

v. A challenging time for the Indo-Pacific,Live Mint , 14 March 2018

vi. A New Order for the Indo-Pacific,Project Syndicate , 12 March 2018

vii. China is ensnaring vulnerable states in debt traps, Nikkei Asian Review, 1 March 2018

viii. India must impose punishing sanctions on the Maldives, Hindustan Times, 21 February 2018

ix. India'sChoice in the Maldives,Project Syndicate , 20 February 2018

x. China ensnares vulnerable states in a debt trap,Nikkei Asian Review,20 February 2018

xi. How Can America Change Pakistani Behavior?,Project Syndicate,30 January 2018

xii. Republic Day 2018 | A legacy of rash decisions,DNA India,, 29 January 2018

xiii. Chinadam frenzy,The Washington Times,, 17 January 2018

xiv. Water shortages pose a threat to Asia's peace and stability,Nikkei Asian Review , 11 January 2018

xv. By denying river water data to us, Beijing is using the resource as a tool of coercive diplomacy,Hindustan Times,, 10 January 2018

xvi. Beijing is pursuing a complex strategy to corner natural resources,The National , 4 January 2018

xvii. Water shortages could trigger Asia conflicts,Nikkei Asian Review, 4 January 2018

xviii. ChinaCreditor Imperialism,Project Syndicate, 22 December 2017

xix. Chinaactions risk creating a coalition of democratic powers,China US Focus, 1 December 2017

xx. Rohingya militancy poses a regional threat,Japan Times,, 29 November 2017

xxi. Democratic forces must join hands to protect Indo-Pacific from Chinahegemony,Hindustan Times,, 17 November 2017

xxii. Asiaâ€™s New Entente,Project Syndicate,, 6 November 2017

xxiii. Xiâ€™s new strength obscures China internal risks,Japan Times,, 30 October 2017

xxiv. A New Front in Asiaâ€™s Water War,Project Syndicate,, 12 October 2017

xxv. Xi Struggling to Keep the PLA in Line?,China US Focus,, 5 October 2017

xxvi. Calling Pakistan â€˜Terroristanâ€™ is not enough, India must back it with tough action,Hindustan Times,, 4 October 2017

xxvii. Democratic powers must intensify Indian Ocean cooperation,Nikkei Asian Review,, 4 October 2017

xxviii. Myanmarâ€™s Jihadi Curse,Project Syndicate,, 28 September 2017

xxix. Doklam Standoff: PLA May Have Been The Thorn In Xi Jinpingâ€™s Side,Swarajya,, 7 September 2017

xxx. Chinatroublesome civil-military relations,Japan Times,, 7 September 2017

xxxi. India, beware: China could seek revenge for Doklam,Nikkei Asian Review,, 4 September 2017

xxxii. China pushes natural allies India, Japan closer to US,The Sunday Guardian,, 28 August 2017

xxxiii. China is waging a water war on India,Hindustan Times,22 August

xxxiv. In Beijins thinking, the best weapons don't win today’s wars, but the best narrative does,The National,, 21 August 2017

xxxv. China wants war with India, make no mistake,DailyO,, 17 August 2017

xxxvi. Calling the Chinese s Bluff,Project Syndicate,, 11 August 2017

xxxvii. By refusing to buckle under threats on Doklam, India has called the bluff,The Times of India,, 3 August 2017

xxxviii. Chinaweaponization of trade,Live Mint,1 August 2017

xxxix. ChinaWeaponisation of Trade,Project Syndicate,, 27 July

xl. What ChinaHimalayan warmongering reveals,The Japan Times,25 July 2017

xli. Let facts speak for themselves on India-China border,The Sunday Guardian,, 24 July 2017 –

xlii. Doklam standoff: India must be ready to give China a real bloody nose ,Hindustan Times,, 24 July 2017

xliii. China's Bhutan land grab aims at bigger target,Nikkei Asian Review,, 12 July 2017

xliv. Itâ€™s time India used its most powerful weapon against China:â€‰Trade,Hindustan Times,, 29 June 2017

xlv. India’s inward nuclear turn: It has taken 12 years for the Indo-US nuclear deal hype to give way to sober realism,Times of India,, 22 June 2017 - 12:30pm

xlvi. 'Homegrown' power plan will boost Indian nuclear industry,Nikkie Asian Review,, 16 June 2017 - 1:05pm

xlvii. Countering ChinaHigh-Altitude Land Grab,Project Syndicate,, 16 June 2017 - 1:02pm

xlviii. The Age of Blowback Terror,Project Syndicate,, 8 June 2017 - 12:27pm

xlix. Vladimir Putinâ€™s geopolitical chessboard,Japan Times,6 June 2017 - 11:45am

l. Revitalising India-Russia ties a challenge for Modi,Hindustan Times,, 2 June 2017 - 2:22pm

li. Why systematically discrediting the ideology behind jihadist terror holds the key to counterterrorism success,Times of India,, 29 May 2017

lii. ChinaImperial Overreach,Project Syndicate,, 25 May 2017

liii. China-Pakistan water pincer against India: As part of CPEC, mega-dams are planned in Gilgit-Baltistan,Economic Times,, 17 May

liv. America's deepening Afghanistan quagmire,Nikkie Asian Review,, 12 May 2017

lv. Asia's American Menace, Project Syndicate,, 26 April 2017

lvi. Rogue neighbours new rogue act, DNA India,18 April 2017

6. During the year under review, Legal Research Director, **Kanchi Kohli** was involved in the following research and allied activities:

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Of a frictionless development : Ports have the potential to endanger the environment, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, May 2017

ii. Keeping civil society at bay hurts climate redressal prospects, Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, June 2017

iii. Firms often understate green impact of projects, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, June 2017

iv. How gram sabha's dissent is crushed under infra projects, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, July 2017

v. Wetlands when reality strikes: Supreme Court fines environment ministry for not following directions, Manju Menon and Kanchi Kohli, India Today, July 2017

vi. Passing on regulatory burdens to people is recipe for disaster, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, August 2017

vii. State regulation is legitimising unfeasible water mining, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, September 2017

viii. Why the courts and the MoEF are on a collision course, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, September 2017

ix. The terrible track record of land governance in India, Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, September 2017

x. Foul air: Thermal power more to blame than crackers, Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, October 2017

xi. The saga of Indian mining: A long lineage of illegality, Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, October 2017

xii. Is ease of doing business undermining green norms?Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, October 2017

xiii. Compensatory afforestation schemes are a charade, Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, October 2017

xiv. Regulatory efforts may push groundwater beyond reach, Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, October 2017

xv. Political leadership failed India's environment in 2017, Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, October 2017

xvi. Raising the bar on democracy and environment, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, 1 January 2018

xvii. Engaging the public to improve environmental compliance, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, 15 January 2018

xviii. Legal ambiguities stymie redress of environmental harm, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, 29 January 2018

xix. Conflicts break out as institutes take over coastal lands, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, 14 March 2018

xx. Government must take a relook at its forest policy, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, 27 March 2018

Web-Based publications:

i. Proposed Amendments to Environment Protection Act, Could Legalise Violations, Manju Menon, Kanchi Kohli, Krithika Dinesh and Debayen Gupta, *The Wire*, August 2017

ii. In State-Level Changes to Land Laws, a Return to Land Grabbing in Development's Manju Menon, Kanchi Kohli and Debayen Gupta, *The Wire*, September 2017

Policy Briefs:

i. Paralegals for Environmental Justice (Version 2.0)EJ Team, 4 January 2018

ii. Around the Landfill Sites: A Groundtruthing of Solid Waste Management Law Across Landfill Sites in Coastal Areas of Uttara Kannada district, Karnataka, EJ Team, March 2018

iii. Closing the Enforcement Gap: Groundtruthing Environmental Violations in Sundargarh, OdishaCIRTD, CPR-Namati EJ Team, March 2018

iv. Regulation for Groundwater Abstraction, EJ Team, March 2018

v. Surface Water: Using Law to Combat Water Pollution, EJ Team, March 2018

vi. Making the law count - Ten environment justice stories by community paralegals in India, EJ Team, March 2018

vii. Surface Water: Using Law to Combat Water Pollution, EJ Team, March 2018

viii. Making the law count - Ten environment justice stories by community paralegals in India, EJ Team, March 2018

7. During the year under review, Honorary Research Professor, **G Parthasarathy** was involved in the following research and allied activities:

Article in Non-Reviewed Periodicals

i. Fostering a special relationship ,Hindu Business Line, 22 March 2018

ii. Pakistani writer Mehr Tarar talks about the frailties and qualities of her home country ,India Today,, 19 March 2018

iii. Turmoil & New Alignments in Islamic World ,*The Indian Express*,, 19 March 2018

iv. Pak may pay price for sponsoring terror ,Business Line, 8 March 2018

v. ASEAN: The right way ahead for India ,The New Indian Express,, 5 March 2018

vi. Sharifâ€™s many hits and misses ,Business Line, 22 February 2018

vii. Free Afghanistan from Talibanâ€™s grip ,Business Line, 8 February 2018

viii. Asean: the right way ahead for India ,*The Indian Express*,, 5 February 2018

ix. Indiaâ€™s foreign policy on show ,Hindu Business Line, 25 January 2018

x. Pakistan army domination marks Jadhav Case ,The New Indian Express,, 16 January 2018

xi. Trump tweets, Pakistan defies, Hindu Business Line, 11 January 2018

xii. The Chinese road to dusty debt ,Hindu Business Line, 28 December 2017

xiii. India's uneasy stand with China and Russia ,The New Indian Express,, 26 December 2017

xiv. The US and its anti-terrorism narrative ,Hindu Business Line, 14 December 2017

xv. China woos Myanmar at the cost of India ,The New Indian Express,, 11 December 2017

xvi. Pakistan faces isolation and uncertainty ,Hindu Business Line, 23 November

xvii. Dealing with China's naval assertiveness ,Hindu Business Line, 16 November 2017

xviii. Beware the China-Pakistan nuclear axis ,Hindu Business Line, 2 November 2017

xix. Big Step, but No Early Solutions ,Times of India , 25 October 2017

xx. Regional priorities change as BIMSTEC replaces SAARC ,The New Indian Express,, 16 October 2017

xxi. The Rohingyas pose a regional challenge ,Hindu Business Line, 5 October 2017

xxii. India can ignore violence-torn Islamic J&K resolution ,The New Indian Express, Wednesday, 4 October 2017

xxiii. Ties that bind ,The Tribune, 22 September 2017

xxiv. Revisiting strategy in the Indo-Pacific ,Hindu Business Line, 21 September 2017

xxv. The way around China ,The Tribune, 18 September 2017

xxvi. Blowback as Trump goes ballistic ,Hindu Business Line, 7 September 2017

xxvii. India stands firm, challenges Chinese hegemony in Asia ,The New Indian Express,, 4 September 2017

xxviii. Chinaâ€™s reaching as far as it can go ,Hindu Business Line, 24 August 2017

xxix. Donâ€™t allow Pakistan to get away with false promises now ,Economic Times, 24 August 2017

xxx. Pakistan finds itself in a political pickle over the paltry sum of $2,700 ,Daily Mail,, 14 August 2017

xxxi. Trump Administration dithers,The Tribune, Friday, 11 August 2017

xxxii. Indiaâ€™s well-timed â€˜Look Westâ€™ policy ,Hindu Business Line, 27 July 2017

xxxiii. Modi Govtâ€™s border policy appears to have rattled China ,The New Indian Express,, 24 July 2017

xxxiv. Change the Kashmir narrative,The Tribune, 13 July 2017

xxxv. US sanctions on Salahuddin threaten Kashmiri separatists ,The New Indian Express,, 10 July 2017

xxxvi. New chemistry to Indo-US ties as Modi and Trump deftly handle potentially divisive issues ,Daily Mail, 30 June 2017

xxxvii. Watch out for Pak Armyâ€™s growing clout ,Hindu Business Line, 29 June 2017

xxxviii. India concerned as tensions rise between gulf monarchies ,The New Indian Express,, 27 June 2017

xxxix. Coping with the China factor in Myanmar ,Hindu Business Line Friday, 16 June 2017

xl. Modi scores with his personal stamp on Indiaâ€™s foreign policy ,The New Indian Express,, 12 June

xli. Letâ€™s be wary of Chinaâ€™s New Silk Road ,Hindu Business Line, 1 June

xlii. Rattled Pakistan will pay a heavy price if it chooses to defy ICJ ,The New Indian Express,, 29 May 2017

xliii. Will Nawaz Sharif wilt under pressure? ,Hindustan Times, 18 May 2017

xliv. Chinaâ€™s dominance at ASEAN bad for India's Act East policy ,The New Indian Express 17 May 2017 - 1:33pm

xlv. Rivalries sharpening in Afghanistan ,Hindu Business Line, 4 May 2017

xlvi. India remains untouched by the turmoil in Islamic world ,The New Indian Express,, 1 May 2017

xlvii. When the Dalai Lama visited Tawang ,Hindu Business Line, 20 April 2017

xlviii. Afghanistan simmers as Trump administration dithers ,The New Indian Express,, 18 April 2017

xlix. Return of the stoning season in Kashmir ,Hindu Business Line, 6 April 2017

l. Suu Kyi seeks ethnic peace as insurgents step up pressures ,The New Indian Express, Wednesday, 5 April 2017

8. During the year under review, Research Professor, **Lavanya Rajmani** was involved in the following research and allied activities:

Books:

i. *International Climate Change Law*, co-authored by Daniel Bodansky and Jutta Brunnée, Oxford University Press, 25 May 2017

Chapters in Edited Volumes:

i. Central Concepts in the Paris Agreement and How They Evolved Emmanuel Guérin, *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, co-edited by Daniel Klein, María Pía Carazo, Meinhard Doelle, Jane Bulmer, and Andrew Higham, Oxford University Press, 20 July 2017

ii. Guiding Principles and General Obligation (Article 2.2 and Article 3), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, co-edited by Daniel Klein, María Pía Carazo, Meinhard Doelle, Jane Bulmer, and Andrew Higham, Oxford University Press, 20 July 2017

Journal Articles:

i. India's approach to international law in the climate change regime, Indian Journal of International Law57(1-2), 29 January 2018

ii. The Legality of Downgrading Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement: Lessons from the US Disengagement, Jutta Brunnée, Journal of Environmental Law29(3), 1 November 2017

Policy Briefs:

i. Structuring the UNFCCC 2018 Facilitative Dialogue, Center for Climate and Energy Solutions (C2ES) Policy Brief in May 2017

ii. Elaborating the Paris Agreement: Implementation and Compliance, Center for Climate and Energy Solutions (C2ES) Policy Brief, November 2017

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Paris climate deal: Trump is on wrong side of history, science, politics and planet, *LiveMint*, 2 June 2017

Web-Based Publications:

i. Landmark climate agreement holds its own, Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, *Oxford University Press Blog (OUP Blog)*, 3 July 2017

ii. Reflections on the US withdrawal from the Paris Climate Change Agreement, *Blog of the European Journal of International Law* (EJIL: Talk!), 5 June 2017

iii. The US and the Paris Agreement: In or Out and at What Cost?, *Blog of the European Journal of International Law* (EJIL: Talk!), 10 May 2017

iv. Lav Q & A on Trump's announcement on US withdrawal from the Paris Agreement, *CPR blog*, 2 June 2017

Presentation at Conferences:

i. Presentation as a part of a visiting fellowship to the Berlin/Potsdam Research Group "The International Rule of Law - Rise or Decline?" on *Reflections on the US decision to withdraw from the Paris Agreement: Better out than Trump*? organised by Humboldt University, Berlin (Germany) in June 2017

ii. Presentation at the German Ministry of Environment *on The Legality of Downgrading Nationally Determined Contributions in the Paris Agreement* organised by German Ministry of Environment in Berlin (Germany) in June 2017

iii. Imagining a Different Future: Overcoming Barriers to Climate Justice on *Equity and Differentiation in the 2015 Paris Agreement*organised by University of Tasmania, Australia in Hobart on 9 February 2018

iv. Negotiators Workshop (C2ES), General Issues in the Elaboration of the Paris Rulebook organised by C2ES (Centre for Climate and Energy Solutions) in Tokyo, Japan on 24-25 February 2018

v. NLU, Delhi & Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" , Winter School The International Climate Change Regime organised by National Law University, Delhi in New Delhi, India on 15 January 2018

vi. Women's Energy and Climate Law Network Launch, Talk on 'The Paris Agreement and the future of international climate law' organised by The University of Melbourne Women's Energy and Climate Law Network on 8 December 2017

vii. COP-23 Roundtable at Bonn, Germany, Completing the Paris Architecture: Compliance and Implementation organsied by C2ES (Centre for Climate and Energy Solutions) in Bonn, Germanyon 12 November 2017

viii. Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement: Fiji/Bonn Climate Law and Governance Day 2017, Global Climate Regime: Context, Connections and Current Issues, with the launch of OUP book International Climate Change Law University Forum, Heussallee 18-24, 53113 Bonn, Germany [COP 23], University of Bonn on 10 November 2017

ix. Negotiators Workshop (C2ES), Elaborating the Paris Agreement: Implementation and Compliance Nadi, Fiji organised by C2ES (Centre for Climate and Energy Solutions) on 19 October 2017

Awards and other Honours:

i. Faculty for Masters in International Human Rights Law, University of Oxford, Oxford, United Kingdom, July 2017

9. During the year under review, Senior Fellow, **Kiran Bhatty** was involved in the following research and allied activities:

Journal Articles:

i. Out Of School Children Some Insights on What We Know and What We Don't, co-authored by Radhika Saraf and Vrinda Gupta, *Economic and Political Weekly, Vol 52. Issue 49*, 9 December 2017

Chapters in Edited Volumes:

i. The Governance Architecture of Monitoring Elementary Education in India: The case for community-based reforms, *Oxford Research Encyclopedia on Education*, Matthew Harris, Geetha Nambissan, Oxford University Press, 2018

ii. People's Participation in the Right to Education: The Scope for Citizen Monitoring, *Right to Education: Opportunities and Challenge*s, co-authored by Avinash Kumar Singh, Sage, 2018

Policy Briefs:

i. Review of the Immoral Traffic Prevention Act, November 2017

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Mid-day Meals and Biometrics: a Hobson's Choice for Children, Dipa Sinha, *Hindustan Times*, 16 March 2017

Web-Based Publications:

i. Public vs. Private Provision of Elementary Education: Challenges facing the Right to Education in India, *Oxford Human Rights Hub*, March 2018

ii. Midday Meals as a form of Social Security in Education, The impact of biometrics in its provision ,*YOJANA*, 13 June 2017

iii. From Blackboard to Digital Board: Budget and its implications for the Education Sector, *YOJANA*, 14 February 2018

iv. Education and the Budget, *The Wire*, 2 February 2017

v. A Budget that promises a great future but does little today, *The Wire*, 1 February, 2018

vi. Why CBSE paper leak reflects collapse of institutions, *DailyO*, 3 March 2018

Paper submitted for Presentation at Conferences:

i. Public Management Research Conference [PMRC] Does the Government's Monitoring of Schools Work? A Study of the Frontline Education Bureaucracy in India, organised by Lee Kwan Yew School of Public Policy in Singapore in March 2018

ii. National Discussion Meet on 'Implementation of RTE Act – Status, Issues and Challenges, Chaired a session organised by National Law School, [NLSIU] in Bangalore on 26 March 2018

Presentation at Conferences:

i. Lecture, Governance matters, Mumbai, TISS, May 18, 2017

ii. Lecture, Governance, Accountability and Quality in Elementary Education, Delhi Gargi College, September 14, 2017

iii. Key note Speaker, State of Elementary Education in India, National Defence College, January 17, 2018

iv. Lecture, Quality Education: State vs Private sector, Dayal Singh College, March 13, 2018

Sitting on Task Forces and Working Groups:

i. Departmental Advisory Committee, NUEPA, Member, February 2018

ii. Research Advisory Committee for University of Warwick study on gender and education in Haryana, Member, February 2018

10. During the year under review, Senior Fellow, **Manju Menon** was involved in the following research and allied activities:

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Of a frictionless development : Ports have the potential to endanger the environment, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, May 2017

ii. Keeping civil society at bay hurts climate redressal prospects, Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, June 2017

iii. Firms often understate green impact of projects, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, June 2017

iv. How gram sabha's dissent is crushed under infra projects, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, July 2017

v. Wetlands when reality strikes: Supreme Court fines environment ministry for not following directions, Manju Menon and Kanchi Kohli, India Today, July 2017

vi. Passing on regulatory burdens to people is recipe for disaster, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, August 2017

vii. State regulation is legitimising unfeasible water mining, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, September 2017

viii. Why the courts and the MoEF are on a collision course, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, September 2017

ix. The terrible track record of land governance in India, Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, September 2017

x. Foul air: Thermal power more to blame than crackers, Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, October 2017

xi. The saga of Indian mining: A long lineage of illegality, Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, October 2017

xii. Is ease of doing business undermining green norms?Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, October 2017

xiii. Compensatory afforestation schemes are a charade, Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, October 2017

xiv. Regulatory efforts may push groundwater beyond reach, Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, October 2017

xv. Political leadership failed India's environment in 2017, Manju Menon and Kanchi Kohli, *DNA India*, October 2017

xvi. Raising the bar on democracy and environment, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, 1 January 2018

xvii. Engaging the public to improve environmental compliance, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, 15 January 2018

xviii. Legal ambiguities stymie redress of environmental harm, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, 29 January 2018

xix. Conflicts break out as institutes take over coastal lands, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, 14 March 2018

xx. Government must take a relook at its forest policy, Kanchi Kohli and Manju Menon, *DNA India*, 27 March 2018

Web-Based publications:

i. Proposed Amendments to Environment Protection Act, Could Legalise Violations, Manju Menon, Kanchi Kohli, Krithika Dinesh and Debayen Gupta, *The Wire*, August 2017

ii. In State-Level Changes to Land Laws, a Return to Land Grabbing in Development's Manju Menon, Kanchi Kohli and Debayen Gupta, *The Wire*, September 2017

iii. CRZ review, begun in 2014, unleashed state govts' aspiration to loosen coastal regulation, Counterview, April 2017

iv. How each review/revision of the CRZ Notification, 2011 only diluted India's coastal regulation, Counterview, May 2017

v. We didn't consult anybody other than state govts and UTs: Dr Shailesh Nayak on CRZ review, Counterview, May 2017

vi. Participatory review of MCRZ Notification critical: Changes will directly affect 3200 marine villages, Counterview, May 2017

vii. Drafted in secrecy, India's new coastal rules enable more tourism, houses closer to shore, Scroll.in, May 2017

Policy Briefs:

i. Paralegals for Environmental Justice (Version 2.0) EJ Team, 4 January 2018

ii. Around the Landfill Sites: A Groundtruthing of Solid Waste Management Law Across Landfill Sites in Coastal Areas of Uttara Kannada district, Karnataka, EJ Team, March 2018

iii. Closing the Enforcement Gap: Groundtruthing Environmental Violations in Sundargarh, Odisha, CIRTD, CPR-Namati EJ Team, March 2018

iv. Regulation for Groundwater Abstraction, EJ Team, March 2018

v. Surface Water: Using Law to Combat Water Pollution, EJ Team, March 2018

vi. Making the law count - Ten environment justice stories by community paralegals in India, EJ Team, March 2018

vii. Surface Water: Using Law to Combat Water Pollution, EJ Team, March 2018

viii. Making the law count - Ten environment justice stories by community paralegals in India, EJ Team, March 2018

11. During the year under review, Fellow, **Navroz K Dubash** was involved in the following research and allied activities:

Journal Articles:

i. The Intergovernmental Panel on Climate Change: A History and Review. Annual Review of Environment and Resources, co-authored by M. Vardy, M. Oppenheimer, N.K. Dubash, J. O'Reilly J., & D. Jamieson, *Annual Review of Environment and Resources 42(1),* October 2017

ii. Multi-criteria decision analysis in policy-making for climate mitigation and development Cohen,B., Blanco,H., Dubash, N.K., Dukkipati, S., Khosla,R., Scrieciu,S., Stewart, T., & Torres-Gunfaus, M., *Climate and Development,* March 2018

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Trumping the climactic, *The Hindu,* June 2017

ii. India must reaffirm its Paris pledge, *The Hindu*, April 2017

Presentation at Conferences/Seminars:

i. Energy Research and Social Sciences on 'The Brave New World of "Nationally Determined Contributions": Returning National Energy Politics to Centre Stage' organised by Energy Research and Social Sciences in Spain from 2-5 April, 2017

ii. 8th International Conference on Climate Change at TISS: Climate Action: Mitigation and Adaptation in a Post Paris World International Negotiations and Domestic Climate Action - Interconnections and Contestations within and outside the Paris Agreement organised by Tata Institute of Social Sciences in Mumbai, Maharashtra from 4-5 August, 2017

iii. Regulators and Policymakers Retreat 2017 (IPPAI) on Mapping Power: The Political Economy of Electricity in Indian States, Belgaum,Karnataka, Independent Power Producers Association of India, 27 October, 2017

iv. Sustainable Mountain Development Summit VI, Understanding Climate Change in Local Context, Aizwal, Mizoram, Integrated Mountain Initiative, and Mizoram Sustainable Development Foundation, Keynote Address, 21 September, 2017

v. India-EU Climate & Clean Energy Conclave 2017 Detailing India's Low Emission Pathway(s) in an INDC World, New Delhi, CII- ITC Centre for Excellence for Sustainable Development, Speaker at a Session, 6 – 7 September, 2017

vi. ICS Conversations: Recent Developments in China-US Relations and their Impact – Panel Discussion, New Delhi, Institute of Chinese Studies and India International Centre, Panelist, 22 August, 2017

vii. The Vidhi Dialogues: India in the Paris Agreement: Ramifications of the US Withdrawal – Panel Discussion, New Delhi, Vidhi: Centre for Legal Policy, Panelist, 5 July, 2017

viii. IPCC Expert Meeting on Mitigation, Sustainability and Climate Stabilization Scenarios, Social Change, Institutions and Policies, Addis Ababa, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Panelist, 27 April, 2017

ix. World Book Fair Panel Discussion on Climate Diplomacy: Innovative approaches for a climate-resilient, low-carbon future in India and Europe - New Delhi, World Book Fair, EU-India Panel Discussion on Climate Diplomacy, 10 January 2018,

x. CSE Book Launch for 'Climate Change Now: Stories of 21st Century Carbon Colonialism', Panel Discussion on climate policy, environmental degradation and the importance of education and awareness to get a better deal in climate negotiations, New Delhi World Book Fair and Centre for Science and Environment, 11 January 2018

xi. Brown bag lunch- Political economy double bill, The Political Economy of Electricity in India's States, Washington D.C., World Bank, 1 February 2018

xii. Roundtable on 'Driving Sub National Leadership on Clean Energy Transition in India', The Political Economy of Electricity in India's States, New Delhi, The Climate Group, 16 February 2018

xiii. Interaction on Sustainable Development Goals (SDGs) with Members of Legislative Assembly, Ensuring sustainable future through protecting environment and developing response to Climate Change in Assam, Dispur, Assam Legislative Assembly, 27 February 2018

xiv. Roundtable on 'Creating India's First Philanthropic Collaborative on Climate Change, Mumbai, Lumen Consulting, 12 March 2018

Sitting on Task Forces and Working Committee:

i. Expert Committee on "Long Term Strategy for Low Carbon Development for India", Member, February 2017 to present

ii. Expert Committee on Renewable Energy Act and /or Renewable Energy Policy Statement for India , Member, Ongoing

Targeted Meeting with Policymakers:

i. Towards an End-Use Agenda for India's Energy Transition Arnulf Gruebler, Ajay Mathur, Anil Jain and representatives from other organizations working towards energy policy , 19 January 2018

12. During the year under review, Fellow, **Namita Wahi** was involved in the following research and allied activities:

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Conflict of benches, Live Law, 5 March 2018

Working Paper:

i. The Legal and Political Economy of Land Rights of Scheduled Tribes in the Scheduled Areas of India Namita Wahi, Ankit Bhatia, January 31, 2018

Podcasts:

i. Understanding Land Conflicts in India, Namita Wahi, CPR Podcast, Episode 15, April 18, 2017

Presentation at Conferences/Seminars:

i. World Bank Land and Poverty Conference, Understanding Land Acquisition Disputes in India , Paper acceptance, Washington D.C., World Bank, 12 December, 2017

ii. Second Batch of Training Programme on "Social Impact Assessment, Rehabilitation and Resettlement", Guest Lecture on "The Law and Practice of Land Acquisition in India", New Delhi, TERI, January 15, 2018

iii. Business-related Human Rights Violations: State or Corporate Responsibility? – Extractive Industries and Land Rights Issues: The Cases of Nigeria and India The Law and Practice of Land Acquisition in India, Bergen, Norway, Rafto Foundation for Human Rights and the Centre on Law and Social Transformation, December 4, 2017

iv. Lesson Learned--The 33rd Anniversary of the Bhopal Gas Disaster , 2017, Bergen, Norway, Rafto Foundation on Human Rights and the Centre on Law and Social Transformation, December 2 2017

v. Guest Lecture The Legal and Political Economy of Land Rights of Scheduled Tribes in India, Tromso, Norway, Centre for Political Studies, University of Tromso, Norway, November 24, 2017

vi. Workshop on Comparative Research on Land Use Change Conflicts and Remedies in Del hi, Land Acquisition Litigation in India: A Review of Supreme Court Cases from 1950 to 2016, Faridabad, TERI, November 14, 2017

vii. Workshop on Comparative Research on Land Use Change Conflicts and Remedies in Delhi, The Legal and Political Economy of Land Rights in the Scheduled Areas of India, Faridabad, TERI, November 13, 2017

viii. iSERP Workshop, EAFIT University Property Rights and Social and Economic Rights, The Post-Colonial State and the Rule of Law in India, Medellin, Colombia EAFIT University, Medellin, Colombia, November 4, 2017

ix. Conference on New Questions concerning land in Neo-liberal India, Understanding Land Acquisition Disputes in India: A Review of Supreme Court cases from 1950 to 2016, Shimla, Indian Institute of Advanced Study, October 10, 2017

x. Bergen Exchanges on Law and Social Transformation, The legal regime and political economy of land rights of Scheduled Tribes in the Scheduled Areas of India, Bergen, Norway, Chr. Michelsen Institute and the University of Bergen, Bergen, Norway, August 25, 2017

xi. Central Information Commission Seminar on "Land Records and Right to Information Act, 2005", The Legal Architecture of Land Governance in India: Access to Information Challenges, New Delhi, Central Information Commission, July 15, 2017

xii. India: Land and Development Conference , Land Acquisition Litigation in India, New Delhi, NITI Aayog, Landesa, WRI India, IFAD, NRMC, India International Centre, New Delhi, April 5, 2017

xiii. "Dispossession without Development: Land Grabs in Neoliberal India", Michael Levien,

xiv. CPR LRI Guest Speaker Series 10, July 19, 2017, Centre for Policy Research, New Delhi, Mapping Land Conflicts in India", Kumar Sambhav Shrivastava, Ankur Paliwal and Bhasker Tripathy, CPR LRI Guest Speaker Series 9, Centre for Policy Research, New Delhi, June 22, 2017

xv. The Future We Need: Natural Resources as a shared inheritance", Rahul Basu, CPR LRI, Guest Speaker Series 8, May 17, 2017, Centre for Policy Research, New Delhi, Conversation with Mr. Ramesh Sharma, National Convenor, Ekta Parishad, Centre for Policy Research, May 9, 2017.

xvi. "Development Conflicts We Know Nothing of", Rohit Prasad, CPR LRI Guest Speaker Series, Centre for Policy Research, New Delhi, April 20, 2017

Sitting on Task Forces and Working Committees:

i. Technical Committee of Pilot Study on Digital Land Records Modernisation Programme, Advisor, January 19 to November 13, 2017

Targeted Meeting with Policy Makers:

i. Discussed findings from Land Acquisition Study on the sidelines of the India: Land and Development Conference , Mr. T. Haque, Chairman, Special Cell on Land Policy, NITI Aayog, April 5, 2017

13. During the year under review, Associate Professor, **Nimmi Kurian** was involved in the following research and allied activities:

Chapters in Edited Volumnes:

i. An Uneven Flow? Navigating Downstream Concerns Over China's Water Policy Nimmi Kurian, Water Conflicts in Northeast India, KJ Joy, Partha J Das, Gorky Chakraborty, Chandan Mahanta, Suhas Paranjape, Shruti Vispute, Routledge, September 20, 2017

Presentation at conferences/Seminars:

i. Book launch and discussion, India and China: Rethinking Borders and Security (co-author), University of Michigan Press, Ann Arbor, 2016 organised by the India China Institute, The New School, New York, 22 May 2017.

ii. Panel discussion on China and South Asia hosted by Michael Kugelman, Wilson Centre, Washington, 25 May 2017.

iii. Academic advisor and discussant of eight research proposal presentations by the China India Scholar-Leaders, India China Institute, The New School, New York, 19-20 May 2017.

iv. 'Unpacking the Rohingya Refugee Crisis', A conversation between Ambassador Shyam Saran and Nimmi Kurian moderated by Srinath Raghavan, Centre for Policy Research, 07 November 2017.

v. Interviewed on the India-China standoff at Doklam, by Luke Vargas for the Wake, a United Nations-based radio programme on foreign affairs, New York, 18 August 2017.

vi. Aiming Low, Hitting Lower? The Subregional Turn in India's Foreign Policy, Public Talk delivered at the Department of International Relations and Resource Governance, Shiv Nadar University, 22 November 2017.

vii. 'Democratising Social Research, Social Science Research' presentation at the Orientation Programme on Social Science Research for Scholars and Lecturers belonging to SC, ST, and other Marginalised Groups, Centre for Policy Research, 1-2 December 2017.

viii. 'Downstream implications of China's dam projects', paper presented at the Calcutta International Dialogue on India-China Relations organised by the Research Centre for East and North East Regional Studies, Kolkata (CENERS-K), 1-3 February 2018.

ix. 'Conversations Beyond the Centre: India's Border Regions as Drivers of the Act East Policy', paper to be presented at the National Seminar on "Border and Connectivity: North-East India and South-East Asia" being organised by the ICSSR North Eastern Regional Centre and the ASEAN Studies Centre (ASC), Shillong, at Mizoram University, Aizawl, on 23rd and 24th March 2018.

x. External Examiner, Viva Voce Board, of R. Veena, 'Harmonizing Xinjiang': Examining China's Ethnic Management Strategy Post-2009', China Studies Centre, Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology Madras, 12 January 2018.

xi. External reviewer of manuscript, 'Transborder people, connected history: Border and relationships in the Indo-Burma borderlands', for the Journal of Borderlands Studies, August 2017.

Policy Briefs and Reports:

i. 'Narendra Modi's Conflicted China Policy', Institute of Asia and Pacific Studies Dialogue, University of Nottingham, 4 September 2017.

ii. 'Doklam: The Game of Shadows', China File, Asia Society, New York, 09 August 2017.

iii. Uncharted Flows: Navigating the Downstream Debate on China's Water Policy, in K. J. Joy et al, Water Conflicts in Northeast India, Routledge, 2017.

iv. 'Addressing the Drought of Ideas on the Brahmaputra', China-India Brief, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, 24 October 2017.

v. 'BCIM Sustainability Dialogue(s): A Network Approach to Capacity Building' in Joshua Thomas and Gurudas Das eds. BCIM: Subregional Cooperation for the Development of Peripheral Areas, Pentagon, 2018.

Articles in Non-reviewed Journals:

i. 'How Suu Kyi Can Change the Rohingya Narrative', *The Diplomatist, Vol. 5, Issue* 11, November 2017.

ii. 'Crossing the Line: The Border as Verb', *Live Encounters*, December 2017.

14. During the year under review, Senior Fellow, **Neelanjan Sircar** was involved in the following research and allied activities:

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. How to win elections, or pick winners, Neelanjan Sircar , HT Syndication Monday, 26 March 2018

ii. Which MPs utilise constituency funds the best?, Neelanjan Sircar , Hindustan Times, Wednesday, 21 February 2018

iii. Education ups attendance of MPs, criminal history lowers it, Neelanjan Sircar , Hindustan Times, Wednesday, 31 January 2018

iv. The inability to move mass leaders up the party ranks has been a problem for the Congress, Ashish Ranjan, Neelanjan Sircar , Hindustan Times, Tuesday, 19 December 2017

v. Its not ideology but aspiration that drives Indias middle classs politicians take note, Devesh Kapur, Neelanjan Sircar, Milan Vaishnav , Quartz, Tuesday, 5 December 2017

vi. Three economists went around India asking: do you call yourself middle class?, Neelanjan Sircar, Devesh Kapur, Milan Vaishnav , The Print, Tuesday, 28 November 2017

Working Paper:

i. Is the BJP in Trouble? Caste, Class, and the Urban-Rural Divide in Gujarat, Ashish Ranjan, Neelanjan Sircar , Wednesday, December 13, 2017

15. During the year under review**,** Senior Fellow**, Partha Mukhopadhyay** was involved in the following research and allied activities:

Working Paper:

i. Engines without Drivers: Cities in India's Growth Story, Partha Mukhopadhyay , March 8, 2018

16. During the year under review, former President and Chief Executive, **Pratap Bhanu Mehta** was involved in the following research and allied activities:

Books:

i. Navigating the Labyrinth: Perspectives on India's Higher Education, Devesh Kapur, Pratap Bhanu Mehta, May 12, 2017

ii. Rethinking Public Institutions in India, Devesh Kapur, Pratap Bhanu Mehta, Milan Vaishnav , May 12, 2017

Chapters in Edited Volumes:

i. The Supreme Court and Indiaâ€™s Judicial System, Madhav Khosla, Ananth Padmanabhan, Rethinking Public Institutions in India, Devesh Kapur, Pratap Bhanu Mehta, Milan Vaishnav , Oxford University Press, , July 25, 2017

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Skimming the shallows, Pratap Bhanu Mehta , *The Indian Express*, Tuesday, 29 August 2017

ii. Small step, no giant leap, Pratap Bhanu Mehta , Indian Express, Wednesday, 23 August 2017

iii. The too late nation, Pratap Bhanu Mehta , Indian Express, Thursday, 17 August 2017

iv. Reading Freedom, Pratap Bhanu Mehta , Indian Express, Monday, 14 August 2017

v. Beyond Jamia, Pratap Bhanu Mehta , *The Indian Express*, Tuesday, 8 August 2017

vi. Old ways die hard, Pratap Bhanu Mehta , *The Indian Express*, Friday, 28 July 2017

vii. Dancing on the edge, Pratap Bhanu Mehta , Indian Express, Wednesday, 26 July 2017

viii. The untimely dissident, Pratap Bhanu Mehta , Indian Express, Monday, 17 July 2017

ix. The fires of Bengal, Pratap Bhanu Mehta , Indian Express, Monday, 10 July 2017

x. May the silent be damned, Pratap Bhanu Mehta , Indian Express, Tuesday, 27 June

xi. Enlarge the frame, Pratap Bhanu Mehta , Indian Express, Friday, 23 June 2017

xii. The power paradox, Pratap Bhanu Mehta , *The Indian Express* Friday, 16 June

xiii. Presstitute chronicles, Pratap Bhanu Mehta , *The Indian Express*, Wednesday, 7 June 2017

xiv. The march to spectacle, Pratap Bhanu Mehta , *The Indian Express*, Monday, 29 May 2017

xv. The Mind of the Saints: Speculations around Ramakrishna Paramhansa and Ramana MaharishiPratap Bhanu Mehta , *The Indian Express*, Monday, 29 May

xvi. On triple talaq, court must say: Religious practice cannot trump modern constitutional morality, Pratap Bhanu Mehta , *The Indian Express*, Thursday, 18 May 2017

xvii. Weak public institutions behind Indiaâ€™s low state capacity Milan Vaishnav, Pratap Bhanu Mehta, Devesh Kapur, Live Mint , Wednesday, 17 May 2017

xviii. Supreme Test, Pratap Bhanu Mehta , *The Indian Express*, Monday, 8 May 2017

xix. Iqbal's wrong turn, Pratap Bhanu Mehta , *The Indian Express*, Wednesday, 19 April 2017

xx. Sinking Valley, Pratap Bhanu Mehta , Indian Express, Tuesday, 18 April 2017

xxi. Itâ€™s about US, not Syria, Pratap Bhanu Mehta , Indian Express, Wednesday, 12 April 2017

Presentation at conferences:

i. Delivered a talk on "Should we have socio economic rights in the constitution" at Advocata Institute, Colombo, 19-24 April 2017

ii. Session at CII, 29 April 2017

iii. Launched event of the book entitled "Rethinking Public Institutions in India at CARNEGIE Endowment for International Peace, Washington, 10 May 2017

iv. Launched event of the book entitled "Rethinking Public Institutions in India at Princeton University, Princeton, NJ, 11 May 2017

v. Delivered a keynote speech at the event on "Broadcasting your career horizons with a master of public policy at the University of Tokyo" at India Habitat Centre, 13 July 2017

17. During the year under review, Senior Visiting Fellow, **Philippe Cullet** was involved in the following research and allied activities:

Books:

i. P. Cullet & S. Koonan eds,, *Water Law in India – An Introduction to Legal Instruments*, Oxford University Press, 2nd ed, 2017, 477p. in June 2017

Journal Articles:

i. P. Cullet, L. Bhullar & S. Koonan, 'Regulating the Interactions between Climate Change and Groundwater: Lessons from India', 42/6 Water International (2017), p. 646-62., August 2017

ii. P. Cullet & R. Stephan, 'Introduction to 'Groundwater and Climate Change – Multi-Level Law and Policy Perspectives', 42/6 Water International (2017), p. 641-45., August 2017.

Chapters in Edited Volumes:

i. P. Cullet, 'The Right to Water in Rural India and Drinking Water Policy Reforms', in Malcolm Langford and Anna F.S. Russell eds, *The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), p. 675-91.

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. P. Cullet, 'A Gathering Crisis: The Need for Groundwater Regulation', The Hindu, , p. 8., 8 August 2017

ii. P. Cullet, 'India's ambitious plans to achieve sanitation for all must look beyond building individual toilets', The Independent, 10 October 2017

Sitting on Task Forces and Working Papers:

i. Committee to Redraft the Draft Model Bill for Conservation Protection and Regulation of Ground Water, 2011 (revived in July 2017), Member, July-August 2017

18. During the year under review, Senior Visiting Fellow, Olivier Telle was involved in the following research and allied activities:

Presentation at Seminars and Conferences:

i. Gis ASIE, The contour of cities in Asia, Paris Sciences po, GIS ASIE, 26 June 2017

ii. Urb-endemic, Paris Sorbonne, 28 and 29 June 2017

iii. Emerging Infectious Diseases in a City: Dengue and Chikungunya NIPFP in Delhi

iv. Ecomore 2: Economic change and impact on health Diffusion of dengue in Vientiane, Laos, Vientiane, Laos, 10 March 2018

v. Emergent forms of urban densification in Asia: shared perspective Urbanisation: what matter for infectious diseases in Vietnam and India, Hanoi, Vietnam, 20 November 2017

vi. New opportunities in controlling vector-borne diseases: Big data, new insecticides and governance in urban India, MCD, WHO Asia, WHO India, NIMR, Organizer (CSH Delhi) 26 February 2018

Articles in Non-reviewed Journals:

i. Emerging infectious diseases in India: the scourge that could boost urban development , The Conversation, 17 April 2018

Sitting on Task Forces and Policy Advisory Committees:

i. Dengue task Force, Adviser, Municipality of Delhi. February 2018

ii. Infectious disease and global change, Adviser, Municipality of Vientiane, Lao Health ministry, March 2018

Targeted Meeting with Policy Makers:

i. Dengue project in Delhi, WHO Asean

ii. Anti microbiotic resistance in India, WHO Asean

19. During the year under review, Fellow, **Radhika Khosla** was involved in the following research and allied activities:

Policy Briefs and Reports:

i. Mainstreaming climate action in Indian cities: Case study of Rajkot, Ankit Bhardwaj, 1 September 2017

ii. Plugging In: A collection of insights on electricity use in Indian homes, Aditya Chunekar, 29 December 2017

Working Paper:

i. India's Energy and Emissions Future: A Synthesis of Recent Scenarios, Navroz Dubash, Narsimha Rao, Ankit Bhardwaj, 11 September 2017

ii. Mainstreaming Climate Actions in Indian Cities: Case Study of Rajkot, Ankit Bhardwaj, September 2017

Web-based Publications:

i. Plugging in: Electricity Consumption in Indian Homes, Aditya Junekar, CPR India website, 31 October 2017

ii. Plugging In: Illuminating Affordable Homes Ankit Bhardwaj, CPR India website, 21 November 2017

iii. Plugging In: Appliances used in Affordable Housing, Ankit Bhardwaj, CPR India website, 6 December 2017

iv. Plugging In: Electrifying the National Capital Region, Ankit Bhardwaj, CPR India website, 13 December 2017

v. Plugging In: Role of human behaviour in driving electricity use, Ankit Bhardwaj, CPR India website, 27 December 2017

Presentation at Conferences and Seminars:

i. Cities and Climate Conference 2017, Postdam , "We are greener than you think" - An Indian city's response to climate change, Postdam (Germany), Project RAMSES, September 19-21 2017

20. During the year under review**,** Associate Professor, **Rajshree Chandra** was involved in the following research and allied activities:

Article in Non-Reviewed Periodicals:

i. Delhi University Can No Longer Turn a Blind Eye to Systemic Flaws Dragging the Institution Down, The Wire, 9 Nov 2017

ii. Law and Immunity, Indian Express, 24 Oct 2017

iii. We Need an Anti-SLAPP Law To Encourage and Protect Free Press, The Wire, 12 Oct, 2017

iv. Why We Need to Be Wary of the Political Centrists, The Wire, 14 August, 2017

v. GM Mustard about to be approved for use: 10 facts that ought to worry you,, Catch News, May 24, 2017

vi. Saffron Blind, Indian Express, 25 April 2017

vii. Free Speech on Social Media May Not Be Civil But Let Us Not Use the Law to Curb It, The Wire, 19 Apr 2017

viii. Why Forest Rights Matter. Indian Express. 17 March 2018 , - By The People.

ix. Review Article of Ornit Shani's book, How India Become Democratic. 9 March, 2018.

x. Understanding the Ratio of Malice to Legality in the AAP MLAs Disqualification Case. The Wire. 22 Jan, 2018

xi. The Ultimate Insider, Review Article of The Coalition Years, Pranab Mukherjee (Rupa 2016) Pioneer. 24 Dec 2017

xii. Law and immunity, Indian Express. 24 Oct 2017

xiii. We Need an Anti-SLAPP Law To Encourage and Protect Free Press, The Wire. 12 October, 2017

Paper presented for Presentations/Seminars:

i. Law Society Association Forest Rights: Notes on an Alternative agenda for Property, Mexico City, Law Society Associaiton, 20 June 2017

21. During the year under review, Senior Fellow**, Ramesh Chandran** was involved in the following research and allied activities:

Targeted Meeting with Policymakers:

i. 2017 Princeton – GPPI-CPR Strategic Affairs Programme for Indian Parliamentarians, Academic Programme for Indian MPs at the Woodrow Wilson School of Public & International Affairs , April 30 – May 5, 2017

ii. Indian MPs' Delegation Visit to Australia, Academic Programme for Indian MPs in Collaboration with Australia Foreign Office, June 17 – 26, 2017

iii. Interactive Discussion on Prioritising Child Health and Nutrition in India, Parliamentarians and Field Experts, 2 August, 2017

iv. 2017 Princeton – GPPI-CPR Strategic Affairs Programme for Indian Parliamentarians, Academic Programme for Indian MPs at the Woodrow Wilson School of Public & International Affairs , April 30 – May 5, 2017

v. Indian MPs' Delegation Visit to Australia, Academic Programme for Indian MPs in Collaboration with Australia Foreign Office, June 17 – 26, 2017

vi. Interactive Discussion on Prioritising Child Health and Nutrition in India, Parliamentarians and Field Experts, 2 August, 2017

vii. 2017 Chevening CPR Parliamentarians Fellowship Programme for Indian leaders,, Annual Academic Programme with Chevening Programme, UK, held at the London School of Economics, October 29-November 4, 2017

viii. Interactive discussion on Technology & Governance: Aadhaar Privacy Concerns & Database Security, Parliamentarians and Field Experts, March 12, 2018

ix. Roundtable Discussion on Health Commitments Made in the Union Budget 2018, Parliamentarians and Field Experts, March 21, 2018

22. During the year under review, Associate Professor**, Rani Mullen** was involved in the following research and allied activities:

Policy Briefs:

i. India-Bangladesh Development Partnership: Extension of a US $4.5 Billion by India Towards its Eastern Neighbour, 25 October 2017

ii. South-South Development Cooperation: Analysis of India and China's Model of Development Cooperation Abroad, 21 December 2017

23. During the year under review, Senior Fellow, **D Shyam Babu** was involved in the following research and allied activities:

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. “A Solution in Search of a Problem”, The Hindu, 27 April 2017

ii. “Beyond the Language Conflict: The Need for a Clear Language Policy” , The Hindu, 30 May 2017

iii. “Reappraising the Raj” , The Hindu, 12 September 2017

iv. “Birth Pangs of a New Federal Polity”, The Hindu, 28 March 2018

Sitting on Task Force and Working Groups:

i. CII Committee on Affirmative Action, Member, Continuing since 2007

24. During the year under review, Senior Fellow, Shyam Saran was involved in the following research and allied activities:

Books:

i. How India Sees the World: Kautilya to the 21st Century , Shyam Saran, Wednesday, 20 September 2017

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Powering India's growth story, Shyam Saran , Business Standard, Friday, 16 March

ii. India must lead the charge in preserving threatened ecology Shyam Saran Hindustan Times, Thursday, 8 March 2018

iii. Enter the Dragon, Shyam Saran , India Today, Saturday, 17 February 2018

iv. India-Asean ties: A cup half full?, Shyam Saran , Hindustan Times, Wednesday, 24 January 2018

v. Our Time Has Comeâ€™: Alyssa Ayresâ€™s chronicle of Indiaâ€™s rise to global prominence, Shyam Saran , The Print, Thursday, 11 January

vi. Time to reaffirm the Constitution of India, Shyam Saran, Business Standard, Wednesday, 10 January 2018

vii. Options will multiply; so will the challenges, Shyam Saran , Business Standard Thursday, 4 January 2018

viii. In 2018, India must balance the demands of the neighbourhood against the compulsions of a global role, Shyam Saran , Hindustan Times, Wednesday, 27 December 2017

ix. Babri recall: A million mutinies, Shyam Saran, Business Standard, Wednesday, 13 December 2017

x. The Quadrilateral: Is it an alliance or an alignment?, Shyam Saran , Hindustan Times, Tuesday, 28 November 2017

xi. In the footsteps of the 'Indian trader' who found Petra, Shyam Saran , Rediff.com, Wednesday, 22 November 2017

xii. Events versus processes, Shyam Saran , Business Standard, Wednesday, 8 November 2017

xiii. Inside Petra, the lost city of stone, Shyam Saran , Business Standard Monday, 30 October 2017

xiv. US in the crosshairs: Whyâ€‰a crisis is looming over the Korean peninsula, Shyam Saran , Hindustan Times, Thursday, 26 October 2017

xv. The shifting sands of West Asia & the Gulf, Shyam Saran , Business Standard, Wednesday, 11 October 2017

xvi. The frenemies within, Shyam Saran , Business Standard, Thursday, 28 September 2017

xvii. The flavours of Tibet, Shyam Saran, Business Standard, Monday, 25 September 2017

xviii. Stand-off with China may have ended but there could be more Doklams, Shyam Saran , Times of India, Monday, 18 September 2017

xix. Diplomacy in the age of Twitter, Shyam Saran , Business Standard, Wednesday, 13 September 2017

xx. Doklamâ€™s Big Picture: Neither Asia nor the World is China-Centric, Shyam Saran The Quint, Tuesday, 29 August 2017

xxi. India's destiny and the US-Pakistan embrace, Shyam Saran , Business Standard, Monday, 14 August 2017

xxii. Factional infighting sharpens in China, Shyam Saran , Business Standard, Wednesday, 9 August 2017

xxiii. Doklam standoff: Develop good ties with South Asian neighbours to counter China, Shyam Saran , Hindustan Times, Friday, 28 July 2017

xxiv. Why India must push back against Chinaâ€™s claims of being Asiaâ€™s natural leader, Shyam Saran , Scroll.in, Friday, 28 July 2017

xxv. China, US and manifest destinies, Shyam Saran , Business Standard, Thursday, 20 July 2017

xxvi. India closing the door to their citizens suits Pakistan Shyam Saran National Herald, Tuesday, 18 July 2017

xxvii. The standoff in Doklam, Shyam Saran , The Tribune, Tuesday, 4 July 2017

xxviii. Read between the US lines, Shyam Saran , Indian Express, Thursday, 29 June 2017

xxix. Renminbi's growing global influence, Shyam Saran , Business Standard, Friday, 16 June 2017

xxx. Is There A Need For A Paris Agreement Between Governments And Citizens? Shyam Saran United Nations India Friday, 16 June 2017 - 12:48pm

xxxi. The road from St. Petersburg, Shyam Saran , The Hindu, Tuesday, 13 June 2017

xxxii. On Climate Change, the United States Needs to Be Isolated, Not Appeased, Shyam Saran , The Wire, Monday, 5 June 2017

xxxiii. In Year Four, Modiâ€™s Foreign Policy Needs Some Course Correction Shyam Saran The Wire, Monday, 29 May 2017

xxxiv. The ancient Indian myth that could save our oceans, Shyam Saran , Rediff.com, Monday, 22 May 2017

xxxv. Looking China in the eye, Shyam Saran , *The Indian Express*, Monday, 22 May 2017

xxxvi. Listen to what the ocean is saying, Shyam Saran , Business Standard, Thursday, 11 May 2017

xxxvii. Nepalâ€™s history, revised, Shyam Saran , *The Indian Express*, Friday, 5 May 2017

xxxviii. Democracy, pluralism and cosmopolitanism can put India in a leading role in a multipolar world, Shyam Saran , Hindustan Times, Thursday, 4 May 2017

xxxix. Trapped between two Indias, Shyam Saran, Rediff.com, Friday, 21 April 2017

xl. Shaping India's future Shyam Saran , Business Standard, Wednesday, 12 April 2017

25. During the year under review, Fellow, **Srinivas Chokkakula** was involved in the following research and allied activities:

Monographs:

i. Why do interstate water disputes emerge and recur?, Srinivas Chokkakula, Thursday, January 4, 2018

Journal Article:

i. Review: Transboundary Water Politics in the Developing World, by Naho Mirumachi, Thursday, October 5, 2017

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Parting the waters, Srinivas Chokkakula , *The Indian Express*, Monday, 19 February 2018

ii. Mahadayi issue demonstrates why India needs a GST Council-like forum for river governance , Srinivas Chokkakula , The Economic Times, Monday, 12 February 2018

iii. Testing waters Srinivas Chokkakula, The Hindu, Thursday, 1 February 2018

iv. Kosi River and the (un)making of a disaster, Srinivas Chokkakula , Asia and the Pacific Policy SocietyThursday, 5 October

v. Telangana: born of historic fissures, Srinivas Chokkakula , Gateway House, Thursday, 21 September 2017

vi. Resolve water disputes politically, Srinivas Chokkakula , Hindu Business Line, Thursday, 21 September 2017

vii. Without Better Interstate Coordination, the Cauvery Dispute Will Continue to Simmer, Srinivas Chokkakula , The Wire ,Thursday, 21 September 2017

viii. Why interstate water disputes are difficult to manage or control, Srinivas Chokkakula , Economic Times, Thursday, 21 September 2017

ix. A stronger river referee, Srinivas Chokkakula , Indian Express, Monday, 24 July 2017

26. During the year under review, Senior Fellow, **Srinath Raghavan** was involved in the following research and allied activities: (Take outputs from sheet)

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Revisiting the 1946 Royal Indian Navy mutiny, Mint, 3 April 2017

ii. Our historians have scant interest in wars or soldiers, Hindustan Times, 27 April 2017

iii. South Asia’s missing intra-regional trade, Mint, 1 May 2017

iv. Defence policy has to be a joint effort between civilians and the military , Hindustan Times, 11 May 2017

v. There are no decent options in Afghanistan, Mint, 29 May 2017

vi. Why private defence manufacturing in India needs to take off, Hindustan Times, 12 June 2017

vii. The evolution of American hegemony, Mint, 12 June 2017

viii. Sheikh Hasina's hate statues can only weaken democracy in Bangladesh, Hindustan Times, 21 June 2017

ix. Towards deciphering BJP's hegemonic project , Mint, 27 June 2017

x. Sikkim standoff: India cannot afford to allow China to change the status quo , Hindustan Times, 6 July 2017

xi. Needed: A mutual restraint pact with China, Mint, 10 July 2017

xii. Kashmir's Article 35A conundrum: New Delhi must tread carefully, Hindustan Times, 4 August 2017

xiii. China is wrong on Sikkim-Tibet boundary, Mint, 7 August 2017

xiv. How armed forces can aid defence manufacturing in India, Mint, 21 August 2017

xv. Beware of the wrong lessons from Doklam, Mint, 4 September 2017

xvi. History's verdict on the Russian Revolution, Mint, 18 September 2017

xvii. Towards a less-restrained China, Mint, 30 October 2017

xviii. India-China: a zero-sum rivalry?, Seminar, 31 January 2018

xix. Army chief Rawat's statements ahistorical, poorly judged, Hindustan Times, 23 February 2018

xx. The 56-Inch Fist, The Telegraph , 11 March 2018

Presentations at Conferences and Seminars:

i. The 1970s: Australian and Indian Perspectives on a Decade of Transition, Australia, Deakin University, May 2017

27**.** During the year under review, Senior Fellow, **Shubhagato Dasgupta** was involved in the following research and allied activities:

Policy Briefs:

i. Towards a New Research and Policy Paradigm: An Analysis of the Sanitation Situation in Large Dense Villages, Shamindra Roy, Aditya Bhol, Deepti Raj, 17 November 2017

Presentation at Conferences and Seminars:

i. ISAS-CPR Panel Discussion on 'The Clean India Mission: Challenges and Prospects', From Taboo to Totem: Continuing Misadventures of Sanitation Policy in India, Singapore, Institute of South Asian Studies (ISAS), National University of Singapore, 30 October 2017

ii. Sustainable Sanitation : from evidence to practice, Towards a Swachh Bharat beyond the Swachh Bharat Mission, New Delhi, Centre for Policy Research, 12 December 2017

Sitting on task forces and committee groups:

i. Member, Urban Flooding Expert Group, NDMA, Government of India, Expert Member, March 2017 onwards

28**.** During the year under review, Senior Fellow, **Shibhani Ghosh** was involved in the following research and allied activities:

Presentation at Conferences and Seminars:

1. FLS Seminar Series, Climate Litigation in India, South Asian University, 18 April 2017, New Delhi
2. National Conference on Air and Water Pollution , Legal Framework for Pollution Regulation in India, NITI Aayog and EPIC-India, 7 July 2017, New Delhi, India
3. Training Programme on 'Environmental Legislations, Interpretation, Enforcement, Legal and Statutory Requirements', National Green Tribunal – Practice and Procedure, Haryana Institute of Public Administration, Gurgaon, Haryana, 23 August 2017
4. Right to Information Learning Programme in India for civil society and media representatives from Kenya , Using the RTI Act for Environmental Protection in India, Commonwealth Foundation's Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI),New Delhi, India, 3 September 2017

Presentation at Roundtables and Conferences:

1. Roundtable Discussion on Environmental Regulation in India, Vidhi Centre For Legal Policy, 20 September 2017, New Delhi, India
2. Workshop For PhD Research Scholars on Resource Rights, Governance and Jurisprudence , Environmental Regulation in India , Mumbai, TISS, 9th December 2017

29**.** During the year under review, Senior Fellow, **Shylashri Shankar** was involved in the following research and allied activities:

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Everyone Loves a Good Serial Killer, Shylashri Shankar , Open Magazine, Tuesday, 26 December 2017

ii. The Tastemakers Trend, Shylashri Shankar , Open Magazine, Tuesday, 27 June 2017

iii. And Then There Were None, Shylashri Shankar , Open Magazine, Monday, 12 June 2017

iv. The Genealogy of Taste, Shylashri Shankar , Open Magazine, Tuesday, 30 May 2017

v. Mysterious Minds, Shylashri Shankar , Open Magazine, Monday, 1 May

vi. Hindus and Sacred Cows: Recipe for Indentity Politics, Shylashri Shankar , Open Magazine, Monday, 24 April

30. During the year under review, Senior Fellow, **Zorawar Daulet Singh** was involved in the following research and allied activities:

Journal Articles:

i. Locating the Belt and Road in Chinaâ€™s Broader Policy Shifts Saturday, June 24, 2017, Zorawar Daulet Singh

Articles in Non-Reviewed Periodicals:

i. Call to democracy, Zorawar Daulet Singh , The Hindu, Thursday, 8 February 2018

ii. The puzzle of the 1972 Shimla summit, or why India did not impose its will, Zorawar Daulet Singh , The Wire, Thursday, 23 November

iii. US And China Will Avoid A â€˜Thucydides Trapâ€™, Zorawar Daulet Singh . Outlook Magazine, Friday, 25 August 2017

iv. Game of chicken in the high Himalayas, Zorawar Daulet Singh , The Hindu, Thursday, 13 July 2017

v. A great wall of paranoia, Zorawar Daulet Singh , The Hindu, Thursday, 18 May 2017

ACTIVITIES OF RESEARCH ASSOCIATES

The Research Associates of CPR were involved in the following research and allied activities during the year 2017-18

1. Aditya Bhol, Research Associate

Working Paper:

i. Horizontal and Vertical Inequalities Explaining Disparities in Access to Urban Sanitation: Evidence from the National Sample Survey of India, 17th May, 2017

Policy Briefs and Research Reports:

i. Towards a new research & policy paradigm. An analysis of the sanitation situation in Large Dense Villages, Shubhagato Dasgupta, Shamindra, Deepti Raj , November 2017

Paper Submitted for Presentation at Conferences:

i. Population Association of America Annual Meeting Horizontal and Vertical Inequalities Explaining Disparities in Access to Urban Sanitation: Evidence from the National Sample Survey of India, Chicago, Illinois, Population Association of America, 28th April 2017

Presentation at Round Tables Conferences:

i. Horizontal and Vertical Inequalities Explaining Disparities in Access to Urban Sanitation: Evidence from the National Sample Survey of India, CPR, New Delhi, May 2017

Sitting On Task Forces and Working Groups/Policy Advisory Committees

i. City Sanitation Planning & annual rolling plan discussion at Balasore with ULB officials, Advisor, Dec 2017
ii. Trainers programme on capacity building on non-sewered sanitation for 2 Amrut towns & 2 towns (Angul & Dhenkanal) Trainer, 23 November 2017

Awards and other achievements:

i. PAA Travel Award and Membership, Population Association of America, Chicago, April 2017

2. Ankit Bhardwaj, Research Associate

Policy briefs and Research reports:

i. Mainstreaming climate action in Indian cities: Case study of Rajkot, Radhika Khosla, 1 September 2017

Articles in Non-reviewed Periodicals:

i. Can Indian cities lead on climate action as they go about their development goals?, Radhika Khosla, Scroll.in, 28 June 2017

Paper submitted for Presentation at Conferences:

i. Cities and Climate Conference 2017, "We are greener than you think", September, Potsdam, Germany, RAMSES
ii. Indo-German Smart Initiative Urban Lab , Integrated approaches in Indian Cities, July, Delhi, Indo-German Smart Initiative
iii. Capa CITIES Climate Action Plan Workshop, Multi-objective approach to climate planning, July, Coimbatore, ICLEI SA

3. Anju Dwivedi, Senior Research Associate

Policy Briefs and Research Reports:

i. Capacity Building Strategy for Urban Local Bodies And State Government On Sanitation: Odisha, Padmaja Nair, 24 January 2018
ii. Improving Urban Sanitation in India: Lessons from Malaysia, Amandeep Sing, 16 June 2017
iii. Capacity Building Need Assessment of Cities (Angul and Dhenkanal) and State Government on Sanitation: A Case Study of Odisha, Padmaja Nair 16 January 2018

Sitting on Task Forces and Working Committees:

i. City Sanitation Planning & annual rolling plan discussion at Balasore with ULB officials, Advisor Dec 2017
ii. Trainers programme on capacity building on non-sewered sanitation for 2 Amrut towns & 2 towns (Angul & Dhenkanal) Trainer23 November 2017

Targeted Meeting with Policy Makers:

i. Meeting on last year plan of the project Nirmal in Angul and Dhenkanal and plan for O & M plan for Dhenkanal Secretary, HUDD, officials from OSSB, TSU, 18 May 2018
ii. Meeting on last year of project support and O&M plan of Dhenkanal DC, Dhenkanal with EO,Chairperson and other district officials, 6 June 2018
iii. Meeting on Capacity Building Modules on Non Sewered Sanitation Officials from HUDD, OWSSB, TSU, Practical Action, SBM PMU officials, 5 July 2017
iv. Meeting on final CB modules on Non Sewered Sanitation , Secretary HUDD, TSU, OWSSB, 10 October 2017

4. Ambarish Karunanithi, Senior Research Associate

Sitting on Task Forces and Working Groups:

i. City Sanitation Planning & annual rolling plan discussion at Balasore with ULB officials, Advisor, 22 and 23 Decemeber 2017
ii. Trainers programme on capacity building on non-sewered sanitation for 2 Amrut towns & 2 towns (Angul & Dhenkanal), Trainer, 23 November 2017

Targeted Meeting with Policymakers:

i. Meeting on last year plan of the project Nirmal in Angul and Dhenkanal and plan for O & M plan for Dhenkanal, Secretary, HUDD, and officials from OWSSB, TSU, 18 May 2018
ii. Meeting on last year of project support and O&M plan of Dhenkanal DC, Dhenkanal with EO,Chairperson and other district officials, 6 June 2018
iii. Meeting on Capacity Building Modules on Non Sewered Sanitation Officials from HUDD, OWSSB, TSU, Practical Action, SBM PMU officials, 5 July 2017
iv. Meeting on final CB modules on Non Sewered Sanitation , Secretary HUDD, TSU, OWSSB, 10 October 2017

5. Ankit Bhatia, Research Associate

Research Report:

i. The Legal Regime and Political Economy of Land Rights Of Scheduled Tribes in the Scheduled Areas of India, Namita Wahi, Ankit Bhatia, March 15, 2018

6. Ashwin Parulkar, Senior Research Associate

Books:

i. Dispossessed: Stories from India's Margins, Amod Shah, Anhad Imaan, Annie Baxi, Ashwin Parulkar, Rhea John, Saba Sharma, Shikha Sethia, January 4, 2018

Articles in non-reviewed periodicals:

i. The government must compensate for the demonetisation setback to migrants mobility, Mukta Naik, Eesha Kunduri, Ashwin Parulkar , Hindustan Times, 17 January 2017

Working paper:

i. Becoming Homeless, Surviving Homelessness, Ashwin Parulkar , April 21, 2017

7. Debayan Gupta, Research Associate

Working Paper:

i. Mapping dilutions in India’s 2013 Land Acquisition Law- Occasional Paper, Kanchi Kohli and Debayan Gupta, 25 September 2017

Web-based Publications:

i. Proposed Amendments to Environment Protection Act Could Legalise Violations, Manju Menon, Kanchi Kohli, Krithika Dinesh and Debayen Gupta, The Wire, 2 August 2017
ii. In State-Level Changes to Land Laws, a Return to Land Grabbing in Development’s Name, Manju Menon, Kanchi Kohli and Debayen Gupta, The Wire, 9 September 2017

8. Deepti Raj, Research Associate

Policy brief:

i. Towards a New Research and Policy Paradigm: An Analysis of the Sanitation Situation in Large Dense Villages, Shubhagato Dasgupta, Shamindra Nath Roy, Aditya Bhol, Deepti Raj, November 17, 2017

9. Devashish Deshpande, Research Associate

Articles in non-reviewed periodicals:

i. Stumbling towards sustainable sanitation, Avani Kapur, Devashish Deshpande , Mint , 24 January 2018

Policy brief:

i. Budget Brief 2018-19: Swachh Bharat Mission - Urban (SBM-U) Devashish Deshpande, Avani Kapur, February 3, 2018
ii. Budget Brief 2018-19:Swachh Bharat Mission- Gramin (SBM-G), Avani Kapur, Devashish Deshpande, February 3, 2018
iii. Budget Brief 2018-19: Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS) Devashish Deshpande, Avani Kapur, February 3, 2018

10. Eesha Kunduri, Research Associate

Policy Briefs:

i. Youth in India: Prospects and Challenges, Bhanu Joshi, 1 July 2017

Presentation at Conferences and Seminars:

i. Social Change Seminar Series, Between 'khet,' 'factory' and 'colony': Exploring intersections of caste and gender among migrant industrial workers, Delhi, CPR, , 28 June 2017
ii. Authors' workshop, Handbook on Internal Migration in India (SHRAMIC Project), City lights or longing for home: Understanding migration decisions to the city of Delhi, Mumbai, IGIDR, July 10, 2017
iii. UJ Sociology, Anthropology and Development Studies Wednesday Seminar, Caste, gender and the (re)shaping of migrant identities: Insights from two Indian cities, Johannesburg, University of Johannesburg (Faculty of Humanities), November 1, 2017

11. Kanhu Charan Pradhan, Senior Research Associate

Journal articles:

i. Only 'Good People', Please: Residential Segregation in Urbanising India, Trina Vithayathil, Gayatri Singh, Kanhu Charan Pradhan, March 8, 2017

Articles in non-reviewed periodicals:

i. Beyond large cities, understanding census towns in India, Kanhu Charan Pradhan , My Digital FC, 4 January 2018

12. Krithika Dinesh, Research Associate

Working Paper:

i. From Prior to Post: Legalising environmental violations, Krithika Dinesh and Kanchi Kohli, July 2017

Web-based Publication:

i. Anatomy of legalising violations: Environment Ministry's policy of post facto approvals, Krithika Dinesh and Kanchi Kohli, Counterview, July 2017
ii. Proposed Amendments to Environment Protection Act Could Legalise Violations, Manju Menon, Kanchi Kohli, Krithika Dinesh and Debayen Gupta, The Wire, August 2017
iii. India's coastal law is being altered in public interest – by bypassing the public Meenakshi Kapoor and Krithika Dinesh, Scroll, October 2017
iv. Upholding World Bank's Immunity in Case Against Gujarat Fishermen Will Have Long-Term Ramifications, Debayan Gupta, Krithika Dinesh, Manju Menon And Kanchi Kohli , The Wire, November 2017
v. Upholding World Bank's Immunity in Case Against Gujarat Fishermen Will Have Long-Term Ramifications, Debayan Gupta, Krithika Dinesh, Manju Menon And Kanchi Kohli , The Wire, November 2017

13. Kashyap Arora, Research Associate

Policy Briefs:

i. India-Bangladesh Development Partnership: Extension of a US $4.5 Billion by India Towards its Eastern Neighbour, Dr. Rani D. Mullen, October 25, 2017
ii. South-South Development Cooperation: Analysis of India and China's Model of Development Cooperation Abroad, Dr. Rani D. Mullen December 21, 2017

Web-based Publications:

i. Measuring inclusivity, Economics of Everything website, 26 November, 2017
ii. Measuring inclusivity in India, Economics of Everything website, 16 December, 2017

14. Madhura Joshi, Senior Research Associate

Presentations at round table conferences:

i. National Consultation on Political Economy of Gender and Energy, New Delhi, M.S. Swaminathan Research Foundation, 1 November, 2017

15. Manish, Research Associate

Articles in non-reviewed periodicals:

i. Despite RERA, Centre and states not doing enough to protect home buyers, Manish , Hindustan Times, 23 August 2017

16. Meghna Srivastava, Research Associate

Targeted meeting with policy makers:

i. Interactive discussion on Technology & Governance: Aadhaar Privacy Concerns & Database Security, Parliamentarians and Field Experts, March 12, 2018
ii. Roundtable Discussion on Health Commitments Made in the Union Budget 2018, Parliamentarians and Field Experts, March 21, 2018
iii. 2017 Princeton – GPPI-CPR Strategic Affairs Programme for Indian Parliamentarians, Academic Programme for Indian MPs at the Woodrow Wilson School of Public & International Affairs, April 30 – May 5, 2017
iv. Indian MPs' Delegation Visit to Australia, Academic Programme for Indian MPs in Collaboration with Australia Foreign Office, June 17 – 26, 2017
v. Interactive Discussion on Prioritising Child Health and Nutrition in India, Parliamentarians and Field Experts, 2 August, 2017
vi. 2017 Chevening-CPR Parliamentarians Fellowship Programme for Indian leaders, Annual Academic Programme with Chevening Programme, UK, held at the London School of Economics, October 29-November 4, 2017
vii. 2017 Princeton – GPPI-CPR Strategic Affairs Programme for Indian Parliamentarians, Academic Programme for Indian MPs at the Woodrow Wilson School of Public & International Affairs, April 30 – May 5, 2017
viii. Indian MPs' Delegation Visit to Australia, Academic Programme for Indian MPs in Collaboration with Australia Foreign Office, June 17 – 26, 2017
ix. Interactive Discussion on Prioritising Child Health and Nutrition in India, Parliamentarians and Field Experts, 2 August, 2017

17. Mukta Naik, Senior Research Associate

Journal articles:

i. An Analysis of 'Migrant-intensity' in India and Indonesia, Gregory F Randolph, Environment and Urbanisation Asia, Vol 8 Issue I, 8 March 2017
ii. Giving Migrants Their Due, Partha Mukhopadhyay, Shelter (HUDCO-HSMI), Vol 18 No , October 2017
iii. On the Importance of Triangulating Data Sets to Examine Indians on the Move, S Chandrasekhar, Shamindra Nath Roy, Economic and Political Weekly, Vol 52 no 47, November 2017

Chapters in edited volumes:

i. Of agency, participation and design: Two contrasting play scenarios in Indian cities , How to Grow a Playspace: Development and Design, Katherine Masiulanis, Elizabeth Cummins, Routledge, Taylor and Francis, March 2017

Policy briefs:

i. Migrants in construction work: Evaluating their welfare framework, Shamindra Nath Roy, Manish , June 2017

Working paper:

i. On the Importance of Triangulating Data Sets to Examine Indians on the Move, S Chandrasekhar, Shamindra Nath Roy, November 2017

Articles in non-reviewed periodicals:

i. The government must compensate for the demonetisation setback to migrants' mobility, Eesha Kunduri, Ashwin Parulkar, Hindustan Times, January 2017

Presentation at conferences:

i. Emergent forms of urban densification in Asia: Shared perspectives , Rental housing as a coping strategy in urban villages' transformation: A comparative study of Phu Dien Village, Vietnam and Sikanderpur Ghosi Village, Gurgaon, India, Hanoi, Vietnam CEPED and Hanoi Architectural University, November 2017
ii. Monthly Seminar Series at CESSMA, IRD, Paris, France Destruction and remaking of commons in Gurgaon: The casualties of a rural to urban transition, Paris, France, CESSMA, IRD, Paris, France, 5 October 2017

Sitting on task forces and working groups:

i. Expert Group for Revision of the National Urban Housing and Habitat Policy, Member, August 2017

18. Mridusmita, Senior Researcher Associate

Policy briefs:

i. Budget Brief 2018-19: Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) Avani Kapur, Mridusmita Bordoloi, & Ritwik Shukla 1st February, 2018
ii. Budget Brief 2018-19: Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Avani Kapur, Mridusmita Bordoloi, & Ritwik Shukla, 1st February, 2018

Presentation at conferences:

i. International Policy Forum on using open school data to combat corruption, UNESCO-IIEP, Use of Open School Data for Improving Accountability and Transparency in Public Education in India, Manila, Phillipines UNESCO-IIEP, 24th to 26th January, 2018

Targeted meeting with policy makers:

i. Exploring potential collaboration with NCERT, Head, Survey Division, February, 2018

19. Sama Khan, Research Associate

Chapters in Edited Volumes:

i. The Other Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission: What Does It Mean for Small Town India?, Sama Khan, Subaltern Urbanisation in India, Eric Denis and Marie-Helene Zerah, Springer, April, 2017

Articles in non-reviewed periodicals:

i. For Swachh India, focus on solid waste management, Hindustan Times, 4 October 2017

20. Stanzin Yumchen, Research Associate

Targeted meeting with policy makers:

i. Interactive discussion on Technology & Governance: Aadhaar Privacy Concerns & Database Security, Parliamentarians and Field Experts, March 12, 2018
ii. Roundtable Discussion on Health Commitments Made in the Union Budget 2018, Parliamentarians and Field Experts, March 21, 2018
iii. 2017 Princeton – GPPI-CPR Strategic Affairs Programme for Indian Parliamentarians, Academic Programme for Indian MPs at the Woodrow Wilson School of Public & International Affairs, April 30 – May 5, 2017
iv. Indian MPs' Delegation Visit to Australia, Academic Programme for Indian MPs in Collaboration with Australia Foreign Office, June 17 – 26, 2017
v. Interactive Discussion on Prioritising Child Health and Nutrition in India, Parliamentarians and Field Experts, 2 August, 2017
vi. 2017 Chevening-CPR Parliamentarians Fellowship Programme for Indian leaders, Annual Academic Programme with Chevening Programme, UK, held at the London School of Economics, October 29-November 4, 2017
vii. 2017 Princeton – GPPI-CPR Strategic Affairs Programme for Indian Parliamentarians, Academic Programme for Indian MPs at the Woodrow Wilson School of Public & International Affairs, April 30 – May 5, 2017
viii. Indian MPs' Delegation Visit to Australia, Academic Programme for Indian MPs in Collaboration with Australia Foreign Office, June 17 – 26, 2017
ix. Interactive Discussion on Prioritising Child Health and Nutrition in India, Parliamentarians and Field Experts, 2 August, 2017

21. Kimberly Noronha

Policy brief:

i. Manual Scavenging in India: A Literature Review & Annotated Bibliography, Kimberly M Noronha, Tripti Singh, Mahima Malik, March 19, 2018

22. Persis Taraporevala, Research Associate

Articles in non-reviewed periodicals:

i. To succeed, citizens must have more say in the Smart Cities Mission, Persis Taraporevala, Bhanu Joshi , HIndustan Times, 22 August 2016

23. Bhanu Joshi, Research Associate

Articles in non-reviewed periodicals:

ii. Bywords in Bundelkhand, Neelanjan Sircar, Bhanu Joshi, Ashish Ranjan , The Hindu , 28 February 2017

iii. To succeed, citizens must have more say in the Smart Cities Mission, Persis Taraporevala, Bhanu Joshi , HIndustan Times, 22 August 2016

Policy briefs:

i. Youth in India: Prospects and Challenges, Bhanu Joshi, Eesha Kunduri, July 1, 2017

24. Shamindra Nath Roy, Research Associate

Journal articles:

i. On the Importance of Triangulating Data Sets to Examine Indians on the Move, S.Chandrasekhar, Mukta Naik, Economic and Political WeeklyVol: 52, Issue: 57, 25 Nov, 2017

Policy briefs:

i. Towards a New Research and Policy Paradigm: An Analysis of the Sanitation Situation in Large Dense Villages, Shubhagato Dasgupta, Aditya Bhol, Deepti Raj, 17 November 2017

Working paper:

i. On the importance of triangulating datasets to examine Indians on the move, S.Chandrasekhar, Mukta Naik, 24 November 2017

25. Tripti Singh, Research Associate

Policy briefs:

i. Manual Scavenging in India: A Literature Review & Annotated Bibliography, Kimberly Noronha, Mahima Malik, March 2018

Presentation at round table conferences

i. Gendered Household Decision Making among the Poor: A Barrier to Toilet Adoption? , IHC, Delhi, CURE, January 2018

Sitting task forces and working groups:

i. The Gender Taskforce on Sanitation, It serves as a platform for its members to address issues that are a critical component of the ecosystem of solutions needed to integrate gender in the national sanitation agenda, February, 2017-Ongoing

Targeted meeting with policy makers:

i. Workshop on Skills and Livelihoods in Sanitation Sector, MHUA, 12 Jan, 2018
ii. Meeting to discuss Caste and Gender based discrimination in Sanitation , UN Special Rapporteur on Human Rights to Water and Sanitation ,29 October 2017

26. Vincy Davis, Research Associate

Journal articles:

i. RTE Act and Paradigm Shifts in Student Assessments Vincy Davis, Taanya Kapoor, IAPS DIALOGUE: THE ONLINE MAGAZINE OF THE INSTITUTE OF ASIA & PACIFIC STUDIES, University of Nottingham, February 2018

Presentation at conferences:

i. Comparative & International Education Society Annual Conference " Remapping Global Education: South-North Dialogue" , "Rethinking teacher practices - Lessons from inquiries into studies on teacher functioning in Delhi", Mexico City, CIES, Teachers College, Columbia University, March 2018

Web-based publications:

i. Bridging Gaps Between Citizens And The Bureaucracy - Part 1, Vincy Davis, Accountabilityindia.in, 30 June
ii. Bridging Gaps Between Citizens And The Bureaucracy – Part 2, Vincy Davis, Accountabilityindia.in, 7 July
iii. Right To Whose Education? Vincy Davis, Accountabilityindia.in, 15 June
iv. Life Hacks To Avail Government Benefits And Services, Vincy Davis, Accountabilityindia.in 9 May

Presentation at round tables conferences:

i. Orientation Programme on Social Science Research for Scholars and Lecturers belonging to SC, ST, and other Marginalised Groups, Using NVivo in Qualitative Research 30 Nov- 2 December, 2017, Centre for Policy Research New Delhi Centre for Policy Research
ii. Research Methods and Its Applications in Development Practice – Workshop Research Methods and Its Applications in Development Practice 13th October, 2017 Indian School of Development Management, Noida Indian School of Development Management

Targeted meeting with policy makers:

i. Discussion of provisional findings of the time allocation study of teachers , Delhi Commission for Protection of Child Right, 11th October 2017
ii. Discussion of findings from the time use study of CRCCs, Bihar State Project Director, Bihar Education Project Council, 25th November 2017
iii. Discussion of preliminary findings from the ongoing project on unpacking the Delhi Education Reforms, Director, Education; Advisors to Education Minister GoNCT Delhi, 20th November 2017

27. Sandeep Bhardwaj, Research Associate

Articles in non-reviewed periodicals:

i. Sri Lanka: The Silly Side Of Chinese "Neo-Imperialism" , IAPS Dialogue 6 February 2018
ii. 'Black Panther' and the tragic history of Asian aspirations, Mint, 27 February 2018
iii. India and the mantle of regional hegemon, IAPS Dialogue 13 March 2018
iv. Why India needs to be aggressive against China in Doklam standoff , Mint 28 July 2017
v. Doklam may bring Bhutan closer to India, Mint, 9 August 2017
vi. Bhutan ki Suraksha, Bharat Ka Jimma (in Hindi), Rashtriya Sahara, 9 August 2017

Web-based publications:

i. Rising Tide Of Extremism In Bangladesh, IAPS Dialogue, University of Nottingham, 20 September 2017
ii. Life And Death Of The India-Pakistan Ceasefire Agreement , IAPS Dialogue, University of Nottingham 16 October 2017

28. Reetika Kalita, Research Associate

Research Report:

i. Infrastructure, Gender And Violence: Women And Slum Sanitation Inequalities In Delhi, Susan Chaplin, Reetika Kalita, 16 October 2017

29.Susan Chaplin

Working paper:

i. Gender, urban sanitation inequalities and everyday lives: A literature review and annotation bibliography, 2017, August
ii. Infrastructure, gender and violence Women and slum sanitation inequalities in Delhi: Research Report, Kalita, Reetika, 2017, October

Presentation at conferences:

i. Sanitation for People: Assessing socio-cultural realities of sanitation practice in Indian cities, Infrastructure, gender and violence: Women and slum sanitation inequalities, 29 March 2017

30. Ritwik Shukla, Research Associate

Policy briefs

i. SSA Budget Brief, Avani Kapur, Mridusmita Bordoloi, 2nd February 2018
ii. RMSA Budget Brief, Avani Kapur, Mridusmita Bordoloi, 2nd February 2018

Web-based publications:

i. Digitising Welfare: Lessons from Rural Bihar, Accountability Initiative Blogs 22nd February 2018

31. Marie – Helene Zerah, Visiting Fellow

Working paper:

i. Demande et acceptabilité sociales de l'assainissement : les, enjeux invisibles de genre, de caste et d'emploi., Sweta Cess In L'assainissement et ses enjeux, Notes Techniques n°21, Agence Française de Développement, Paris, March 2018
ii. Working in Tandem: The informal septic tank emptying business in Aya Nagar, Delhi, Sweta Cess, CPR Working Report ,December 2017

Articles in non-reviewed periodicals:

i. Les petits villes, l'autre visage de l'urbanisation en Inde, The Conversation, 8 March 2018

Paper presented for presentation at conferences:

i. Emergent Forms of Urban Densification in Asia. Shared Issues. Debating the relationships between density and governance and basic services: Comparative views from two case studies in India and Indonesia, Hanoi, Vietnam , Hanoi Architectural University , Co-written with Paramita Rahayu and Sweta Cess, November 2017

32. Pranav Kuttiah, Research Assistant

Articles in non-reviewed periodicals:

i. Hinduism not a monolith: Lingayat push will redefine south Indian politicsPranav Kuttaiah , The News Minute, 27 March 2018

LIBRARY AND INFORMATION & DISSEMINATION SERVICES

During the year 2017-18,119 books were added to the library of the Centre. The acquisition mainly related to books of subjects such as Policy Sciences, Economic Policy, Urbanisation, Political Science, Futurology, Social Indicators, Foreign Policy, Defence and other fields of relevance to Research Programmes of the Centre.

The CPR library has a collection of a total of 10742 books after weeding a few old books. The library subscribed to 46 journals and received gratis 50 periodicals. These cover major policy fields of concern to scholars at CPR. In addition to these, 16 daily newspapers are being received in the library.

The library continued to be a member of the Developing Library Network (DELNET), New Delhi. One Samsung SCX 4521F multifunctional fax machine and e-mail service are being used extensively for communication and information retrieval purposes. One HP Elite 8300 is being used by CPR faculty/researchers.

With the help of RICOH AFICIO MP 4000 B Digital Plain Paper Copier with Reverse Automatic Document Feeder, Duplexing for Automatic Back to Back copying, Set making, Sorting, Rotate sorting, 25%- 400% Zoom with A-3 Size Network Laser Printer and Scanner, and 40 GB Hard Disc for document server, better and efficient reprographic facilities were provided to researchers and other staff of the Centre.

For other material and publications, the CPR library depends upon the services of 20 libraries of various academic and other research institutions in Delhi which have been generous enough to lend their books and journals for the Centre's use on the principle of reciprocity.

COMPUTER UNIT's ACTIVITIES

During the year under report, following activities were undertaken by the Computer Centre.

1. Services hosted at cprindia.org domain on Google Suite were maintained and configured as per requirement.
2. The Centre migrated its Internet Lease Line (ILL) link from Tata Communications Ltd to Tata Teleservices Ltd & the Internet bandwidth was also increased from 16 Mbps to 30 Mbps to meet its data traffic demand. Bandwidth allocation policy was fine-tuned by distributing it among groups such as Faculty, Staff, and Communications etc. as per their usage (downloading/uploading).
3. To protect Centre's network and gateway from external threats, prevent undesirable content filtering into the network and implementing various policies required for smooth functioning of the Network, definitions of Dell SonicWALL firewall were configured.
4. Hardware & software licenses procured and disposed
    a. Fourteen laptops, One HP LaserJet printer, one Apple IPad, Two Tablets, one Projector and one Zone Flex R610 Access Point (AP) were purchased, configured and installed as per requirements of the users.
    b. Licenses of Adobe creative cloud suite (02 nos.), Auto Cad LT 2018 Desktop DTS (01 no.) were purchased and installed.
    c. License of CGSS Suite & hardware replacement warranty plus support of SonicWALL Firewall NSA 250 installed at the Centre was renewed.
    d. One more license to support AP was purchased & configured thereby increasing Wireless controller's capacity to support seven Access Points (A.P's).
    e. Obsolete hardware (04 PC's, 15 Laptops, 05 Printers, 04 UPS, 03 Network Switches) were disposed off.
5. Maintenance and Configuration of Centre's Local Area and Wi-Fi Network, Hardware and software were carried out as per requirement. IT support services were provided to all users of the Centre by attending their hardware & software issues. Support services related to seminars and conferences held at the Centre during the year were also provided. Periodical backup of the data stored on Network Storage Device (NAS) was taken on the external hard drive. Annual Stock verification of IT related hardware installed/issued at the Centre was carried out.

GRANTS

The CPR received the following grants from the ICSSR during the financial year 2017-18 (in lakhs):

1.	Recurring grant OH (36)	Rs. 95.00
2.	Recurring grant OH (31)	Rs. 54.00
-	Total:	Rs.149.00

The CPR gross corpus fund now stands at Rs. 1013.82 lakh. CPR's gross receipts (including specific project receipts) during the year was Rs. 2134.55 lakh. ICSSR recurring grant is 6.98% of CPR's gross receipts during the year.

A number of agencies and Government departments as named below continued their support to the Centre during the year:

List of Project Grantors

1. Indian Council of Social Science Research, New Delhi
2. IDRC, Canada
3. Bill and Melinda Gates Foundation, USA
4. William & Flora Hewlett Foundation, USA
5. Ford Foundation, USA
6. Oak Foundation
7. The Asia Foundation, USA
8. NAMATI Inc. USA
9. Omidyar Network Foundation, USA
10. Mac Arthur Foundation, USA
11. Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai
12. Chr. Michelsen Institute, Norway
13. Institute of Research and Development, France
14. Korea Foundation
15. Duleep Mathai Nature Conservation Trust
16. Jamnalal Bajaj Foundation
17. World Bank

TAX EXEMPTION FOR DONATIONS TO CPR

CPR has been approved u/s 35(1)(iii) of the Income Tax Act 1961 w.e.f. April 1, 2005 which entitles the Donor under the present Income Tax Laws a weighted deduction @ 125% of the amount of donation. CPR has also been approved u/s 80G(5) (vi) of the Income Tax Act, 1961 for the period from April 1, 2011 onwards which entitles the donor 50% tax deduction of the net qualifying amount

CPR FACULTY AND STAFF

(As on 31 March 2018)

Professors and Senior Fellows

1. Yamini Aiyar — September 2017
   President & Chief Executive
2. Brahma Chellaney — July 1993
   Professor , PhD (Jawaharlal Nehru University)
3. Lavanya Rajamani — September 2006
   Professor, D Phil (University of Oxford)
4. Srinath Raghavan
   Professor

Professor Emeritus

5. Charan Wadhva (Ph.D, Yale, USA) — September 2005

Honorary Research/Visiting Professors

6. Subhash C Kashyap
7. Ved Marwah (Retd. IPS)
8. K R G Nair
9. R. Rangachari
10. B N Saxena
11. Sanjib Baruah
12. Sanjoy Hazarika
13. G Parthasarathy
14. Bharat Karnad

Associate Professors

15. Nimmi Kurian Ph.D. (JNU)

Senior Fellows

16. Partha Mukhopadhyay
17. Shylashri Shankar
18. Ramesh Chandran
19. Shubhagato Dasgupta
20. Navroz Dubash
21. Shyam Saran
22. Shyam Babu
23. Anjali Chikersal
24. Neelanjan Sircar
25. Kiran Bhatty
26. Manju Menon

Senior Visiting Fellows

27. Philippe Cullet
28. Jishnu Das
29. Rani Mullen
30. Marie- Helene Zerah
31. Sanjaya Baru

Legal Research Director, Namati

32. Kanchi Kohli

Fellows

33. Avani Kapur
34. Namita Wahi
35. Radhika Khosla
36. Srinivas Chokkakula
37. Arkaja Singh
38. Shibani Ghosh
39. Zorawar Daulet Singh

Visiting Fellow

40. Ashwini Swain

Senior Researchers

41. Mridusmita Bordoloi
42. Ashwin Parulkar
43. Mukta Naik
44. Anindita Mukherjee
45. Anju Dwivedi
46. Shamindranath Roy

Senior Research Associate

47. Devashish Deshpande
48. Aditya Bhol
49. MM Shankar Gowda (Part-Time)
50. Ambarish Karunanithi
51. Vincy Davis
52. Kanhu Charan Pradhan
53. Parma Chakravarti

Research Associates

54. Sandeep Bhardwaj
55. Tanya Kapoor
56. Stanzin Yumchen
57. Sama Khan
58. Prerananandita Baisnab
59. Swati Dhiman (Part-time)
60. Sharonee Dasgupta
61. Babu Lal
62. Ankit Bhardwaj
63. Reetika Kalita
64. Ankit Bhatia
65. Sahithya Venkatesan
66. Kashyap Arora
67. Jaidev Joshi
68. Neha Agarwal
69. Meghna Paul
70. Sweta Celine Xess
71. Ritwik Shukla
72. Meghna Shrivastav
73. Tripti Singh
74. Krithika A Dinesh
75. Ruchi Junnarkar
76. Manish
77. Abhishri Aggarwal
78. Eesha Kunduri
79. Sunil Kumar Singh
80. Deepti Raj
81. Parth Bhatia

Research Assistants

82. Bal Govind
83. Suneel Kumar
84. Prashant Arya
85. Dona Mathew
86. Pranav Kuttaiah

Program Staff

87. Vidya Vishwanathan, Senior Program Manager
88. Nilanjan Chaudhary, Program Coordinator
89. Bharat Bhai Hari Bhai Dodiya, Enviro-Legal Coordinator
90. Meenakshi Kapoor, Program Manager
91. Mahabaleshwar Hegde, Senior Program Manager
92. Santosh Rao Dara, Program Manager

Administration, Accounts, IT, Communications & Other Services

93. L. Ravi
    Chief, Administrative Services
94. Ajay Nayyar
    Senior System Analyst
95. Richa Bansal
    Director (Communications)
96. Dhruv Arora, Digital Communications Manager
97. Neha Gour, Central Communications Coordinator

98. Bipin Bihari Nayak (Part-Time), Junior Designer
99. Pradeep Khanna
Chief Accounts Officer
100. M.C. Bhatt
Accounts Officer
101. Ramesh Kumar
Accounts Assistant
102. V.K. Tanwar
Assistant System Analyst Assistant Programmes
103. Dinesh Chandra
Senior Supervisor
104. Shiv Charan
Senior Supervisor
105. Y.G.S. Chauhan
Assistant Librarian
106. Sunil Kumar
Associate to President
107. Pramod Kumar Malik
Associate to President
108. Sonia Bhutani Gulati
Public Relations Associate
109. Vinod Kumar
Deputy Supervisor
110. Sarala Gopinathan
Secretarial Assistant
111. Satnam Kaur
Finance and Admn. Manager
112. Ajit Kumar Misra
Finance and Admn. Associate
113. Ravi Raunaq Robin, Administrative Assistant
114. Pankaj Kumar Mishra, Network Assistant
115. Avantika Srivastava, Senior Communications Officer

Other Supporting Staff

116. Ranjit Singh
117. Poona Ram
118. Rohan

V. SANKAR AIYAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Flat No.202 & 301, Satyam Cinema Complex
Ranjit Nagar Community Centre, New Delhi – 110008
Tel.(011) 25702691, 25704639; e-mail: newdelhi@vsa.co.in

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF CENTRE FOR POLICY RESEARCH

Report on Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **CENTRE FOR POLICY RESEARCH (the Society)**, which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2018 and the Income and Expenditure Account for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Society in accordance with the Generally Accepted Accounting Practices in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the organization and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Society's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting principles used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Society's Governing Board, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

V. SANKAR AIYAR & CO. NEW DELHI FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements, read with other notes given thereto, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at 31st March 2018; and

b) in the case of the Income and Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date;

Other Matters

a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Society so far as appears from our examination of the books of accounts.

c) The Balance Sheet, and the Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account

For V. Sankar Aiyar & Co.
Chartered Accountants
(Firm Regn. No.: 109208W)

M.S. BALACHANDRAN
Partner (M. No: 024282)

V. SANKAR AIYAR & CO. NEW DELHI FRN 109208W CHARTERED ACCOUNTANTS

Place: NEW DELHI
Dated: 19/07/2018

CENTRE FOR POLICY RESEARCH					
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2018					
					Amount in Rs.
FUNDS AND LIABILITIES	**Sch**		**As on 31.3.2018**		**As on 31.3.2017**
CORPUS FUND (SPECIFIC)	1		37,959,000		37,959,000
CORPUS FUND (GENERAL)	1		62,723,405		62,723,405
CAPITAL FUND (ASSETS)	2		8,562,407		9,387,087
CAPITAL RESERVE			4,408,025		4,408,025
ENDOWMENT FUND			700,000		700,000
RESERVE FOR CONTINGENCIES			10,200,000		10,200,000
UNSPENT BALANCES IN SPECIFIED PURPOSES/ PROJECTS	3		224,425,037		230,114,206
GRANT - NATIONAL KNOWLEDGE COMMISSION	4		1,370,804		1,081,532
PROVISIONS	5		12,918,644		12,918,644
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT			37,649,495		35,355,682
CURRENT LIABILITIES	9		735,511		691,849
TOTAL			401,652,328		405,539,430
PROPERTY & ASSETS					
FIXED ASSETS	6				
Gross Block		37,427,295		37,293,332	
Less: Accumulated Depreciation		28,864,888	8,562,407	27,906,245	9,387,087
INVESTMENTS	7		355,082,059		379,373,247
(including Corpus Fund Invetments)					

CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES:	8				
Cash and Bank Balances	8(a)	22,775,648		7,722,851	
Advances recoverable/ adjustable	8(b)	15,232,214	38,007,862	9,056,245	16,779,096
TOTAL			401,652,328		405,539,430
Accounting policies and notes on accounts	10				
					For and on behalf of
sd					**CENTRE FOR POLICY RESEARCH**
AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE.					
FOR V.SANKAR AIYAR & CO.					
CHARTERED ACCOUNTANTS					
(Firm's Registation No. 109208W)					sd
					(YAMINI MRINALIKA AIYAR)
sd					PRESIDENT
(M.S.BALACHANDRAN)					
PARTNER (M.No. 024282)					
				sd	sd
PLACE: NEW DELHI				**(PRADEEP KHANNA)**	**(L RAVI)**
DATED: 19.07.2018				CHIEF ACCOUNTS OFFICER	CHIEF - ADMINISTRATIVE SERVICES

CENTRE FOR POLICY RESEARCH					
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018					
					Amount in Rs.
INCOME			**2017-18**		**2016-17**
Grant-in-Aid from ICSSR			14,900,000		13,271,000
Interest on Investments:					
Endowment and Corpus Interest		4,359,552		4,711,144	
Dividend Income on Corpus		153,105		153,104	
Interest on Income Tax Refunds		92,854		180,886	
Other Interest Income		5,114,473	9,719,984	5,040,647	10,085,781
Miscellaneous Income			147,442		291,271
Transfer from Grants			17,723,850		17,751,772
Completed Projects - Balances written back (Net)			69,140		612,236
Proceeds on sale of assets			81,507		17,265
Service Tax Written Back			-		1,127,280
Royalty			657		1,440
TOTAL			42,642,580		43,158,045
EXPENDITURE			**2017-18**		**2016-17**
SALARIES,WAGES & BENEFITS TO STAFF					
Salaries and wages		29,169,247		29,003,183	
Contribution to Provident Fund		1,906,235		1,954,642	
Contribution to Gratuity Fund (LIC)		1,000,000		1,000,000	

Contribution to / payment of Leave Encashment Benefits		1,019,460		1,000,000	
Medical Insurance & other Staff Welfare		300,091	33,395,033	311,472	33,269,297
Travel and conveyance			498,341		286,028
Rates and taxes			296,220		836,782
Printing, stationery, office supplies			123,403		122,176
Communication expenses			168,352		236,405
Electricity and water			608,144		578,876
Office maintenance and repairs			748,763		677,031
Hospitality and common courtesy			152,426		188,680
Insurance			38,531		37,588
Library books, newspapers and periodicals			591,987		378,784
Audit and other fee			402,500		363,025
Miscellaneous expenses			34,829		45,886
Membership and subscriptions			-		74,750
Service tax input credit written off			72,630		-
Bank charges and interest			7,994		18,533
Conference and Programmes			888,131		570,758
Advertsiement			223,569		-
Vehicle maintenance			87,255		72,090
Legal and professional			1,926,059		520,120
Depreciation		2,051,495		2,264,854	-
Less: Met from Capital Fund		2,051,495	-	2,264,854	-

Total C.O.			40,264,167		38,276,809
EXPENDITURE			**2017-18**		**2016-17**
Total B.F.			40,264,167		38,276,809
Provisions/ Appropriations:					
Transfer to Capital Fund - Amount equivalent to addition to assets out of non-project fund			84,600		1,576,280
			40,348,767		39,853,089
Surplus for the year after appropriations			2,293,813		3,304,956
Surplus brought forward			35,355,682		32,050,726
Accumulated surplus carried to Balance sheet			37,649,495		35,355,682
					sd
					For and on behalf of
					CENTRE FOR POLICY RESEARCH
AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE.					
FOR V.SANKAR AIYAR & CO.					
CHARTERED ACCOUNTANTS					
(Firm's Registation No. 109208W)					
					sd
					(YAMINI MRINALIKA AIYAR)
sd					PRESIDENT
(M.S.BALACHANDRAN)					

PARTNER (M.No. 024282)					
				sd	
PLACE: NEW DELHI				**(PRADEEP KHANNA)**	**sd (L RAVI)**
DATED: 19.07.2018				CHIEF ACCOUNTS OFFICER	CHIEF-ADMINISTRATIVE SERVICES

CENTRE FOR POLICY RESEARCH										
BALANCE OF CONTRIBUTION FOR SPECIFIED PURPOSES/PROJECTS AS ON 31.03.2018										
										SCHEDULE - 3
										(AMOUNT IN Rs)
S. No.	**NAME OF SPONSOR AND PROJECT**	**Opening Balance (01.04.2017)**		**Receipts during the year**	**Interest/ Dividend**	**Transfer to Income and Exp A/c**	**Disbursements during the year**	**Completed projects balances written off/ back (NET)**	**Closing Balance (31.03.2018)**	
		DR.	**CR.**						**DR.**	**CR.**
	FOREIGN CONTRIBUTION GRANTS									
1	THE ASIA FOUNDATION-WATER INCIDENCE MONITORING SYSTEMS (WIMS) FOR THE KRISHNA RIVER BASIN	-	-	1,456,000	-	220,000	1,369,668	(133,668)	-	-
2	BILL MILINDA GATES FOUNDATION-STRENGTHENING AWARENESS OF ELECTED REPRESENTATIVES ON MATERNAL AND CHILD HEALTH AND DIGITAL FINANCIAL INCULSIONS IN INDIA (GPPI)	-	686,928	-	-	1,307	16,789	-	-	668,832
3	BILL MILINDA GATES FOUNDATION- SCI -FI	-	43,749,991	-	3,196,376	980,017	6,534,347	-	-	39,432,003

4	BILL MILINDA GATES FOUNDATION- SCI F-II		62,470,556	-	4,847,540	4,627,743	30,854,339	-	-	31,836,014
5	BILL MILINDA GATES FOUNDATION-SUPPLIMENTARY GRANT NO. OPP1038511 - NIRMAL STUDY	-	26,844,907	9,608,630	3,349,701	1,311,254	8,742,401	-	-	29,749,583
6	BILL MILINDA GATES FOUNDATION-TRACKING NUTRITION EXPENDITURE	-	-	28,526,822	173,250	266,535	1,777,601	-	-	26,655,936
7	BROWN UNIVERSITY-DIGITAL URBAN OBSERVATORY	-	-	785,985	-	-	589,075	-	-	196,910
8	CARNEIGE ENDOWMENT INTERNATIONAL PEACE-REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPSESNS	-	-	81,724	-	-	81,724	-	-	-
9	CLIMATE AND DEVELOPMENT KNOWLEDGE NETWORK (CDKN) - TOWARDS ROBUST CLIMATE COMPATIBLE DEVELOPMENT PLANNING IN INDIA	924,034	-	1,665,903	-	-	740,786	1,083	-	-
10	CEBRAP BRAZIL - POLICY PROCESS IN INDIA:RIGHT TO INFORMATION,SOCIAL AUDIT AND PARTICIPATORY IRRIGATION MANAGEMENT	-	322,602	-	-	-	131,080	-	-	191,522

11	CMI- LAND RIGHTS, ENVIRONMENTAL PROTECTION	-	528,914	1,570,012	-	-	2,098,926	-	-	-
12	CMI- WATER RIGHTS	-	-	963,670	-	-	775,146	-		188,524
13	CENTER DE SCIENCES HUMAINES - SUBURBIN ON SUBALTERN URBANIZATION IN INDIA	-	293,889				65,600	-	-	228,289
14	EMBASSY OF JAPAN- REIMBURSEMENT OF WORKSHOP EXPENSES	511,608	-	1,141,807			362,511	-	-	267,688
15	THE FORD FOUNDATION - ACCOUNTABILITY INITIATIVE	-	5,290,315	-	48,616	332,415	5,006,516	-	-	-
16	THE FORD FOUNDATION (INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION) - KOLKATTA EXPERIENCE	-	169,316	-	-	-	-	-	-	169,316
17	THE FORD FOUNDATION- FOREIGN CURRENCY CORPUS INCOME (FCCI)	-	2,542,566	-	440,610	-	344,722	-	-	2,638,454
18	FORD FOUNDATION - PERPETUITY CHAIR- SAARC	-	16,432,086	-	1,217,561	-	-	-	-	17,649,647
19	THE FORD FOUNDATION CORPUS INCOME FOR TRACK II DIALOGUES	-	7,996,586		2,465,222	-	3,980,313	-	-	6,481,495
20	THE FORD FOUNDATION - STUDY URBAN RESEARCH NETWORK IN	-	-	23,697,814	553,931	761,793	12,888,945	-	-	10,601,007

	INDIA TO SURFACE THE TACIT KNOWLEDGE ON URBAN INFORMALITY									
21	GEORGE TOWN UNIVERSITY- DIGITAL URBAN OBSERVATORY	-	-	835,640	-	-	835,640	-	-	-
22	GLOBAL HEALTH STRATEGIES EMERGING ECONOMIES - GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY INITIATIVE	-	1,600,472	7,020,000	59,836	428,852	4,873,520	-	-	3,377,936
23	HARVARD UNIVERSITY CAMBRIDGE MASSACHUSETTS - REIMBURSUMENT OF EXPENSES	-	106,381	-	-	-	-	-	-	106,381
24	HEINRICH BOLL STIFTUNG- ENVIRONMENTAL REGULATION TO ADDRESS IMPACTS OF INDUSTRIAL	-	17,896	(17,896)	-	-	-	-	-	-
25	IDRC-CANADA-ROLE OF SMALL CITIES IN SHAPING YOUTH EMPLOYMENT OUTCOMES IN INDIA	-	3,001,294	1,622,411	145,734	-	2,146,482	-	-	2,622,957
26	INNOVATION FOR POVERTY ACTION- GLOBAL HEALTH PROGRAM TO ACCESS THE AVAILABILITY AND DELIVERY HEALTH SERVICES IN INDIA AND INDONESIA	-	4,541,371	-	-	-	31,882	-	-	4,509,489

27	INSTITUE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FRANCE (IRD)- INDIAN RURAL BOUNDARIES AND BASIC SERVICES ETC	-	2,211,828	-	-	140,517	1,405,865	-	-	665,446
28	KOREA FOUNDATION-THE NEW GREAT GAME IN EAST ASIA	-	-	3,236,750	-	13,315	133,153	-	-	3,090,282
29	JOHN D.AND CATHERINE T. 'MAC ARTHUR FOUNDATION-FOR DEVELOPING PRACTICE ON INTEGRATING CLIMATE, ENERGY AND ENVIRONMENT IN INDIA'S DEVELOPMENT FUTURE 16-1603-150748-CLS	288,000	-	6,447,168		545,940	3,640,296	-	-	1,972,932
30	MRS CHANDRIKA PATHAK AND MR DALIP PATHAK-RESEARCH ON DRINKING WATER IN INDIA	-	480,573	-	85,701	-	552,184	14,090	-	-
31	NAMATI-ENVIORNMENTAL JUSTICE	90,378	-	29,096,851	112,879	3,309,347	22,065,474	-	-	3,744,531
32	OAK FOUNDATION-UNRESTRICTED SUPPORT -CLIMATE INITIATIVE - II	-	4,864,778	5,262,635	7,181	775,352	5,162,942	-	-	4,196,300
33	OMIDYAR NETWORK FUND -ACCOUNTABILITY INITIATIVE	377,497	-	10,956,500	238,615	1,377,633	9,184,218	-	-	255,767

34	SEPHIS-NEETHERLANDS	-	907,904	-	146,204	-	138,806	-	-	915,302
35	INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE-THINK TANK INITIATIVE PHASE II	-	2,676,001	16,074,106	115,183	-	17,445,297	-	-	1,419,993
36	UNIVERSITY OF CALIFORNIA- SC	-	-	415,926	-	67,852	516,027	-	167,953	-
37	UNIVERSITY OF MANCHESTER-REIMBURSEMENT OF WORKSHOP EXPENSES IN CONNECTION WITH THE ACCOUNTABILITY INITIATIVE	-	204,328	-				-	-	204,328
38	UNESCO ACCOUNTABILITY INITIATIVE	-	-	578,790	-	57,879	520,911	-	-	-
39	WILLIAM & FLORA HEWLETT FOUNDATION-ACCOUNTABILITY INITIATIVE- NEW INFRASTRUCTURE GRANT	-	4,969,112	-	160,434	997,381	6,651,594	-	2,519,429	-
	SUB TOTAL	2,191,517	192,910,594	151,027,248	17,364,574	16,215,132	151,664,780	(118,495)	2,687,382	194,036,864
	DOMESTIC GRANTS									
40	APCO WORLDWIDE INDIA PVT LTD-ASSESSMENT ON THE EXISTING IMMORAL TRAFIC (PREVENTION)	-	-	407,100	-	-	389,100	18,000	-	-

	ACT,1986 TO DEVELOP A POLICY BRIEF									
41	ASHOKA UNIVERSITY-URBANISATION AND URBAN SYSTEM CITY DEBATES	-	-	30,509	-	-	58,438	-	27,929	-
41	DELHI COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS (DCPCR)	-	-	-	-	-	111,381	-	111,381	-
42	DULEEP MATHAI NATURE CONSERVATION TRUST-DESIGNING OF INFORMATION,EDUCATION AND COMMUNICATION MATERIAL ON WATER POLUTION ,THE COMMON ORDER AND HUMAN WILDLIFE CONFLICT	-	-	1,300,000	-	99,673	996,727	-	-	203,600
43	HUMAN SETTLEMENT MANAGEMENT INSTITUTE (HSMI) - HOMELESSNESS	-	-	-	-	-	15,645	-	15,645	
44	INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH-PPP MATERNAL CARE	-	19,940		-	-	-	-	-	19,940
45	INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH-CENTRE HEALTH POLICIES RESEARCH WITH EMPHASIS ON REPRODUCTIVE HEALTH MATTERS	-	9,523		-	-	-	-	-	9,523

46	ICSSR-DOMINANT CASTE DEMAND	-	-	80,000	-	-	17,062	-	-	62,938
47	ICSSR-SECULARISM & SOCIAL CAPITAL AMONG THE MARGINALISED	-	17,989		-	-	-	-	-	17,989
48	ICSSR-INDIA'S MIDDLE CLASS	-	1,148,339	(1,148,339)	-	-	-	-	-	-
49	ICSSR- URBAN TRNASFORMATION IN INDIA	-	43,143	156,121	-	199,264	-	-	-	-
50	ICSSR- AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY	368,251	-		-	-	-	-	368,251	-
51	ICSSR-ENVIRONMENTAL JURISPRUDENCE	264,736	-	264,736	-	-	-	-	-	-
52	ICSSR-UNDERSTANDING METROPOLITAN HOMLESSNESS A CASE STUDY OF DELHI	-	1,510,510	-	-	-	1,924,809	-	414,299	-
53	ICSSR- LAND RIGHTS DEVELOPMENT AND THE CONSTITUTION:MAPPIN G LAND LEGISLATION IN INDIA	-	1,441,926	-	-	-	1,144,305	-	-	297,621
54	ICSSR ORIENTATION PROGRAMME- FOR RESEARCH SCHOLARS AND FACULTY MEMBERS BELONGINGS TO SC ST AND OTHER MARGINALISED GROUPS UNDER SC COMPONENT	-	1,285,718	1,000,000	-	-	333,812	-	-	1,951,906

55	IGIDR/SHRAMIC - STRENGTHEN AND HARMONIZE RESEARCH AND ACTION ON MIGRATION IN THE INDIAN CONTEXT (SHRAMIC)	817,222	-	1,688,457	-	-	871,235	-	-	-
56	IGIDR/SHRAMIC - REIMBURSEMENT OF SEMINAR EXPENSES	-	16,441	1,881	-	-	18,322	-	-	-
57	INDIA HEALTH ACTION TRUST-SERVICES FOR IMPROVING FINANCIAL MANAGEMENT AT NATIONAL HEALTH MISSION, UTTAR PRADESH	-	-	463,740	-	19,615	463,045	-	18,920	-
58	JAMNALAL BAJAJ FOUNDATION-GOVERNANCE IN PUBLIC POLICY INITIATIVE	-	10,388,012	5,000,000	325,613	577,798	5,778,660	-	-	9,357,167
59	INSTITUTE FOR FINANCIAL MANAGEMENT AND SEARCH- (IFMR)-CHENNAI -CONDUCT A QUALITATIVE STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF CHUNAUTI THE INITIATIVE OF GOVERNMENT OF NCT DELHI	-	180,000	-	-	-	486,000	-	306,000	-
60	KILA REIMB OF WORKSHOP EXPENSES	-	-	-	-	-	26,223	-	26,223	-
61	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS- BCIM 10TH	-	112,699	-	-	-	-	-	-	112,699

	DIALOGUE 18-19 FEB 12 AND BCIM 11TH DIALOGUE 23-24 FEB 2013									
62	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS,GOVERNMENT OF INDIA-CORPUS INCOME FOR TRACK II DIALOGUES	2,926	-	-	-	-	-	-	2,926	-
63	MINISTRY OF FINANCE-GOVERNMENT OF INDIA-CORPUS INCOME	-	8,189		450,000	450,000	118	-	-	8,071
64	METAMORPHOSES TECH TALK SERIES	-	-	200,000	-	-	13,843	-	-	186,157
65	NATIONAL COMMISSION ON POPULATION (NCP) - CORPUS INCOME	-	14,661,773	-	712,463	-	-	-	-	15,374,236
66	NITI AAYOG-METAMORPHOSE TECH TALK SERIES	-	-	1,180,000	-	-	314,964	-	-	865,036
67	POPULATION FOUNDATION OF INDIA-OVERALL PROGRAM IMPLIMENTATION PLAN (PIP) OUTCOME ANALYSIS FOR 18 SATES AND IN DEPTH PIP PROCESS IN TWO STATES -ACCOUNTABILITY INITIATIVE	-	470,988	2,098,936	-	177,680	2,061,145	-	-	331,099
68	SAMBODHI RESEARCH AND COMMUNICATIONS PVT LTD - MONITORING AND EVALUATING THE UP TECHNICAL SUPPORT	-	4,226,087	-	-	-	4,056,452	169,635	-	-

69	SWISS AGENCY FOR DEVELOPMENT AND COOPERATION - EMBASSY OF SWITZERLAND NEW DELHI (SDC) - INTEGRATING ENERGY AND CLIMATE OBJECTIVE AND INDIAN CITIES	966,554	-	3,500,000	-	387,724	2,584,826	-	439,104	-
70	TATA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES-URBAN RELATED (TISS)	7,913	-	259,540	-	-	247,666	-	-	3,961
71	UNOPS/WSSCC -DESIGN AND IMPLEMENTATION OF RESEARCH IN INDIA ON THE HUMAN RIGHTS TO SAFE DRINKING WATER AND SANITATION	-	1,416,335	-	-	8,625	50,000	-	-	1,357,710
72	UNESCO-ACCOUNTABILITY INITIATIVE	-	-	383,385		38,339	345,046	-	-	-
73	UNESCO-DESIGNING MOBILE PHONE BASED DATA COLLECTION TOOL FOR ADMINISTRING ATTENDANCE IN SCHOOL	-	246,000	-	-	-	246,000	-	-	-
74	UNICEF-ACCOUNTABILITY INITIATIVE UNDER THE PROGRAMME COOPERATION AGREEMENT (IV)	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-

75	UNICEF-ACCOUNTABILITY INITIATIVE UNDER THE PROGRAMME COOPERATION AGREEMENT (V)	225,684	-	-	-	-	-	-	225,684	-
76	WORLD BANK - REIMBURSEMENT OF EXPENSES OF WORKSHOP ON INTERNATIONAL EXPERIENCE AND LESSONS LEARNT FROM BRAZIL IN DECENTRALISATION	39,007	-	39,007	-	-	-	-	-	-
77	WORLD BANK - WATER PARTNERSHIP PROGRAME GRANT NO. 7183221	-	-	1,021,480	-	-	972,980	-	-	48,500
78	WORLD BANK - SOCIAL PROTECTION IN ODISHA GRANT NO. 7183159	-	-	1,036,088	-	-	1,229,388	-	193,300	-
79	WORLD BANK - HEALTH AND EDUCATION DISTRIBUTIONAL ANALYSIS GRANT NO. 7185776	-	-	212,424	-	-	32,404	-	-	180,020
	SUB TOTAL	2,892,293	37,203,612	19,175,065	1,488,076	1,958,718	24,789,596	187,635	2,349,662	30,388,173
	TOTAL	**5,083,810**	**230,114,206**	**170,202,313**	**18,852,650**	**18,173,850**	**176,454,376**	**69,140**	**5,037,044**	**224,425,037**

CENTRE FOR POLICY RESEARCH

SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS ON 31.03.2018

										(Amount in Rs)	**SCHEDULE -6**
PARTICULARS	RATE OF DEP	COST				DEPRECIATION				WRITTEN DOWN VALUE	
		As on 01.04.2017	Additions	Deletions	As on 31.03.2018	Upto 01.04.2017	Additions	Deletions	Upto 31.03.2018	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
LAND		85,221	-	-	85,221		-	-	-	85,221	85,221
BUILDING	5%	9,643,471	-	-	9,643,471	6,660,235	149,162	-	6,809,397	2,834,074	2,983,236
FURNITURE & FIXTURE	15%	3,526,571	96,779	35,020	3,588,330	2,877,104	111,910	34,843	2,954,171	634,159	649,467
OFFICE EQUIPMENT	15%	6,450,160	141,641	157,870	6,433,931	4,529,035	302,984	114,996	4,717,023	1,716,908	1,921,125
ELECTRIC INSTALLATIONS	15%	319,331	7,200	-	326,531	316,186	1,552	-	317,738	8,793	3,145
VEHICLES	20%	799,668	-	35,199	764,469	484,390	62,991	34,874	512,507	251,962	315,278
AIR COOLING SYSTEM	15%	56,789	-	-	56,789	56,707	12	-	56,719	70	82
OFFICE MACHINERY	40%	11,859,388	1,098,594	982,162	11,975,820	10,004,957	1,151,601	908,139	10,248,419	1,727,401	1,854,431
LIFT	15%	1,805,413	-	-	1,805,413	650,630	173,217	-	823,847	981,566	1,154,783
FIRE FIGHTING EQUIPMENT	15%	1,510,369	-	-	1,510,369	1,353,920	23,467	-	1,377,387	132,982	156,449

OPTICAL MARK SCANNER	40%	740,000	-	-	740,000	682,458	23,017	-	705,475	34,525	57,542
INTANGIBLE ASSETS	25%	496,951	-	-	496,951	290,623	51,582	-	342,205	154,746	206,328
TOTAL		**37,293,332**	**1,344,214**	**1,210,251**	**37,427,295**	**27,906,245**	**2,051,495**	**1,092,852**	**28,864,888**	**8,562,407**	**9,387,087**
PREVIOUS YEAR		34,841,996	2,515,883	64,547	37,293,332	25,692,570	2,264,854	51,179	27,906,245	9,387,087	9,149,426

CENTRE FOR POLICY RESEARCH					
SCHEDULES TO STATEMENT OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018					
					Amount in Rs.
PARTICULARS			**As on 31.3.2018**		**As on 31.3.2017**
INVESTMENTS (At cost)					**Schedule - 7**
(including Corpus Fund Invetments)					
GOI 8 % Savings (Taxable) Bonds			20,720,000		20,220,000
Fixed Deposits with Banks			218,685,739		237,979,246
Fixed Deposits with HDFC Ltd			37,237,457		39,161,113
Fixed Deposits with PNB Housing Finance Ltd			33,954,973		37,528,998
Fixed Deposits with LIC Housing Finance Ltd			40,387,000		40,387,000
Fixed Deposits with HUDCO			1,500,000		1,500,000
Units of UTI			2,096,890		2,096,890
Units of Canara Robeco Mutual Fund			500,000		500,000
Total			355,082,059		379,373,247
a) CASH AND BANK BALANCES					**Schedule - 8**
In current Accounts with:					
Canara Bank C/A NO-0157201000348 - F/C			9,515,238		636,054
Canara Bank - C/A NO-0157201004775			12,891,158		6,269,290
Canara Bank -C/A 0157201005222			8,071		8,189

Punjab National Bank - C/A 1736002100011174			339,689		791,950
Canara Bank -C/A 0157201005827 (NKC)			11,010		11,010
Cash in hand - FC		9,598			4,664
Cash in hand - Non-FC		884	10,482		1,694
Sub-total			22,775,648		7,722,851
b) ADVANCES RECOVERABLE/ ADJUSTABLE					
(Unsecured - considered good and recoverable)					
Staff Imprest and Advances to others			408,814		1,055,744
Security Deposits			137,245		125,245
Tax Deducted at Source			3,360,334		2,791,446
Onward Grants awaiting settlement			6,288,777		-
Debit balances in Specified Grants/ Projects			5,037,044		5,083,810
(excess spent in anticipation of Grant) (Refer Schedule - 3)					
Sub-total			15,232,214		9,056,245
Total			38,007,862		16,779,096
CURRENT LIABILITIES					**Schedule - 9**
Outstanding liabilities			735,511		691,849
Total			735,511		691,849

CENTRE FOR POLICY RESEARCH	
Schedule - 10	
Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	
1	**BASIS OF ACCOUNTING** The financial statements have been prepared under historical cost convention and on a going concern basis. For recognition of Income and Expenses, the Centre follows cash basis of accounting. However, in the case of specified projects the amount incurred by the project staff/ consultants is accounted through individual imprest account, as to exhibit correct utilisation of project funds. The primary objects and activities of the Society are in the field of research and education. The Society has not carried on any activity this year in the nature of commercial, industrial and business and consequently the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India are not mandatory. However, the Standards are followed to the extent relevant and practical.
2	**FIXED ASSETS** Fixed Assets are recorded at cost less depreciation. Fixed Assets purchased out of specific grants, an equal amount is transferred to capital fund. Fixed assets acquired out of non-projects fund (i.e., own funds), an equivalent amount is transferred from current year income and expenditure account. Depreciation though debited to Income and Expenditure Account, is met out of Capital Fund. Capital Fund shows the amount funds (own or projects) utilised for acquistion of assets, net of depreciation to date.
3	**DEPRECIATION** Depreciation is charged on written down value method. In respect of additions, depreciation is charged for the full year. It is ignored on the deletion of assets.
4	**INVESTMENTS**: Investments are valued at cost.
5	**EMPLOYEE BENEFITS** The Centre makes regular contributions to duly constituted fund in respect of Provident , Gratuity and Leave Encashment. The Centre has taken up policies under the Group Gratuity and Leave Encashment Schemes of LIC for meeting the liability. The Centre makes adhoc contributions to the funds and the same is accounted for, as and when paid. The accruing liability for future payment is not ascertained. The Fund balance with the LIC as on 31.03.2018, (including interest credit on funded balances) for Gratuity Fund and Leave Encashment Policy are Rs. 168.75 lakhs and Rs. 87.55 lakhs respectively.

6	**FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS** Foreign currency transactions are generally recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction.
7	**Income Tax:** (i) CPR is registered u/s 12 A (a) of the Income Tax Act, 1961 bearing registration No.DLI (C) (I – 682) dt. 15.04.1976. (ii) The Permanent Account No. (PAN) allotted under the Act is **AAATC0180H**. (iii) CPR is regular in filing the income tax returns, the last one filed being for the Assesment year 2017–18 (relating to FY 2016–17). There are no demands in respect of income tax. (iv) CPR is also approved u/s 80G of the Act covering the period A.Y. 2012-13 and onwards vide letter of the Office of Director of Income Tax (Exemption) dt. 15.09.2011.
8	CPR is registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 bearing Registration No. 231650007 and is regular in filing the annual return, the last one filed being for the financial year 2016-17. The Registration has been renewed by the Ministry of Home Affairs for a period of five years, ie., till 30th November, 2021, under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and Rules made thereunder.
9	The Planning Commission [as a nodal agency for providing services to the National Knowledge Commission (NKC)] had issued an order dt. 3.10.2005, which provided for CPR to act as a secretariat of NKC. The Order further stated that CPR shall maintain a separate account of the expenses of the Secretariat, to be met out of the grant in aid to NKC and would furnish an audited statement of accounts to the Planning Commission. Accordingly, the balance and the corresponding investment thereon are reflected separately.
10	Claims against the society, not acknowledged as debts:- Subsequent to 31st March, 2016, counter-claim towards damages alleging deficiencies in examination conducting service, which the Society has not accepted - Rs.11.73 crore.
11	Estimated amount of outstanding Capital Contracts - Rs. NIL
12	The Office of the Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi. carried out inspection of the accounts of CPR for the period 2004-2005 to 2006-2007. In their observations they have expressed their view that as per the terms and conditions stipulated in the sanction letters for grant issued by the ICSSR, the CPR has received excess grant of Rs.110.75 lakhs during the years 2005-06 and 2006-07, which is refundable. CPR has not accepted the conclusion reached by the government audit. Their report is under examination.

	SIGNATURES TO SCHEDULES 1 TO 10					
						For and on behalf of
						CENTRE FOR POLICY RESEARCH
	FOR V.SANKAR AIYAR & CO.					
	CHARTERED ACCOUNTANTS					
	(Firm's Registation No. 109208W)					sd
						(YAMINI MRINALIKA AIYAR)
						PRESIDENT
	sd					
	(M.S.BALACHANDRAN)					
	PARTNER (M.No. 024282)					
						sd
	PLACE: NEW DELHI					**(PRADEEP KHANNA)** **(L RAVI)**
	DATED: 19.7.2018					CHIEF ACCOUNTS OFFICER CHIEF - ADMINISTRATIVE SERVICES